ISSN No 2347-7075
Impact Factor- 7.328
Volume-1 Issue-2

INTERNATIONAL JOURNAL of ADVANCE and APPLIED RESEARCH

Publisher: P. R. Talekar
Secretary,
Young Researcher Association
Kolhapur(M.S), India

Young Researcher Association

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)

A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal

13th September 2021 Volume-1 Issue-2

On

Impact of Globalization on Sustainable Development

Chief Editor
P. R. Talekar
Secretary, Young Researcher Association, Kolhapur (M.S), India

Executive Editors
Dr. C. B. Kolekar
Principal
Sahakar Maharshi Shankarrao Mohite Patil Mahavidyalaya, Natepute

Co- Editors		
Dr. R. J. Khandare	S. R. Nalawade	D. S. Thorat
J. D. Mulik	S. H. Pawar	Dr. B. T. Nikam
R. A. Shaikh	U. A. Sawant	

Published by- Dr. C. B. Kolekar, Principal, Sahakar Maharshi Shankarrao Mohite Patil Mahavidyalaya, Natepute

The Editors shall not be responsible for originality and thought expressed in the papers. The author shall be solely held responsible for the originality and thoughts expressed in their papers.

© All rights reserved with the Editors

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

CONTENTS

Sr No	Paper Title	Page No.
1	राष्ट्रीय एकीकरण **Dr. Sanjay Tukaram Waghmare**	1-3
2	जागतिकीकरण आणि अनुवादित मराठी साहित्य **प्रोफेसर डॉ. राजेंद्र खंदारे**	4-8
3	आंतरराष्ट्रीयत्ववाद **प्रा. मोहन भाऊसाहेब सावंत**	9-11
4	जागतिकीकरणाचे भारतीय संस्कृतीवर झालेले परिणाम : - एक समाजशास्त्रीय अभ्यास **प्रा. लक्ष्मण बापूराव नैताम**	12-14
5	सोलापूर जिल्ह्यातील कृषी तंत्रज्ञानाचा एक अभ्यास **प्रा.पवार एस.एच., प्रा. मगर एस. बी.**	15-17
6	महाराष्ट्र कुपोषण आणि राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियान **प्रा. नितिन विश्वनाथ खरात, प्राचार्य डॉ. रविंद्र भा. घागस**	18-21
7	वर्धा जिल्ह्यातील रस्ते वितरणाचा भौगोलिक अभ्यास **प्रा. बुद्धघोष म. लोहकरे**	22-25
8	फॅसिझम एक ऐतिहासिक अभ्यास **प्रा. सुहास रामचंद्र नलावडे**	26-32
9	जगतिकीकरणाचा अरुण काळे आणि अजिम नवाज राही यांच्या कवितेवर प्रभाव **डॉ. बालाजी विठ्ठलराव डिगोळे**	33-38
10	भारतातील कोरोना काळातील विद्यार्थी वर्गावर झालेला परिणाम – एक विश्लेषण **प्रा. विजय देविदास वाकोडे**	39-43
11	वैश्वीकरण में अनुवाद का महत्व **प्रा. किसन भानुदास वाघमोडे**	44-47
12	जागतिकीकरणाचा मराठी ग्रामीण साहित्यावरील प्रभाव **प्रा.डॉ. जनार्धन परकाळे**	48-52
13	१९७० च्या दशकातील भारताचे परराष्ट्र धोरण **प्रा. सुहास रामचंद्र नलावडे**	53-57
14	प्रसार:माध्यम आणि शाश्वत विकास **डॉ. बालाजी लक्ष्मणराव शिंदे**	58-60
15	वैश्वीकरण और भारतीय समाज **प्रा. रज्जाक शेख**	61-62
16	राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण **प्रा. मोहन भाऊसाहेब सावंत**	63-67
17	शेतीचे यांत्रिकीकरण :सद्यस्थिती व भविष्यातील दिशा **डॉ.बी.टी.निकम**	68-72
18	जागतिकीकरणात आर्थिक क्षेत्रात उद्योगपती रतन टाटा यांचे योगदान **डॉ.मनीषा जगदीशलाल वर्मा**	73-79
19	विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे धार्मिक विचार **श्री. तेलसंग हनमंत भिमराव**	80-81
20	जागतिकीकरणाचे प्रखर चित्रण करणारी कथासंग्रह 'गुलाबी सिर - द पिंक हेडेड डक' **प्रा. डॉ. अशोक गौरीशंकर माळगे**	82-85
21	पर्यावरणविषयक चळवळी **डॉ. हरी साधू वाघमारे**	86-91
22	**जागतिकीकरणाचा कृषी क्षेत्रावरील परिणाम** **अभिनव गजानन फुटाणे**	92-102
23	आळंदी येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या प्रादेशिक वितरणाचा भौगोलिक अभ्यास **दादासाहेब मारकड डॉ.ओमप्रकाश मुंदे**	103-108

24	जागतिकीकरणाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम **प्रा. डॉ. अनिल पंढरीनाथ कांबळे**	109-114
25	ग्रंथालय माहितीचे व्यवस्थापन व अर्थकारण विविध उदाहरणांसह स्पष्ट करून ग्रंथालयीन व्यवस्थापनातील माहितीच्या अर्थकरणाचे उदाहरणांसह विवेचन **प्रा. पाटील रमेश नवनाथ**	115-119
26	जागतिकीकरणाचा ग्रामीण हुंकार सिझर कर म्हणतेय माती **डॉ. सुनिता पांडुरंग सूर्यवंशी**	120-123
27	जगतिकीकरण आणि भारतीय शेती **प्रा. डॉ. पी. डी. हुडेकर**	124-128

-1International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

राष्ट्रीय एकीकरण

Dr. Sanjay Tukaram Waghmare
Asst. Professor & Head Dept. of History Shankarrao Mohite Mahavidyalay, Akluj - 413101 (MH) PAH Solapur University, Solapur

प्रस्तावना : -

राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातीयों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदाय के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होनी जरूरी है। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबुत करती है। असलमें राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकीकरण को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह देश के लोगों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक और साथ ही असमानताओं के अंतर को कम करने का एक सकारात्मक पैलू है। यह किसी भी समूह, समाज, समुदाय और पुरे देश के लोगों के बीच एक दिन राष्ट्रीय एकता लाने के लिए एकता को मजबूत करने का वादा करता है। यह किसी भी प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता है, हालांकि यह लोगों से हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का अनुरोध है। यह लोगों की एकता और सद्भाव से ही संभव है। उन्हें अपने भावनात्मक बंधन को बढ़ाने के लिए अपने विचारों, मूल्यों और अन्य मुद्दों को साजा करना चाहिए। लोगों को विविधता के भीतर एकता को महसूस करना और जीना चाहिए और हमारी राष्ट्रीय पहचान को सर्वोच्च शक्ति बनाने का प्रयास करना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता का महत्त्व: -

किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकीकरण का अत्याधिक महत्त्व है। यह लोगों को करीब लाने में मदद करता है और समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह एक शांतिपूर्व राष्ट्र का आधार है। नागरिकों को सुरक्षित और सुरक्षित माहौल देने के लिए राष्ट्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोइसे अपने कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। जब व्यक्ति सुरक्षित महसूस करते हैं तभी वे समृध्द और विकसित हो सकते हैं। यह इस प्रकार एक राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारत सहित कई तीसरी दुनिया के देश राष्ट्रीय एकीकरण की कमी के कारण पहले विश्व देशों के बराबर नहीं आ सके हैं। इन देशों में लोग एक-दुसरे को नीचे खींचने में इतने तल्लीन हैं कि उन्हे समझ नहीं आ रहा है कि वे इस आयोजन में अपनी वृध्दि को रोक रहे हैं। वे अपने क्षुद्र मुद्दों के लिए लड़ते रहते हैं और बड़ी तस्वीर को देखने में असमर्थ होते हैं। उनमें समग्र रूप से राष्ट्र को देखने की क्षमता का अभाव हैं। ऐसे मुठ्ठी भर लोग अपने आस-पास के लोगों को उकसाते हैं और समूहों का निर्माण करते हैं जिससे लोगों में घृणा को बढ़वा मिलता है जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा है जो बदल में देश की शांति और सद्भाव के लिए खरता है। सरकार को यहां हस्तक्षेप करना चाहिए और लोगों को नफरत की भावना ने दूर करने और राष्ट्रीय एकता की दिशा में योगदान करने के बारे में जागरूक करना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह : -

19 नवंबर को वर्ष 2013 से भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह देश की पहली महिला प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। 19 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर एक पुरा राष्ट्रीय एकता सप्ताह या कौमी एकता सप्ताह कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ऐकता सप्ताह की शुरूआत देश के नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस सप्ताह को मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता शिबिर, राष्ट्रीय युवा महोत्सव और अंतर्राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम इस सप्ताह का आनंद लेने और हमारे देश के लोगों की बीच एकता को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित कुछ घटनाओं में से एक है।इसके अलावा, लोगों को करीब लाने और मतभेदों को प्रसारित करने के लिए विभिन्न् सांस्कृतिक गतिविधयों और सेमिनार आयोजित किए जाते है।

भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतियां: -

भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों और जातियों आदि की विशाल विविधता का देश है। इन सभी विशेषताओं के कारण ही भारत में अलग-अलग समूह के लोग बसते हैं। भारत में सभी जातियां आगे उप-जातियों में विभाजित की गई हैं और भाषाओं को बोलियों में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जो सबसे महत्त्वपूर्ण है वह है धर्म जिसे उप-धर्मों में विभाजित किया जाता हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते है की भारत एक अनंत विविध सांस्कृतिक परिभाषा को प्रस्तुत करता है क्योंकि यह एक सकते है की भारत अनंत विविध सांस्कृतिक परिभाषा को प्रस्तुत करता है क्योंकि यह एक बड़ी आबादी वाला विशाल देश है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि भारत में विविधता के बीच एकता भी दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे इस प्रकार है।

जातीय विविधता : -

भारत कई विभिन्न समूहों के लोगों से बना है इसलिए इसकी विविधता देश की एकता के लिए एक अव्यक्त खतरा बन गई है। भारतीय समाज देश की एकता के लिए एक अव्यक्त खतरा बन गई है। भारतीय समाज हमेशा जाति, पंथ और धर्मों और भाषाओं के संदर्भ में विभाजित किया गया है। इसी कारण अंग्रेज को विभाजित करने के अपने इरादे में सफल रहे थे। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों में तेजी देखी गई अंतत: भारत से ब्रिटिशों को बाहर करने का काम केवल राष्ट्रीय एकीकरण की सोच रखने वाले व्यक्तियों, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, आदि के कारण ही संभव हो सका।

जातिवाद : -

जातिवाद को पहले से ही एक सामाजिक बुराई माना जाता है। अभी भी लोग अपनी जाति की पहचान पर विभाजित हैं। खासकर राजनीति में जाति एक निर्णायक भूमिका निभा रहीं है। हालांकि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण मुख्यधारा से वंचित लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए दिया गया है, लेकिन कभी-कभी इससे अलग-अलग जातियों के बीच संघर्ष और आंदोलन देखने को मिले है जिससे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा हो गया है। अक्सर ऐसा देखे गया हैं कि चुनावों के दौरान लोग आम तौर पर उम्मीदवार के धर्म और जाति के मद्देनजर वोट देते हैं, व्यक्ति की योग्यता के आधार पर नहीं। चुनाव के बाद जब राजनीतिक सत्ता किसी व्यक्ति या विशेष वर्ग के हाथों में होती है तो वह सबके लिए कार्य करने की बजाए अपने वर्ग या अपने धर्म के लोगों को लाभ देने की कोशिश करता है।

आर्थिक असमानता : -

सामाजिक विविधता के साथ-साथ हमारे देश में आर्थिक असमानता भी देखने को मिलती है। अमीर, जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है, वे और अमीर हो रहे हैं जबकि अधिकांश गरीब लोग अपने दो वक्त की रोटी का प्रबंध भी नहीं कर पा रहे है। अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ता हुआ यह अंतर उनके बीच परस्पर दुश्मनी पैदा कर रहा है। भाईचारे विभाजनकारी प्रवृत्तियों में तेजी देखी गई अंतत: भारत से ब्रिटिशों को बाहर करने का काम केवल राष्ट्रीय एकीकरण की सोच रखने वाले व्यक्तियों, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, आदि के कारण ही संभव हो सका।

सांप्रदायिकता : -

विभिन्न धार्मिक समुदायों में संकीर्ण सोच का व्यवहार राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रमुख खतरों में से एक हैं। लोगों के विभिन्न क्षेत्रीय पहचान के कैदी बनने के पीछे मुख्य कारण हमारी देश की राजनीति ही हैं। यहां तक कि हमारे देश में कुछ विशेष धर्मों से जुड़ी विभिन्न भाषाओं के आधार पर कुछ राज्य भी बनाए गए हैं। सांप्रदायिकता ने धर्मों के आधार पर लोगों के बीच मतभेद पैदा करने में अहम् भूमिका निभाई है। हालांकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, फिर भी कभी-कभी सांप्रदायिक मतभेद सामने आ रहे हैं जिससे जीवन और संपत्तियों को काफी नुकसान पहुँच रहा हैं। सांस्कृतिक मतभेद कभी-कभी राष्ट्रीय अखंडता की

राह में एक प्रमुख बाधा बन जाते हैं। इसे हम उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच मतभेद के रूप में साफ देख सकते है जो अक्सर लोगों के बीच पारस्परिक विरोधाभास और विरोधाभास और शत्रुता पैदा करते हैं।

परिणाम: -

राष्ट्रीय एकीकरण में साम्राज्यवाद विस्तारनिती निजी स्वार्थ, धर्म की भावना बढी तो निचे दिये हुअे परिणाम भोगना पडता है ।

1) सामूहिक संघर्ष की चेतना का लोप

2) सामूहिक भागीदारी और जबाबदेही का पतन

3) तहा नहस हुई सामूहिकता

4) कहा है समाज?

5) राजनीति ने समाज को खंड खंड किया

6) समाज तो तमाशा बन कर रह गया

7) स्वार्थ सबसे बड़ी बाधा

8) स्वार्थ ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया

निष्कर्ष: -

राष्ट्रीय एकीकरण एक राष्ट्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी की आवश्यकता महसूस की जा रही है लेकिन इसे प्रोत्साहित करने के प्रयास भरात में उतने सफल नहीं हुए हैं। हमारे देश के लोगों में अभी भी बहुत अधिक असमानता और नफरत है। सरकार को राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ कडे कदम उठाने चाहिए और लोगों को राष्ट्र को मजबूत बनाने और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देने के लिए इसका समर्थन करना चाहिए।

संदर्भ (References): -

1) Social Background of Indian Nationalism, A.R. Desai. Digital Library of India New-Delhi
2) India Wins Freedom : The complete version Maoulana Aazad
3) Indian Nationalism, Irfan Habib.
4) मन मे है विश्वास - विश्वास नांगरे-पाटील राजहंस प्रकाशन, पुणे
5) अग्निपंख - ए. पी. जे. अब्दुल कमाल अनुवाद : माधुरी शानबाग, राजहंस प्रकाशन, पुणे
6) आधुनिक भारताचा इतिहास डॉ. बी. एल. ग्रोवर, डॉ. एन. के. बेल्हेकर: एस. चंद. कंपनी लि. नवी दिल्ली.
7) Nationalism : Ravindranath Tagor
8) हिदुस्थानच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास डॉ. जयसिंगराव पवार : फडके प्रकाशन, कोल्हापूर
9) Indian Constitutional Development by Banarjee, A. C.
10) आधुनिक भारताचा इतिहास डॉ. बिपीन चंद्रा : प्रकाशक एस. चाँद पब्लिकेशन, नवी दिल्ली.
11) Gandhi and Nationalism : Simone Panter-Brick, I.B.S. London 2012

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

जागतिकीकरण आणि अनुवादित मराठी साहित्य

प्रोफेसर डॉ. राजेंद्र खंदारे
मराठी विभागप्रमुख सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील महाविद्यालय, नातेपुते ता. माळशिरस जि.सोलापूर
Email: rajkhandare2012@gmail.com

प्रस्तावना :

जागतिकीकरण म्हणजे स्थानिक वस्तूंची किंवा घडामोडींची जागतिक स्थरावर स्थानांतरणाची प्रक्रिया ह्या संज्ञेचा उपयोग सहसा आर्थिक जागतिकीकरणाच्या संदर्भात केला जातो. पण जेंव्हा आपण आजचा कालखंड हा जागतिकीकरणाचा कालखंड आहे असे म्हणतो तेंव्हा जागतिकीकरणाची व्याप्ती वाढल्याचे लक्षात येते. केवळ आर्थिक व्यवस्थेवरच जागतिकीकरणाचा परिणाम झालेला आहे असे म्हणता येणार नाही. तर शैक्षणिक, राजकीय,धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्राबरोबरच, मानवी भाषेवर एकूणच समाज जीवनपद्धतीवर देखील जागतिकीकरणाचा परिणाम झालेला आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. २१व्या शतकाचे पहिले दशक ओलांडताना जागतिकीकरणजन्य परिस्थितीशी समायोजन करीत आपली वाटचाल सुरु आहे. तसे पहिले तर जागतिकीकरणाची प्रक्रिया पूर्णत: नवी आहे असे म्हणता येत नाही. जागतिकीकरणाची संकल्पना बहुपदरी आणि बहुधर्मी स्वरुपाची आहे. या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे काहींच्याकडून स्वागत झाले तर काहींच्याकडून विरोध झाल्याचे पहावयास मिळते. ज्यांना देश प्रांताच्या सीमा ओलांडून जागतिकीकरणाच्या लाटेवर आरूढ होऊन जगभर भ्रमंती करता आली त्यांच्याकडून जागतिकीकरणाचे गोडवे गायिले गेले. आणि जे या जागतिकीकरणाच्या चक्रात आडकले त्यांची मात्र ससेहोलपट होऊन या जागतिकीकरणाच्या विरोधात रान उठविले असल्याचे दिसते. जागतिकिकरणाची प्रक्रिया ही आपल्या जीवनातील आणि सभोवतालच्या पर्यावरणातील अटळ अशी प्रक्रिया आहे हे दुर्लक्षून चालणार नाही. पूर्वीचे जागतिकीकरण हे उत्क्रांत मक्तेदारी भांडवलशाहीचे उदारमतवादी जागतिकीकरण होते. तर आजचे जागतिकीकरण माहिती तंत्रज्ञानाने सज्ज परिपक्व मक्तेदारी भांडवलशाहीचे म्हणजेच साम्राज्यवादाचे नवउदारमतवादी जागतिकीकरण आहे.[१] जागतिकीकरणाची प्रक्रिया १९९० नंतर भारतात जोर धरू लागली. याबद्दल माहिती देताना Bosworth आणि Gordon हे अभ्यासक म्हणतात, 'Over the past decade globalization has been driven by technological advances .... but has also been driven by policies and ideas.' इंग्रजी साम्राज्यशाहीच्या काळातही आपण इंग्रजी भाषा आत्मसात केली. साम्राज्यशाहीला विरोध केला पण इंग्रज माणसाचा द्वेष केला नाही. इंग्रजी भाषेमुळे आपल्या ज्ञानात आणि जाणिवांत भर पडली, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण इंगलंडशी आपण वैर ठेवले नाही. जागतिकीकरण म्हणजे सर्व क्षेत्रात पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण असा अर्थ रूढ आहे. वेशभूषा, केशभूषा, खाद्यपदार्थ, जेवण्याची पद्धती एकूणच जीवनपद्धतीवर पश्चिमेच्या मूल्याचे आक्रमण होत आहे. स्वावलंबी, सार्वभौमित्व यांना या जागतिकीकरणात कात्री लागणार हे उघडच आहे. स्वदेशी ही संकल्पनाच कालबाह्य होऊ पाहत आहे.[२] यामुळे काही वर्षातच देश आपापली संस्कृती वैशिष्ट्ये गमवून बसतील कि काय अशी भीती वाटते.

या पार्श्वभूमीवर आपल्या साहित्य व्यवस्थेचा विचार करणे आवश्यक आहे. जागतिकीकरणाच्या कालखंडात वाङ्मय व्यवहाराला विशेष करून वाङ्मयाचा भाषांतरणाला म्हणजेच अनुवादाला फार महत्व आहे. केशव तुपे म्हणतात त्याप्रमाणे, 'काळाच्या ओघात बदल होऊन संगणक आले जागतिकीकरण आर्थिक बाजूने जोरात घुसले त्यामुळे "विश्वग्राम"(global village) संकल्पना आली.' अलीकडच्या संगणक व माहिती तंत्रज्ञानामुळे जग अंत्यतिक जवळ आले आहे. ज्या अर्थी जग अधिकाधिक आंकुचित होत आहे त्या अर्थी साहित्य व्यवहार अधिक व्यापक होणे क्रमप्राप्त आहे. साहित्यनिर्मिती वा साहित्यव्यवहार गतिमान व विश्वव्यापी होणेसाठी भाषांतर वा अनुवादाची प्रक्रिया होणे अत्यंत महत्वाची आहे. अनुवादामुळे स्थानिक भाषेतील वाङ्मयाला नव्या नव्या आशयाच्या व भिन्न भिन्न विषयाच्या छटा प्राप्त होतात हे ध्यानात घेणे महत्वाचे आहे. अनुवादाच्या आधारे भिन्न भाषेतील विचार, भावाभिव्यक्ती स्थानिक भाषेत सहजपणे आणता येते हे जागतिकीकरणाने सिध्द होत आहे असे म्हणता येईल.

अनुवाद हे एक जागतिकीकरणाचे साधन :

अनुवाद प्रक्रिया आणि जागतिकीकरण यांचा निकटत्वाचा संबध आहे. साहित्याचे भाषांतर याला आता दिवसेंदिवस अधिकाधिक महत्त्व येत चालले आहे. ऑक्टो २००६ मध्ये फ्रांकफुर्ट, जर्मनी येथे भरलेल्या पुस्तकाच्या

प्रदर्शनात भारत हा देश प्रमुख अतिथी देश होता. भारतातून अनेक प्रकाशक पुढील बेत आखण्यासाठी जर्मनीत जाऊन आले. पाश्चात्य देशांनी चीन आणि भारत या दोन महा-देशांबरोबर या ना त्या प्रकारे संबंध प्रस्थापित करणे, वाढविणे आणि भक्कम करणे यासाठी कंबर कसली आहे. आर्थिक आणि व्यापारी हितसंबंध भक्कम होण्यासाठी त्या त्या भाषेतून व्यवहार कसे चालतात, त्या देशातील सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये कोणती आणि ती आता वर्तमानकाळात कशा प्रकारे आविष्कृत होत आहेत या साऱ्याबाबत पश्चिमेकडच्या देशांना उस्तुकता आहे. जागतिक आणि स्थानिक यांच्यातील ताण दूर करण्याचे भाषांतर एक उत्तम साधन आहे. Translation as negotiation हा एक नवाच विचार उदयाला येत आहे. जागतिकीकरणाच्या कालखंडात व अनुवादाचे महत्त्व याविषयी परामर्श घेत असताना साहित्याव्यवहार आणि जागतिकीकरण यांच्यातील संबंध स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.त्र्यं.वि. सरदेशमुख अनुवादाचे महत्व विषद करताना म्हणतात, 'अनुवाद ही एक अत्यंत निसर्गनिष्ठ, स्फुरणशील व स्फुरणदायी क्रिया आहे.'[३] तर भालचंद्र नेमाडे यांनी, "खरे तर साहित्य आणि जागतिकिरण या दोन्ही गोष्टी परस्पर विरोधी गोष्टी आहेत." असे म्हटले आहे.[४] तसे पहिले तर परभाषेतील भाषांतर ही एक सांस्कृतिक गरज आहे. जागतिकीकरण हे स्थानिक भाषा व साहित्य यामध्ये एक सांस्कृतिकतेची भूमिका निर्माण करीत असते. चंद्रकांत पाटील यांनीही जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अनुवादाचे योगदान किती महत्वाचे याविषयी ते म्हणतात, ललितकृतींची अनुवाद किंवा जिथं निव्वळ भाषिक अंगापेक्षाही जास्त काहीतरी देण्याचा प्रयत्न असेल असे वाङ्मयाचे किंवा साहित्यकृतीविषयक अनुवाद यांच्यासाठी अनुवाद हा शब्द वापरावा.[५] जागतिकीकरण स्थानिक भाषा व साहित्यामध्ये एक सांस्कृतिकतेची भूमिका निर्माण करीत असते. या संदर्भात नेमाडे म्हणतात, "आपली जी पारंपरिक बहुसांस्कृतिकता आहे. बहुभाषिकता आहे ती आज या घटकेला टिकवून ठेवणं ही सुद्धा सर्वात महत्वाची कृती आहे.ती जर आपण टिकवली तर या जागतिकीकरणाच्या लाटेतून आपण वर येऊ. एक सांस्कृतिक दृष्टी बाळगली तर आपला सर्वनाश अगदी निश्चित आहे. बहुसांस्कृतिकतेमध्ये निश्चितपणे अशी ताकद आहे की, ती जागतिकीकरणाला पुरून उरेल."[६] या सर्व मतांचा विचार केला असता, जागतिकीकरणात अनुवाद, भाषांतर ही भाषिक वा साहित्य क्रिया किती महत्वाची आहे अधोरेखित होते.

अनुवाद म्हणजे अनुवादित कृतीचा किंवा तिच्या भाषेच्या केवळ गौरव असतो असे नव्हे. तो आपल्याही राष्ट्रीय समृद्धीत भर घालणारा, आपल्या भाषेची आणि साहित्याची क्षमता वाढविणारा, आपले मन अधिक संस्कारित करणारा असा एक महत्वाचा व्यापार आहे. वसंत बापटांनी नोंदविलेल्या प्रतिक्रियेवरून आपणास अनुवादाचे महत्व लक्षात येते.[७] भाषांतराच्या वा अनुवादाच्या सहाय्याने परसंस्कृती आणि परजीवन आपणास सूक्ष्मपणे समजून घेता येते. आणि आपल्या जीवनाच्या कक्षा वर्धिष्णू करता येते. भाषांतर वा अनुवाद झाल्याशिवाय भाषेचे सामर्थ्य वाढू शकत नाही. तसेच आपल्या साहित्याला अद्ययावत ठेवण्यासाठी, विचार तत्त्वांना नित्यनूतन ठेवण्यासाठी भाषांतर वा अनुवाद हे जागतिकीकरणातील एक महत्वाचे साधन आहे असे म्हणता येईल.अनुवादाचा विचार करताना प्रामुख्याने परकीय साहित्याचे भाषांतर व भारतीय साहित्याचे भाषांतर अशा दोन पातळयांवर विचार करणे महत्वाचे आहे. स्वभाषेतील संस्कृतीला आणि साहित्याला उन्नत बनविण्यासाठी साहित्याचे भाषांतरण होणे अपरिहार्य आहे. एत्तद्देशियत्वाला समृद्ध, सदृढ आणि विकसनशील ठेवण्यासाठी विदेशियत्वाचा स्वीकार होणे गरजेचे आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, 'पर भाषेतील भाषांतर वा अनुवाद ह एक सांस्कृतिक गरज आहे.'[८] या गरजेच्या पुर्ततेमधूनच भाषांतरण प्रक्रियेबरोबारच जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होईल.

भारतीय साहित्य, भारतीयत्व आणि अनुवाद :

भारतीय साहित्याचा अभ्यास करताना तो अभ्यास भारतीय परिप्रेक्ष्यात असावा, हे जरी खरे असले तरी केवळ देशियत्वाच्या आधारे भारतीय साहित्याचा अभ्यास करणे मर्यादित ठरेल. अशा परिस्थितीत भारतीय भाषांच्या संदर्भात अनुवादाचा विचार करताना भारतीय राजघटनेला आणि निकोप भारतीयत्वाला समोर ठेवून अनुवादाचे आणि अनुवादकांचा विकास होणे आवश्यक ठरते. परस्पर संस्कृतीचा आदरभाव राखत मराठी संस्कृतीचे उन्नयन करणे आणि भारतीयत्वाची सदृढ संस्कृती सिद्ध करणे हे अनुवादाचे कर्तव्य ठरते. या दृष्टीने अनुवादाची अनुवादाची प्रक्रिया गतिमान होणे आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात अत्यंत महत्वाचे आहे. भारतातील विविध पंथ, जाती, जमाती, धर्म, लोकपरंपरा, लोकसंस्कृती या सर्व घटकांना समजून घेणे आणि त्या त्या जीवनानुभूतींना साकारणाऱ्या साहित्यकृतींचे अनुवाद करणे त्यातून एक लोकशाहीनिष्ठ असणारी निकोप, सांमजस्य संस्कृती पुढे येऊ शकेल हे लक्षात घेऊनच भारतीय साहित्याचे अनुवाद कार्य पुढे जाणे कालसुसंगत आणि कालोचित ठरेल.[९] मराठी भाषेची व मराठी साहित्याची ओळख भारतीय आणि जागतिक स्तरावर करून देण्यासाठी अनुवादाची वा भाषांतराची नितांत गरज आहे. कारण जागतिकीकरणातून अधिकाधिक गतिमान झालेल्या अनुवादामुळे भारतीय पातळीवरील संस्कृतीचे अवलोकन करणे, त्या संस्कृतीचे संस्कार आत्मसात करणे आणि त्या संस्कारातून आपल्या

स्थानिक संस्कृतीचे उन्नयन करणे या सर्व गोष्टी घडून येताना दिसताहेत. महाराष्ट्रीयत्व, भारतीयत्व आणि जागतिकिकत्व या तिन्ही बिंदुना एकत्र जोडण्याचे कार्य भाषा, साहित्य, भाषांतर यांच्यामुळे पुढे जाताना दिसून येते. मराठीपणाला जपत जपत भारतीयत्वापर्यंत पोहचण्याची प्रक्रिया ही आपल्या संस्कृतीचे पूर्ण विकसन मानावे लागेल. भारतीयत्वाची संस्कृती निर्माण करणं हे देखील आपले मराठीपणासोबत महत्वाचे कर्तव्य आहे.

अनुवादित मराठी साहित्य :

अलीकडच्या जागतिकीकरणामुळे मराठीत बरेच अनुवाद यायला लागले आहेत. जागतिकीकरणामुळे अनुवादाला गती मिळाली तरी यापूर्वी कमी अधिक प्रमाणात अनुवाद होत होतेच. १९ व्या शतकात भाषांतर होत होते. त्यापूर्वी म्हणजे संत काळात अनुवाद झाल्याचे दिसून येते.अनेक पंडित कवींनी रामायण, महाभारत यासारख्या महाकाव्यातील काही सर्ग, कांड यांचे अनुवाद आपल्याला भेटत जातात. संत ज्ञानेश्वर यांचा 'ज्ञानेश्वरी' हाच एक अनुवाद की जो अनुसर्जनाच्या गीतेवरील भाष्य असून ते स्वतंत्र प्रातिभ पातळीवर पोहोचतो आहे.मुळातच भारतीय भूमी हीच अनुवादासाठी अनुकूल आहे. अनुवादाला पूरक नि पोषक ठरणारे वातावरण व अनुवादाला हवी असणारी सामग्री भारतीय उपखंडात विपुल प्रमाणात आहे. याचे कारण म्हणजे भारत देश हा एक भाषिक वा द्विभाषिक देश नसून बहुभाषिक देश आहे. या देशात बावीस अधिकृत भाषा आहेत. विविध बोली आहेत. त्याचबरोबर अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय हजारो वर्षापासून या देशात आहेत. त्यातून प्रत्येक प्रांताची वाङ्मयीन संस्कृती तयार झाल्याचे दिसून येते. अशी ही पार्श्वभूमी असलेल्या भारतात अनुवादाच्या माध्यमातून सांस्कृतिकदृष्ट्या,वाङ्मयीनदृष्ट्या आणि भाषिकदृष्ट्या आदान-प्रदान होणे अपरिहार्य आहे. राजकीय,व्यावहारिक, प्रशासकीय, आर्थिक, धार्मिक या हेतूने अनुवाद झाले आहे. पण वाङ्मयीन व सांस्कृतिक संवर्धनासाठी जाणीवपूर्वक अनुवाद होणे अपेक्षित होते तसे झाले नाही असे म्हणता येईल.बाराव्या शतकात म्हणजे मध्यकाळात सुरु झालेल्या भक्ती चळवळीने देशपातळीवरील अनुवादाला चांगली गती दिली असे म्हणता येईल. 'ज्ञानेश्वरी' हा ग्रंथ केवळ अनुवाद म्हणून समजून घेण्यापेक्षा संवाद बंद करू पाहणाऱ्या संस्कृतीविरुद्ध पुकारलेल्या बंडासाठी अनुवादाचा एक हत्यार म्हणून कसा वापर म्हणून कसा होऊ शकतो याचे द्योतक आहे. याचे कारण म्हणजे त्याकाळातील धर्मसंस्कृतीचा पगडा अधिक असल्याने अनुवाद व भाष्य, करणे व टीका करणे पाप समजले जात होते. हा प्रतिगामी विचार तत्कालीन समाजात रुजलेला असल्याने कोणीही अनुवाद करण्यास पुढे येत नव्हते. हे पवित्र पाप करण्यासाठी अनेक संतानी अनुवादाचा अंगीकार केला असे म्हणता येईल. तेव्हापासून भाषांचा कुंठीत झालेला प्रवाह जोरदारपणे वाहू लागला असे म्हंटले तर वावगे ठरू नये.संस्कृत भाषेतील रामायण, महाभारत, भगवद्गीता यासारखे ग्रंथ प्राचीन मराठी भाषेकरिता प्रेरणापूंज ठरले आणि त्या ग्रंथांच्या आधारे टीकात्मक काव्यग्रंथांची निर्मिती झाली आहे. असे असले तरी अभ्यासक भाषांतर वा अनुवाद म्हणून त्याचा समावेश करीत नाहीत. अनुवादाचा वा भाषांतराचा विचार करताना मराठी भाषेचा आधुनिक कालखंड अधिक महत्वाचा आहे. सर्वसाधारणपणे १८१८ ते १८७५ या कालखंडाला भाषांतराचा कालखंड मानण्यात आले आहे. काही अभ्यासक या कालखंडाचा उल्लेख 'भाषांतर युग' असा करतात. या कालखंडात वाङ्मयकृतींची नवनिर्मिती दिसत नसल्याने या कालखंडाला 'तमोयुग' असेही म्हटले जाते. १९७५ ते १९०० या कालखंडात परकीय आणि संस्कृत भाषेतील साहित्यकृतींचे भाषांतरित व अनुवादित साहित्याची निर्मिती विपुल प्रमाणत झाल्याचे दिसते. कृष्णाशास्त्री चिपळूणकर यांनी 'मेघदूत', गणेशशास्त्री लेले यांनी रघुवंश यासारखे काव्य अभिजात संस्कृत काव्याच्या पद्यानुवादातून काव्याच्या रूपांतरातून अवतरल्याचे दिसून येते. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात बुकीश नाटकाची परंपरा मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली. स.ब.अमरापूरकर व रावजी बापट या लेखकद्वयाचे 'प्रबोधचंद्र' हे मराठील पहिले भाषांतरित नाटक संस्कृतवरूनच भाषांतरीत केले असल्याचे लक्षात येते. या एकोणिसाव्या शतकातील इंग्रजी आणि संस्कृतमधून मराठीत करण्यात आलेल्या भाषांतरणातून एकप्रकारची भाषांतर संस्कृतीच अवतरल्याचे दिसून येते. या संदर्भात महत्वपूर्ण निष्कर्ष नोंदविताना माया पंडित म्हणतात, 'आपली भाषांतर संस्कृती ही साम्राज्यवादी पाश्चात्य संस्कृती व एतद्देशीय संस्कृती यांच्यातील संघर्षकाळाचे अपत्य असल्याने तिचा विचार वासाहतिक व्यूहाच्या संदर्भ चौकटीतच अधिक अर्थपूर्ण करता येतो. किंबहुना याहीपुढे जाऊन, एकोणिसाव्या शतकातील भाषांतर संस्कृती म्हणजे वासाहतिक व्युहातील एक व्यामिश्र रणनीती आहे.'[१०] यामुळेच या काळातील भाषांतर संस्कृती कोती राहिलेली दिसते. कारण केवळ रंजनवादी रुपन्तारांचा मार्ग स्वीकारला गेला. त्याचा परिणाम वाङ्मयीन आणि भाषिक विकासाच्या वाटाच बंद झाल्या अशा निष्कर्षापर्यंत त्या येतात. विसाव्या शतकात भारतीय भाषाभगिनीमधून मराठीमध्ये करण्यात आलेले अनुवादाचे कार्य निश्चितच महत्वाचे आहे. तितकेच वेगळेदेखील आहे. या कालखंडात भारतातील विविध भाषामधील कलाकृती भाषांतरित होऊन मराठीत आल्याचे दिसून येते. मराठीभाषेचा ज्या भाषाभगिनींचा संपर्क आला व मराठी संकृतीशी ज्या

संस्कृती मिळत्या-जुळत्या राहिल्या त्याच भाषा संस्कृतीतील साहित्याचे मराठीत भाषांतर झाल्याचे दिसून येते. उदा. बंगाली, हिंदी, व कन्नड या भाषांतील साहित्यकृतींचे भाषांतर विशेषत्वाने झाले आहे.

बंगाली साहित्यकृतींचे भाषांतर:

विशाव्या शतकात भारतीय भाषांमधील अभिजात साहित्यकृतींचे मराठी भाषेत झालेले भाषांतर विपुल प्रमाणात आढळते.बंगाली फाळणीविरुद्ध टिळकांनी चालवलेल्या चळवळीमागून बंगाल महाराष्ट्र यातील सख्य वाढत गेले तसे बंगाली साहित्याचे अनुवाद मराठीमध्ये विपुलतेने आले. बंकिमचंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टागोर, शरच्चंद्र चटर्जी, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, सत्यजित राय या बंगाली साहित्यिकांच्या साहित्यकृतींचे भाषांतर मराठीत झाले आहे. बंकिमचंद्र चटर्जी यांच्या 'आनंदमठ' या कादंबरीपासून तर रविंद्रनाथ टागोर यांच्या 'गीतांजली' पर्यंतच्या अनुवादांनी इतर भाषाभगिनीना आशय तत्त्वाचे व भावविश्वाचे नवे बळ दिलेले आहे. या अनुवादामुळे भारतीय भाषाभगिनींमध्ये परस्परएकत्वाची भावना स्वातंत्र्यकाळात आकारास आले. एव्हढेच नव्हे तर सामाजिक व धार्मिक पर्यावरणाकडे वैविध्यपूर्ण दृष्टी देखील नव्याने आकारास आली आहे. असे हे अनुवादाचे महत्वाचे कार्य आहे असे म्हणता येईल.शरच्चंद्र चटर्जी यांच्या 'अरक्षणिया', 'चरित्रहीन', 'देना पावना', 'देवदास', 'रामेर सुमती', 'परिणीता', 'श्रीकांत', 'विराज बहू', 'विप्रदास', 'शेषप्रश्न', इत्यादी कथा-कादंबऱ्या मराठीत भाषांतरीत झालेले आहेत. वि.सी. गुर्जर, शंकर बाळशास्त्री, पी.बी. कुळकर्णी आणि मामा वरेरकर या सर्वांनी शरच्चंद्र चटर्जी यांच्या साहित्यकृतींचे भाषांतर केले आहेत. या अनुवादाच्या प्रक्रियेमुळे भारतीय स्त्रीजीवनाचे विवध कंगोरे मराठी साहित्याकृतीमधून समर्थपणे आलेली नव्हती. पण शरच्चंद्र चटर्जींच्या अनुवादित कादंबरीद्वारे व्यापक पातळीवर स्त्रीसंकृतीचा परिचय झलेला आहे असे म्हंटले तरी वावगे ठरू नये. नाटक या वाङ्मयप्रकारातदेखील बंगाली नाटके मराठी भाषेत आणण्यात आली. उत्पल दत्त, बादल सरकार यांच्या नाटकाचे अनुवाद मराठी झालेले आहेत. 'जुलुस', 'बाकी इतिहास', 'एवम् इंद्रजीत' या बदल सरकारच्या अनुवादित नाटकांना मराठीमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. बंगाली रंगभूमीचा चांगल्या प्रकारे परिचय त्यामधून मराठी रंगभूमीला झाला असे म्हणता येईल. सत्यजित राय यांच्या अनुवादित कथा-कादंबऱ्यामुळे मराठी साहित्याच्या आशयविश्वात मौलिक भर पडली आहे असे म्हणता येईल. थोडक्यात, बंगाली भाषेतून मराठी भाषेत झालेल्या या अनुवादामुळे तौलनिक साहित्याभ्यासाला चांगली गती मिळाली असे म्हणता येईल.

हिंदी साहित्यकृतींचे भाषांतर :

मराठीमध्ये भारतीय भाषेत झालेल्या अनुवादाचा विचार करताना हिंदीतून मराठीत झालेल्या अनुवादाचा विचारदेखील महत्वाचा आहे. हिंदी मराठी अनुवादाचे कार्य व्यापक स्वरूपाचे आहे. मराठी हिंदी आणि हिंदी मराठी अनुवादाच्या कार्यामुळे आणि दुसरे विशेष म्हणजे लिपिसाधार्म्यामुळे दोन्ही भाषेतील भाषांतरण प्रक्रियेला गती मिळाली.केंद्राच्या 'नॅशनल ट्रस्ट', 'साहित्य आकादमी' या सारख्या साहित्यासंस्थाच्या धोरणामुळे मराठी हिंदी यांच्यामधील अनुवाद प्रक्रियेला संधी प्राप्त मिळाली असे म्हणता येईल. हिंदीमधून मराठीमध्ये अनुवाद करण्याच्या प्रक्रियेला एका अर्थाने राष्ट्रभाषासंबंधीच्या आंदोलनामुळे गती मिळाल्याचे दिसून येते. फणीश्वरनाथ रेणू या बिहारमधील प्रथितयश कादंबरीकाराच्या 'मैला आँचल' १९५४ या कादंबरीचे मराठीमध्ये 'काळी माती-हिरवी नाती' १९७५ या नावाने श्री.ज.जोशी यांनी अनुवाद केले.श्रीलाल शुल्क यांच्या नावाजलेल्या 'रागदरबारी'१९६८ या कादंबरीचे भाषांतर श्री.ज.जोशी यांनी केले. मोहन राकेश यांच्या 'आधेअधुरे' या नाटकाचे भाषांतर विजय तेंडूलकर यांनी केले. संत तुलसीदासांच्या 'रामचरित्रमानस' या महाकाव्याचे रा.चिं. श्रीखंडे यांनी 'सुश्लोकमानस' नावाचे भाषांतर केले. तुलसीदासांच्या 'दोहावली'चेही त्यांनीच 'सुरलोक दोहावली' नावाने भाषांतर केले. हरिवंशराय बच्चन यांच्या १९३४मध्ये लोकप्रिय अशा 'मधुशाला'काव्याचे केलेले भाषांतर मराठीत अनेक अनुवादकांनी केल्याचे दिसून येते. पद्माकर जोशी यांनी हिंदी कादंबरीकार जैनेंद्र कुमार यांच्या 'परख', 'त्यागपत्र', ',मुक्तिबोध' या कादंबऱ्या भाषांतरीत केल्या आहेत. मन्नू भंडारी, भगवतीचरण वर्मा या साहित्यिकांच्या साहित्यकृतींचे भाषांतर झाले आहे. चंद्रकांत बांदिवडेकर, चंद्रकांत पाटील, सूर्यनारायण रणसुभे, निशिकांत ठकार, प्रकाश भातंब्रेकर या अनुवादकांचे कार्य अत्यंत महत्वाचे ठरलेले आहे. निष्कर्ष : या सर्व अनुवादामधून मराठी भाषिक प्रदेश व हिंदी भाषिक प्रदेश यांच्यामध्ये विचार भावनाची आदानप्रदान अधिकाधिक उत्तम प्रकारे होण्यास मदत झालेली आहे. हिंदीमधून मराठीत झालेल्या अनुवादाच्या तुलनेत मराठीतून हिंदी भाषेत झालेले अनुवादकार्य संख्यात्मकदृष्ट्या अधिक आहे. तसेच ते गुणात्मकदृष्ट्या देखील तितकेच महत्वाचे आहे. मराठी भाषेतील दलित साहित्य हे या अनुवाद कार्यामुळे हिंदी भाषिक प्रदेशमध्ये पोहोचू शकले. मराठीतील दलित साहित्याचे व त्याच्या अनुवादाचे हे ऐतिहासिक कार्य आहे म्हणता येईल. मानवाचे जागतिक पार्लमेंट व्हावे, युद्धे नष्ट व्हावीत, सार्त्र शांतता नांदावी, मानवाची प्रगती व्हावी याला विरोध कोण करणार ? आपल्याकडे रवींद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी यांनी

विश्वराज्याची, जागतिक शांततेची कल्पना पुरस्कारली. 'वसुंधैव कुटुंबकम हे तत्त्वज्ञान संपूर्ण पुथ्वी एका कुटुंबाप्रमाणे आहे ते तत्त्व भारताने प्रथम जगाला दिले त्यात पृथ्वीवरील जीवसृष्टीची काळजी घेण्याची संकल्पना आहे सध्याचे जागतिकीकरण या ध्येयाकडे वाटचाल करावे अशी अपेक्षा आहे.

संदर्भ सूची :

1. तेलतुंबडे, आनंद, 'सामाजिक न्याय आणि जागतिकीकरण', लोकवाङ्मय गृह, मुंबई. २००६, पृ.क्र. २.
2. डॉ. ना.य. डोळे, 'उदारीकरण : नवे आर्थिक धोरण', 'जागतिकीकरण', विद्या प्रकाशन नागपूर, प्रथमावृत्ती
    a. १९९७ पृ.क्र. १६९
3. तुपे केशव, 'अनुवादमीमांसा','त्र्यं.वि. सरदेशमुख, अनुवाद:संस्कृतीसंगमासाठी', साक्षात प्रकाशन,
    a. औरंगाबाद, प.आ., ७ जून, २०१२, पृ.क्र. ३७
4. भालचंद्र नेमाडे, 'साहित्य संस्कृती आणि जागतिकीकरण', लोकवाङ्मय गृह, मुंबई- २००३, पृ.क्र.४
5. तुपे केशव, 'अनुवादमीमांसा', उ.नि. पृ.क्र. २२१
6. भालचंद्र नेमाडे, 'साहित्य संस्कृती आणि जागतिकीकरण', उ.नि. पृ.क्र.२३
7. वसंत बापट, 'तौलनिक साहित्याभ्यास', मौज प्रकाशनगृह आंतरभारती मुंबई. १९८१, पृ.क्र. ५९
8. सदा कऱ्हाडे, उ.नि.पृ.क्र. २३
9. तुपे केशव, उ.नि. पृ.क्र.१४९
10. माया पंडित, 'एकोणिसाव्य शतकातील भाषांतर संस्कृती: वासाहतिक व्यूहातील रणनीती, 'श्रीवाणी'
11. 'संपा- रमेश वरखेडे, वसंत आबाजी डहाके' का.स. वाणी माराठी अध्ययन संस्था, धुळे, १९९४, पृ.क्र.१३

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

आंतरराष्ट्रीयत्ववाद

प्रा. मोहन भाऊसाहेब सावंत

इतिहास विभाग, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील महाविद्यालय नातेपुते

प्रस्तावना

जागतिकीकरण भाषेवर थांबत नाही. वाढत्या "आंतरराष्ट्रीयत्ववादाने" हे स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीयत्ववादाचे शब्द अनेक भाषांमध्ये अस्तित्वात आहेत. या शब्दांचे अर्थ समान किंवा त्या सदृश्य असतात. उच्चारणसुद्धा अनेकदा एकसारखेच असते. या शब्दांचे वर्ण देखील बहुधा एकसमानच असतात. आंतरराष्ट्रीयत्ववादाचा प्रसार चित्तवेधक आहे. ते मऱ्यादांवर लक्ष देत नाही. भौगोलिक मऱ्यांदावरही नाहीच. आणि विशेषत: भाषिक मऱ्यादांवरही नाही. असेही काही शब्द आहेत जे सर्व खंडावर समजले जातात. हॉटेल हा शब्द याचे चांगले उदाहरण आहे. तो जगात सर्वत्र अस्तित्वात आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीयवाद विज्ञानातून येतात. तांत्रिक बाबी पटकन आणि जगभर पसरतात. जुना आंतरराष्ट्रीयपणा हा एकाच मुळापासून अस्तित्वात आला आहे. ते एकाच शब्दापासून जन्माला आले आहेत. परंतु, पुष्कळसा आंतरराष्ट्रीयपणा हा उसना घेतलेला आहे. सांगायचे झाले तर, शब्द हे बाकीच्या भाषांमध्ये विलीन झाले आहेत. स्वीकृती करण्यामध्ये सांस्कृतिक वर्तुळे महत्वाची भूमिका बजावतात. प्रत्येक संस्कृती आणि सभ्यता यांना स्वतःची परंपरा आहे. म्हणून, सर्व नवीन कल्पना सर्वांना समजत नाही. कोणत्या गोष्टी स्विकारल्या जातील हे सांस्कृतिक नियम ठरवितात. काही गोष्टी जगाच्या काही भागांमध्येच सापडतील. बाकीच्या गोष्टी जगामध्ये लवकर पसरतात. पण, फक्त तेव्हाच जेव्हा ते त्यांच्या नावाने पसरतात. अगदी हेच, आंतरराष्ट्रीयपणा अगदी रोमांचकारी बनवितो. जेव्हा आपण भाषा शोधतो, तेव्हा आपण संस्कृती देखील शोधतो.

उद्देश:- आंतरराष्ट्रीयत्ववाद अभ्यास करणे

जगातील भिन्न भिन्न राष्ट्रांमध्ये सलोख्याचे, सहकाराचे व परस्परसामंजस्याचे संबंध राहावेत, लहानमोठे संघर्ष व युद्धे बंद व्हावीत, मानवजातीस सततची शांतता लाभावी, यांसाठी आवश्यक त्या तत्त्वांचा प्रचार व्हावा आणि ती तत्त्वे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणाऱ्या संघटना स्थापन व्हाव्यात, असे प्रतिपादन करणारी विचारप्रणाली म्हणजेच आंतरराष्ट्रीयत्ववाद होय. ह्या विचारात मानवी एकता व जागतिक ऐक्य ही अभिप्रेत असली, तरी विश्वराज्य व आंतरराष्ट्रीयत्व ह्या दोन कल्पनांत फरक आहे. मानवी एकतेच्या आदर्शात वंशभेद, धर्मभेद, संस्कृतिभेद हे सर्व नष्ट झालेले असतात. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीयत्वासारखी प्रादेशिक किंवा सांस्कृतिक मूल्येही नाहीशी झालेली असतात. त्यात मानवी समता गृहीत धरलेली असते. एका विश्वराज्याचे शासनाच्या सोयीसाठी प्रादेशिक विभाग पाडले जातीलही; परंतु ते एकमेकांशी स्पर्धा व संघर्ष करणारे भिन्न भिन्न समाजगट असणार नाहीत.

आंतरराष्ट्रीयत्वाचे तत्वज्ञान वरील विश्वराज्याच्या कल्पनेहून वेगळे आहे. आंतरराष्ट्रीयत्वात भिन्न भिन्न राष्ट्रे किंवा राष्ट्र-राज्ये अस्तित्वात आहेत आणि त्यांच्या विविध संस्कृतीही आहेत, हे मान्य केलेले असते. पुढे अशी अनेक राष्ट्र-राज्ये त्यांच्या अनेक जीवनपद्धतींमुळे अस्तित्वात राहिली, तरी त्यांना शांततामय सहजीवन शक्य आहे, असा आंतरराष्ट्रीयत्वावाद्यांचा विश्वास असतो. अर्थात आंतरराष्ट्रीयत्ववादीही अस्तित्वात असलेले राजकीय आणि सांस्कृतिक भेद पुष्कळदा अपरिहार्य म्हणूनच मान्य करीत असतात. त्यांनाही हे भेद वरवरचे, कृत्रिम आणि कालांतराने नाहीसे होणारे आहेत, असा विश्वास वाटत असतो. म्हणजे आंतरराष्ट्रीयत्व हा मानवी एकतेच्या किंवा विश्वराज्याच्या आदर्शाकडे जाणाऱ्या मार्गावरील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे म्हणता येईल. राष्ट्र–राज्ये किंवा राजकीय दृष्ट्या स्वायत्त असे वेगवेगळे प्रदेश आणि त्यांच्यातील वेगवेगळया संस्कृतींतील समाज हे समान हितासाठी एकत्र येऊ शकतील, हा विचार अगदी नवीनच आहे असे नाही. शोध घेतला, तर अगदी प्राचीन तत्त्वचिंतकांच्या लेखनांतून, तसेच राजकारणी व्यक्तींच्या उक्तींतून आणि कृतींतूनही आंतरराष्ट्रीयत्ववादाचे तत्त्वज्ञान हुडकून काढता येईल. तथापि आंतरराष्ट्रीयत्ववादाचे तत्त्वज्ञान हुडकून काढता येईल. तथापि आंतरराष्ट्रीयत्वाच्या विचाराला फार मोठी चालना मिळाली ती औद्यागिक क्रांतीनंतरच एकोणिसाव्या शतकात, नव्या यंत्रयुगात जगातील निरनिराळया लोकसमूहांचे आर्थिक परस्परावलंबित्व फार मोठ्या प्रमाणावर वाढले. काही विशिष्ट गरजांच्या संदर्भात एका राष्ट्राचे दुसऱ्या राष्ट्रांवाचून चालू शकत नाही, अशी परिस्थिती जवळजवळ जगभर निर्माण झाली. ह्याचबरोबर दळणवळणाच्या नवीन यांत्रिक साधनांमुळे जगाच्या निरनिराळया भागांतील माणसे अनेक वेळा अनेक प्रकारे एकमेकांच्या जवळ येऊ लागली. दूरत्वामुळे जे भेद फार खोल व मूलभूत आहेत असे धरले जात असे, ते वरवरचे व कृत्रिम आहेत ह्याची जाणीव होऊ लागली. जीवशास्त्रादी विषयांतील नव्या विज्ञाननिष्ठ संशोधनाने मूलभूत मानवी एकता स्पष्टपणे सांगितली गेली. ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणून मानवी एकतेसारखे, आंतरराष्ट्रीयत्वासारखे विचार सर्वसामान्य माणसांच्या मनातही हळूहळू रुजू लागले.

वरील विचारांनुसार प्रत्यक्ष व्यवहार होण्यासाठी काही एका संघटनात्मक यंत्रणेची आवश्यकताही एकोणिसाव्या शतकापासूनच जाणंवू लागलेली होती. युद्धानंतरच्या तहाच्या वाटाघाटींसाठीच एकत्र येणारे निरनिराळया राष्ट्रांचे प्रतिनिधी ह्या दृष्टीने काही प्रयत्न करीत व योजना मांडीत. परंतु राष्ट्राराष्ट्रांतील संघर्ष जगभर व विशेषत: यूरोपात इतके तीव्र होते, की अशा संघटना कायम स्वरूपात अस्तित्वात येऊ शकल्या नाहीत. राष्ट्राराष्ट्रांतील सहजीवन चिरस्वरूपाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेशिवाय अशक्यच आहे. अशा तऱ्हेचा आंतरराष्ट्रीय राजकीय क्षेत्रातील पहिला प्रयत्न म्हणजे पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेला राष्ट्रसंघ. हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रे ही दुसरी आंतरराष्ट्रीय संघटना अस्तित्वात आली. ती आजतागायत कार्यान्वित आहे. अर्थात तीही आंतरराष्ट्रीय सहजीवन निर्माण करण्यात, युद्धे टाळण्यात व शांततेची हमी देण्यात म्हणावी तशी यशस्वी होत नाही, असे अनुभवास येत आहे. मात्र ह्या संघटनांचे यशापयश काहीही असले, तरी मानवजात राष्ट्र-राज्यांमध्ये विभागली आहे ही

वस्तुस्थिती लक्षात घेतली आणि वास्तव, व्यवहार्य पद्धतीने होईल तेवढे कार्य करावयाचे ठरविले, तर अशा संघटनांशिवाय गत्यंतरच नाही.

सारांश

आजची राष्ट्र–राज्ये वांशिक, प्रादेशिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अशा अनेक भेदांवर उभी आहेत. राष्ट्रीयत्व आणि त्याचा आग्रह हीच मानवी एकतेच्या मार्गातील मुख्य अडचण आहे. राष्ट्रीयत्वच नसेल, तर आंतरराष्ट्रीयत्वाचा प्रश्नही उद्भवणार नाही. म्हणूनच मानवी एकतेच्या अंतिम ध्येयाच्या दृष्टीने विचार केला, तर राष्ट्रीयत्वाचे मूल्य आणि त्यातून निर्माण होणारी भेदाची भावना नष्ट करणे हीच पहिली गरज आहे. आंतरराष्ट्रीयत्वात राष्ट्रे गृहीत धरलेली आहेत. आणि म्हणूनच आंतरराष्ट्रीयत्ववादाच्या तत्त्वज्ञानाच्या मर्यादाही स्पष्ट होतात. तथापि राष्ट्रीयत्व ही लवकर नाहीशी होणारी गोष्ट नसल्यामुळे जोपर्यंत माणसे राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेला व राष्ट्र ह्या संस्थेला चिकटून आहेत, तोपर्यंत राष्ट्राराष्ट्रांनी एकत्र यावे, परस्परसहकार्याची भावना ठेवावी आणि सर्वांच्याच हिताच्या दृष्टीने एकमेकांतील संघर्ष टाळावेत अशा तऱ्हेच्या विचारप्रणालीचा पाठपुरावा करणे अगत्याचे आहे.

संदर्भ:

1. Sprout, Harold; Sprout, Margaret, Foundations of International Politics, New York, 1962.
2. Vandenbosch, Amry; Hogan, Willard, Towards World Order,New York, 1963.
3. Wright, Quincy, The Study of International Relations, New York, 1965.

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

जागतिकीकरणाचे भारतीय संस्कृतीवर झालेले परिणाम : - एक समाजशास्त्रीय अभ्यास

प्रा. लक्ष्मण बापूराव नैताम
समाजशास्त्र विभाग बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालय वेंगुर्ला जि. सिंधुदुर्ग

प्रस्तावना :

जागतिकीकरण म्हणजे संपूर्ण जग ही एकमेव बाजारपेठ करण्याची प्रक्रिया होय. अशा प्रकारच्या बाजारपेठेत कोणताही माल , भांडवल किंवा मनुष्यबळ यांच्या हालचालीसाठी कोणताही अडथळा येत नाही. म्हणजेच राष्ट्रीय सरकारने करामध्ये कपात करुन राजकोषीय आणि द्रव्यविषयक व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना देशात कोठेही व्यवसाय चालू करण्याची मुभा देणे आवश्यक आहे. एखाद्या देशाने स्वत:च्या भौगोलिक कक्षेच्या बाहेर आर्थिक उपक्रम सुरू करणे म्हणजे जागतिकीकरण होय.जागतिकीकरणाची जगभरात मोठी भूमिका आहे. भारतीय संस्कृती या परिवर्तन प्रक्रियेला अडथळा नाही. आपल्या खोलवर रुजलेल्या परंपरा आणि चालीरितीनी -जागतिकीकरणाच्या उदयामुळे त्यांची पकड सैल केली आहे. भारताची समृद्ध सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आहे. आणि त्यामुळे संस्कृतीचा अभिमान जगभरात प्रसिद्ध आहे. सामाजिक परिवर्तनाचा विचार करताना वर्तमान काळात जागतिकीकरण प्रक्रियेला लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जागतिकीकरणामुळे भारतीय संस्कृतीवर परिणाम झालेला आहे. सामाजिक , आर्थिक ,शैक्षणिक ,राजकीय या क्षेत्रांवर परिणाम झालेला आहे. भारतात १९९१ पासून जागतिकीकरणाचा प्रारंभ झाला.

अध्ययनाची उद्दिष्ट्ये : -

१) जागतिकीकरणाचा भारतीय संस्कृतीवर झालेल्या परिणामाचा चिकित्सक अभ्यास करणे.

संशोधन आराखडा : -

प्रस्तुत संशोधांनासाठी वर्णनात्मक आराखड्याचा वापर करण्यात आला.

प्रस्तुत संशोधन हे दुय्यम साधनांवर आधारित आहे. पुस्तके, नियतकालिके , इंटरनेट इ.

जागतिकीकरणाचे सामाजिक घटकावर झालेले परिणाम : -

१.) सामाजिक : -

जागतिकीकरणामुळे भारतीय संस्कृतीवर परिणाम झालेला आहे. भारतीय समाजाचे तीन विभागात स्तरीकरण होते. १.) नागरी ,२.) ग्रामीण, ३) आदिवासी असे तीन भाग पडतात.

२) कुटुंब पद्धती : -

जागतिकीकरणामुळे कुटुंब पद्धतीवर परिणाम झालेला आहे. पारंपारिक समाज व्यवस्थेत संयुक्त कुटुंब पद्धती होती. शेतीवर व शेतीशी निगडीत कामावर कुटुंब पद्धती होती. पण जागतिकीकरणामुळे औद्योगिक कारखाने शहरामध्ये आल्यामुळे नोकरी करण्यासाठी लोक शहरात स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे संयुक्त कुटुंब पद्धतीवर परिणाम होत आहे. शहरामध्ये औद्योगिक वसाहत मूलभूत सोयी सुविधा मिळत असल्याने विभक्त कुटुंब पद्धती अस्तीत्वात येत आहे. नोकरीमुळे शहरांचे वाढते आकर्षण इत्यादि मुळे संयुक्त कुटुंब न राहता विभक्त होऊ लागली आहेत. संयुक्त कुटुंबात समयोजित होण्यासाठी आई वडिलांच्या बरोबर न राहता शहरात काम धंद्यासाठी व नोकरीसाठी विभक्त राहत असल्यामुळे लहान मुलांना आजी आजोबांची ओळख नसते. त्यामुळे आजी आजोबांच्या छायेखाली वाढण्याचा संगम गमावलेला आहे. मुलांनी आजी आजोबांना पाहुणे किंवा पाहूण्यासारखे वागवण्यास सुरुवात केली. हेच संगोपन वृद्धाश्रम वाढण्याचे मुख्य कारण आहे. आज ही ग्रामीण भागात काही प्रमाणात संयुक्त कुटुंब पद्धती अस्तीत्वात आहे. पण त्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. जागतिकीकरण , औद्योगीकरण दळण – वळणाच्या साधनांमुळे शहरात स्थलांतर होण्याचे प्रमाण वाढले. परिणामी संयुक्त कुटुंब पद्धतीची जागा विभक्त कुटुंबपद्धतीने घेतलेली दिसत आहे.

३.) आर्थिक : -

जागतिकीकरणाचचा परिणाम आर्थिक क्षेत्रावर झालेला आहे. अविकसित आणि विकसित देशावर बरेचदा

जागतिकीकरणामुळे व व्यावसायिक जगत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या झालेल्या प्रवेशामुळे अनेक समस्या निर्माण होत असल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळत नाही. त्यमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतात. शेतामध्ये उत्पादन केलेला कापूस, सोयाबीन , हरभरा , गहू, ज्वारी यांना हमीभाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे सरकारने रद्द करावे यासाठी जवळपास एक वर्ष होत आहे. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करीत आहेत. कृषीमाल आहे त्याला हमीभाव मिळाला पाहिजे कापुस , उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य प्रकारे बाजारपेठा उपलब्ध करून दिल्या तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण कमी होईल. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळे यजमान देशांच्या गुंतवणुक दरात वाढ होते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या केवळ स्वत:चा नफा वाढविण्याचा उद्देश ठेवतात. व यजमान देशाच्या गरजा भागविण्यात दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे जागतिकीकरणाचा आर्थिक परिणाम होत आहे.

४.) शैक्षणिक : -

जागतिकीकरणाचा एक परिणाम म्हणून भारत सरकारने १९९१ साली मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे सर्व क्षेत्रात खाजगीकरणाला व मुक्त व्यापाराला प्राधान्य प्राप्त झाले आहे. याचा परिणाम पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे १९९० च्या दशकानंतर शिक्षण ध्येयवादी न राहता ते बाजारातील एक विक्रेय वस्तु बनले. खाजगीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू झाल्या. त्यामुळे ग्रामीण आदिवासी भागातील शाळा बंद होत आहेत. खाजगीकरणामुळे अनेक शैक्षणिक संस्था सुरू झाल्या . व्यावसायिक कोर्स , इंग्रजी माध्यम खाजगी विद्यापीठे , खाजगी महाविद्यालये व खाजगी विद्यापीठे अनुदानित महाविद्यालयात कायम विना अनुदानित अभ्यासक्रम यांना मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देण्यात आले. कोरोना महामारीमुळे जवळपास १८ महिन्यापासून शाळा , महाविद्यालये , शैक्षणिक संस्था बंद असल्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू असून त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक मानसिकतेवर होत आहे. ग्रामीण भागातील आदिवासी भागातील विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.

५.) राजकीय : -

जागतिकीकरणाचा परिणाम राजकारणामध्ये झालेला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान ने सत्ता स्थापन केल्यानंतर जागतिक स्तरावर परिणाम झाले कारण तालिबानने भारता सोबत व्यापार आयात निर्यात बंद केल्यामुळे भारतीय खाद्य पदार्थ व अफगाणीस्तानातून आयात होणरे सुका मेवा, फळे यांच्या व्यापारावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. त्याचबरोबर जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम झालेले दिसून येतात.

६) वैवाहिक : -

जागतिकीकरणाचा परिणाम विवाह पद्धतीवर देखील होत आहे. घटस्फोटाचे प्रमाण वाढले. कौटुंबिक हिंसाचार वाढला. वृद्धाश्रमांची संख्या वाढत आहे. विवाह पद्धतीने त्यांची मूल्ये गमवलेली आहेत. पण आज विवाह हा पवित्र संस्कार नसून ते केवळ व्यावसायिक स्वरूपाचे झालेले आहे. सामाजिक संबंध दुरावलेत. पती पत्नी मध्ये कौटुंबिक वाद होत आहेत. कुटुंबा प्रती आत्मीयता कमी होत आहे. जगतिकीकरणामुळे विवाह पद्धतीवर परिणाम होत आहेत.

७.) पर्यावरण : -

जागतिकीकरणाचे परिणाम हे पर्यावरणावर देखील झालेले आहेत. जल, जमीन जंगल यांचे संरक्षण व संवर्धन झाले पाहिजे. पर्यावरणाचा ह्रास होत आहे. जंगल नष्ट होत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणात बदल होत आहेत. भूकंप, महापूर, दुष्काळ पडत आहेत. हरितगृहांची संख्या कमी होत आहे. पर्यावरणवादी चळवळी सामाजिक समता आणि पर्यावरणीय चिरंजीवीत्व संवर्धन करण्यासाठी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर आणि वापराचा प्रकार यांची पुनर्रचना करतात. अशा प्रकारे पर्यावरणवादी चळवळींनी आर्थिक विकासाचे आणि त्यासंबधी संकल्पना यांच्या यथार्थतेला आव्हान दिले आहे. यातूनच पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी चिपको आंदोलन ही भारतातील सर्वात शक्तीशाली अशी पर्यावरण चळवळ आहे.

८) क्रीडाक्षेत्र : -

जागतिकीकरणाचा परिणाम भारतीय क्रीडा क्षेत्रावर झाला आहे. कबड्डी , खो-खो विटी दांडू इ. खेळ भारतीय पारंपारिक खेळ आहेत. क्रिकेट, हॉलीबॉल टेनिस भारतात खेळतात पण जागतिकीकरणामुळे भारतीय पारंपारिक खेळांवर परिणाम झालेला आहे.

९) राहणीमान व बोलीभाषा : -

जागतिकीकरणामुळे राहणीमान व बोलीभाषा यावर देखील परिणाम झालेला आहे. वेशभूषा व केशभूषा यामध्ये

देखील बदल झालेला आहे. बोलीभाषेवर परिणाम झालेला आहे.पारंपारिक लोकगीते , लोककला यांच्यावर परिणाम झालेला आहे. मोठ - मोठी सिनेमगृहे , नाट्यगृह यांच्यामुळे पारंपारिक लोकगीते , लोककला हे लोप पावत चालले आहेत. यावर जागतिकीकरणाचा परिणाम झालेला आहे. राहणीमनात बदल झालेला आहे.पारंपारिक सण उत्सव साजरे करण्यावर परिणाम झालेला आहे.

निष्कर्ष : -

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सन १९९१ पासून पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळात सुरू झाली. जागतिकीकरणाचे प्रमुख उद्दीष्ट मुक्त बाजारपेठ असले तरी भारतातील समाजावर त्याचा दूरगामी परिणाम झालेला आहे. कुटुंब पद्धती , विवाह संस्था राजकीय कार्यप्रणाली शिक्षण व्यवस्था पर्यावरण चळवळी , लोकगीते , बोलीभाषा , वेशभूषा त्याबरोबरच पारंपारिक सण , उत्सव साजरे करण्याच्या पद्धती यांच्यावर जागतिकीकरणाचा परिणाम झालेला दिसून येत आहे.

संदर्भ सूची :

1. https://www.careerride.com
2. सैद्धांतिक समाजशास्त्र लेखक : - सौ. सरिता देहाडराय प्राची प्रकाशन , मुंबई – १२
3 .समाजशस्त्र :- लेखक – डॉ. भा.कि.खडसे हिमालया पब्लिशिंग हाऊस , मुंबई
4. सीमांतीक समूह:- लेखक : - डॉ.जगन कराडे एबीएस पब्लिकेशन वाराणसी
5. प्रगत सांख्यिकीय व संशोधन पद्धती लेखक : - डॉ. दिलीप खाइरणार डायमंड पब्लिकेशन , पुणे
6. https://timesofindia.indiatimes.com

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

सोलापूर जिल्ह्यातील कृषी तंत्रज्ञानाचा एक अभ्यास

प्रा.पवार एस.एच.[1] प्रा. मगर एस. बी.[2]

[1]अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, स. म. शंकरराव मोहिते पाटील महाविद्यालय, नातेपुते.
तालुका – माळशिरस, जिल्हा – सोलापूर
[2]अर्थशास्त्र विभागप्रमुख समीर गांधी कला महाविद्यालय, माळशिरस.

प्रस्तावना –

भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. आर्थिक विकासात कृषी हा महत्वाचा घटक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही मुलभूतपणे शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था आहे. भारतातील दोन तृतीयांश लोकांना कृषीतून रोजगार मिळतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषीला अनन्य साधारण महत्व आहे. कृषी या घटकामुळे देशाची अन्नाची गरज भागविली जाते. कार्यक्षम लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पूर्वी शेतीमधील सर्व प्रकारची मशागत करण्यासाठी जनावरांचा वापर केला जात होता. शेतीमध्ये श्रमप्रधान तंत्राचा वापर केला जात होता. परंतु, अलीकडील काळात कृषी तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्राचा वापर केला जात आहे. देशामध्ये हरीत क्रांतीनंतर शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. अलीकडच्या काळात नवनवीन तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, जैवतंत्रज्ञान, किटकनाशके, रासायनिक खते, बि-बियाणे यांचा वापर करून कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त कृषी उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. कृषीसाठी जलसिंचन हा महत्वाचा घटक आहे. जलसिंचन बरोबरच कृषीमध्ये सुधारित बि - बियाणे, कीटकनाशके, जैविक खते, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान अशा अनेक साधनांमुळे कृषीचा विकास होऊन कृषी उत्पादनात वाढ होत असल्याचे दिसून येते.

अभ्यासाची उद्दिष्ठये -

1) सोलापूर जिल्ह्यातील रासायनिक खते, तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करणे.
2) सोलापूर जिल्ह्यातील बि-बियाणे तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करणे.
3) सोलापूर जिल्ह्यातील जलसिंचन तंत्रज्ञानाच्या बदलाचा अभ्यास करणे.
4) कृषी अवजारे तंत्रज्ञानाचे विश्लेषण करणे व कृषी अवजारे तंत्रज्ञानाच्या जिल्ह्यातील वापराचा आढावा घेणे.

संशोधन पद्धती –

सोलापुर जिल्ह्यातील कृषी तंत्रज्ञानाचा अभ्यास हा शोधनिबंध दुय्यम सामुग्रीवर आधारित असून सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कृषी अर्थशास्त्र, कृषी विषयक रिपोर्ट, वेगवेगळे मासिके, अहवाल, संदर्भ ग्रंथ, इंटरनेट, वर्तमानपत्रे इ. चा आधार घेण्यात आला आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतात शेती हाच अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार आहे. कारण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात 33% वाटा हा शेती व्यवसायातून देशाला प्राप्त होतो. नवीन कृषी तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन कृषी उत्पादनातून प्रचंड वाढ होते. शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. जगातील वाढत्या लोकसंख्येची अन्नाची गरज भागविण्यासाठी कृषी उत्पादनात वाढ करणे गरजेचे आहे. कारण जमीन मर्यादित आहे, लोकसंख्या मात्र वाढत आहे. या लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सोडविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे महत्वाचे आहे. कृषी तंत्रज्ञानातील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणून जलसिंचन तंत्रज्ञांनास महत्त्व आहे. जलसिंचन तंत्रज्ञान हे कृषी उत्पादन वाढीसाठीमहत्वाचे तंत्रज्ञान आहे. कृषी तंत्रज्ञानामुळे जलसिंचन तंत्रज्ञान उच्च उत्पादन देणारी बियाणे, रासायनिक खते, जैविक खते, कीटकनाशके धान्य साठवणूक गोदाम आणि आधुनिक यांत्रिकी कृषी अवजारे इ. स्वीकार केल्यामुळे उत्पादनात वाढ होण्यास प्रामुख्याने मदत होते. सोलापूर जिल्ह्यात नवनवीन कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक प्रमाणात केला जात असून उत्पादनात वाढ होत असलेले दिसून येते. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये कृषी तंत्रज्ञानाचे विश्लेषण करण्यासाठी कृषी विकास व उत्पादनातील वाढ अभ्यासण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

संकरीत बि- बियाणे –

कृषी उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी पिकांच्या उच्च उत्पादन देणा-या सुधारित दर्जेदार वाणांचा विकास करणे म्हणजे संकरीत बि-बियाणे तंत्रज्ञान होय. बि–बियाणाची निर्मिती किंवा उत्पादन करीत असताना

विविध जातीतील बियाणाचा संकर घडवून आणून नवनवीन वाणांची निर्मिती केली जाते. दर्जेदार बियाणाचे उत्पादन व वितरण करणा-या महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ व राष्ट्रीय बीज निगमन या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख संस्था आहेत.

जलसिंचन तंत्रज्ञान –

अ.क्र.	तालुक्याचे नाव	पिकाखालील क्षेत्र	ओलिताखाली क्षेत्र	एकूण पिकाखालील क्षेत्राशी ओलिताखालील क्षेत्राचे प्रमाण
1	करमाळा	124226	43178	34.76 %
2	माढा	86945	40845	46.98 %
3	उ. सोलापूर	31056	9351	30.11 %
4	मोहोळ	76537	34790	45.46 %
5	पंढरपूर	48581	42201	86.87 %
6	माळशिरस	43801	34047	77.73 %
7	सांगोला	71556	10418	14.56 %
8	मंगळवेढा	89493	19672	21.98 %
9	द. सोलापूर	79204	23597	29.79 %
10	अक्कलकोट	127958	29007	22.67 %
11	बार्शी	91220	17676	19.38 %
एकूण		870577	304782	35.00 %

पिकांच्या समाधान कारक वाढीकरीता पाणी देण्याच्या क्रियेला सिंचन म्हणतात. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ठीबक सिंचन तंत्राचा अवलंब करून जमीन ओलिताखाली आणली जात आहे. जिल्ह्यातील शेतीला विहिरी, कुपनलिका कॅनॉल, नदी-नाले, सरोवर, धरणे, तलाव इ. तलावातील पाणी, विद्युत किंवा डीझेल पंपाद्वारे पुरविले जाते. जिल्ह्यातील सरसरी 35 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. परंतु, सर्व तालुक्यातील सिंचनाखालील क्षेत्रात समानता नाही. जिल्ह्यात सर्वाधिक सिंचन क्षेत्र पंढरपूर तालुक्यांत 86.87 % तर त्याखालोखाल माळशिरस तालुक्यात 77.73 % इतके आहे. सर्वात कमी सिंचन क्षेत्र सांगोला तालुक्यात आहे.

कृषी अवजारे तंत्रज्ञान –

शेती मशागतीसाठी व इतर कामासाठी कृषी अवजारांचा अमर्यादित स्वरूपात वापर म्हणजे कृषी यांत्रिकीकरण होय. कृषी अवजारे तंत्रज्ञान म्हणजे जमिनीची मशागत करण्यासाठी वापरली जाणारी सुधारित नवनवीन उपकरणे म्हणजे, कृषी अवजारे तंत्रज्ञान होय. कृषी विकासातील दुसरे महत्वाचे तंत्रज्ञान सुधारित कृषी अवजारे तंत्रज्ञान होय. या आधुनिक कृषी अवजारांद्वारे जमिनीच्या मशागतीपासून सर्व प्रकारचे कार्य कमी खर्चात कमी वेळेत व नियोजनबद्ध केली जातात.

रासायनिक खते तंत्रज्ञान –

रासायनिक खत तंत्रज्ञान हे अतिशय महत्वाचे तंत्रज्ञान म्हणून ओळखले जाते. नत्र, स्फुरद व पालाश या पोषक अन्न द्रवांची गरज भरून काढण्यासाठी विविध प्रकार च्या रासायनिक खतांचा वापर पिकासाठी करणे, म्हणजे रासायनिक खत तंत्रज्ञान होय. रासायनिक खतांचा व उच्च उत्पादन देणारी बि- बियांणाचा संतुलित वापर करणे गरजेचे आहे. जमिनीची सुपीकता सेंद्रिय व रासायनिक खतांच्या वापरावर अवलंबून आहे.

निष्कर्ष –

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राला महत्वाचे स्थान दिले आहे. सोलापूर जिल्ह्यांध्ये मागील 20 वर्षापासून कृषी अवजारांचा वापर वाढत आहे. जलसिंचन क्षेत्रामध्ये शेतीला पाणीपुरवठा करण्यात विहीरी, कुपनलिका, तलाव, कालवे यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. कृषी क्षेत्रात रासायनिक खत तंत्रज्ञान हे महत्वाचे तंत्रज्ञान म्हणून ओळखले जाते. सोलापूर जिल्ह्यात कृषी तंत्रज्ञानाबरोबरच हरितगृह तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला

जातो. कृषी विकासातील हरितगृह तंत्रज्ञान प्रभावी तंत्रज्ञान म्हणून ओळखले जाते. सुधारित व संकरीत बि-बियाणांचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे. त्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होऊन देशाच्या विकासाला हातभार लागला आहे.

संदर्भ -

1) सोलापूर जिल्हा सामाजिक आर्थिक समालोचन, 2015.
2) महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2020-21.
3) प्रा. भोसले, प्रा. काटे, कृषी अर्थशास्त्र, फडके प्रकाशन कोल्हापूर.
4) उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कृषी तंत्रज्ञानाचा भौगोलिक अभ्यास.
5) इंटरनेट लिंकिंग.
6) मासिके.
7) अहवाल.

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

महाराष्ट्र कुपोषण आणि राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियान

प्रा. नितिन विश्वनाथ खरात[1] प्राचार्य डॉ. रविंद्र भा. घागस[2]
[1]सहाय्यक प्रा. कीर्ती महाविद्यालय, दादर मुंबई-२८.
[2] प्राचार्य सौ. सीताबाई रा. करंदीकर महाविद्यालय वडकून, ता- डहाणू, जिल्हा- पालघर.

प्रस्तावना-

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागामध्ये कुपोषण मुक्त निर्मूलनासाठी महिला बाल विकास विभागांतर्गत व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या माध्यमातून ही योजना प्रभाविपणे काम करत आहे. या कार्यक्रमामध्ये ग्रामीण व आदिवासी भागातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या माध्यमातून महत्वाची भूमिका बजावत आहे. आज महाराष्ट्र राज्यापुढे अनेक आव्हानांपैकी कुपोषण हे एक आव्हान आहे. या आव्हानावर मात करण्यासाठी शासन महिला व बाल विकास सेवा योजनेच्या राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियांतर्गत कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत माता-बालकांच्या आरोग्य व पोषणाची काळजी करताना पूरक पोषण आहाराबरोबर माता व बालकांना अतिरिक्त आहार मिळावा म्हणून ग्रामीण व आदिवासी भागात परसबागची संकल्पना प्रत्येक घरोघरी व अंगणवाडी केंद्रामध्ये राबविण्यात आले आहेत. तसेच कुपोषण रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. या प्रयत्नांमध्ये शासनातील सर्व विभाग, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट व खाजगी क्षेत्र व्यवस्थापन यामध्ये सहकार्य करत आहे. त्याचबरोबर टाटा ट्रस्ट, जिंदाल स्टील वर्क्स, रिलायन्स फाउंडेशन इत्यादी कार्पोरेट या कामासाठी पुढे येऊन ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार व अमरावती या जिल्ह्यामध्ये कुपोषण थांबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे. बालकांच्या पोषण स्थितीचा विचार केला तर, महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्ये कुपोषणासाठी अतिसंवदनेशील दिसून येते. ग्रामीण व आदिवासी भागात शासन विविध उपाययोजना करत आहेत. ० ते ६ वर्ष लहान बालकांच्या कमी वजनात घट होत आहे यामध्ये लोकांचा सहभाग आणि शासनातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनातील कर्मचारी व अंगणवाडी सेविका या बालकांच्या पोषणाबाबत शासकीय उपक्रम जसे मुठभर धान्य योजना, माता-बाल माध्यमातून प्रभावी समुपदेशन, स्थानिक स्वराज्य संस्था सहकार्याने मोफत व्यवस्था उपलब्ध करून देत आहेत. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियान मार्फत महिला सक्षमीकरणाची विशेष मोहीम राबविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील प्रकल्प अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधून मातांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी भूमिका नाटय, विविध खेळ, फिल्म शो, इत्यादी वापर केला आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी महाराष्ट्र राज्यात लोकसहभागातून घडत असलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहेत. तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अधिकारी व कर्मचारी लोकसहभागातून राबविण्यात आलेले उपक्रम बालकांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी फायदेशीर ठरत आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन हे सन २००५ मध्ये स्थापना झाली. गेल्या १५ वर्षांमध्ये सर्वांनी केलेल्या प्रयत्नांना २०१२ मध्ये (Comprehensive Nutrition Survey in Maharashtra - CNSM) या अंतर्गत दाखवून दिले आहे.

उद्धेश-

१) राजमाता जिजाऊ बाल आरोग्य व पोषण अभियांतर्गत कुपोषणाचे व मृत्यूचा अभ्यास करणे.

२) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत ० ते २ वर्ष वयोगटातील मध्यम व तीव्र कमी वजनाच्या बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे.

३) गर्भवती स्त्रियांची व स्तनदा माता यांची काळजी घेणे, कमी वजनाची व रक्तक्षय असलेल्या स्त्रियांकडे विशेष लक्ष देणे.

४) नवजात अर्भक, ० ते २ वर्ष पर्यंतच्या वयोगटातील बालकांचे आरोग्य, आहार, वाढ, विकास व लसीकरण विशेष प्रयत्न करणे.

५) किशोरवयीन मुलींच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देऊन बालविवाहाचे प्रमाण कमी करणे, पहिले गरोदरपण लांबविणे, दोन अपत्यांमधील अंतर वाढविणे.

६) लहान बालकांमधील कुपोषणाचे सर्व प्रयत्नांनी तीव्रता कमी करणे व जनजागृती करणे.
७) गरोदर मातांचे वजन व हिमोग्लोबिन मोजणे व त्यांचे सनियंत्रण कारणे.

गृहीतके-

१) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंतर्गत राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियान ही कुपोषण व बालमृत्यू प्रमाण कमी करण्यासाठी सक्षम व यशस्वी यंत्रणा आहे.

संशोधन पद्धती-

प्रस्तुत शोधनिबंध संशोधकाने महाराष्ट्र राज्यातील कुपोषण आणि राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियान हा दुय्यम स्रोत म्हणून पुस्तके, मॅगझीन, शासकीय वेबसाईट, न्यूजपेपर, महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभागातील परिपत्रक इत्यादी.

माहितीचे विश्लेषण-

महाराष्ट्र राज्यातील बाल कुपोषण व बालमृत्यू ही गंभीर समस्या निर्माण झाल्यामुळे शासनाने ११ मार्च २००५ मध्ये राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियानांची स्थापना केली. या अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्यामध्ये यश प्राप्ती झालेली दिसून येते. अति कुपोषित मुलांची संख्या २००५ मध्ये १७६७२ वरून २०१० मध्ये ७८७३ पर्यंत कमी झालेली दिसून येते. महाराष्ट्रात बाल कुपोषणाची समस्या कायम असून त्याला आळा घालण्याची गरज आहे. म्हणून राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन हे लहान वयातील सर्व बालकांचे कुपोषण कमी करण्यावर भर दिला आहे. विशेषतः अंगणवाडी मार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कुपोषण कमी करण्यासाठी स्तनदा माता, गरोदर महिला व दोन वर्षापर्यंतच्या बालकांवर (९ महिने ते २ वर्ष) विशेष: जास्त लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. कारण याच कालावधीत कुपोषणाची सुरुवात होते व याच वयोगटातील सर्वात अधिक बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत जाते. एकात्मिक बाल विकास विकास सेवा योजनेंतर्गत (९ महिने ते २ वर्ष) गरोदर स्त्रिया आणि २ वर्ष वयापर्यंतच्या बालकांना विविध सेवा पुरवण्यावर नेहमी दुर्लक्ष होते. कारण या गरोदर स्त्रिया आणि २ वर्ष पर्यंतची (९ महिने ते २ वर्ष पर्यंत) बालके अंगणवाडीमध्ये दाखल करता येत नाहीत. म्हणून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घरीच व आई मार्फतच घेणे आवश्यक आहे. गर्भ धारणेपासून ६ महिन्यापर्यंतच्या मुलांना शासनाच्या पूरक पोषण आहार योजनेचा फायदा सुद्धा घेत नाही, कारण या मुलांना निव्वळ स्तनपान देणेच आवश्यक आहे. यामुळे राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियानाचे उद्धेश हे शासन एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत उपक्रम या आयुक्तांमार्फत पूर्णपणे स्वतंत्र जबाबदारी दिली गेली आहे. त्यामुळे मिशनला ९ महिने ते २ वर्ष वयोगटातील लहान बालकांवर विशेष: लक्ष केंद्रित करण्यात येते. राज्याच्या ग्रामीण व आदिवासीबहूल क्षेत्रामध्ये आरोग्य आणि पोषणाबाबत बऱ्याच गैरसमजूती, अंधश्रद्धा व अज्ञान आहे. शासनाने सुरु केलेली एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही बालकांच्या वाढीव विकासामध्ये सहकार्याची भूमिका बजावत आहे. बालकांची पोषणस्थिती सुधारण्यासाठीची जबाबदारी ही त्या-त्या कुटुंबातील व्यक्तींची आहे. कारण बालकांचा सर्वांगीण विकास हा खऱ्या अर्थाने कुटुंबामध्ये राहून मातेच्या संगोपनातून होत असतो. या जाणीवेतून कुटुंबातील प्रत्येक माता सक्षम झाली पाहिजे, हा उद्धेश डोळ्यापुढे ठेऊन राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य पोषण मिशन मार्फत आंतरव्यक्ती संवादाच्या माध्यमातून माता व कुटुंबांना सक्षम करण्याचे कार्य हाती शासनाने घेतले आहे. यामध्ये सर्वात प्रथम अंगणवाडी कार्यकर्ती, पर्यवेक्षिका, आशा कार्यकर्ती इत्यादी समुपदेशनाचे कौशल्ये, दृक-श्राव्य संवाद माध्यमे कशी हाताळायची याच ज्ञान देण्यात येत आहे. किशोरवयीन मुली, गरोदरमाता, स्तनदा माता व कुपोषित बालके यांच्या आहाराबाबत समाजात बऱ्याच गैरसमज आहेत. अशा गैरसमज दूर करून मातांच्या विचारात बदल करण्याचे कार्य केले जाते. अंगणवाडी कार्यकर्ती, आशा इत्यादींच्या माध्यमातून बालकांच्या वजनवाढीचे संनियंत्रण करण्यात आले आहेत. कुपोषण निर्मूलनासाठी माता व कुटुंब सक्षमीकरण हा केंद्रबिंदू ठेऊन प्रसार माध्यमातून आरोग्य व पोषणबाबतची जनजागृती मोठया प्रमाणात करण्यात येत आहे. त्यामध्ये टीव्ही, रेडीओ, सिनेमागृह, बस पॅनल्स, वेबसाईट, वर्तमानपात्र, फिल्म-शो, अंगणवाडी केंद्र, लोकराज्य मासिके, पारंपारिक माध्यमे जसे कलापथम, कीर्तनकार इ. प्रसार माध्यमांचा जनजागृतीसाठी मोठया प्रमाणात वापर होतो.

गरीब व गरजू गरोदर माता यांचे शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम होऊन तिच्या पोटी जन्माला येणारे बाळ सुदृढ व निरोगी असावे अशी मदर केअर सेंटर स्थापना करण्यात आले आहेत. गरीब कुटुंबामध्ये बहुतांश मातांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी कष्टाची कामे करावी लागते. त्यात माता जर गरोदर असेल तर तिचे अशा कामांमुळे आरोग्य व पोषणाकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे तिच्या पोटी जन्माला येणारे बाळ हे कुपोषित असते. यावर गरोदर माता, मातांच्या आरोग्य, पोषण व रोजगाराची हमी जर गावाने घेतली तर कुपोषणावर कायमस्वरूपी प्रतिबंध निर्माण करता येईल. अशी जर प्रत्येकाने ठेवली तर कुपोषण रोखण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील

गरोदर मातांना गावातच रोजगाराची सोय म्हणून मदर केअर सेंटरची स्थापना केली. या सेंटरमध्ये हलक्या सरूपाचे काम देण्यात येते व त्यामध्ये ६० रुपये मजुरी व आहार ४० रुपये देण्यात येते.राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त अभियानाची अंबलबजावणी करत असताना अंगणवाडी केंद्रातील जाणाऱ्या बालकांना चांगले वातावरण मिळून, त्यांची लहान वयातच शिक्षणा विषयी ओढ निर्माण व्हावी म्हणून अंगणवाडी सक्षम करण्यात येत आहे. शहरी भागात शिक्षण मिळते तसेच गावात शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. अंगणवाडी केंद्रामध्ये बालकांचा शारीरिक व बौद्धिक विकास व्हावा आणि त्यांच्या आरोग्य व पोषणाकडे लक्ष केंद्रित केल्यास संस्कारक्षम पिढी निर्माण होण्यास मदत होते. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी सक्षमीकरण लोकांचा सहभाग मिळावा तसेच बालकांना सर्व मुलभूत सोई-सुविधा देतात अंगणवाडयांमध्ये उपस्थिती वाढावी यासाठी आदर्श अंगणवाडी निर्माण करावी. अंगणवाडी परिसर स्वच्छ व ठिकठिकाणी फुले-झाडे लावण्यात यावी. बालकांना खेळण्यासाठी खेळणी ठेवण्यात यावी. भिंती रंगविण्यात यावी. बालकांना शुद्ध पिण्याच्या व शौचालयाची व्यवस्था करून द्यावी.कुपोषण निर्मुलनामध्ये शासनाबरोबर समाजाच्या सर्व घटकांचा सक्रीय सहभाग घेण्यासाठी शासन राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियान राबवत आहे. या अभियानाव्दारे पहिले १००० दिवस बाळाच्या - पंचसूत्री कार्यक्रमावर भर देण्यात येते. गर्भवती मातेच्या पोटी साधारण किंवा चांगल्या वजनाचे बाळ जन्माला येण्यासाठी गर्भवती मातेस अतिरिक्त आहाराची गरज आहे. महाराष्ट्रातील जन्मत: कमी वजनाच्या (LBW) बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी याबाबत जनजागृती, क्षमता बांधणीवर भर देण्यात येत आहे. या कामी लोकसहभाग मिळवताना अनेक नाविन्यपूर्ण कल्पना प्रत्यक्षात अंबलबजावणी करण्यात आली. माहेर मधून आदिवासी भागातील कुपोषण व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी गरोदर मातांना एकवेळचा चौरस आहार देण्यात येतो. गरोदर मातेस तो आहार दुपारी १२.०० ते १.०० यावेळेत अंगणवाडीमध्ये देण्यात येतो. आहार घेतल्यानंतर मातेस दोन तास विश्रांती दिली जाते. विश्रांती कालावधीत मातेस चौरस आहार, दवाखान्याची प्रसूती, जन्मतःबाळाचे वजन, अर्ध्या तासाच्या आत स्तनपान, चिकाच्या दुधाचे महत्व, सहा महिने निव्वळ स्तनपान, ६ महिन्यानंतर अंगावरील दुध व पूरक आहार असे दोन वर्ष बाळास देणे हे मार्गदर्शन सीडी, पुस्तक, मार्गदर्शिका, नाटीका यामधून पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका यांच्यामार्फत देण्यात येते.

कुपोषणावर प्रतिबंध घालण्यासाठी राजमाता जिजाऊ मिशन मार्फत – ९ ते २४ महिने या कालावधीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येते. त्यासाठी या मिशनमार्फत शासकीय स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी समाजात जनजागृती करण्यात येते. आदिवासी क्षेत्रामध्ये कमी वजनाचे बाळ जन्माला येण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी मिशनमार्फत गरोदर मातांना एक वेळचा अतिरिक्त आहार महाराष्ट्रात रुजवून प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये डोहाळे जेवणासारखे उपक्रम लोकसहभागातून राबविले जाते. त्याचबरोबर अंगणवाडी कार्यक्षेत्रातील सर्व गर्भवती महिलांना सातवा महिना सुरु झाल्यानंतर त्यांच्या डोहाळे जेवणाचा कार्यक्रम अंगणवाडीत साजरा करून सातवा ते नववा महिना या शेवटच्या तिमाही तरी अतिरिक्त आहार मिळतो. या उपक्रमांतर्गत गरोदरपणातील शेवटच्या तिमाहीत गरोदर मातेला चौरस आहार देण्यात येतो. या आहारात डाळ, हिरव्या पालेभाज्या, फळ भाज्या, भाकरी किंवा पोळी, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी आदींचा समावेश असतो. या डोहाळे जेवणातून अंगणवाडी स्तरावर गरोदर मातेचे गरोदरपणातील वजन वाढीचे सनियंत्रण करण्यात येते. हा उपक्रम सर्व अंगणवाडी केंद्रामध्ये मोठया उत्साहात केला जातो.

कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी लोक सहभागातून गर्भसंस्कार केंद्रामध्ये ज्या गरोदर महिलेला ७ वा, ८वा व ९वा महिना सुरु आहे अशा स्त्रियांना गावातुन मिळालेल्या लोक सहभागातून एक वेळचा अतिरिक्त आहार दिला जातो. तसेच दुपारी २ तास या गरोदर स्त्रिया अंगणवाडी केंद्रामध्ये आराम करीत असतात. या २ तासांमध्ये त्यांना आहार व पोषणाबाबत गर्भसंस्काराचे मार्गदर्शन, लोहयुक्त गोळयांचे प्रत्येक्षात सेवन, स्तनपानाविषयी माहिती दिली जाते. जेणेकरून या महिलांच्या पोटी जन्माला येणारे आपत्य हे ३ किलोचे असणार आहे.म्हणून यासाठी अंगणवाडी सेविकेने गावातुन लोकसहभागाच्या माध्यमातून निधी जमा करावे तसेच या निधीचा वापर गावातील गरोदर स्त्रियांच्या एकवेळचा आहारासाठी केला जावा. अंगणवाडी केंद्रातील या गर्भसंस्कार केंद्रामध्ये लाभ घेणाऱ्या गर्भवती महिलांकडून या विषयीची माहिती इतर महिलांनाही दिली जाते. जेणेकरून गावातील सर्व ० ते ६ वर्ष वयोगटातील मुले साधारण श्रेणीमध्ये राहण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न केले जाते.राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण हे कृषी व पोषण या दोन गोष्टीत शासन कृषी विभाग स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट या सारख्या सहकार्यासाठी सक्षम असतात. याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील घरोघरी परसबाग विकसित होण्यासाठी महिलांचे स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून काम करतात. याबरोबर अंगणवाडी केंद्र, प्राथमिक शाळा, आदिवासी आश्रमशाळा इ. सर्व शासकीय संस्थामध्ये परसबाग विकसित करण्याच्या दृष्टीने सहकार्य घेत आहे. अंगणवाडी परिसरात व घराभोवती

असलेल्या जमिनीत भाजीपाला लावणे आणि उगवलेल्या भाज्यांच्या वापर अंगणवाडीतील आहार किंवा स्वयंपाकात वापरणे. ज्यामुळे शरीरासाठी आवश्यक असलेली पोषणमुल्ये मिळून बालकांची पोषणस्थिती सुधारेल यासाठी राज्यात परसबाग विकसित करणे हे राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन मार्फत पुढाकार घेतला आहे.

निष्कर्ष-

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य पोषण मिशन मार्फत आंतरव्यक्ती संवादाच्या माध्यमातून माता व कुटुंबांना सक्षम करण्याचे कार्य शासनाने हाती घेऊन कुपोषण व बालमृत्यू प्रमाण कमी केले आहे.

संदर्भसूची-

१) महिला आणि बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन हे निरंतर बाल जीवन रक्षण माहिती पुस्तिका (महाराष्ट्र शासन)

२) अंगणवाडया आणि कुपोषण, लोकसत्ता पेपर ११ डिसेंबर, २०१३.

३) महिला व बाल विकास विभाग, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन, महाराष्ट्रातील कुपोषण निर्मूलन यशोगाथा, महाराष्ट्र शासन माहिती पुस्तिका.

४) दास के. सुजाता, (२०१६), कुपोषण एक ज्वलंत समस्या,

५) डॉ. मालती कारवारकर, (२०१३)आहारातून कायाकल्प, मैत्रेय प्रकाशन.

६) योजना मासिक, २०१८ पोषण आहार

७) पालघर बाल आरोग्याची यशस्वी वाटचाल, प्रकाशक: सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन पुस्तिका.

८) वृत्तपत्रातील बातम्या व पालघर मित्र न्यूस पेपर

९) ग्राम बाल विकास केंद्र, मार्गदर्शिका माहिती पुस्तिका, महाराष्ट्र शासन.

१०) लेखक, सौ. खैरे निर्मला, बालविकास परिचय, मेरी एलन डरेट, सौ. कमला कोसांबी भूता. साधना प्रकाशन, पुणे.

११) पालघर जिल्ह्यात टाळेबंदीत कुपोषण प्रमाण वाढले, पालघर, लोकसत्ता पेपर बातमी, १४ जुलै, २०२०.

१२) लेखक, सावंत डॉ. दीपक, आरोग्य मंत्री 'वास्तव कुपोषणाचे' महाराष्ट्र शासन.

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR) **ISSN – 2347-7075**
Peer Reviewed Bi-Monthly **Impact Factor –7.328**
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

वर्धा जिल्ह्यातील रस्ते वितरणाचा भौगोलिक अभ्यास

प्रा. बुद्धघोष म. लोहकरे
सह्योगी प्राध्यापक, यशवंत महाविद्यालय वर्धा.
budhaghosh@rediffmail.com

सारांश :

प्रस्तुत संशोधन लेखामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील रस्ते वितरणाचा व तालुकानिहाय रस्ते घनतेच्या वितरणाचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यासाठी वर्धा जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2018 मधील सांख्यिकीय माहिती प्राप्त करून व रस्ते घनतेच्या सूत्राचा वापर करून तालुकानिहाय रस्त्यांच्या घनतेची गणना केली आहे. त्या आधारावर वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट, वर्धा, देवळी आणि आर्वी या तालुक्यात रस्त्यांची घनता ही जास्त आहे. मात्र जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील कारंजा, आष्टी आणि समुद्रपूर या तालुक्यात रस्त्याची घनता कमी असलेली पहावयास मिळते.

प्रस्तावना :

वस्तुची, मालाची किंवा मनुष्याची एका प्रदेशाकडून दुसऱ्या प्रदेशाकडे हेतूपुरस्परपणे केलेली ने–आण म्हणजे वाहतूक होय. आधुनिक काळात वाहतुकीचे स्वरुप, प्रकार आणि उपयोगिता यामध्ये पुष्कळ बदल झालेला पहावयास मिळतो. एकप्रकारे वाहतुकीला आर्थिक विकासाची जीवनरेषा म्हणता येते. आधुनिक काळात विविध वस्तु किंवा मालाच्या ने–आण करण्यासाठीच वाहतूकीचा वापर केला जात नाही तर विविध प्रकारच्या सेवा ग्राहकांपर्यत पोहचविण्यासाठी देखील वाहतूकीचा वापर केला जातो. ग्राहक आणि सेवा यांच्यामधील सेतुचे कार्य वाहतूक हा घटक करीत असल्याने आधुनिक काळातील सेवा क्षेत्रात वाहतुकीला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. वाहतूक सुगम होण्यासाठी रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. भौगोलिक दृष्ट्या एखाद्या प्रदेशातील भूरचना कशा प्रकारची आहे यावर त्या प्रदेशातील वाहतूक मार्गांचा विकास अवलंबून असतो; याचा अर्थ असा की वाहतूक मार्ग आणि भूरचनेची सुगमता यांचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. पर्वतीय प्रदेश हे अतिशय उंच व तीव्र उताराचे असल्याने तिथे रस्ते विकासाला मर्यादा येतात. मात्र मैदानी प्रदेश कमी उंची चे व मंद उताराचे असल्याने अशा प्रदेशात वाहतूक मार्गांचा विकास अधिक प्रमाणात होतो. प्रस्तुत संशोधन लेखामध्ये याच दृष्टीने अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.जगातील अमेरीका, इंग्लड, फ्रान्स, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, जपान या विकसित देशांच्या रस्ते वितरणाचा अभ्यास केल्यास त्यांच्या विकासाची जीवन रेषा ही रस्तेच असल्याचे दिसून येते. एखाद्या क्षेत्रातून कच्चामाल, कुशल कामगार, शेती उत्पादने, तंत्रज्ञान पोचवण्यासाठी रस्ते उपयोगाचे ठरतात. भारत अलीकडच्या काळात रस्ते विकासाला प्राधान्य देताना दिसतो आहे. विशेषता शेती क्षेत्रातून निघणारा भाजीपाला, फळे, दुध हा जितक्या लवकर नागरी क्षेत्रामध्ये पोहोचेल तितक्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेले पहावयास मिळते. आरोग्य सेवा आणि वाहतुक यांचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या मतानुसार कोणत्याही भागात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत आरोग्य केंद्र असणे गरजेचे आहे. परंतु 40 ते 60 टक्केच गरीब देश हे उद्दीष्ट पूर्ण करताना दिसून येतात. (ट्रान्सेड, 1990) रस्त्यांचे जाळे हे जितक्या मोठ्या प्रमाणात एखाद्या प्रदेशांमध्ये पसरलेले असेल तितक्या प्रमाणात त्या प्रदेशाचा व लोकांचा विकास झालेला पहावयास मिळतो. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, कृषी, उद्योगधंदे या सगळयांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून रस्त्यांचा विकास होणे अपेक्षित आहे. याच उद्देशाने या संशोधन लेखांमध्ये वर्धा जिल्ह्यातील तालुकानिहाय रस्त्यांच्या वितरणाचा व घनतेचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

उद्दीष्ट्ये :

1) वर्धा जिल्ह्यातील रस्ते प्रकार वितरणाचा अभ्यास करणे.

2) वर्धा जिल्ह्यातील तुलनात्मक रस्ता घनतेच्या वितरणाचा अभ्यास करणे.

माहिती स्त्रोत व अभ्यास पद्धती

प्रस्तुत संशोधनासाठी वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2018 मधील माहितीचा उपयोग केलेला आहे. रस्त्यांची घनता काढण्यासाठी रस्ता घनतेच्या सूत्राचा उपयोग केलेला आहे. त्याच प्रमाणे विविध आकृत्या व नकाशाचा वापर करून वर्धा जिल्ह्यातील तालुकानिहाय रस्त्यांचे वितरण दर्शविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

वर्धा जिल्हा : रस्ते प्रकारांचे प्रमाण

वर्धा जिल्ह्यात वाहतुक मार्गामध्ये रेल्वे मार्गाचे प्रमाण अत्यंत कमी असून मुंबई दिल्ली हा एकमेव मार्ग आढळतो. याशिवाय संपूर्ण जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग या रस्त्यांचे विविध प्रकाराचे जाळे पसरलेले दिसून येते.

तक्ता क्र. 1 : रस्त्यांचे विविध प्रकार लांबी

क्र.	तालुका	रस्त्यांचे प्रकार व रस्त्यांची लांबी (कि.मी)						
		राष्ट्रीय महामार्ग	मुख्य राज्य महामार्ग	राज्य महामार्ग	मुख्य जिल्हा मार्ग	इतर जिल्हा मार्ग	ग्रामीण रस्ते	एकूण रस्त्यांची लांबी (प्रति100कि.मी.)
1	आष्टी	14	0	56.8	80.45	84	160.3	395.55
2	कारंजा	30	0	94	140.6	135.55	157.2	557.35
3	आर्वी	57.46	0	132.05	77.55	553.1	195.5	1015.66
4	सेलू	56.41	0	67.5	155.5	162.97	263.55	705.93
5	वर्धा	107.12	8.2	140.6	143.3	223.03	298.2	920.45
6	देवळी	40.8	29	128.7	52.45	258.6	177	686.55
7	हिंगणघाट	3.18	0	89.6	136	669.15	250	1147.93
8	समुद्रपूर	16.24	0	70.8	88.9	142.62	315.19	633.75
9	एकूण	325.21	37.2	780.05	874.75	2229.02	1816.94	6063.17

स्त्रोत : वर्धा जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2018

वर्धा जिल्ह्यातील विविध प्रकारच्या रस्ते वितरणावर दृष्टीक्षेप टाकल्यास असे दिसून येते की, 2017 च्या शासकिय माहीतीनुसार प्रती 100 चौ किमी मागे जिल्ह्यात रस्त्यांची एकूण लांबी 6063.17 किमी असून त्यात राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी 325.21 कि.मी., राज्य मार्गाची लांबी 817.25, मुख्य जिल्हा मार्गाची लांबी 2229.02 कि.मी., इतर जिल्हा मार्गाची लांबी 1816.94कि.मी.इतकी आहे. हे तुलनात्मक वितरण पुढील आकृती वरुन लक्षात येते. तालुकानिहाय रस्त्या प्रकारानुसारची लांबी तक्ता क्र. 1 मध्ये दिलेली आहे.

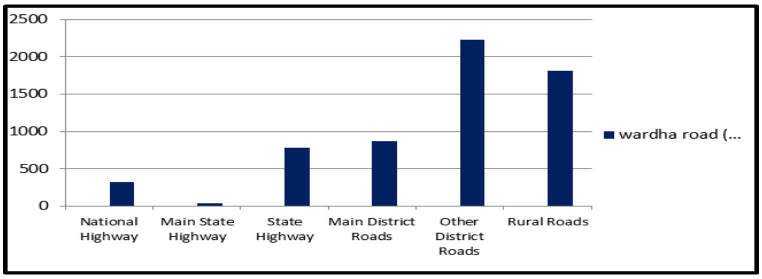

आकृती : वर्धा जिल्हाः रस्ते प्रकारांचे प्रमाण

वर्धा जिल्हा : तालुका निहाय रस्त्यांची घनता

वर्धा जिल्हा कमी क्षेत्रफळाचा जिल्हा असून या जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 6309 चौ. किमी इतके आहे. 2017 च्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात रस्त्यांची एकूण लांबी 6063.17 कि. मी. इतकी आहे. परंतू वाहतूक मार्गावर भौगोलिक घटकांचा प्रभाव पडत असतो. त्यामुळे जिल्ह्याच्या वेगवेगळया तालुक्यांच्या भागात रस्त्यांचे प्रमाण भिन्न– भिन्न आढळते.

तक्ता क्र. 2. : तालुकानिहाय रस्त्यांची लांबी आणि घनता

क्र.	तालुका	एकुण क्षेत्रफळ (चौकिमी .)	रस्त्यांची लांबी (कि.मी .)	रस्त्यांची घनता (कि.मी .)
1	आष्टी	551.67	395.55	71.70
2	कारंजा	751.12	557.35	74.20
3	आर्वी	908.27	1015.66	111.82
4	सेलू	765.13	705.93	92.26
5	वर्धा	774.67	920.45	118.81
6	देवळी	680.91	686.55	100.82
7	हिंगणघाट	910.83	1147.93	126.03
8	समुद्रपूर	966.4	633.75	65.57
9	एकूण	6309	6063.17	96.10

स्त्रोत : वर्धा जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2018

वाहतूक मार्गाच्या लांबीच्या आधारावर वितरणाचा विचार केल्यास सर्वात जास्त वाहतूक मार्गाचे प्रमाण हिंगणघाट तालुक्यात असून यात रस्त्याची एकुण लांबी 1147.93 कि.मी. आहे. त्याखालोखाल आर्वी तालुक्याचा क्रमांक येतो. या तालुक्यात 1015.66 ला लांबीचे वाहतूक मार्ग आहेत. याशिवाय वर्धा, सेलू, देवळी, समुद्रपूर, कारंजा आणि आष्टी या तालुक्यातील वाहतूक मार्गाची लांबी अनुक्रमे 920.45 कि.मी., 705.93 कि.मी., 686.55 कि.मी., 633.55 कि.मी., 557.35 कि.मी. आणि 395.55 कि.मी. आढळते. वाहतूक मार्गाच्या वितरणावर भूपृष्ठरचेनेशिवाय प्रदेशाचे क्षेत्रफळ, वसाहतींचे प्रमाण, वस्त्यांची घनता, अंतर यांचाही प्रभाव पडतो. त्यामुळे वाहतुकीचे मार्गाचे प्रमाण व स्वरुपही बदलते. प्रदेशाचे क्षेत्रफळ हा घटक वाहतूक मार्गाच्या वितरणावर अधिक प्रभावित करीत असल्याने प्रदेशाचे क्षेत्रफळ व वाहतूक मार्गाच्या लांबीच्या गुणोत्तराचा विचार वाहतूक घनतेच्या स्वरुपात करणे योग्य राहते. वर्धा जिल्हयातील सरासरी रस्त्यांची घनता प्रती 100 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाच्या संदर्भात केल्यास असे दिसून येते की, वर्धा जिल्ह्यात हि घनता 96.10 कि.मी. इतकी आहे. सरासरीनुसार तालुकानिहाय रस्ता घनतेचा विचार केल्यास सरासरी पेक्षा जास्त घनता हिंगणघाट, वर्धा आर्वी, आणि देवळी या तालुक्यात अनुक्रमे 126.03 कि.मी. 118.81 कि.मी. 111.82 कि.मी. आणि 100.82 कि.मी. असल्याचे दिसते. तर सरासरी पेक्षा रस्त्यांची कमी घनता सेलू, कारंजा, आष्टी आणि समुद्रपूर या तालुक्यात अनुक्रमे 92.26 कि.मी., 74.20 कि.मी., 71.70 कि.मी. आणि 65.70 कि.मी. असल्याचे दिसते. सगळयात जास्त रस्त्यांची घनता हिंगणघाट तालुक्यात 126.03 कि.मी. तर सगळयात कमी समुद्रपूर तालुक्यात 65.70 कि.मी. आढळते.

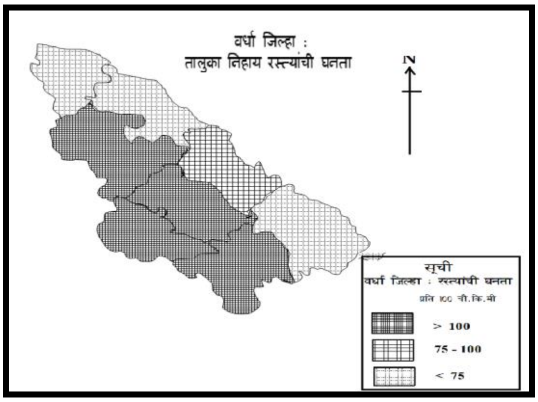

नकाशा क्र. -1 तालुकानिहाय रस्त्यांची घनता

सोबत दिलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या नकाशात वर्धा जिल्ह्यातील वाहतूक मार्ग घनतेचे वितरण दर्शविलेले आहे. या वितरणाचा विचार केल्यास असे दिसून येते की, हिंगणघाट, वर्धा, देवळी आणि आर्वी या चार तालूक्यात वाहतूक मार्गाची घनता 100 कि.मी. पेक्षा जास्त आहे. सेलू तालूक्यात वाहतूक घनता 100 कि.मी. पेक्षा जास्त मात्र 75 कि.मी. पेक्षा कमी दिसून येते. तर 75 कि.मी. पेक्षा कमी वाहतूक घनता समुद्रपूर, आष्टी आणि कारंजा या तालुक्यात पहावयास मिळते. आष्टी, कांरजा या तालुक्यातील बहुतेक प्रदेश डोंगरटेकडयांचा असल्याने या प्रदेशातील वाहतूक मार्गावर भूपृष्ठरचनेचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो.

निष्कर्ष

प्रस्तुत संशोधन पत्रामध्ये केलेल्या संशोधनामध्ये हे आढळून येते की, वर्धा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात रस्त्यांचे वितरण समान प्रमाणात झालेले नसून आर्वी, वर्धा आणि हिंगणघाट या तालुक्यात रस्त्यांचे प्रकार व त्यांची लांबी अधिक आहे. वर्धा तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रमाण जास्त तर आर्वी आणि देवळी तालुक्यात राज्य महामार्गाचे प्रमाण जास्त आहे. उर्वरित तालुक्यात याचे प्रमाण कमी दिसते सोबतच एकंदरीत प्रदेशातील क्षेत्रफळ व रस्त्यांची लांबी या दोन घटकांचा विचार करून काढलेल्या घनतेमध्ये सर्वात जास्त रस्त्यांची घनता ही हिंगणघाट तालुक्यात असून त्याच्या खालोखाल वर्धा, आर्वी, देवळी आणि सेलू तालुक्यांचा समावेश होतो. मात्र उर्वरित आष्टी, कारंजा आणि समुद्रपूर तालुक्यात रस्त्यांची घनता ही वर्धा जिल्ह्याच्या सरासरीपेक्षा कमी असलेली दिसून येते. अलीकडच्या काळात सध्याच्या सरकारचे धोरण रस्त्यांची लांबी, रस्त्यांचा प्रकार यांच्या विकासाकडे अधिक लक्ष पुरविणारे असल्याने भविष्यात वर्धा जिल्ह्याच्या काही क्षेत्रात यामध्ये निश्चितच बदल झालेला पाहावयास मिळणार आहे.

संदर्भ :

1. अहिरराव आणि अलिझाड (1992) : “आर्थिक भूगोल” निराली प्रकाशन, पुणे
2. कौशिक अर्जुन (2012) : “परिवहन भूगोल” पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
3. पाल पुष्पा (2020) : “परिवहन भूगोल” भाषा प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली
4. वर्धा जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन – 2018
5. Transaid (2001): “*A practical transport management system for non- profit and service delivery organization”.* Transaid Worldwide, London
6. Gautam P.S. (2010) : “ *Transport Geography of India*” Mittal Publications, Dariyaganj, New Delhi
7. Bose Samrat (2003) : *Road Density, Resource Intensity and Efficiency in National Highways of India: (1958-1997)* Economic and Political Weekly Vol. 38, No. 6 (Feb. 8-14, 2003), pp. 561-571

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

फॅसिझम एक ऐतिहासिक अभ्यास

प्रा. सुहास रामचंद्र नलावडे

इतिहास विभाग प्रमुख, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील महाविद्यालय नातेपुते

प्रस्तावना

इटलीमध्ये पहिल्या महायुद्धानंतर उदयास आलेली एक सर्वंकष सत्तावादी आधुनिक राजकीय विचारप्रणाली. इटलीत अडचणीच्या आणि गोंधळाच्या परिस्थितीत फॅसिझम निर्माण झाला. नीतोमुसोलिनीने त्या नव्याने वाढणाऱ्या चळवळीचे व संघटनेचे नेतृत्व केले. मुसोलिनी सुरुवातीला समाजवादी होता. समाजवादी पक्षाचे मुखपत्र अवंती(Avanti) या दैनिकाचा तो संपादकही होता; परंतु नंतर त्याचे मन बदलले आणि तो समाजवादाला कडवा विरोध करणाऱ्या फॅसिस्ट पक्षाचा निर्माता आणि पुढारी झाला. हे १९२० च्या सुमारास घडले. फॅसिझम हा शब्द 'फॅसिओ' वरून निघालेला आहे. फॅसिओ म्हणजे लाकडांच्या जुटीमध्ये बांधलेली कुऱ्हाड.रोमन साम्राज्याचे ते चिन्ह होते. फॅसिझमचा पुढे वाढलेला साम्राज्य वाद आणि युद्धखोर वृत्ती यांचा त्या चिन्हाने चांगला बोध होतो. पहिल्या महायुद्धानंतर इटलीची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली होती. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होता आणि बाजारभाव खूप वाढले होते. बेकारीही खूप वाढली होती. जनता संत्रस्त झाली होती व कामगारवर्गामध्ये बंडखोर प्रवृत्ती वाढली होती. त्यांनी त्या काळात अनेक संप केले. काही ठिकाणी कामगारांनी कारखानेही ताब्यात घेतले. रशियाचे उदाहरण त्यांच्यासमोर होतेच. भांडवलदारादी प्रस्थापित वर्गाला ही परिस्थिती अत्यंत भयावह वाटली. त्यांना ती काबूत आणून आपले स्वतःचे संरक्षण करावयाचे होते व प्रचलित समाजव्यवस्था कायम टिकवायची होती. कामगारांच्या संपाला उत्तर म्हणून त्यांनी अनेक वेळा टाळेबंदी पुकारली, पण तेवढ्याने भागेना, म्हणून कामगार चळवळ समूळ दडपून टाकण्याचे त्यांनी ठरवले. फॅसिस्ट पक्षाने त्या वेळी त्यांना खूप साहाय्य केले व भांडवलशाही समाजपद्धत जी कोलमडून पडत होती, तिला त्याने स्थिर पायावर उभे केले. मुसोलिनीने उभारलेल्या फॅसिस्ट पक्षात मुख्य भरणा होता, तो बेकार कामगारांचा आणि मध्यम वर्गातील दिशाहीन तरुणांचा.

सुरुवातीला हा पक्ष लहान होता. भांडवलदारांच्या व इतर श्रीमंत मंडळींच्या पाठिंब्यामुळे तो हलके हलके वाढत गेला, पण त्याची खरी वाढ झाली, ती राजकीय सत्ता हातात आल्यानंतर. राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी फॅसिस्टांनी २८ ऑक्टोबर १९२२ रोजी राजधानीच्या रोम शहरावर मोर्चा काढला. या रोम शहरावरील मोर्चाचा फॅसिस्ट चळवळीत 'मोठी वीरश्रीची घटना' म्हणून उल्लेख होतो; परंतु त्या मोर्चामध्ये वीरश्री दाखविण्याचे कारणच पडले नाही. मोर्चाला कुणाचाही विरोध झाला नाही. फॅसिस्टांना रोममध्ये बिनविरोध प्रवेश मिळाला आणि राजाने आपण होऊन राजसूत्रे मुसोलिनाला बहाल केली. मुसोलिनी राजाच्या आमंत्रणावरून देशाचा मुख्यमंत्री बनला आणि तेव्हापासून इटलीमध्ये फॅशस्ट राजवट सुरू झाली. या काळात इटलीमध्ये समाजवादी, साम्यवादी व अराज्यवादी असे वाममार्गी पक्ष होते.

यांखेरीज उजव्या विचारसरणीचे व मध्यममार्गाचे असे इतरही काही पक्ष होते. या सर्व पक्षांच्या सभासदांची संख्या फॅसिस्ट पक्षाच्या सभासदांपेक्षा कितीतरी अधिक होती.

उद्देश - फॅसिझम एक ऐतिहासिक अभ्यास

सर्वांनी मिळून एकजुटीने फॅसिस्ट पक्षाला विरोध केला असता, तर त्या पक्षाचे पाऊल पुढे पडले नसते; पण ते सर्व पक्ष एकमेकांत भांडत होते, विशेषतः समाजवादी व साम्यवादी पक्षांतील भांडण अत्यंत तीव्र होते. त्यामुळे ते नामोहरम झाले आणि देशात फॅसिस्ट पक्षाची हुकूमशाही स्थापन झाली. सत्ता हाती आल्याबरोबर मुसोलिनीने विरोधकांचा छळ सुरू केला. भाषणस्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य, संघटनास्वातंत्र्य इ. नष्ट केले आणि मुसोलिनी व त्याचा पक्ष यांच्याविरूद्ध ब्र काढणेही अशक्य झाले. विरोधकांची धरपकड चालूच होती, यावेळी मुसोलिनीने विरोधकांना जबरदस्तीने एरंडेल तेल पाजण्याचे नवे तंत्र सुरू केले. अनेक विरोधक या जाचाला कंटाळून देश सोडून गेले, अनेकांना वर्षानुवर्षे तुरूंगात खितपत पडावे लागले. तरीदेखील थोडासा विरोध झालाच, पण फॅसिस्टांना पाशवी उपायांचा अवलंब करून तो चिरडून टाकला.

राज्यसत्ता हातात आली, त्या वेळी लोकसभेत फॅसिस्ट पक्ष अल्पसंख्य होता. एकदोन वर्षात मुसोलिनीने राज्यघटना बदलली आणि त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत फॅसिस्ट १०० %निवडून आले. त्या निवडणुकीची तऱ्हा मोठी वेगळी होती. फॅसिस्ट पक्षाने तयार केलेल्या उमेदवारांच्या यादीवर 'होय किंवा नाही' एवढेच जाहीर करण्याचा मतदारांचा हक्क होता आणि तो हक्कदेखील त्यांनी उघडपणे बजावला पाहिजे, अशी योजना होती. म्हणजेच मतदान गुप्त नव्हते, शिवाय मतदान आपल्या बाजूने व्हावे, म्हणून फॅसिस्ट गुंडांची धाकदपटशाही आणि गुंडगिरी होतीच. निकाल अर्थातच त्यांच्या बाजूने लागला. मुसोलिनीचा लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि लोकशाही हक्क यांवर विश्वास नव्हता. लोकशाहीमुळे देशामध्ये नाना पक्ष आणि पंथ माजतात, त्यामुळे देश विस्कळीत होतो. व त्याला कोणतेही निश्चित धोरण आखता येत नाही, असे त्याचे मत होते.लोकशाही स्वातंत्र्यामुळेही तेच घडते, असेही त्याला वाटत होते. म्हणून देशाचा कारभार सुरळीत रीतीने चालावयाचा आणि देशाची प्रगती व्हावयाची तर देशामध्ये एकच पुढारी असला पाहिजे व देशातील सर्व कारभार त्याच्या एकट्याच्या मर्जीनुसार चालला पाहिजे, असा त्याचा आग्रह होता म्हणूनच त्याने एकतंत्री राज्यकारभार सुरू केला आणि त्या कारभाराला कुणाचाही विरोध होऊ नये, म्हणून हुकूमशाही स्थापन केली. देशामध्ये एकच पुढारी असला पाहिजे म्हणून तो राज्याचा सर्वाधिकारी व पक्षाचा एकमेव नेता बनला. फॅसिस्ट पक्षाखेरीज इतर सर्व पक्ष त्याने बेकायदा ठरवले व देशातील सर्व राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक संस्था आपल्या पक्षाच्या हुकूमतीखाली आणल्या. फॅसिझमला, फॅसिस्ट पक्षाला व मुसोलिनीला इटलीमध्ये सर्वसामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळाला. त्याचे मुख्य कारण हे की लोक तत्कालीन दुरवस्थेला, शासनाच्या दुबळेपणाला व समाजातील गोंधळाला कंटाळले होते. त्यांना स्थिर व समर्थ सरकार हवे होते. असे सरकारच आर्थिक अरिष्टातून मार्ग काढून उद्योगधंदे वाढवू शकेल, बेकारी दूर करू शकेल व राष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करू शकेल, असे त्यांना वाटत होते. पहिल्या महायुद्धात विजयी राष्ट्रांच्या बाजूने युद्धात भाग घेऊनही हवा असलेला मूलुख पदरात पडला नाही. म्हणून इटलीचा मोठा मानभंग झाला होता. या सर्व बाबतीत मुसोलिनीने व फॅसिस्ट पक्षाने मोठी आकर्षक

आश्वासने दिली. लोक त्यामुळे भुलले व त्यांना फॅसिझमला पाठिंबा दिला. पुढे ती आश्वासने फसवी ठरली, ही गोष्ट वेगळी. शिवाय देशामध्ये लोकशाही परंपरा नव्हती. राजा, सरदार, चर्च व वरिष्ठवर्ग यांचे लोकांच्या मनावर खूप दडपण होते. त्यांनी राज्य करावे व आपण आपली परंपरागत शेती करावी किंवा कारखान्यात अगर लहान-सहान उद्योगात काम करावे, अशी लोकांची भावना होती. प्रत्येक बाबतीत त्यांना कुणीतरी पुढारी हवा असे व त्या पुढाऱ्याच्या म्हणण्याप्रमाणे वागावे अशी त्यांची वृत्ती होती. त्यांना स्वास्थ्य व सुरक्षितता हवी होती. स्वातंत्र्याबद्दल त्यांचा विशेष आग्रह नव्हता. लोकांच्या या मनोवृत्तीचा मुसोलिनीने फायदा घेतला आणि त्यांना फॅसिझमच्या दावणीला जुंपले. आधुनिक जगात ही मनोवृत्ती अनेक समाजांत दृष्टीस पडते.उत्पादन यंत्रणा प्रचंड वाढलेली आहे, राज्यसत्ता खूप प्रबळ झालेली आहे व समाज फार विसकळीत झालेला आहे, त्यामुळे व्यक्तीला हतबल झाल्यासारखे वाटते. त्याला एकलेपणाची व स्वातंत्र्याची भीती वाटू लागेत. तो आधार शोधू लागतो. तो आधार त्याला पुष्कळ वेळा बलदंड पुढाऱ्यात आणि त्या पुढाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील एकतंत्र राज्यव्यवस्थेत आढळतो. अलीकडील समाजातील या समस्येचे एरिखफ्रॉम या सामाजिक तत्त्वज्ञाने आपल्या फीअरऑफफ्रीडम किंवा एस्केपफ्रॉमफ्रीडम या ग्रंथात अतिशय सुदंर विवेचन केले आहे. फॅसिझम इटलीपुरता मर्यादित राहिला नाही. इटलीमध्ये पाय रोवल्यानंतर तो जर्मनी, जपान, स्पेन, पोर्तुगाल, अर्जेंटिना आदी देशांत पसरला. जर्मनीमध्ये हिटलरच्या नेतृत्वाखालील नाझी पक्षाच्या रूपाने त्याने अत्यंत विकृत व भीषण स्वरूप धारण केले. प्रत्येक देशात फॅसिझमचे स्वरूप तेथील परिस्थित्यनुसार भिन्न होते. कारण त्याला सुस्पष्ट व सुसंगत असे तत्त्वज्ञान नव्हते. उदा., जर्मनीमध्ये वंश तत्त्वावर भर होता. हिटलरच्या राजकीय तत्त्वज्ञानात आर्यवंश हाच सर्व मानवी वंशांमध्ये जन्मत: श्रेष्ठ असून तोच मानवजातीवर राज्य करण्यास समर्थ आहे, असा मूलभूत सिद्धांत गृहीत धरला आहे. तसा सिद्धांत फॅसिझमने मान्य केला नव्हता; परंतु प्राचीन रोमन साम्राज्याप्रमाणे इटलीचे साम्राज्य निर्माण करण्याचे स्वप्न फॅसिझम पाहू लागला. फॅसिझमचे सुसंगत असे तत्त्वज्ञान नसले, तरी काही तत्त्वे आहेत.त्यांपैकी काही तत्त्वे जुन्या जगातील प्लेटो व आधुनिक युगातील हेगेल यांसारख्या विश्वविख्यात तत्त्वज्ञांच्या ग्रंथांतही आढळतात. याखेरीज मॅकिआव्हेली, हॉब्ज, नीत्शे, पारेतो यांसारख्या विचारवंतांच्या विचारांचाही फॅसिझमच्या विचारसरणीवर परिणाम झाला आहे. तरीदेखील सर्वात अधिक परिणाम झाला आहे, तो जॉर्ज सॉरेल यांच्या हिंसक क्रांतीवादाचा. जोव्हान्नी जेंतीले व आल्फ्रेदो रॉक्को हे तर फॅसिझमचे तत्त्वचिंतक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. मुसोलिनीने १९३३ साली इटालियन विश्वकोशात फॅसिझमवर जो लेख लिहिला, त्याचा पहिला मसुदा जेंतीलेने तयार करून दिला होता असे म्हणतात. म्हणून फॅसिझमची तत्त्वे व कार्यक्रम यांचा विचार करताना तो लेख व मुसोलिनीच्या कृती यांनाच अधिक महत्त्व देणे योग्य ठरेल. तत्त्वज्ञानापेक्षाही आम्ही कृतीलाच अधिक महत्त्व देतो, हा मुसोलिनीचा सिद्धांत या बाबतीत लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. समाजामध्ये राज्यसंस्था ही सर्वश्रेष्ठ संस्था व सर्वंकष राज्य आहे, असे फॅसिझम मानतो. समाज ही सावयव एकात्मक वस्तू असून व्यक्ती ह्या समाजाचे घटकांश आहेत. शरीराचे अवयव व पेशी हे जसे अंश होत, तसेच व्यक्ती हे अंश होत. अवयव वा पेशी जशा शरीराकरिता असतात, तशा व्यक्ती समाजाकरिता असतात. राष्ट्र वा राज्य हे समाजाचेच विकसित वा उन्नत रूप होय. म्हणून

राज्याचे आदेश सर्वांनी बिनतक्रार मानले पाहिजेत. राज्याचे हित ते सर्वांचे हित. व्यक्तीचा विकास राज्याच्या छायाछत्राखालीच होऊ शकतो. राज्याचे संरक्षण व संवर्धन सर्वांनी मिळून केले पाहिजे आणि त्यासाठी झीज सोसण्याची वा आत्मत्याग करण्याची प्रत्येकाची तयारी हवी. राज्य, राष्ट्र आणि समाज यांमध्ये भेद नाही.राष्ट्राचा नेता हाच राज्याचा आणि समाजाचा नेता असतो. त्याच्या हाती अनियंत्रित सत्ता हवी. राष्ट्राचे हित कशात आहे, हे तोच जाणतो. ते हित साधण्यासाठी सर्वांना त्यांच्या कुवतीनुसार कामाला लावणे, हा त्याचा अधिकार आहे. तो एक पक्ष निर्माण करतो. एक राष्ट्र, एक नेता व एक पक्ष अशी घोषणा केली जाते. राष्ट्र एकजीव असते. त्यामध्ये वर्गभेद माजवणे म्हणजे त्याची ताकत खच्ची करण्यासारखे आहे. कामगार, भांडवलदार, शेतकरी व जमीनदार यांनी एकजुटीने काम करून राष्ट्राची ताकत वाढवली पाहिजे. राष्ट्र हे वर्धिष्णू असले पाहिजे. त्याने आपले साम्राज्य निर्माण केले पाहिजे. त्यासाठी युद्ध करावे लागते. युद्धाची नेहमी तयारी हवी. युद्धामध्ये पाप नाही, त्यामुळे व्यक्तीचे शौर्य, धैर्य व त्यांच्या गुणांची कसोटी लागते. लोकशाही लोकांच्या हिताची नाही. तिने श्रीमंतांचे व धंदेवाईक राजकारण्याचे फावते व लोकांचे नुकसान होते. सर्वसामान्य लोकांना राष्ट्रहिताचे गहन प्रश्न समजत नाहीत, त्यांना त्यामध्ये रस नसतो, म्हणून ते प्रश्न जाणत्या लोकांनी हाताळणे हे उत्तम. या तत्त्वावरून फॅसिझमचा अभिजनवाद (इलिटिझम) उघड होतो; पण फॅसिस्टांना तो दोष आहे, असे वाटत नाही. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व व्यक्तीची समानता फॅसिझमला मान्य नाही. विषमता निसर्गदत्त आहे, ती नाहीशी होणार नाही. काही व्यक्तींमध्ये पुढारीपणाचे गुण असतात, त्यांच्या आज्ञेनुसार काम करणे हेच इतरजनांचे कर्तव्य; त्यातच त्यांचे स्वातंत्र्य आहे व जीवनाची परिपूर्तीही आहे. इतिहास आर्थिक कारणामुळे घडत नाही. तो घडतो तो पराक्रमी पुरुषांच्या पराक्रमामुळे. त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार पराक्रम गाजविण्याची संधी देणे यातच समाजाचे हित आहे. राष्ट्राच्या नेत्याला मदत करण्यासाठी व त्याचे कार्यक्रम अमलांत आणण्यासाठी संघटना हवी. ती संघटना म्हणजे फॅसिस्ट पक्ष. तो पक्ष शिस्तबद्ध व लढाऊ वृत्तीचा हवा व त्याचा नेत्यावर संपूर्ण विश्वास हवा. ही झाली फॅसिझमची वा नाझीझमची सर्वसाधारण तत्त्वे. त्याच्या तत्त्वज्ञानाचा म्हणजेच विश्वविषयक कल्पनांचा मुद्दामच उल्लेख केलेला नाही, कारण त्या फार गोंधळाच्या व परस्पर विसंगत आहेत. फॅसिझम जडवादी आहे की आदर्शवादी आहे, हे सांगणेही कठीण आहे.त्याच्या कृतीमध्ये खालच्या दर्जाचा जडवाद किंवा भौतिकवाद दृष्टीस पडतो. तर त्याच्या सर्वांत महत्त्वाच्या राज्य या संकल्पनेत आदर्शवाद दृष्टीस पडतो. फॅसिझमचा वा नाझीझमला हिंसेचे वावडे नाही, त्यांमध्ये उलट हिंसेचा पुरस्कारच आढळतो. तसेच नीती-अनितीचाही त्याला विधीनिषेध नाही. राष्ट्रीय उद्दिष्ट साधण्यासाठी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब केला तरी त्याला चालते. फॅसिझम शांततावादी नसून उलट तो युद्धवादी आहे, तसाच तो उग्र राष्ट्रवादी आहे. उग्र राष्ट्रवाद आणि युद्ध यांचे नेहमी साहचर्य असतेच. ऐतिहासिक दृष्ट्या फॅसिझम व त्याचे जुळे भावंड नाझीझम जन्माला आले, ते पहिल्या महायुद्धाच्या अंतानंतर. व्हर्सायच्या तहामुळे जी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण झाली, तिचा उच्छेद करण्याच्या हेतूने युद्धात जर्मनीचा पराभव झाला होता. त्यामुळे त्याला आपल्या वसाहतींना मुकावे लागले व अॅल्सेस-लॉरेन यांसारख्या काही

भागानाही मुकावे लागले. इटलीचा पराभव झाला नव्हता, पण युद्धानंतर आपले साम्राज्य वाढविण्यासाठी दक्षिण यूरोपमध्ये व उत्तर आफ्रिकेमध्ये आपल्याला काही मुलूख मिळेल, अशी त्याची अपेक्षा होती. ती पूर्ण झाली नव्हती. म्हणून इटलीही असंतुष्ट होता. आपल्यावर अन्याय झाला आहे अशी दोन्ही देशांची भावना होती. अन्याय दूर करून घेण्यासाठी त्यांना युद्ध हवे होते. म्हणून त्यांनी उग्र राष्ट्रवादाला व युद्धखोर प्रवृतींना उत्तेजन दिले. फॅसिस्ट व नाझी पक्षांचा तर तोच कार्यक्रम होता. त्यामुळे त्यांना राजाश्रय मिळाला व दोन्ही पक्षांची ताकत व महत्त्व एकदम खूप वाढले. याचवेळी दुसरीही एक घटना घडत होती. ती म्हणजे पगारकाट, कामवाढ, नोकरकपात इ. स्वरूपाचा भांडवलशाहीचा कामगारांवरील हल्ला, युद्धानंतरच्या आर्थिक परिस्थितीत कामगारांना नवीन सवलती देणे, तर भांडवलशाहांना शक्य नव्हते; पण जुन्या सवलती चालू ठेवणेही अशक्य झाले होते. कारण भांडवलशाहीची वाढ थांबली होती. त्यामुळे अटळ असे तीव्र वर्गयुद्ध सुरू झाले होते. कामगार संप, निदर्शने वगैरे तर करतच होते; पण त्यांनी राजकीय लढाही सुरू केला होता. रशियात तो लढा यशस्वीही झाला होता व तिथे कामगारांचे राज्य स्थापन झाले होते. इतर देशांतील भांडवलदारांना तीच धास्ती वाटत होती. अशा वेळी त्यांना आधार दिला तो फॅसिस्ट विचारसरणीने व फॅसिस्ट पक्षाने. साम्यवादी व समाजवादी विचारांना उत्तर देणारे विचार त्यांना फॅसिझममध्ये आढळले आणि कामगारांच्या चळवळी व संघटना दडपून टाकणारी यंत्रणा त्यांना फॅसिस्ट पक्षाने पुरवली. म्हणून भांडवलशाही व फॅसिझम यांच्यामध्ये निकटचे नाते निर्माण झाले. मार्क्सवाद्यांचा फॅसिझमबद्दलचा सिद्धांत या अनुभवावरून तयार झाला. त्यांचा सिद्धांत असा की, भांडवलशाहीला उतरती कळा लागते, त्या वेळी ती फॅसिझमला जन्म देते. चढत्या काळात तिला लोकशाही, कामगारसंघ, कामगारांचे संप वगैरे परवडत होते. पण उतरती कळा लागल्यानंतर त्या गोष्टी परवडणार नाहीत, असे दृष्टीस पडल्यामुळे त्यांच्या विनाशासाठी भांडवलशाहीने फॅसिझम निर्माण केला. या उपपत्तीतील दोष असा की फॅसिझमला भांडवलशाहीची खूप मदत झाली असली, तरी तिने तो निर्माण केला असे म्हणणे कठीण आहे. तो अगोदरच अस्तित्वात आलेला होता, त्याची उपयुक्तता ओळखून भांडवलशाहीने नंतर त्याला जोपासले. तसेच राजकीय सत्ता हस्तगत केल्यानंतर त्यानेही भांडवलशाहीला वेठीस धरले, ही गोष्टदेखील विसरता कामा नये. शिवाय फॅसिझमला मध्यम वर्गाचा जो पाठिंबा लाभला, त्याचेही स्पष्टीकरण या उपपत्तीमुळे होत नाही. केवळ भांडवलदारांचा पक्ष एवढेच त्याचे स्वरूप असते, तर मध्यम वर्गाने फॅसिझमला पाठिंबा दिला नसता; पण त्याचा उग्र राष्ट्रवाद व मध्यम वर्गाला वेगळे व स्वतंत्र स्थान देण्याची घोषणा यांनी मध्यम वर्गीयांच्या मनाला भुरळ पडली आणि त्यांनी फॅसिझमच्या जुलूमजबरदस्तीकडे दुर्लक्ष केले. त्याचे प्रायश्चित्त त्यांना अर्थातच नंतर भोगावे लागले. फॅसिझम प्रत्यक्षात समाजवाद व साम्यवाद यांचा शत्रू म्हणून वाढला, या गोष्टीमुळे मात्र त्या उपपत्तीला पाठिंबा मिळतो. सत्तासंपादनानंतरची पहिली तीन-चार वर्षे मुसोलिनीला सत्ता सुसंघटित व स्थिर बनविण्यात घालवावी लागली. या काळात त्याने सर्व विरोधी पक्ष व विरोधी संस्था नष्ट केल्या आणि देशातील कायदेमंडळ, नोकरशाही, लष्कर, वर्तमानपत्रे, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्था यांवर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित केले. म्हणजेच देशामध्ये एक नेता, एक पक्ष व एक आवाज असला पाहिजे, हा जो फॅसिझमचा कार्यक्रम, तो त्याने अंमलात आणला. तो अंमलात आणताना

त्याने खूप दडपशाही केली. विरोधकांवर अत्याचार केले व सर्व लोकशाही हक्क पायदळी तुडविले, पण देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली होती. ती त्याने पुनर्प्रस्थापित केली. त्याचेच पुष्कळांना कौतुक झाले. मुसोलिनीच्या राज्यात गाड्या वेळेवर सुटतात म्हणून अनेकांनी त्याची स्तुती केली, पण त्यासाठी केवढी किंमत मोजावी लागली व पुढे मोजावी लागणार आहे, याचा विसर पडला. त्यानंतर मुसोलिनीचे साम्राज्ययुग सुरू झाले आणि तेदेखील फॅसिझमच्या कार्यक्रमानुसार. साम्राज्यवाद फॅसिझमचा अविभाज्य भाग आहे. उग्र राष्ट्रवादाची परिणती नेहमी साम्राज्यवादातच होते. फॅसिझमपुढे उद्दिष्ट होते, ते जुन्या रोमन साम्राज्याचे. त्या काळात इटलीला जी प्रतिष्ठा होती, ती पुन्हा परत मिळवण्याची स्वप्ने फॅसिस्टांना पडत होती. त्यासाठी युद्धे करावी लागतील, हे त्यांना माहीत होते. म्हणून त्यांनी लष्कर सुसज्ज करण्याकडे लक्ष दिले.फॅसिझमचा वा नाझीझमला हिंसेचे वावडे नाही, त्यांमध्ये उलट हिंसेचा पुरस्कारच आढळतो. तसेच नीती-अनितीचाही त्याला विधीनिषेध नाही. राष्ट्रीय उद्दिष्ट साधण्यासाठी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब केला तरी त्याला चालते. फॅसिझम शांततावादी नसून उलट तो युद्धवादी आहे, तसाच तो उग्र राष्ट्रवादी आहे. उग्र राष्ट्रवाद आणि युद्ध यांचे नेहमी साहचर्य असतेच. ऐतिहासिक दृष्ट्या फॅसिझम व त्याचे जुळे भावंड नाझीझम जन्माला आले, ते पहिल्या महायुद्धाच्या अंतानंतर. व्हर्सायच्या तहामुळे जी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण झाली, तिचा उच्छेद करण्याच्या हेतूने युद्धात जर्मनीचा पराभव झाला होता. त्यामुळे त्याला आपल्या वसाहतींना मुकावे लागले व अॅल्सेस-लॉरेन यांसारख्या काही भागानाही मुकावे लागले. इटलीचा पराभव झाला नव्हता, पण युद्धानंतर आपले साम्राज्य वाढविण्यासाठी दक्षिण यूरोपमध्ये व उत्तर आफ्रिकेमध्ये आपल्याला काही मुलूख मिळेल, अशी त्याची अपेक्षा होती. ती पूर्ण झाली नव्हती. म्हणून इटलीही असंतुष्ट होता. आपल्यावर अन्याय झाला आहे अशी दोन्ही देशांची भावना होती. अन्याय दूर करून घेण्यासाठी त्यांना युद्ध हवे होते. म्हणून त्यांनी उग्र राष्ट्रवादाला व युद्धखोर प्रवृतींना उत्तेजन दिले. फॅसिस्ट व नाझी पक्षांचा तर तोच कार्यक्रम होता. त्यामुळे त्यांना राजाश्रय मिळाला व दोन्ही पक्षांची ताकत व महत्त्व एकदम खूप वाढले. याचवेळी दुसरीही एक घटना घडत होती. ती म्हणजे पगारकाट, कामवाढ, नोकरकपात इ. स्वरूपाचा भांडवलशाहीचा कामगारांवरील हल्ला, युद्धानंतरच्या आर्थिक परिस्थितीत कामगारांना नवीन सवलती देणे, तर भांडवलशहांना शक्य नव्हते; पण जुन्या सवलती चालू ठेवणेही अशक्य झाले होते. कारण भांडवलशाहीची वाढ थांबली होती. त्यामुळे अटळ असे तीव्र वर्गयुद्ध सुरू झाले होते. कामगार संप, निदर्शने वगैरे तर करतच होते; पण त्यांनी राजकीय लढाही सुरू केला होता. रशियात तो लढा यशस्वीही झाला होता व तिथे कामगारांचे राज्य स्थापन झाले होते. इतर देशांतील भांडवलदारांना तीच धास्ती वाटत होती. अशा वेळी त्यांना आधार दिला तो फॅसिस्ट विचारसरणीने व फॅसिस्ट पक्षाने. साम्यवादी व समाजवादी विचारांना उत्तर देणारे विचार त्यांना फॅसिझममध्ये आढळले आणि कामगारांच्या चळवळी व संघटना दडपून टाकणारी यंत्रणा त्यांना फॅसिस्ट पक्षाने पुरवली. म्हणून भांडवलशाही व फॅसिझम यांच्यामध्ये निकटचे नाते निर्माण झाले. मार्क्सवाद्यांचा फॅसिझमबद्दलचा सिद्धांत या अनुभवावरून तयार झाला. त्यांचा सिद्धांत असा की, भांडवलशाहीला उतरती कळा लागते, त्या वेळी

ती फॅसिझमला जन्म देते. चढत्या काळात तिला लोकशाही, कामगारसंघ, कामगारांचे संप वगैरे परवडत होते. पण उतरती कळा लागल्यानंतर त्या गोष्टी परवडणार नाहीत, असे दृष्टीस पडल्यामुळे त्यांच्या विनाशासाठी भांडवलशाहीने फॅसिझम निर्माण केला. या उपपत्तीतील दोष असा की फॅसिझमला भांडवलशाहीची खूप मदत झाली असली, तरी तिने तो निर्माण केला असे म्हणणे कठीण आहे. तो अगोदरच अस्तित्वात आलेला होता, त्याची उपयुक्तता ओळखून भांडवलशाहीने नंतर त्याला जोपासले. तसेच राजकीय सत्ता हस्तगत केल्यानंतर त्यानेही भांडवलशाहीला वेठीस धरले, ही गोष्टदेखील विसरता कामा नये. शिवाय फॅसिझमला मध्यम वर्गाचा जो पाठिंबा लाभला, त्याचेही स्पष्टीकरण या उपपत्तीमुळे होत नाही. केवळ भांडवलदारांचा पक्ष एवढेच त्याचे स्वरूप असते, तर मध्यम वर्गाने फॅसिझमला पाठिंबा दिला नसता; पण त्याचा उग्र राष्ट्रवाद व मध्यम वर्गाला वेगळे व स्वतंत्र स्थान देण्याची घोषणा यांनी मध्यम वर्गीयांच्या मनाला भुरळ पडली आणि त्यांनी फॅसिझमच्या जुलूमजबरदस्तीकडे दुर्लक्ष केले. त्याचे प्रायश्चित्त त्यांना अर्थातच नंतर भोगावे लागले.

सारांश

फॅसिझम प्रत्यक्षात समाजवाद व साम्यवाद यांचा शत्रू म्हणून वाढला, या गोष्टीमुळे मात्र त्या उपपत्तीला पाठिंबा मिळतो. सत्तासंपादनानंतरची पहिली तीन-चार वर्षे मुसोलिनीला सत्ता सुसंघटित व स्थिर बनविण्यात घालवावी लागली. या काळात त्याने सर्व विरोधी पक्ष व विरोधी संस्था नष्ट केल्या आणि देशातील कायदेमंडळ, नोकरशाही, लष्कर, वर्तमानपत्रे, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्था यांवर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित केले. म्हणजेच देशामध्ये एक नेता, एक पक्ष व एक आवाज असला पाहिजे, हा जो फॅसिझमचा कार्यक्रम, तो त्याने अंमलात आणला. तो अंमलात आणताना त्याने खूप दडपशाही केली. विरोधकांवर अत्याचार केले व सर्व लोकशाही हक्क पायदळी तुडविले, पण देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली होती. ती त्याने पुनर्प्रस्थापित केली. त्याचेच पुष्कळांना कौतुक झाले. मुसोलिनीच्या राज्यात गाड्या वेळेवर सुटतात म्हणून अनेकांनी त्याची स्तुती केली, पण त्यासाठी केवढी किंमत मोजावी लागली व पुढे मोजावी लागणार आहे, याचा विसर पडला. त्यानंतर मुसोलिनीचे साम्राज्ययुग सुरू झाले आणि तेदेखील फॅसिझमच्या कार्यक्रमानुसार. साम्राज्यवाद फॅसिझमचा अविभाज्य भाग आहे. उग्र राष्ट्रवादाची परिणती नेहमी साम्राज्यवादातच होते. फॅसिझमपुढे उद्दिष्ट होते, ते जुन्या रोमन साम्राज्याचे. त्या काळात इटलीला जी प्रतिष्ठा होती, ती पुन्हा परत मिळवण्याची स्वप्ने फॅसिस्टांना पडत होती. त्यासाठी युद्धे करावी लागतील, हे त्यांना माहीत होते. म्हणून त्यांनी लष्कर सुसज्ज करण्याकडे लक्ष दिले.

संदर्भ :

1. Ebenstein, William, Today's Isms, Englewood Cliffs (N.J.), 1973.
2. Radel, J. L. The Roots of Totalitarianism, New York, 1975. 3. Woolf, S. J. Ed. The Nature of Fascism, London, 1968.

प्रा. सुहास रामचंद्र नलावडे

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

जगतिकीकरणाचा अरुण काळे आणि अजिम नवाज राही यांच्या कवितेवर प्रभाव

डॉ. बालाजी विठ्ठलराव डिगोळे
मराठी विभाग प्रमुख शिवजागृती महाविद्यालय नळेगाव
ईमेल- bdigole007@gmail.com

१९९० नंतरच्या कालखंडामध्ये जागतिक पातळीवर जागतिकीकरणाची लाट तीव्रपणे सुरू झाली. याचे परिणाम भारतावरही झाले. खेड्या-पाड्यापर्यंत नव्या तंत्रज्ञानाने आणि विज्ञानाने आपले हात पसरले. खेडी आणि शहर हा भेद उरला नाही. शहरातील सर्व भौतिक सोई सुविधांचे लोन ग्रामीण भागापर्यंत पसरले. दळणवळणाच्या साधनामुळे अलीकडच्या काळात खेड्याकडून शहरात लोंढे आले. जगतिकीकरणाचे वारे वाईट परिणाम तीव्रतेने जाणवू लागले. विशेषत: ग्रामीण भागात याचा परिणाम झाला. श्रीमंत आणि गरिब अशा दोन न मिटणाऱ्या अभेद्य भिंती निर्माण झाल्या. इथली समाजव्यवस्था संस्कृतीसुद्धा जागतिकीकरणाच्या विळख्यात सापडली. जागतिकीकरणाच्या परिणामामुळे शहरात अनेक सुखसोयी आल्या. त्याचबरोबर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. भोगवाद, चंगळवाद वाढला. आता महानगरे अनेक प्रश्नाच्या चक्रव्युहात सापडली. जातीय, धार्मिक आणि वांशिक अधिसत्ता प्रबळ करीत जाणाऱ्या आजच्या एकविसाव्या शतकात जागतिकीकरण, खाजगीकरण, आर्थिक उदारीकरण या प्रक्रियेने माणसाला सर्वच पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेतून नामशेष केले जात आहे. माणसाच्या जगण्यामरण्याचे अधिकार आता ग्लोबल व्यवस्थेने आपल्या हातात घेतले आहेत. माणसाने अथक परिश्रमातून निर्माण केलेल्या अनेक विध मौलिक गोष्टीचे पेटंट म्हणजे आपलीच जहागीरी असे महासत्तेला वाटत आहे. हे जागतिकीकरण दलित पीडितांच्या बाजूचे नाही तर जागतिकीकरणाच्या कराल रूपातून एक नवी शोषक व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. या व्यवस्थेचे ताणे-बाणे, शोषणाच्या तऱ्हा, वर्चस्वाचे रूप विद्रूप जेवढ्या बारकाईने आणि अभ्यासपूर्ण रीतीने मराठी कवितेने समजून घेतले आहे. या जागतिकीकरणाने माहिती तंत्रज्ञान दिले; पण ज्ञान दिले नाही. माणसाची अनेकविध रूपे दाखविली; पण त्याचे अंतरंग, भावभावना, नातीगोती, त्याचे जगणे-मरणे, त्यांचा संघर्ष, त्यांची गोची नाही दाखवली, त्याबद्दल हे जागतिकीकरणाचे युग एक ब्र शब्दही बोलत नाही. या युगाच्या व्यापारी दृष्टीने केवळ लुटालूट इलाज प्राधान्यक्रम दिला आहे. जागतिकीकरणामुळे भौतिक विकास आणि वैभवाबरोबरच बकालपणा, भेसळ, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, मूल्य ऱ्हास, असुरक्षितता, दंगली, बॉम्बस्फोट, गोळीबार, मोर्चे, बंद इत्यादीमुळे माणूस भोगवादी, स्वार्थी, मतलबी बनल्यामुळे त्याचा कोंडमारा झाला. मानवी जीवनात माणसापेक्षा वस्तूला महत्त्व आले टी.व्ही., मोबाईल, कम्प्युटर, लॅपटॉप, व्हाट्सअप, कॅफे, फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, लॉकडाऊन, कॅप्सूल, टॅबलेट, ऑक्सीजन, मास्क, कोविशील्ड, कोवक्सीन, रेमिडिसीवीर, प्लाजमा अशा साधनांच्या आहारी आजचा माणूस गेला. याचा परिणाम होऊन माणूस एकलकोंडा बनला त्यामुळे चिडचिड, टेंशन उदासीनता त्याच्या वाट्याला आली आहे. हे सर्व जागतिकीकरणाच्या अतिरेकामुळे होत आहे. माणसामाणसातील वाढलेले अंतर, तुटत जाणारे नातेसंबंध, भावनाहीनता, स्वकेंद्रितपणा, जीवनाबद्दलची उदासीनता, जागतिकीकरणामुळे भाषा, संस्कृतीसकट मानवी जीवनात झालेली जटिलता, गुंतागुंत आणि अशा सगळया गुंतागुंतीतून आकाराला आलेले अनपेक्षित वास्तव डोळयांसमोर तरंगत आहे. अशा या गुंतागुंतीच्या भयावह जागतिकीकरणाचे चित्रण करणाऱ्या कवितांचा शोध घ्यावयाचा आहे. सायबर युगाने माणसाची कोंडी फोडली. नवे युग अवतरले म्हणून विषमता कमी झालेली नाही. उलट या मागील दोन दशकात जात, गरिबी, श्रीमंती ही समस्या अधिकच ते टेकूळीप्रमाणे वर आली. जेवढे जास्त उच्चशिक्षित तेवढे जातीयवादी, कारण प्रत्येक जातीनुसार मोर्चे, आंदोलने, संघटना, कंपन्या निघाल्या आहेत. मॉल्सपासून पानठेल्यापर्यंत आणि स्पेसशटलपासून

सायकलरिक्षापर्यंतचे हेलपाटे ही विषमता कायमच झाडांचे सोटमूळ जमिनीत खोलवर रुजल्याप्रमाणे रुजलेली आहे. नव्या रूपात कामगार-भांडवलदार, आहेरे, नाहीरे ही दरी वटवृक्षाप्रमाणे रुंदावत गेली आहे. निसर्गाने दिलेले शाश्वत मूल्यांचे अमूल्य जीवन, परंतु मानवी स्वार्थाने हजारो वर्षांपासून जोपासलेली शोषण व्यवस्था यांच्यामध्ये होरपळून निघालेल्या मानवी मूल्यांचे आत्मभान जोपासणारी वृत्ती घेऊन समकालीन कवीतेत जे काही प्रयोग होत आहेत. त्यामध्ये अरुण काळे, मंगेश नारायण काळे, उत्तम कांबळे, श्रीधर तिळवे, हेमंत दिवटे, मन्या जोशी, महेंद्र भवरे, सलील वाघ, संजीव खांडेकर, श्रीधर तीळवे, सचिन केतकर, मल्हार जोशी, वीरधवल परब, प्रज्ञा लोखंडे, मल्लिका अमर शेख, यशवंत मनोहर, अजीम नवाज राही, प्रवीण बांदेकर, सतीश काळसेकर, वजेश सोलंकी, अविनाश पाटील, राजकुमार मस्के, बालाजी इंगळे इत्यादी कवींच्या कवितातून जागतिकीकरणातील जीवन वास्तव शब्दरूप घेत आहेत. त्याचा शोध या शोधनिबंधात शोधनिबंधकाने घेण्याचे ठरवले आहे. कवी अरुण काळे हे मराठी साहित्यातील एक महत्त्वाचे कवी होते मॅकगार्डन, सायरणचे शहर, नंतर आलेले लोक आणि ग्लोबल गावकूस या चार काव्य काव्यसंग्रहाच्या शीर्षकावरून आपण नजर फिरविली तर अरुण काळे यांच्या कवितेवर जागतिकीकरणाचा प्रभाव जाणवतो. विशेषता नव्वदोत्तर काळात जागतिक पातळीवर खूप मोठी उलथापालथ होऊन बदल होत गेले. त्याचा विशेष प्रभाव हा भारतीय मानसिकतेवरही पडला. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे समाजमन ढवळून निघाले. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या नव्या संस्कृतीच्या उदयामुळे चंगळवाद, भोगवाद, सत्तालोलुपता उत्तरोत्तर आधुनिकता भौतिकवाद बोकाळला. शहरी संस्कृतीचे जुने सोज्वळ रूप कालबाह्य झाले आणि नवे बकाल आणि विध्वंसक रूप तयार झाले. श्रमसंस्कृती या संस्कृतीने छळले मानवी अस्तित्वाला मल्टिनॅशनल आणि मॉल संस्कृतीचे यंत्र, मशिनी संस्कृतीचे ग्रहण लागले. पर्यायाने इथल्या मूळ माणसांना गावंढळ, निरक्षर ठरवून भांडवलदारांनी आपली मूळं मातीत पसरून अलंकृत केली. छोटे कुटिरोद्योग, हस्तव्यवसाय अठरा अलुतेदार, बाराबलुतेदार नष्ट केले, तर औद्योगीकरण, शिक्षण, अर्थकारण तसेच समाजकारण आणि राजकारणात भांडवलीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलायझेशन या नव्या व्यवस्थेने आपला पाया अत्यंत मजबूत करून घेतला. नंतर आलेले लोक हे विशेषण या कवितेचा अर्थ उलगडून दाखवू शकते. जागतिकीकरणामुळे नवी वसाहतवादी प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे. कवी अरुण काळे लिहितात “बजा ऽ ऽ ऽ व नाचो ऽ ऽ ऽ झिंग लपालपालपा झिंग लपालपा खुल्क है खुदा का आणि मुल्क जनताका हुकुम कंपनीका नाचो झिंग लपालपा घुंब नकघुंब, झिंग झिंग लपालपा श्वापदाणे मारली शिकार तोंड खुपसून दिली डकार टुक टुह पाहणाऱ्यांनो कोल्हे लांडगे, गिधाडांनो तुटून पडा लुटालुटा, दात विचका पुढे घुसा हाव आहेत, ताव मारा पोटं तुडुंब भरली आता जणाऱ्याची जान गेली. खेद नको खंत नको, तो नालायक गेला म्हणा, नाचा आनंद करा खुल्क है खुदाका आणि मुल्क जनताका हुकूम कंपनीका, नाचो झिंग झिंग लपालपा. जागतिकीकरणानं वसाहतवादी संस्कृतीने इथल्या देशी व्यवस्थेला अगदी ओरबाडून खाल्ले आहे. सांस्कृतीक क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रात खाऊजा, पोटोबा, भडोबा संस्कृतीने आजगराप्रमाणे विळखा घातला आहे. वसाहतवादी मनोवृत्तीमुळे अनेक गोरगरीब, शेतकरी, मजूरदारांचा बळी गेला. मूल्यभान आणि मानवी तत्त्वांचा या नव्या युगात चेंदामेंदा झाला आहे. केवळ आता दुसऱ्याच्या तालावर आपण नृत्याचा ठेका धरायचा. स्वतःचे अस्तित्व धुळीला मिळून भ्रष्ट राजकारणी, पुढारी, भांडवलदार यांची चांदी झाली. गोर-गरिबांच्या टाळूवरील लोणी खायची सवय लागली. गोरगरीबांचे शोषण म्हणजे कणगीतील ज्वारी वाटू लागली. हवे तेव्हा कणगीत टोपली खुपसून खाता येईल अशी मालमत्ता वाटू लागली आहे. यांना आपण आता शरण यावे असे वाटत आहे. पण लांडगे अस्वल ज्याप्रमाणे दुबळ्या प्राण्यांची शिकार करतात. हिंस्त्र श्वापदांच्या तोंडाला रक्त लागले की, ते सोडत नाहीत. त्याप्रमाणे या जागतिकीकरणातील संस्कृतीने माणसाच्या जगण्याच्या चाव्या आपल्या कमरेला ठेवून शिकार करत आहेत. आपल्यातल्याच माणसावर या नराधम व्यवस्थेने गतीने

झडप मारली आहे. त्याचे दुःख करायचे नाही. उलट आनंदाने नाचायचे, अवघड जागचा घाव दाखवायचंबी नाही आणि झाकायचाबी नाही असे कवी अरुण काळे यांनी उपरोधाने म्हंटले आहे. कंपनीचा वटहुकूम आहे मग काय नाचू लपालपा गोरे गेले पण आता नवे आतून व बाहेरून काळे शोषक आले आहेत. त्यांनी सर्वसामान्यांना नागडे करून फास टाकून शिकार केली आहे. माणसामाणसात तीव्र स्पर्धा, बाजारीकरण, यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक युगाचे भूत माणसांच्या उरावर बसले आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे माणसाची ससेहोलपट झाली आहे. गवा ताकदवान होता, समुहाच्या बाहेर होता कुत्र्यांनी कॉर्नर केला, भुंकून, भुंकून भांडायला टेकडावर नेला. युक्तीने खाली पाडला पडला आणि तुटून गेला. शक्तीसह मरून गेला दुसरा एक घावला त्याला आधी हवेत नेला हळूच झाडावर चढवला, तो जरा नादावला खाक करताच दचकला धापकन आवाज आला, शिकारी वर्ग तुटून पडला, पूर्ण फडशा पाडला गेला. कवी अरुण काळे यांनी प्रतिकात्मक भाषेत धलप्या तासाव्यात त्याप्रमाणे शोषणाची नवी ढब चव्हाट्यावर मांडली आहे. जागतिकीकरण आणि भांडवलशाहीने कसे खापऱ्या गेचडाप्रमाणे गोरगरिबांचे रक्तच पिले आहे. कंपनी म्हणजे गुलामी आपण आता एका जागतिकीकरणाच्या गोड बंगाल गुलामीत अडकलो आहोत. आपण कितीही बलवान असलो तरी त्यांच्या सत्तेपुढे, पैशापुढे आपले काही चालत नाही. सत्तेपुढे पैशापुढे गाढवही शहाणा म्हटले जाते. बलदंड गव्याला कुत्र्यांनी ठार करावे आणि त्याचा चावा घ्यावा असेच सर्वसामान्यांच्या बाबतीत घडत आहे. तत्त्व, निष्ठा फिशचा काटा घशात अडकून घरघर लागल्यामुळे गोरगरीब हतबल झाले आहेत. त्यांनी वाटा अडवल्या, पाणवठे अडवले, दुबळयांची कोंडी झाली समूह अस्ताव्यस्त झाले किंवा त्यांचे वाढदिवस आले, शुभेच्छांचे पीक आले चंगळचंगळ चंगळचंगळचंगळ झाली, चंगळीच्या झाल्या कविता चंगळीची झाली गाणी. परिणाम स्वरूप खुली अर्थव्यवस्था आणि तिचे भांडवलशाही वृत्तीचे अराजक माजले. यामुळे माणूस पण धोक्यात आलेले आहे. अशा वेळी मानवी तत्वांची, मूल्यांची राखरांगोळी कशी होते त्याची मिमांसा अरुण काळे करतात. शोषण, अन्याय, अत्याचाराचे मार्ग कुठून वाहतात. याची वास्तव जाणीव येते. अर्थयुद्ध या कवितेतूनही जागतिकीकरणावर आसूड ओढून दलित समाजातील अन्याय, अत्याचार, अगतिकता मांडलेली आहे. जागतिकीकरणाचे हे गोंडस सशासारखे नाव धारण करून नव्या भांडवलदाराचे अर्थकरण्यासाठी चाललेले अर्थयुद्ध कसे सुरु आहे त्यामध्ये सर्वसामान्य शेतकरी, मजूरदार माणसांना परत एकदा वामनावतार धारण करून त्यांच्या घरावरून नांगर फिरवून देशोधडीला लावले आहे. याचे वास्तव चित्र अरुण काळे यांनी अर्थयुद्ध या कवितेतून रेखाटले आहे. हे युद्ध सर्व जाती धर्माच्या लोकांसाठी खुले आहे. हे युद्ध उतरले आहे रणभूमी वरून रस्त्यात या शतकात सहस्त्रकात. जागतिकीकरण ही सीमापार उत्पादने, भांडवलसेवा आणि आर्थिक क्रियाप्रक्रियेच्या जंजाळात अडकून कात धारण करणारी आहे. म्हणजे खुली अर्थव्यवस्था, खुल्या बाजारपेठा म्हणजे कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे अशी व्यवस्था यालाच जागतिकीकरण असे बाळसेदार नाव दिले आहे. अरुण काळे यांचा जागतिकीकरणाला प्रखर असा विरोध आहे. ही जागतिकीकरणाची व्यवस्था सर्व जाती धर्माच्या लोकांसाठी खुली आहे. आता हे अर्थयुद्ध रंगभूमीवरून गोरगरिबांच्या अंगणात उतरले आहे. शतकातून सहस्त्रकात या जागतिकीकरणातील अर्थ युद्धाची गणना केली जात आहे. हे रेडियल टायर्सवर बसून येणारे कोट वाले सैनिक हे टायर फाटलेले फूटपाथी पायदळ हे बाटलीक पेयांचे शीतयुद्ध हे घट्टे पडलेले कटिबंध उष्ण पाण्याचे प्लास्ट टिनपाट वाहून साहून. सामान्य माणसाचे शोषण हाच जागतिकीकरणाचा मुख्य गाभा आहे. त्याचे भांडवलदाराकडून शोषण हे कोटवाले रंगीत चष्मा अडकवून हे लोक रेडियल हवाई टायर्सच्या गाडीत एसीत बसून येतात आणि फुटपाथवर जीवन जगणाऱ्या सामान्य लोकांचे शोषण करतात. बाटलीत जोपर्यंत शीतपेये असते तोपर्यंतच बाटलीच्या झाकणाला किंमत असते. पाण्याची प्लास्टिक बाटली हे गोरगरीबासारखं नष्ट न होणारी प्रतिमा आहे. छकड्याच्या बैलाप्रमाणे मानेला घट्टे पडलेले कटिबद्ध उष्ण गरीब भुकेल्या लोकांची प्रतिमा म्हणून वारली आहे. हे महोत्सव कॉन्टिनेन्टल फूडसचे हे लोक राशन मांगे मोअर ही यांची विविधरंगी राशनकार्ड बुलेटसच्या पुढे धावतात. या नाजूककारी हे कंडोमला लावलेले लुब्रिकटस. महानगरीय संस्कृतीत लोकसंख्या भस्मासुरासारखी वाढून विस्फोट झाला. त्यामुळे माणुसकी संपुष्टात आली. श्रीमंत आणि गरीब,

भांडवलदार आणि कामगार, मालक आणि नोकर यांच्यातील दरी वाढत आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात पैसा हेच माणसाच्या जीवनाचे मूल्य बनले. शहरांमध्ये अनेक महोत्सव कॉन्टिनेन्टल फूडसचे साजरे होतात. पण सामान्य जनता दारिद्र्यरेषेखाली खितपत पडली आहे. सामान्य माणसांना मिठात शिजवलेल्या घुगऱ्या मिळत नाहीत तर भांडवलदार तुपात तळलेली हंडी, चिकन, सिक्सटी फाईव्ह त्यांच्यावर ताव मारत आहेत. सामान्य माणूस जागतिकीकरणात भिकेला लागला आहे. लाल, पांढरी, केशरी विविध रंगाची राशन कार्ड हे त्याचे प्रतीक पुढे आले आहे. भांडवलदारांच्या गाड्या एखाद्या बंदुकीतील बुलेट्स पुढे धावतील अशी व्यवस्था भांडवलदारांची आहे. शोषणकर्त्याची फक्त नावे बदललेली आहेत. पूर्वी सरंजामदार शोषण करत होते. आता भांडवलदार शोषण करत आहेत. जणू काही ती कंडोमला लुब्रिकँटस केबलच्या छत्र्या, लिंगाचा पेपरवेट, डोअरबेल सारख्या दिसत आहेत. हे दहा रुपये लिटरचे पांढरे रॉकेल जाळते दिव्याला, बाईला, तत्वाला, तत्ववेत्याला, स्कूटर आणि रिक्षाचा इंजिनला हे सायबर/हार्डवेयर, सॉफ्टवेअर. जागतिकीकरणातील नव्या युगातील नव्या भांडवलदारांचे अर्थयुद्ध सामान्य जनतेला खडे फोडायला लावत आहे. दहा रुपयाच्या रॉकेलला आज बाजारात खूप किंमत आहे. ते रॉकेल आज गरिबाला चिमणीला, बाईला, स्कूटर, रिक्षाला आणि तत्वाला तत्ववेत्यांच्या विचाराला जाळून राख करणारे आहे. हे कामगारांचे हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर म्हणजे त्यांचे काम करण्याचे टिकाव, कुदळ-फावडे घूसा यापासून शहरातील अनेक उड्डाण पुलापासून हजारो योजनेमध्ये ते समूहाने वापरलेली आहेत. पण जागतिकीकरणात पारंपरिक साधनांचा, व्यवसायांचा नायनाट होऊन त्यांची जागा यंत्राने घेतली आहे. पारंपारिक उद्योगधंदे बंद पडल्याने त्या लोकांची उपासमारी, कर्जबाजारी, गुलामी वृत्ती बनल्यामुळे आत्महत्या करताहेत. पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना जागतिकीकरणात डिलीट करण्याचे षड्यंत्र आखण्यात आले आहे. बगले बगलेतून वाहणारे डिओड्रटचे वारे अन् हे नाकात गेलेली किडे डब्ल्यू डब्ल्यू एफच्या मिलापी कुस्त्या वियाग्राच्या पुलावरून उड्या मारणारे दमलेले घोडे. माणूस स्वतःचा स्वार्थ साधण्यापलीकडे दुसऱ्याचा विचार करायचा विसरून गेला आहे. धर्म, जात, पंथ, देव यांच्या भिंती जागतिकीकरणाने मजबूत केले आहेत. सामान्य माणसाच्या जीवन जगण्याला दमछाक करून भयावहता, क्रूरता, विद्रुपता वर वाढीस लागली आहे. डब्ल्यू डब्ल्यूएफ च्या मीलापी कुस्त्यांची ही स्पर्धा सर्वसामान्य लोकांच्या जीवावर नरडं दाबून घोट घ्यायला निघाली आहे. या जागतिकीकरणातील अर्थयुद्धामुळे शेतमजूर, शेतकरी, गोरगरीब लोक काँक्रीटच्या पुलावरून उड्या मारून जीव दमून आता दमलेले आहेत. त्यांचे भांडवलदाराकडून सतत शोषण करणे चालूच आहे. सत्याची जागा असत्याने, नैतिकतेची जागा अनैतिकतेने, सृष्टाची जागा दुष्टाने, सत्प्रवृत्तीची जागा दुष्ट प्रवृत्तीने, खर्याची जागा खोट्याने, विवेकाची जागा अविवेकाने, लबाड वृत्ती वाढल्याने मानवी मूल्य नायनाट झाली आहे. गुलामी वृत्ती वाढीस लागली आहे. आर्थिकदृष्ट्या सामान्य माणूस कंगाल झाला आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणि खेड्यात हाताला काम मिळत नाही, तुटपुंज्या मजुरीच्या पैशात चूल पेटत नसल्यामुळे जागतिकीकरणाने खेड्यातून लोक शहराकडे धावू लागली. त्याचा परिणाम होऊन शहरे भरमसाठ फुगली त्यामुळे शहरातही ही सर्वसामान्य माणसांच्या समस्या वाढल्या. एकीकडे गगनाला भिडणाऱ्या कुबेराप्रमाणे अनेक मजली इमारती, रस्ते, रस्त्यावरचे दिवे. धावणाऱ्या गाड्या, बाजारपेठा, रेल्वेलाईन, मुंगीच्या रांगे प्रमाणे माणसे असे शहरातील डोळे दिपवणारे भौतिक वैभव, चंगळवाद नजरेत भरण्यासारखे परंतु त्याच वैभवाच्या दुसऱ्या बाजूला झोपडपट्टीत राहण्यासाठी जागा नाही. वीज, पाणी याचा अभाव, घाणीचे साम्राज्य, दंगली, गुंडागर्दी, टाळेबंदी, गोळीबार, मोर्चे, ट्राफिक, अ‍ॅम्ब्युलेन्स, फायरब्रिगेड अशा कितीतरी समस्यांचे थैमान माजले आहेत. या सगळ्यातून दारिद्र्य, अस्थिरता, बकालपणा, अविश्वास, संवेदनहीनता अशा अनेक समस्यांना सर्वसामान्य माणसाला सामोरे जावे लागत आहे. हे चित्रण अरुण काळे यांनी सायरनचे शहर या कवितेतून रेखाटले आहे.

अजीम नवाज राही हे नव्वदोत्तर पिढीतील जागतिकीकरणावर आपल्या ग्लोबल मेंदीची नक्षी या कवितेतून उत्तम भाष्य करून एक वेगळी जाणीव मांडणारे कवी आहेत. आधुनिकतावादी वळणाने लिहिणारे अजीम नवाज राही आधुनिक माणसाच्या हतबलतेचे आणि नव्या काळाने त्याच्यापुढे उभ्या केलेल्या सामाजिक, सांस्कृतिक, विकासाचे चित्रण मांडून ग्रामीण संवेदनशीलतेची ही कविता विघटनाचे नवे चित्र विस्तृतपणे आपल्यासमोर रेखाटताना मांडते, माणसे रोजगारासाठी घराबाहेर पडल्यावर दिवस मोहल्ल्यातल्या बाया बापड्यांचा गुलगुले विकल्यानंतरच्या जब्बारच्या टोपलीसारख्या मन उदास भकास लोडशेडिंग वेळेतल्या पीठ गिरणी सारखे. कवी अजीम राही यांची नाळ ग्रामीण जीवनाशी घट्ट जुळलेली आहे. त्यातही ते मुस्लीम वस्तीत राहतात. अतिशय गरीब, दीन-दुबळी ही माणसं हातावर पोट घेऊन जीव मुठीत घेऊन जीवन कंठत आहेत. स्त्री-पुरुष सर्वांनाच उदरनिर्वाहासाठी घराबाहेर पडण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मोहल्यातल्या बाया-बापड्यांना सुद्धा रोजगाराशिवाय पर्याय उरला नाही. एक प्रकारची उदासीनता यामुळे आपल्याला वेढून आहे. कवीच्या भावविश्वात मोहल्ला खूप महत्त्वाचा आहे. गरजांच्या साखळदंडांनी बांधलेलं आयुष्य विसावत नाही. घटकाभरासाठी लाकूड अपेक्षांचे भेदणारी करवत उजाडताच डोक्यावर विवंचनाचे पर्वत आदळताहेत. कोणत्या प्रदेशात ग्लोबली लाटा गेल्या नाहीत अजून मोहल्याला खेटून बिग बाजारच्या रंगीबेरंगी वाटा. एकीकडे जागतिकीकरणाचे नगरे आणि महानगरे बदलली. जगण्याची नवी साधने आणि नवी रीत तयार झाली. त्याचा दृश्य-अदृश्य परिणाम खेड्यातल्या जनजीवनावरही झाला. पण म्हणून काही काम करणे बंद झाले नाही. सूर्य उगवला की, कामासाठी वन वन पायपीट करावी लागते. गरजा संपत नाहीत आणि काम थांबत नाही. कुठलेच आर्थिक स्थैर्य नसलेल्या मोहल्यातल्या लोकांची विवंचना थांबत नाही. शहरात उंच-उंच रंगीबेरंगी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि मल्टिप्लेक्स तयार झाली पण खेड्यात मात्र याचा थांगपत्ता नाही. फक्त जगण्यासाठीची धडपड लक्षात येते. कौंदा सिलाते आम्मा आणि आनंद यादवांच्या कष्टाची लक्ष्मी याकथांची आठवण अजीम राही यांची कविता अभ्यासताना होते. न्याहाळतात बाया नजरेने अचंबित उंच इमारतीवरच्या लांबलांब टाक्या सिंटेक्स चघळतात कुतूहलाने त्यावरच्या थंड गरम पाण्याच्या नळांचा विषय गातात रांजणे कोरडी वाळवंटी गाणी येथे आठवडा उलटल्यावर नळाला पाणी वारसाहक्काने आलेली प्रवास माहेर ते सासर पर्यंतचा देण्याचा दारिद्र्याकडे मुक्काम दळणकांडण, भांडीकुंडी, धूनीपाणी बाळंतपण उपासमारीचा रोज्याला रमजानचा सलाम होत नाही. जगण्याची मुळे कधी पक्की गिळते स्वप्नांच्या पोस्टरला वास्तवाची जळजळीत चिक्की. कवी विद्यमान जागतिकीकरणातील नव्या युगाकडे उपरोधाने बघत आहेत. इथे अस्तित्वात असलेल्या दोन संस्कृतीतला फरक त्यांच्या नजरेतून हटत नाही. खेडे आणि शहर असा संघर्ष आहे. खेड्यातल्या बाया अचंबित होऊन इमारती वरच्या ओसंडून वाहणाऱ्या पाण्याच्या टाक्या बघतात शावर आणि थंड गरम पाण्याची सुविधा असलेल्या गोष्टी ऐकतात. त्याचवेळी आपल्या मनात मात्र पाणी नसल्याची खंत मन पोखरून टाकते. जणूकाही पिढीजात हे दारिद्र्य खेड्याला मिळालेले आहे. समृद्धीचा जराही वारा खेड्यापर्यंत पोहोचला नाही. खेड्यातले दुःख सगळ्यांचे आहे. रोजगाराचा पैशाचा अभाव पर्यायाने गरीबीमुळे व्यसनाधीन झालेली दरिद्री माणसं खंगून गेली, मनाने खचली आहेत. मग पत्नीला मारणे, त्रास देणे, सुनेच्या सासरी होणारा छळ जीवघेणा असतो. आपल्या मोहल्यातल्या आंतरिक पडझडीची ईथल्या भेदक वास्तवाची जाणीव वाचकांना कवी करून देतात. आधुनिक स्त्री-पुरुषांच्या जगण्याचा हा पेच अस्वस्थ करणारा आहे. जागतिकीकरणाच्या जगात प्रचंड व्यापारीकरण आणि ग्रामीण भागातील जगण्यासाठीचा संघर्ष यांच्या कचाट्यात माणूस अडकला आहे. बंदुका अनिश्चिततेच्या शक्यताकडे रोखलेल्या वागतो फटकून चंद्र पौर्णिमेचा पंख अमावस्येचे मोहल्ला भर पसरलेले. गरिबी एवढी पाचवीला पुजलेली आहे की स्वतःच्या अस्तित्वाचा माणसाला विसर पडावा. तारुण्य बहरले आणि संपले; पण हाताला हळद लावता आली नाही. माणसं दुःखाने मेली आणि उरलेली शासकीय योजनांसाठी खेटे मारू लागली. अनुदानाच्या पोस्टमनची वाट पाहणारी म्हातारी माणसं वाचकांचे अंतःकरण पिळवटून टाकतात. काळाने सूड उगवावा तसा हा वर्तमान काळ एकीकडे जागतिकीकरणाची मेहंदी रेखाटली जात आहे. झकपक जगणे होत आहे. भौतिक सुविधाच्या गादीवर उच्चभ्रू माणसं लोळत आहेत. तर दुसरीकडे मात्र दुःखाला कवटाळून बसला आहे. खेड्यापाड्यातला माणसाचे जगणे म्हणजे महाभयंकर शोकांतिकाच आहे. संवेदनशील माणसाला आणि त्याच्या अस्तित्वाला तडा देणाऱ्या या घटना जागतिकीकरणाच्या झंझावातात दिसतात काय? असा प्रश्न आपल्याला पडतो. दुःखात जगणारी आणि दुःख पचवणारी ही निराधार माणसं कोणत्या सांस्कृतिक कप्प्यात राहतात, असा प्रश्न सतावतो. काळजी जमान्याला शेअर बाजाराची वाहिन्यांच्या टीआरपीची स्टार्सची मानधनाच्या चढ-उताराची बोकांडी प्राथमिक गरजेच्या स्कोअर क्रिकेटचा. जागतिकीकरणातले माणसाचे आधुनिक जगणे हे माणूसपण हरवून बसले आहे. केवळ टीव्ही, शेअर बाजार, चित्रपट, स्टार, क्रिकेट अशा नव्या घटनांशी माणसाने जोडून घेतले आहे. माध्यमामुळे माणसाचे जगणे केवळ व्यवहारवादी झाले आहे. असे नवे पेच माणसापुढे उभे राहिले आहेत. जागतिकीकरण ही विकासाची प्रक्रिया असूनही खेड्यांचा विकास होणार

नसेल, तिथल्या समस्या संपणार नसतील, तर कोणत्या हातावर आपण ग्लोबल मेंदीची नक्षी कोरणार आहोत असा कवीने केलेला प्रश्न सूचक आणि मार्मिक आहे.

निष्कर्ष :-

1) मल्टी लुटालुटीचा झिंग लपालपा ही कविता जागतिकीकरणाने प्रभावित झालेल्या समाजाचे चित्रण करते.

2) अरुण काळे यांची कविता सर्वसामान्यांचे आत्मभान जागृत करते.

3) नादानुकारी शब्द योजनेमुळे ही कविता आपले कवितापण हरवु देत नाही. संपूर्ण कवितेत आधुनिक जगण्याशी संबंधित असलेल्या अनेक प्रतिमा येतात. स्विचऑफ, नॉट रिचेबल, आऊट ऑफ कव्हरेज, कंपनी यासारख्या नव्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित शब्दांचाही कवी अत्यंत चपखल वापर करतात.

4) समकालीन वास्तव किती भयानक आहे याची जाणीवच ही कविता केवळ करून देत नाही तर ती या शोषकांचा खरा चेहराही उघड करते.

5) अर्थयुद्ध या कवितेमध्ये सामान्य माणूस हाच जागतिकीकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. त्याचे भांडवलदाराकडून सततचे शोषण चालू आहे. मानवी मूल्यांचा ऱ्हास, गुलामी प्रवृत्ती समाज मनामध्ये रुतून बसली आहे. मानवी वृत्तीला जागतिकीकरणाचा फटका बसला आहे.

6) ग्लोबल मेंदीची नक्षी ही कविता जागतिकीकरणावर भाष्य करून शहराचा चेहरा बदलला आणि खेड्यांचा चेहरा अक्राळ विक्राळ झाला आणि नवे पेच माणसापुढे उभे राहिले याचे चित्रण करते. ग्रामीण आणि शहरी संवेदनशीलतेचा अविष्कार आणि मोहल्ल्यातील पडझडीचे चित्रण अजीम राही करतात.

संदर्भ ग्रंथ :-

1) (संपादक) मोतीराम कटारे व गंगाधर अहिरे, अरुण काळे व्यक्ती आणि वांग्मय, कौशल्य प्रकाशन, औरंगाबाद.

2) (संपा.) बाबुराव खंदारे व जयद्रथ जाधव, आधुनिक मराठी कविता, अथर्व पब्लिकेशन्स, धुळे, प्रथमावृत्ती, 2019.

3) किशोर सानप, युगांतरची कविता, ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई, प्रथमावृत्ती, 2019

4) (संपा.) नागनाथ कोतापल्ले आणि दत्ता भगत, जागतिकीकरणानंतरचे मराठी साहित्य, प्रा. प्रल्हाद लुलेकर गौरव ग्रंथ, सायन पब्लिकेशन्स, पुणे, प्रथमावृत्ती, 2017.

5) विश्राम गुप्ते, नवं जग नवी कविता, संस्कृती प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती, 2016.

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

भारतातील कोरोना काळातील विद्यार्थी वर्गावर झालेला परिणाम – एक विश्लेषण

प्रा. विजय देविदास वाकोडे
सहाय्यक प्राध्यापक इतिहास विभाग प्रमुख श्री ज्ञानेश महाविद्यालय, नवरगाव, ता. सिंदेवाही, जिल्हा: चंद्रपूर
इमेल : vwakode29@gmail.com

प्रस्तावना:

भारतात कोविड -19 ची पहिली घटना 30 जानेवारी 2020 रोजी नोंदविली गेली. 24 मार्च 2020 पासून संपूर्ण देशभरात लॉकडाउन करण्याचे आदेश भारत सरकारने दिले. 1 जून 2020 रोजी टप्प्याटप्प्याने अनलॉकची सुरुवात देशातील मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे आणि कोलकाता या सहा शहरांपैकी निम्म्या शहरांमधील नोंदवली गेली आहे. सप्टेंबर 2020 पर्यंत भारतात आशिया खंडात सर्वाधिक पुष्टी झालेली प्रकरणे होती; आणि 1 सप्टेंबर 2020 रोजी, पुष्टी झालेल्या प्रकरणांची संख्या , 5,000,000 झाली. 30 ऑगस्ट 2020 रोजी एका दिवसात 78,00,000 पेक्षा जास्त प्रकरणे नोंदवल्या गेल्याने भारताने अमेरिकेच्या रेकॉर्डला मागे टाकले आणि नवा विक्रम केला 16 सप्टेंबर 2020 रोजी त्या दिवशी जवळपास 98,000 प्रकरणे नोंदली गेली. 30 ऑगस्ट 2020 पर्यंत भारतातील मृत्यूची संख्या जागतिक 9.9% च्या तुलनेत 2.3% इतकी कमी होती. कोरोनाचा देशाच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेने (युनेस्को) एक अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार भारतातील सुमारे 32 कोटी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कोरोना साथीच्या आजारावर परिणाम झाले असून यामध्ये 15.81 कोटी मुली आणि 16.25 कोटी मुले आहेत. जागतिक स्तरावर, साथीच्या आजाराने जगातील 193 देशांतील 157 कोटी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला आहे, जे विविध स्तरावर दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 91.3 टक्के आहे. शिक्षणावर होणाऱ्या या मोठ्या परिणामाविषयी चर्चा करत अनेक बदल आणि आव्हाने जाणवली जात आहेत. कोरोनानंतरच्या काळात हा परिणाम आमच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक बनू शकतो, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोरोना साथीच्या आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊननंतर शाळा आणि महाविद्यालयांना शाश्वत तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. यात शिक्षकांचे प्रशिक्षण डिजिटल वातावरणात काम करण्याच्या कौशल्यांवर केंद्रित केले जाईल. पारंपारिक पद्धतीने उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात येत आहे. हा शोधपत्र कोविड -19 चे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या परिणामाचे चिकीत्सक अध्ययन करण्याच्या हेतूने लिहण्यात आलेला आहे.

शोध निबंधासाठी वापरण्यात येणारी संशोधनाची पद्धती:

प्रस्तुत शोध निबंधासाठी वापरण्यात येणारी माहिती व तथ्ये ही विषयाशी संबंधित विविध पुस्तके, मासिके, लेख, वर्तमानपत्र व सांकेतिक स्थळावरुन संकलित करण्यात आली आहे.

संशोधनाचे उद्देश: प्रस्तुत संशोधनाचे मुख्य उद्देश खालील प्रमाणे आहेत.

1) कोविड -19 चे विद्यार्थ्यांवर झालेले परिणामाचे चिकीत्सक अध्ययन करणे.
2) भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवरील कोरोनाच्या परिणामाविषयी माहिती शोधणे.
3) शिक्षण क्षेत्रावरील कोरोनाचा प्रभाव कमी करणारे उपाय शोधणे.

4) संशोधना पासून निघालेल्या निष्कर्षांच्या माहितीच्या आधारे विद्यार्थ्यांवर आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या विकासासाठी सूचना देणे.

संशोधनाची गरज व महत्व:

शिक्षण तरुण पिढीला जीवन कौशल्य प्रदान करते आणि आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी प्रेरित करते. तसेच, सामान्य लोकांना चांगल्या कर्माबद्दल जागरूक करण्यात ही महत्वाची भूमिका बजावते. शिक्षण परिपक्व लोकशाही साध्य करण्यात आणि 'मजबूत सरकार व योग्य शासन' करण्याचे ध्येय ठेवण्यास मदत करू शकते. हुंड्या, स्त्री भ्रूणहत्या आणि कामाच्या ठिकाणी होणा-या छळासारख्या अनेक सामाजिक दुष्परिणामांवर मात करण्यासाठी महिलांना शिक्षित करणे हीच गुरुकिल्ली असल्याचे सिद्ध झाले आहे. महिलांना शिक्षित करणे त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करुन देऊ शकते. कौशल्य-आधारित शिक्षण सामान्य लोकांना सामर्थ्यवान बनवू शकते आणि भारताच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विकासात त्यांची भूमिका सुनिश्चित करू शकते. तसेच, शिक्षणामुळे लोकांना रोजगार निर्मिती देखील होऊ शकते. जागतिक स्तरावर संसाधने फारच मर्यादित आहेत आणि म्हणूनच त्यांचा शाश्वत उपयोग फार महत्वाचा आहे, या उद्देशाने तरुण पिढीला शिक्षणाद्वारे मर्यादित स्त्रोतांचा शाश्वत उपयोग शिकविला जाऊ शकतो. मानवी विकास निर्देशांक (एचडीआय) आणि पीसा रँकिंग यासारख्या महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांपैकी, भारताची स्थिती सुधारण्यासाठी देशातील शैक्षणिक प्रणाली सुधारणे फार महत्वाचे आहे. परंतु कोविड -19 चे विद्यार्थ्यांवर परिणामाचे दिसून येत आहे. ते परिणाम सकारात्मक असतील तर काही हरकत नाही. परंतु हे परिणाम नकारात्मक असतील तर देशाच्या विकासावर याचा विपरीत परिणाम होवू शकतो. या दृष्टिकोणातून कोविड -19 चे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या परिणामाचे चिकीत्सक अध्ययन करण्याची गरज आहे. यामुळे संशोधनाचा विषय महत्वाचा ठरतो.

कोविड -19 चे विद्यार्थ्यांवर झालेले परिणाम :

कोरोनाव्हायरस ही एक शोकांतिका आहे जी संपूर्ण समाज सध्या पळवून लावत आहे. समाजातील असा एखादा विभाग नाही जो त्याच्या प्रभावामुळे प्रभावित झाला नसेल. या संपूर्ण दुर्घटनेमुळे समाजीकरणाच्या प्रक्रियेवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे समाजात अनेक प्रकारची उलथापालथ झाली आहे. परंतु या दुर्घटनेचा सर्वाधिक परिणाम ज्येष्ठ नागरिक आणि मुले यांच्यावर झाला आहे. ज्या मुलांना सुरुवातीच्या टप्प्यात मुक्त आणि गतिशील वातावरणाची आवश्यकता असते त्यांना घराच्या भिंतींमध्ये कैद व्हावे लागले आहे. पूर्वी असे वाटत होते की ही शोकांतिका काही काळासाठी आहे परंतु आता असे दिसते की मुलांचा बराच काळ घराच्या भिंती दरम्यान घालवला जाईल. जेव्हा कोविडचा उद्रेक सुरू झाला होता, त्याच वेळी शाळा बंद केल्या गेल्या परंतु एप्रिलपर्यंत शाळांकडून नवीन मेल आणि फोन येऊ लागले की आता अभ्यास ऑनलाइन होईल. काही काळासाठी, मुलांनी अद्याप हा विनोद सहन केला, परंतु जुलै होताच, पुन्हा मुलांच्या शाळांकडून सूचना येऊ लागल्या. त्यासाठी टाइम टेबलदेखील तयार केले गेले. शाळांना शिक्षकांना पगार द्यावा लागतो यात काही शंका नाही आणि शाळांना फी घ्यावी लागत आहे ज्यामुळे त्यांना असे वाटते की वर्ग चालविणे आवश्यक आहे कारण वर्गशिवाय लोक फी भरणार नाहीत. परंतु या सर्वांच्या दरम्यानही मुलांचे बालपण कसे घसरेल याकडे लक्ष नाही. ही मुले सकाळी ते दुपार या वेळेत वर्ग कसे करतील आणि त्यांची एकाग्रता कशी वाढवायची हा एक मोठा प्रश्न आहे. हा प्रयोग काही काळ माध्यमिक वर्गातील मुलांसमवेत पाहायला मिळाला, परंतु नर्सरी आणि प्राथमिक मुलांवर हा प्रयोग केला जाणे अव्यवहार्यच नाही तर अमानुषही आहे. घरात कैद केलेली मुले निरनिराळया मानसिक दबावांशी झगडत आहेत. या मुलांना 5 तास पडद्यासमोर बसवीणे अमानुष कृत्य आहे. ज्यावर बाल हक्क आयोगाच्या बरोबर शिक्षण

मंत्रालयाचीही जबाबदारी आहे की त्यामध्ये हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घ्या. प्राथमिक आणि नर्सरीची मुले ज्यांना आपले बरेच काम करण्यासाठी इतर लोकांची गरज असते त्यांना पडद्यासमोर बसून ही शिक्षण व्यवस्था आपल्या कर्तव्याची जबाबदारी स्वीकारत आहे. जी मुले नवीन वर्गांमध्ये गेली आहेत आणि जे पहिल्यांदाच शाळेचे नाव ऐकत आहेत ते सर्वजण ऑनलाईन मार्फत शाळा आणि वर्ग पाहत आहेत ही खरोखरच त्रासदायक घटना आहे. कोविड -19 नंतर शिक्षण क्षेत्रात उदयास येणाऱ्या आयामांवरील अभ्यासात असे म्हटले जाते की कोविड -19 साथीच्या आजारामुळे बरेच लोक डिजिटल माध्यमात शिकत आहेत आणि अल्प कालावधीचे अभ्यासक्रमही लोकप्रिय होत आहेत. हे बदल अडचणींना कारणीभूत ठरत आहेत, परंतु ते शिक्षण क्षेत्रात नवीन कल्पनांची उदाहरणेही दिली जात आहेत. यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की डिजिटल माध्यमाचा प्रभाव शैक्षणिक जगात दीर्घकाळ टिकणार आहे. कोरोनाच्या दबावामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये अभ्यास करण्यासाठी डिजिटल माध्यमाचा अधिक वापर केला जाईल. शैक्षणिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप, झूम, टीम यासारख्या अॅप्स आणि ई-मेलचा वापर वाढविला जाईल. शैक्षणिक संस्था अशी रचना विकसित करतील ज्यामध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी शैक्षणिक कार्यशाळेच्या बाहेर राहून वाचू आणि अभ्यास करू शकतात. संस्था अशा कायम तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करतील ज्याद्वारे दर्जेदार ऑनलाइन शिक्षण दिले जाऊ शकते. यामुळे परकीय गुंतवणूकही आकर्षित होईल. राज्यांच्या शिक्षण मंत्रालय आणि केंद्रातील मनुष्यबळ व विकास मंत्रालय, जे उच्च शिक्षणावर सातत्याने प्रतिक्रिया देतात, असे दिसते की ते प्राथमिक वर्गातील मुलांबद्दल आणि इतर विषयांप्रमाणेच त्यांच्या चिंतांबद्दल तितकेसे गंभीर नाहीत. याची अनेक कारणे असू शकतात. उदाहरणार्थ, विद्यापीठ आणि उच्च माध्यमिक स्तराचे विद्यार्थी अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे सरकारच्या धोरणांवर प्रतिक्रिया देत असतात, परंतु प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थी एकतर त्यांच्या पालकांद्वारे किंवा शिक्षकांद्वारे बोलू शकतात. शिक्षकांच्या जगण्याशी संबंधित विषयामुळे त्यांचा प्रतिसाद यात येत नाही. आज जेव्हा जगातील सर्व देश मुलांच्या मानसिक आरोग्याबद्दल चिंतातूर आहेत, तेव्हा आपली शिक्षण प्रणाली शिक्षकांच्या वापराबद्दल आणि फायद्यांबद्दल काळजीत आहे. प्राथमिक शिक्षण ही आमच्या शिक्षण प्रणालीतील सर्वात दुर्लक्षित क्षेत्र आहे कारण या क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणूकीचा निकाल येण्यास वेळ लागतो, परंतु जगातील सर्व देश प्राथमिक शिक्षणामध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूकीवर लक्ष केंद्रित करतात कारण ते असे क्षेत्र आहे जे उद्याचा पाया आहे. पण आपल्या देशात तसे होताना दिसत नाही. शाळांमधील एकमेव समस्या शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांना व्यस्त कसे ठेवायचे हे असेल तर त्या दरम्यान त्यांना आणखी काही शैक्षणिक जबाबदारी देखील देऊ शकते. सत्र सुरू झाल्यावर, ते यासाठी काही सामग्री तयार करू शकतात आणि या वेळी त्यांचा ज्ञान सामग्री वाढविण्यासाठी वापरू शकतात. यासाठी मुलांवर आवश्यक दबाव निर्माण करणे आवश्यक नाही. सरकारने शाळांकरिता सर्वसमावेशक धोरणही तयार केले पाहिजे जेणेकरून ज्या शाळांना आर्थिक दबाव सहन करता येत नाही त्यांना काही प्रमाणात मदत मिळेल. बऱ्याच शाळा आहेत ज्या बऱ्याच काळासाठी कोविड -19 शी संबंधित आर्थिक परिस्थितीचा सामना करू शकणार नाहीत. त्यांच्यासाठी शिक्षण मंत्रालय आणि मानव संसाधन मंत्रालय यांनी काही योजना तयार केल्या पाहिजेत.ही अशी वेळ आहे जी शिक्षणाची संपूर्ण रचना सुधारण्यासाठी आणि नवीन करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, परंतु दुर्दैवाने, शिक्षणातील बहुतेक घटक या वेळेचा उपयोग शॉर्टकट शोधण्यासाठी करीत आहेत जे भविष्यातील शिक्षणासाठी दुर्दैवी आहे. मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे आणि ऑनलाईन शिक्षणाची ही प्रवृत्ती कमी करण्याचा किंवा थांबविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.उच्च शिक्षण संस्था वेगवेगळया देशांमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या पद्धतींच्या आधारे परिक्षेच्या पारंपारिक पद्धतीऐवजी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन पद्धतीने मूल्यांकन करतील. देशातील ऑनलाईन शिक्षणाशी संबंधित अडचणी दूर कराव्या लागतील. इंटरनेट आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा पोहोच फारच अरुंद आहे. चांगल्या स्पीड इंटरनेटची

उपलब्धता देशातील प्रत्येकासाठी कठीण कार्य आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार महिन्यातून एकदा इंटरनेट वापरणाऱ्यांना इंटरनेटशी जोडलेले मानले गेले तर केवळ 34 टक्के शहरी आणि 11 टक्के ग्रामीण लोक इंटरनेटचा वापर करतात. स्मार्टफोन अद्याप प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हाती पोहोचलेला नाही. कोविड-19 मुळे परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या 48 टक्के पेक्षा जास्त भारतीय विद्यार्थ्यांच्या निर्णयावर परिणाम झाला आहे. जगभरातील उच्च शिक्षण संस्थांचे विश्लेषण करण्यात आणि या संस्थांच्या क्रमवारीत काम करणाऱ्या ब्रिटीश कंपनीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की परदेशात महागड्या अभ्यासासाठी मिळणारी गुंतवणूक कमी झाली आहे आणि कोविड -19 नंतरच्या विद्यार्थ्यांच्या परदेशात अभ्यास करण्याच्या योजनेवर परिणाम कमी झाला आहे. आज भारतीय विद्यापीठांपर्यंत पोहोचणाऱ्या लोकांची संख्या खूपच कमी आहे. उच्च शिक्षणातील एकूण पटसंख्या प्रमाण फक्त 2 टक्के आहे, जे बऱ्याच देशांपेक्षा कमी आहे. देशाच्या शैक्षणिक संस्थांसाठी ही एक चांगली संधी आहे, आम्हाला आपल्या देशात शैक्षणिक गुणवत्तेची पातळी आणखी सुधारित करावी लागेल जेणेकरुन देशातील विद्यार्थ्यांचा परदेशी अभ्यासाचा मोह कमी होईल. चपळ संस्थेप्रमाणेच, आपल्या शैक्षणिक संस्थांनी कोरोनानंतरच्या संधीकडे पुढे जावे आणि शिक्षणात गुंतलेल्यांनी डिजिटल डिलीव्हरीच्या कलाचे सर्वात सर्जनशील मार्ग शिकावे, कोरोना साथीचा एक परिणाम हा आहे की उच्च शिक्षण संस्थांचे भविष्य ते चालवण्याच्या मार्गात मूलभूत बदल होण्याची अपेक्षा आहे.शाळा व शैक्षणिक संस्था बंद झाल्याने जगातील सुमारे 94 % विद्यार्थी आणि कमी आणि मध्यम-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील 99% विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. याव्यतिरिक्त कोविड -19 साथीच्या रोगाने शिक्षणपद्धतीत सध्या असमानता वाढली आहे. या साथीमुळे, कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशातील कमकुवत व असुरक्षित लोकसंख्या यावर विषाणूचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. सन 2020च्या दुसऱ्या तिमाहीत प्राथमिक पातळीवरील सुमारे 86% मुले कमी उत्पन्न असलेल्या देशांत शाळा सोडून गेली आहेत, त्या तुलनेत फक्त २०% उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये आहेत. जगभरातील कोट्यावधी लोकांचे शिक्षण घेण्याच्या दृष्टीकोनात कोरोना विषाणूच्या साथीने बदल केला आहे.

निष्कर्ष:

अध्ययनात असे लक्षात आले की, कोरोना साथीचा सर्वाधिक परिणाम मुली व स्त्रियांवर दिसून येतो, शाळा बंद झाल्याने बालविवाह आणि लिंग-आधारित हिंसाचारात वाढ झाली आहे. तसेच मुलांवरील गुन्ह्यांमध्येही वाढ झाली आहे. 2020 पर्यंत, असा अंदाज वर्तविला जात होता की जगातील बहुतेक निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये शैक्षणिक बजेट आणि गुणवत्ता शिक्षणाच्या विकासाच्या उद्दीष्टापर्यंत पोचण्यासाठी आवश्यक असणारी रक्कम यांच्यात सुमारे 188 अब्ज डॉलर्सचे अंतर आहे. कोरोना साथीच्या आजारामुळे ही आर्थिक तूट दोन तृतीयांश वाढू शकते. कमकुवत पायाभूत सुविधा ही भारताच्या उच्च शिक्षण प्रणालीसाठी एक मोठे आव्हान आहे, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था कमकुवत पायाभूत सुविधा आणि पायाभूत सुविधांमुळे त्रस्त आहेत. प्राध्यापकांची कमतरता व पात्रता असणाऱ्या शिक्षकांना आकर्षित करण्यास व राखण्यासाठी राज्य शैक्षणिक यंत्रणेची असमर्थता ही बऱ्याच वर्षांपासून दर्जेदार शिक्षणासाठी एक आव्हान आहे.

सूचना:

1. शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे.
2. कोरोना च्या या स्थितीत शिक्षणाच्या विकासा संदर्भात राज्ये आणि केंद्र सरकारने वेळोवेळी ज्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत त्यांचे पालन करण्याची नितांत गरज आहे.
3. प्रदान केलेले शिक्षण उद्योगासाठी आवश्यक असलेले शिक्षण असणे गरजेचे आहे.
4. शिक्षण क्षेत्रात संशोधनावर सरकारी खर्च वाढवणे आवश्यक आहे.

5. सर्वसमावेशक शिक्षण प्रणालीवर जोर दिले पाहिजे.
6. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत विद्यमान शिक्षणपद्धतीत बदल करने गरजेचे आहे.
7. ऑनलाइन वर्गाचे सत्र केवळ विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठीच तयार केले पाहिजे, केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी नाही.
8. शिक्षणाच्या जागतिक मानकांचा अवलंब करण्यासाठी शैक्षणिक धोरणात तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. *MD Dr. Md. Khaleel, Handbook on Novel Coronavirus: What You Need to Know?, Innovative Publication; 1 edition (1 January 2020)*
2. *Mayank Rajput, Impact of COVID-19 on Education: 20 Effects on Schooling in India, Kindle edition, June 2020.*
3. *McKimm and Prof Abdulrahman O Al-Youbi, Perspectives on Higher Education: Impact of the COVID-19 Pandemic, Kindle Edition, 2020.*
4. *Dr Swapneil Parikh, Maherra Desai, Dr Rajesh Parikh, The Coronavirus: What you Need to Know about the Global Pandemic, Penguin eBury Press (22 June 2020)*
5. *Surjit Singha, Impact of COVID-19 on Economy, Business, Education and Social Life, The Native Tribe publication, July 11, 2020.*

वर्तमानपत्र : *नवभारत, लोकमत, टाईम्स ऑफ इंडिया*

संकेतस्थळ:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic
2. https://www.punjabkesari.in/blogs/news/lockdown-corona-virus-study-unesco-1177955
3. https://hindi.theprint.in/opinion/how-online-classes-started-in-schools-amid-corona-epidemic-affecting-children-lives/151497/
4. https://khabar.ndtv.com/news/career/coronavirus-may-make-education-outcomes-worse-says-world-bank-2227034
5. https://www.prabhasakshi.com/politics-articles/education-sector-has-also-suffered-unprecedented-loss-in-corona-period
6. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1638502
7. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1619531
8. https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/corona-lockdown-education-online-revolution-digital-education-power-supply-connectivity-data-1073442-2020-05-28
9. https://www.newslaundry.com/2020/07/08/online-education-during-coronavirus-pandemic-2
10. https://www.jagran.com/blogs/svsingh/lockdown-effect-on-education-system/
11. https://www.amarujala.com/channels/downloads?tm_source=text_share
12. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/24-million-may-drop-out-of-school-due-to-covid-19-impact-u-n-
13. https://www.bhaskar.com/coronavirus/news/current-and-later-effects-of-corona-virus-globally-127290995.html

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR) ISSN – 2347-7075
Peer Reviewed Bi-Monthly Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

वैश्वीकरण में अनुवाद का महत्व

प्रा. किसन भानुदास वाघमोडे
वालचंद कॉलेज ऑफ आर्टस अँड सायन्स, सोलापूर
ईमेल- digkisan@gmail.com

सारांश

अनुवाद से मिलने वाले ज्ञान ने मनुष्य के समाजशास्त्र को एक देश की सीमा से निकाल कर दूसरे देश तक पहुंचाया है। संस्कृत और यूनानी साहित्य कला और दर्शन के प्रचार-प्रसार का श्रेय अनुवाद को ही जाता है।आधुनिक नवजागरण काल में पश्चिम के नए ज्ञान विज्ञान से हमारे ज्ञान और चेतना के विकास में अनुवाद ही सबसे बड़ा सहारा बना है। विश्व के सभी विकसित देशों की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथ प्रौद्योगिकीपरक विकास में अनुवाद की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आज विज्ञान के तेजी से बदलते हुए विश्व में प्रौद्योगिकी चिकित्सा कृषि आदि के क्षेत्र में हो रहे नए नए अविष्कारों और अनुसंधान हमसे जुड़े रहने के लिएअनुवाद सबसे बड़ा साधन है।

'वैश्वीकरण' अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन (Globalisation) का हिन्दी रूपान्तरण है, जिसका अर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण वैश्विक भूखण्ड से है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री Anthony Giddens के अनुसार "वैश्वीकरण दूरी और समय को सीमित करने का प्रयास है जिसमें संप्रेषण के माध्यम से तुरंत ही पूरे विश्व में एक साथ ज्ञान एवं संस्कृति का आदान-प्रदान किया जा सकाता है।"[1]अनुवाद देश और काल की सीमाओं को समाप्त करने वाला एक महत्वपूर्ण भाषिक साधन है। अनुवाद माध्यम से भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषिक सीमाएँ को दूर करके परस्पर मानवता का संबंध स्थापित किया जा सकाता है। विश्व के विभिन्न भाषाएँ आज अपनी-अपनी संस्कृति और जीवन की विधियों को संचालित कर रही है। विश्व की संस्कृति और जीवन की विधियों में समन्वय स्थापित करने का एक मात्र साधन अनुवाद ही है। अत: विन्टर के अनुसार "अनुवाद कार्य विश्व के एक खंड को प्रतिपादित करने वाले माध्यम से दूसरे माध्यम द्वारा लगभग वैसे ही अनुभव का पुन:सर्जन है।"[2] मनुष्य के भाषा ज्ञान की सीमा को अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों की सीमा नहीं बनाना चाहता। वह उन लोगों से संपर्क में आता है जिनकी भाषा नहीं जानता। उनके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंध स्थापित करता है। इन कार्यों में वहा दुभाषिए और अनुवादक की सहायता लेता है। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में वह अपनी जानकीरी सीमित नहीं रखना चाहता। देश-विदेश में हुए अनुसंधान एवं विकास की निरंतर जानकारी पाना चाहता है। दूसरी भाषओं की ऐतिहासिक, सांस्कुतिक, साहित्यिक धरोहर की गहनता एवं व्यापकता का अध्ययन करना चाहता है और यह सब अनुवाद के माध्यम से ही संभव होता है। दूसरी ओर वह एक तरह की सर्जनात्मक प्रेरणा से भी अनुवाद का ओर प्रेरित होता है। अन्य भाषओं में जो कुछ नया और विशिष्ट उसे दिखाई देता है उसे अपनी भाषा के लोगों तक पहुँचाने का माध्यम बनने में उसे एक विशिष्ट प्रकार का सर्जनात्मक सुख प्राप्त होता है जो किसी हद तक मौलिक सृजन के सुख से कम नहीं होता। इस सृजनात्मक प्रेरणा के कारण ही साहित्यिक कृतियों के अनुवाद प्राचीन काल से होते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। जो कृति जितनी अधिक श्रेष्ठ होती है उतनी ही अधिक अनुवाद की प्रेरणा देती है। विभिन्न भाषओं के लोग उसका अनुवाद करते हैं। इतना ही नहीं एक ही भाषा में उस कृति के अनेक अनुवाद देखने को मिलते हैं। अत: हर युग में उसका अनुवाद होता रहता है। कालिदास, शेक्सपियर, वाल्मीकि आदि की रचनाएँ और इनके अनुवाद इसका उदाहरण हैं।विज्ञान के विकास के साथ-साथ सूचना का महत्व बढ़ा है। विज्ञान के क्षेत्र में खोजों की जानकारी वैज्ञानिक तुरंत पाना चाहते हैं। जिस भाषा में वह उपलब्ध है उसे तुरंत अपनी भाषा में पाने के लिए उन्हें अनुवादकों की जरुरत

पड़ती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ आज दुनिया भर के लोंगों का आपसी संपर्क बढ़ा है। ज्ञान के क्षेत्र के अतिरिक्त व्यापार, उद्योग, पर्यटन आदि के क्षेत्र में दुनिया सिमट कर काफी छोटी हो गई है। भूमंडलीकरण (Globalization) के जमाने मेंजब मनुष्य एक दुसरे की आवश्यकताओं और पूर्ति में ज्यादा और निकट का साझीदार हुआ है तब अनुवाद की जरुरत और ज्यादा बढ़ गई है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसारक हैं और इन कंपनियों के माल के बाजार दुनिया भर में फैले हैं। इन बाजारों में माल की खपत के लिए अनुवाद अपने ढंग से जरुरी हो गया है। कंपनियों के उत्पाद भाषा की सीमाओं को लाँघते हुए सब जगह पहुँच रहे है।

शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद

शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व अपिरिहार्य है। देश-विदेश के ज्ञान-विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए अनुवाद की जरुरत पड़ती रहेगी। इसके साथ ही विभिन्न देशों और समाजों के प्राचीन ज्ञान-उन भाषाओं मं उपलब्ध ज्ञान जो अब बहुत प्रचलन में नहीं हैं- वहा तक पहुँचने के लिए अनुवाद वाहक का कार्य करता है। प्राचीन संस्कृति, ग्रीक आदि लेखकों की कृतियों को हम अनुवाद के माध्यम से ही पढ़ते हैं।शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उपयुक्त ज्ञान और विज्ञान की सामग्री अंतरराष्ट्रीय धारातल पर विश्व के सभी देश आपस में आदान-प्रदान करते है। इस आदान-प्रदान में अनुवाद का सबसे बड़ा योगदान रहा है। विश्व कल्याण के लिए विश्व में जो भी शोध और अनुसंधान हो रहे है, जिनमें असंख्य वैज्ञानिक कार्यरत हैं, उनके नतीजे समूच मानव जाति तक पहुँचाने का कार्य अनुवाद द्वारा ही संभव है। वर्तमान समय में कोरोनो जैसे माहामारी की जानकारी, उसके संबंधीत टीका से ***जुड़ी*** सूचनाएं और सुझाव सभी जानकारी देश विदेश के स्थानीक लोंगों को स्थानीय भाषा में दी जाती है, इसके पीछे विशेषज्ञ अनुवादकों का परिश्रम रहता है। विश्व में जितनी भी भाषाएँ है उन सभी भाषाओं में सभी ज्ञान-विज्ञान की सामग्री स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो रही है- इसका श्रेय अनुवाद को ही जाता है।अनुवाद से मिलने वाले ज्ञान ने मनुष्य के समाजशास्त्र को एक देश की सीमा से निकाल कर दूसरे देश तक पहुंचाया है। संस्कृत और यूनानी साहित्य कला और दर्शन के प्रचार-प्रसार का श्रेय अनुवाद को ही जाता है।आधुनिक नवजागरण काल में पश्चिम के नए ज्ञान विज्ञान से हमारे ज्ञान और चेतना के विकास में अनुवाद ही सबसे बड़ा सहारा बना है। विश्व के सभी विकसित देशों की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीपरक विकास में अनुवाद की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आज विज्ञान के तेजी से बदलते हुए विश्व में प्रौद्योगिकी चिकित्सा कृषि आदि के क्षेत्र में हो रहे नए नए अविष्कारों और अनुसंधान हमसे जुड़े रहने के लिए अनुवाद सबसे बड़ा साधन है।

वैश्विक सामाजिक संस्कृति के विकास में अनुवाद का महत्व

"विश्व की सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास में अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। यूनान मिश्र चीन आदि की प्राचीन सभ्यताओं से भारत का घनिष्ठ संबंध रहा है और इस संबंध में अनुवाद की विशेष महत्ता रही है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समूचे एशिया में अनुवाद की जीवंत परंपरा का परिणाम है। विश्व भर में गीता तथा उपनिषद के ज्ञान का अनुवाद अपने ढंग से किया जाता रहा है। पंचतंत्र के लघु संग्रहों का अनुवाद अरबी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। वास्तव में अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को जानने व समझने में इसकी निश्चित रूप से भूमिका सिद्ध हो। विश्व की सांस्कृतिक एकता में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आज की भारतीय संस्कृति जिसे हम सामासिक संस्कृति कहते हैं उसके निर्माण में हजारों वर्षों के विभिन्न धर्मों, मतों एवं विश्वासों की साधना छिपी हुई है। इन सभी मतों एवं विश्वासों को आत्मसात कर जिस भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है उसके पीछे अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका असंदिग्ध है। अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों की सांस्कृतिक निधियां आज हमारे सामने हैं। अनुवाद के माध्यम से ही हम एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत के भागीदार बनें हैं।"[3] संस्कृति अपने वृहत्तर अर्थ में पूरी मानव सभ्यता की उपलब्धियों का साझा कोष है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाओं का दूसरा नाम संस्कृति है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुजाती, देश में एक साथ इतनी संस्कृतियों, धर्मो और आचार-विचारों का समन्वय हुआ है कि इस देश में संस्कृति का एक समन्वित और मिश्रित स्वरुप अब स्थिर हो गया है। जिस तरह सागर अनंत नदियों की

जलराशि को समाहित कर विशलता अर्जित करता है, उसी तरह भारतीय संस्कृति ने भी कई चिंतनधाराओं, कई विचारशैलियों और न जाने कितनी व्यवहारगत असमानताओं को अपने भीतर पचा कर अनूठी समन्वयात्मकता का परिचय दिया है। भारत की इस बहुआयामी संस्कृति को ही समासिक कहा गया है, जिसमें चिंतन, सृजन, भाषा, कल्पना और आचरण की तमाम विभिन्नताओं के बावजूद अद्भूत समासिकता लक्षित होती है। भारतीय जनजीवन में व्याप्त अनेकता में विद्यमान सांस्कृतिक समीकरण ही इस समासिक संस्कृति की मूलभूत विशिष्टता है। भारतीय संस्कृति में भारत की विविधाताएँ अपनी संपूर्ण मौलिकता के साथ गुँथी हुई है। सामासिक संस्कृति की इस समन्वयात्मक चेतना का पल्लवन करने में अनुवाद का महत्व अप्रतिम है। अनुवाद के बिना हम कैसे जान पाते कि मौजूदा भारतीय साहित्य और चिंतन किन दिशाओं में अग्रसर है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सोच और अभिव्यक्ति की दशा-दिशा की जानकारी अनुवाद के बिना संभव ही नहीं।

विश्व साहित्य में अनुवाद महत्व

विश्व साहित्य की संकल्पना अनुवाद के बिना संभव नहीं है। विश्व के सभी राष्ट्रीय साहित्य को समग्रता में विश्व साहित्य कहा जाता है। पर व्यवहारत: जो कृति राष्ट्रीय सीमा पारकर विभिन्न देशों में अपनी व्यापक ख्याति बना ले उसे विश्व साहित्य में गिनने लगते हैं। प्राचीन कृतियाँ सहित, वैश्विक परिदृश्य की समझ के साथ लिखा गया सभी समकालीन साहित्य आज विश्व साहित्य समझा जाता है। बीसवीं सदी के अंत आते-आते दुनिया भर के बुध्दिजीवी विश्व साहित्य के मद्देनजर अपनी राष्ट्रीय कृतियों की संरचना के बारे में गहनता से सोचने लगे। "वर्तमान समय में रॉबर्ट टी.कियोसाकी कृत 'रिच डैड, पुअर डैड' यह किताब चमत्कारिक सफलता के रूप में सबके सामने है। सौ से अधिक देशों में पचास से ज्यादा भाषाओं में 'रिच डैड, पुअर डैड' यह किताब अनुदित हो चुकी की हैं। यह ऐसी किताब है, जिस पर करीब एक दर्जन किताबें दूसरे लेखक लिख चुके हैं।"[4] साथ ही डॉ. जोसेफ़ मर्फ़ी की कालजयी पुस्तक द पावर ऑफ़ यॉर सबकॉन्शस माइंड (आपके अवचेतन मन की शक्ति) 1963 में प्रकाशित हुई I इसे आज भी सर्वश्रेष्ठ सेल्फ़ - हेल्प पुस्तकों में मन जाता है I इस पुस्तक की सफलता के बाद डॉ. मर्फ़ी पूरे संसार में हज़ारों लोगों के समक्ष व्याख्यान देने लगे और अपने दैनिक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को संबोधित किया I इस प्रकार उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी बताई बातों पर अमल करके कितने ही लोगों ने अपने जीवन में किस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं।"[5]

पर्यटन क्षेत्र में अनुवाद का महत्व

पर्यटन क्षेत्र में अनुवाद का बहुत महत्व है। पर्यटन का संबंध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों मे होता है। इसमें यात्रा, आवास, मनोरंजन, पर्यटन स्थल संबंधी सूचना, प्रचार सामग्री आदि का उपयोग होता है। इस क्षेत्र में अनुवाद के दोनों रुप लिखित और मौखिक रुपों की आवश्यकता होती है। देश-विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए परिवहन संबंधी सुविधाओं और होटल एवं यात्री निवास आदि पर अनुवादकों की बहुत आवश्यकता होती है। पर्यटकों के साथ मार्ग-दर्शक(गाइड) को पर्यटन व स्थल संबंधी जानकारी कई भाषओं में देनी पड़ती है। वास्तव में पर्यटन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अनुवाद पर बहुत हद तक निर्भर करता है। पर्यटन की गतिविधि खेल गतिविधि, चिकित्सा, धार्मिक एवं अध्यात्मिक यात्रा, ऐतिहासिक झुकाव, शिक्षा, जलवायु, संगोष्ठी, नौकरी, आयात-निर्यात, व्यापर आदि उद्देश्यों से प्रेरित होती है।"[6] अंत: आज के युग को अनुवाद का युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। सोच और व्यवहार के हर स्तर पर हम अनुवाद पर आश्रित हैं, अनुवाद के आग्रही हैं। शायद ही जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र हो, जिसमें अनुवाद की उपादेयता प्रमाणित न की जा सके। अपरिहार्य तौर पर अनुवाद एक व्यापक और प्रासंगिक स्थिति है। इसलिए यह सर्वथा स्वाभाविक ही है कि नए संसाधनों के विकास और व्यापकतर मानवीय संपर्कों के संद्रभ में अनुवाद के महतव, प्रासंगिता और भविष्य का अनुशीलन किया जाए। संसार भर में प्रयुक्त विभिन्न भाषओं और बोलियों के बीच वैचारिक, सर्जनात्मक और कार्यात्मक तालमेंल स्थापित रखने के लिए अनुवाद ही सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी माध्यम माना गया है।

संदर्भ

1. https://sarkariguider.in
2. वैश्वीकरण के परिदृश्य में अनुवाद की भूमिका- डॉ.एम. वेंकटेश्वर
3. 'अनुवाद का महत्व' (आलेख)- डॉ.सुनीत शर्मा पृ. 1
4. https://navbharattimes.indiatimes.com
5. https://manjulindia.com
6. पर्यटन और अनुवाद- हरिष जैन

प्रा. किसन भानुदास वाघमोडे

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

जागतिकीकरणाचा मराठी ग्रामीण साहित्यावरील प्रभाव

प्रा.डॉ. जनार्धन परकाळे
सहयोगी प्राध्यापक मराठी विभाग शंकरराव मोहिते महाविद्यालय अकलूज

प्रस्तावना

भारताने आपल्या देशात 1990 पासून जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण याचा स्वीकार केला.जागतिकीकरणामुळे आलेल्या सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाचा पहिला धक्का मोठ्या शहराला बसला. त्यानंतर लहान शहरे व खेडे गावांनाही तो धक्का बसला आहे.जागतिकीकरणामुळे आता सर्वांनाच बदलाला सामोरे जावे लागले. आर्थिक धोरणांना नवे रूप आले.सामान्य माणसाचे जीवनमान बदलत गेले. सामान्य माणसाला या जागतिकीकरणामध्ये जगण्यासाठी फार मोठा संघर्ष करावा लागतो. सामाजिक पातळीवर सर्वांनाच वेगवेगळे परिणाम भोगावे लागतात. शहरात जसे माहिती तंत्रज्ञान ,बीपीओ, कॉल सेंटर ,बडे मॉल्स आले तसे खेड्यात कुणब्याचे जिने दुष्कर झाले. सामान्य शेतकऱ्याच्या आत्महत्या वाढल्या. खेडेगावात व्यापारीकरण होऊ लागले. खेड्यातील जमिनी, नदी-नाले यांचे सौदे होऊ लागले. धनदांडगे राजकीय लोक शेतकऱ्याला एकंदरीत ग्रामीण माणसाला कंगाल बनवू लागले. याचा परिणाम मराठी साहित्यावर मोठ्या प्रमाणात झाला. त्यातून ग्रामीण शेतकऱ्याचे, शेत मजुराचे दुःख साहित्यिक आपल्या साहित्यातून मोठ्या प्रमाणात मांडू लागले. जागतिकीकरणाने नव्या जीवन जाणिवा निर्माण होऊन ते साहित्यात येऊ लागले. त्या साहित्याची समीक्षा होऊ लागली. संपूर्ण जीवन ढवळून टाकणारी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया काय आहे आणि त्याचा मराठी साहित्य विश्वावर काय परिणाम झाला हे या शोधनिबंधात ऊन मांडण्यात येणार आहे जागतिकीकरणामुळे सर्व देशाच्या सीमा पुसट होत जाऊन व्यापाराच्या दृष्टीने स्थलांतर होऊन भांडवलाचे वहन मोठ्या प्रमाणात झाले. जागतिकीकरण हे दळणवळण आणि तंत्रज्ञानामुळे तीव्र गतिशील झाले. ते रोखणे कठीण झाले जागतिकीकरण ही एक प्रक्रिया सर्व मानवी जीवनाशी संस्कृतीशी संबंधित आहे. औद्योगीकरणाने सर्व जग जवळ आले व ते अधिकच ढवळून निघाले. त्यामुळे उत्पादकतला महत्त्व प्राप्त झाले. त्यातून समाजाचे शोषण मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले. सारा समाज जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गुंतला आहे. 1990 नंतर खुल्या अर्थ धोरणाचा स्वीकार झाल्याने त्याचा वाईट परिणाम समाजावर झाला. नवा पेटंट कायदा आला, मुक्त बाजारपेठ तयार झाली, निर्बंधाचे शिथिलीकरण झाली, कृषी धोरण त्याचा अनुदानावर परिणाम झाला, आयात-निर्यात धोरण बदल झाले. या सर्वांचा परिणाम समाजव्यवस्थेवर झालेला दिसून येतो. जागतिकीकरणामुळे खुल्या धोरणाच्या आधारे भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाची मोठी बाजारपेठ काबीज केली गेली. त्यामुळे भारतातील सामान्य माणूस व शेतकरी दुबळा बनत गेला .मध्यमवर्गीय शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांना नव्या अर्थव्यवस्थेत कोठेच स्थान मिळत नव्हते. तो आर्थिक मागास बनत चालला होता. त्याच्या शोषणावर नवी व्यवस्था उभी राहत होती .या सर्वांचा परिणाम मराठी साहित्य विश्वावर होत होता .जागतिकीकरणामुळे मध्यमवर्गीयांच्या मनातील साहित्याची जागा घसरत चाललेली दिसते व्यावहारिक जगात वाचनाला जागा किंवा वेळच मिळत नसल्याची खंत बोलून दाखवली जाते धावपळीच्या या जीवन व्यवस्थित एकमेकांना भेटण्यासाठी सुद्धा वेळ नसल्याचे बोलले जाते त्याचबरोबर या जागतिकीकरणाचा परिणाम नातेसंबंधावर ही मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते.

जागतिकीकरणाच्या व्याख्या

1) जागतिकीकरण म्हणजे जगातल्या वेगवेगळया मानवी संस्कृतींनी एकमेकाशी संवाद करणे एकमेकांना भेटणे त्यांच्यात काही व्यवहार होणे म्हणजेच जागतिकीकरण होय.

2)ज्या ठिकाणी स्वस्त आणि रास्त कच्चा माल आणि इतर स्त्रोत्र उपलब्ध असतील अशा जगातील कोणत्याही ठिकाणी उत्पादन घेणे होय.

3) जागतिकीकरण ही प्रक्रिया जगातील मोजक्याच श्रीमंत लोकांची अर्थव्यवस्था बांधण्यात येते चार

4) जागतिकीकरणामुळे वैश्वीकरण करून सामान्य लोकांची जगण्याची दमछाक करणे होय.

5) जगातील कोणत्याही कानाकोपऱ्यापर्यंत वस्तू आणि सेवा पुरविणे व संपूर्ण जग हीच बाजारपेठ असणे भांडवलाच्या चौफेर विकासासाठी वाटा मोकळया करणे आणि कायद्याचे अडथळे दूर करणे म्हणजेच जागतिकीकरण होय.

6) जगाच्या विविध भागात भौगोलिक क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांमध्ये वाढते सामाजिक आर्थिक औद्योगिक व्यापारी सांस्कृतिक संबंध दर्शवणारी व्यापक प्रक्रिया म्हणजे जागतिकीकरण होय. .बायलीसआणि स्मिथ

7) जागतिक भांडवलशाही मधून निर्माण झालेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, संस्था यांचा प्रभाव असणारी आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक व्यवस्थेत राष्ट्राची भूमिका मर्यादित करणारी प्रक्रिया म्हणजे जागतिकीकरण होय .

जागतिकीकरणाच्या प्रसाराच्या चर्चा सुरू झाल्या तेव्हा त्याचा कशा कशावर परिणाम होईल याची ही चर्चा सुरू झाली होती. 1990 सालात नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले, मुक्त धोरणाचा पुरस्कार केला, सर्वच क्षेत्रात खुलेपणा आला. त्याचा परिणाम कमी-जास्त प्रमाणात सर्वत्रच दिसू लागला. जागतिकीकरणाने साहित्यावर काय परिणाम झाले याचीही चर्चा सुरू झाली. लेखक व वाचक यांच्या चर्चासत्रातून सर्व साहित्यिक संत ज्ञानेश्वरांपासून ते आजच्या नव लेखक कविता पर्यंत जागतिकीकरणाच्या परिणामाची चर्चा करू लागले. नव साहित्यिक जागतिकीकरणामुळे माणसाची कशी फरफट होते याचे सूक्ष्म चित्रण कथा, कविता, कादंबरी, नाटक, या साहित्य प्रकारात ऊन तो व्यक्त करू लागला लेखनाची बदललेली भाषा शैली नवेनवे शब्दप्रयोग याची तो मांडणी करू लागला, जागतिकीकरणाने सकल जगच एक खेडे बनले आहे .नवनव्या आज्ञा नक्षत्राच्या प्रसारामुळे जीवनाच्या सर्व क्षेत्रावर परिणाम होत आहेत. भारतासारख्या बहुभाषिक प्रदेशात याचा परिणाम पडणे अपरिहार्य आहे जागतिकीकरणामुळे आर्थिक विषमता वाढत गेली व गरीब राष्ट्रीय गरीबच बनत गेली जनतेच्या दारिद्र्यात भर पडली. त्याचबरोबर पर्यावरणाचेही प्रचंड नुकसान झाले गेले. जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात खंबीर उभे राहायचे असेल तर साहित्यही समृद्धता वाढवली पाहिजे. साहित्याचे असे व अनुभव विश्व विस्तारले पाहिजे. मानवतावादी मूल्यं कडे लक्ष दिले पाहिजे. मात्र प्रसारमाध्यमांमुळे मानवी मूल्याचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होताना दिसतो आहे. उपभोगवाद चंगळवाद वाढत गेला आहे. सवंग लोकप्रियतेसाठी लेखन वाढत गेले आहे. चिंतन-मनन या अभावी मोठ्या प्रमाणात लिखाण केले जाऊ लागले .साचेबद्धपणा एकसुरीपणा कंटाळवाणेपणा हा लेखन प्रपंच वाढत गेला. इतर भाषेतील साहित्य व मराठी भाषेतील साहित्य याची तुलना मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली मराठी भाषेतील ज्ञानपीठ पुरस्कार यावरूनच आपल्या भाषेतील साहित्याची स्थिती लक्षात येते असे हे जागतिकीकरणाचे परिणाम मराठी साहित्यावर झालेले दिसून येतात .. मराठी साहित्य क्षेत्रात अजरामर अशा काही साहित्यकृती आहेत त्यामध्ये वि स खांडेकरांची “ययाती” ही कादंबरी लोकविलक्षण प्रतिभाशक्ती मुळे प्रसिद्ध झाली. वि वा शिरवाडकर कथा कुसुमाग्रज यांचे “नटसम्राट” नाटक मराठी वाचकाच्या हृदयाचा ठाव घेते. विंदा करंदीकरांची कविता ऐकून मराठी मन हेलावून जाते त्यांच्या कवितांचा आस्वाद आतून माजी राष्ट्रपती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांना मराठी भाषा शिकावी अशी मनोमन इच्छा झाली. याचा अर्थ असा की उत्कृष्ट साहित्यकृती श्रेष्ठ अभिव्यक्ती साहित्यास गती देते. आज मराठी

साहित्य विश्वात ऐतिहासिक साहित्य आदिवासी साहित्य ग्रामीण साहित्य दलित साहित्य नागर साहित्य स्त्रीवादी साहित्य विज्ञानवादी साहित्य निर्माण झाले आहेत. त्याच बरोबर चरित्रे ,आत्मचरित्रे, कथा ,कविता, कादंबरी, ललित साहित्य समृद्ध स्वरूपात झाले आहे. याचा सार्थ अभिमान आपणा सर्वांनाच आहे. जागतिकीकरणानंतर मराठी साहित्यातील विषय बदलत आहेत. तीव्र संघर्ष जगण्याची धडपड साहित्याचे विषय मांडले जाऊ लागले .नव्या दिशेने मराठी लेखकाचे साहित्यप्रकार वाढू लागले. महाराष्ट्रातील लोकजीवन समृद्ध झालेले चित्रण साहित्यातून येऊ लागले मराठी जीवनाच्या कक्षा साहित्यातून विस्तारल्या गेल्या आहेत. त्याचा प्रत्यय मराठी साहित्यकृतीतून पाहूया मिळतो तहान बारोमास या कादंबऱ्या त्याच बरोबर 'तुर्तास जागतिकीकरनात माझी कविता' हा कवितासंग्रह शिक्षण शेती संगणक जग कुटुंब नातेसंबंध या विषयाची जाणीव मराठी लेखकात येऊ लागली जगाला कवेत घेणारे मराठी साहित्य लेखन होऊ लागले. आत्म प्रकटीकरण आतून वेगवेगळे मराठी साहित्य प्रकार लिहिले जाऊ लागले. ते जागतिकीकरणाच्या परिणामाला सामोरे जाऊन मराठी साहित्य तग धरू लागले जागतिकीकरण आणि मराठी ग्रामीण कादंबरी साहित्य जागतिकीकरणाचा परिणाम आपल्या कृषी जीवनावर पर्यायाने ग्रामीण जीवनावर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाल्याचे दिसून येते. खुले आयात-निर्यात धोरण आणि शेतकऱ्याची पारंपारिक शेती त्यामुळे शेतकऱ्याला उत्पादित मालाची किंमत ही मिळत नाही त्यामुळे तो पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे त्याच बरोबर जागतिकीकरणामुळे सहकार व शिक्षण क्षेत्र ही उद्ध्वस्त झाले आहे. उच्च शिक्षण खेड्यात आले पदवीधर झालेली मुले नोकरीसाठी शहराकडे शिरू लागली मात्र जागतिकीकरणामुळे ोकऱ्या मिळणे दुरापास्तच झाले जागतिकीकरणामुळे शहरात आर्थिक गुन्हेगारी वाढली त्याचबरोबर जागतिकीकरणाचा प्रभाव मराठी साहित्यावरही पडला आहे साहित्य व समाज यांचा सहसंबंध आहे जे समाजात निर्माण होते तेच साहित्यात निर्माण होते म्हणजेच साहित्य हा समाजाचा आरसा असतो साहित्यही समाजाभिमुख अनुभवातून निर्माण होते.1990 नंतरच्या काळात मराठी साहित्य जे निर्माण झाले ते जागतिकीकरणाच्या प्रभाव आतूनच झाले आहे विशेषता ग्रामीण साहित्याचा विचार येथे करणे गरजेचे आहे. जागतिकीकरणाने माणसाचा चेहरा हरवला आहे याविषयी रंगनाथ पठारे म्हणतात, 'जागतिकीकरणाचा आजचा चेहरा मानवी आहे यात देवाण-घेवाण होत नाही ताकद वान धनदांडगे देखील ते बाकीच्यांनी घ्यायचं त्यांच्या तालावर नाचायचं जग म्हणतील तोवर जगायचं त्यांना तुम्ही उपभोगाचे राहिला नाही तर मरायचं दुनियेच्या प्रगतीसाठी गरिबांनी तेवढा त्याग केला पाहिजे खाजगीकरण व उदारीकरण या अशा जागतिकीकरणाच्या सोबतच या भिन्न गोष्टी आहेत .गरीब देशांनी आपल्या सामाजिक व्यवस्था धनदांडग्यांच्या साठी खुल्या करायच्या त्यांनी आपल्या देशात काय व कसं जगायचं कायदा व न्याय व्यवस्था कशी ठेवायची हे सुद्धा हे धनदांडगे ठरवणार यावरून जागतिकीकरणाचा परिणाम किती भयानक आहे याची कल्पना आपणास येते.'

जागतिकीकरण आणि मराठी ग्रामीण कादंबरी

जागतिकीकरणाने निर्माण झालेल्या नव्या जीवन जाणिवा मराठी ग्रामीण कादंबरीकारांनी अचूकपणे टिपल्या आहेत विशेषतः हा परिणाम ग्रामीण भागात जाणवतो जागतिकीकरणाने कृषी क्षेत्रावर गंभीर असा परिणाम झाला ग्रामीण भागातला शेतकरी उध्वस्त झाला 1990 नंतरच्या काळात शेतकऱ्यांनी ज्या आत्महत्या केल्या त्यातून परिणामी भयानकता लक्षात येते बदलत्या आर्थिक धोरणाने शेतकऱ्याच्या समोरील समस्या वाढल्या होत्या सरकारी कर्जबाजारीपणा यांनी ग्रामीण भागातील शेतकरी ग्रासला होता याचे सर्व चित्रण हाल्या हाल्या दुधू दे 1985 या कादंबरीत बाबाराव मुसळे यांनी रेखाटले आहे.यावेळी जागतिकीकरण म्हणजेच खुली आर्थिक धोरण भारताने स्वीकारले नव्हते परंतु त्याचा विचार सुरू झाला होता रवींद्र शोभणे यांनी 'कोंडी' (1992) मधून शेतकऱ्याच्या शोषणाची मुळे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा त्यांचा प्रयत्न व्यक्तिगत अनुभवातून असला तरी जागतिकीकरणाची ती आगाऊ सूचना होती असेच म्हणावे लागेल. जागतिकीकरणात स्वीकारलेल्या खुल्या आर्थिक दुकानाचा शेती जीवनावर कसा परिणाम झाला याचे वास्तवदर्शी चित्रण सदानंद देशमुख यांच्या बारोमास या कादंबरीत पाहावयास

मिळते शेती वर जीवापाड प्रेम करणारा शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो त्याच्यात उदासीनता कशी येते नव्या जुन्या पिढीचा संघर्ष का सुरू होतो यासारख्या अनेक प्रश्नांना देशमुख यांनी वाचा फोडली आहे. नव्या अर्थव्यवस्थेने ग्रामीण भागावर झालेल्या बदलाचे चित्र मराठी कादंबरी मध्ये मोठ्या प्रमाणात पाहावयास मिळते घसरलेली गावे वाढलेली महागाई शासनाची उदासीनता खते व बियाणे यांच्या किमती भयानक दारिद्र्य नव्या पिढीतील चंगळवाद या सर्वांचा वेध मराठी ग्रामीण कादंबरीतून घेऊन शेतकऱ्याचे दुःख मांडले आहे. सदानंद देशमुख यांच्या तहान कादंबरीतून जागतिकीकरणामुळे खुल्या अर्थव्यवस्थेचा म्हणजेच मुक्त बाजारपेठेचा शेती व शेतकऱ्यावर झालेला परिणाम चित्रित केला आहे.' पाडा' या अशोक कोळी यांच्या कादंबरीतून ही त्याचा वेध घेतला आहे. त्याचबरोबर 'अंधार इथला संपत नाही' या भालचंद्र देशपांडे यांच्या कादंबरी मधुन जागतिकीकरणाच्या बदलाचा वेध घेतला आहे. भीमराव वाघचौरे यांच्या गराडा या कादंबरीतून जागतिकीकरणामुळे शेतकऱ्याची दिवसेंदिवस होणारी हालअपेष्टा व सतत तोट्यात व दुःखात दिवस काढणे याचे चित्रण या कादंबरीतून केले आहे याशिवाय ज्ञानेश्वर लेंडवे यांची काळीज घात, मोहन पाटील यांची साखर फेरा, प्रकाश देशपांडे यांची बारदाना, माधव कोंडविलकर यांची डाळं, बाबाराव मुसळे यांची वारूळ, राजन गवस यांची तणकट, गणेश आवटे यांची भिरूड, भारत काळे यांची ऐसे कुणयी भूपाळी, सतीश यादव यांची बळ, शेषराव मोहिते यांची असं जगणं तोलाचं, त्याचबरोबर विश्वास पाटील यांची झाडाझडती,एस ई झेड ,पांगिरा या कादंबऱ्या आहेत.सरदार जाधव यांची कोयता व योगीराज वाघमारे यांची धुराळा, महादेव मोरे यांची झोंबड,वासुदेव मुलाटे यांची विष वृक्षाच्या मुळया इत्यादी सर्व कादंबऱ्यांतून ग्रामीण भागातला शेतकरी जागतिकीकरणाचा बळी ठरल्याचे चित्रण आलेले आहे.

जागतिकीकरण आणि मराठी ग्रामीण कथा

जागतिकीकरणामुळे मराठी माणसाचे जीवन अंतर्बाह्य ढवळून निघाले आहे त्याने अनेक स्थित्यंतरे मराठी साहित्यात घडून आले माणसाचे जीवन अतिशय गुंतागुंतीचे झाले आहे त्यामुळे नव्या जाणिवा निर्माण होऊन जगण्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत मराठी साहित्य नवा चेहरा नवे तंत्रज्ञ घेऊन मराठी कथा आहे जागतिकीकरण आर मध्ये बदलत गेल्याचे दिसून येते जागतिकीकरणाच्या १९९० नंतरच्या काळात अनेक मराठी कथाकार आपले साहित्य लिहून लागले त्यामध्ये प्रामुख्याने भास्कर चंदनशिव, द.ता. भोसले, रा रं बोराडे, आनंद यादव, नागनाथ कोत्तापल्ले, बाबाराव मुसळे, सदानंद देशमुख, आसाराम लोमटे, प्रतिमा इंगोले, सतीश आळतेकर, आदी नव लेखकांनी ग्रामीण भागातील वास्तव समाजजीवनाचा वेद आपल्या कथांतून घेतला आहे. भास्कर चंदनशिव यांच्या "मरणकळा, जांभळढव्ह, नवी वारुळे, अंगार माती" या कथासंग्रहातील कथा तून कृषी जीवनातील जागतिकीकरणामुळे झालेला बदल रेखाटून तेथील शेतकरी कसा हतबल झाला आहे याचे चित्र वास्तव पूर्ण चित्रण रेखाटले आहे. माणसाच्या मनात शिरलेला स्वार्थीपणा त्यामुळे माणसाचे जगणेच मुश्कील झाले आहे याचे ही चित्रण रेखाटले आहे. सदानंद देशमुख यांनी " लचांड आणि उठावं"या कथासंग्रहातून ग्रामीण जीवनाच्या बदलाचा वेध घेतला आहे.श्रीराम गुंदेकर यांनी ही 'उचल' या कथासंग्रहातून जागतिकीकरणामुळे आलेली हतबलता कथासंग्रहातून रेखाटली आहे. त्याच बरोबर आसाराम लोमटे यांनी 'इडा पिडा टळू' या कथासंग्रहातून ग्रामीण जीवनातील बदलत्या वास्तव जीवनाचे आणि ग्रामीण मानसिकतेचे दर्शन घडविले आहे. राजेंद्र गहाळ यांचा 'कोंडी' व सतीश तराळ यांचा 'लढा' ,गणू शिंदे यांचा 'चक्रव्हूव', विजय चव्हाण यांचा खान, आनंद कदम यांचे 'सोयरीक आणि आडतास' व राम वाघचौरे यांचा 'डोन्ट वरी' इत्यादी कथासंग्रहातून बदलत्या ग्रामीण जीवनाच्या स्थितीचे दर्शन घडविले आहे.

जागतिकीकरण आणि मराठी ग्रामीण कविता

जागतिकीकरणाने गावाचा विकास झाला असे वरवर दिसत असले तरी ते खरे नाही गावे व सांड बनली हेच वास्तव आहे गावगाड्याचे स्वरूप बदलत जाऊन स्वावलंबी असला असलेली गावे परावलंबी बनली गरीब माणसाचे जीवन जगणे मुश्कील झाले ग्राम व्यवस्थेला तडे जाऊन आलुतेदार यांनी बलुतेदारी संपुष्टात आली जागतिकीकरणाने खेड्यातील नात्याचा जिव्हाळा संपून गेला शेतीवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या शेतकऱ्याचा मुलगा शेती विकायला सांगू

लागला आलेल्या पैशातून चैन बाजी करू लागला, मोबाईल शॉपी काढू लागला, तंबाखूची टपरी टाकून लागला, किंवा रस्त्याच्या कडेला ढाबा टाकून त्याचा विपरीत उपयोग करू लागला. हे सर्व जागतिकीकरणाच्या प्रभावातूनच घडू लागले होते. या सर्वांचा वेध ग्रामीण कवींनी आपल्या कवितेतून शब्दबद्ध केला आहे. इंद्रजीत भालेराव यांनी "टाहो" या कवितासंग्रहातून जागतिकीकरणाचा वेध घेतला आहे. ते म्हणतात,

"जागतिकीकरणाचा एड्रीन डबा
कुणी धुतला माझा निर्मळ गंगेत
निरागस विहार करणाऱ्या नौकात
कुणी आणून उतला अचानक आकांत" (टाहो-कविता)

बदलत्या व्यवस्थेलाच इंद्रजीत भालेराव प्रश्न विचारतात जागतिकीकरणाचा विषारी डबा कोणी आणला आहे. देशात अनेक समस्या असताना गरिबासाठी नसलेल्या जागतिकीकरणाने अनेक समस्या निर्माण केल्या आहेत.

जागतिकीकरणामुळे गावाची होणारी वाताहात सदानंद देशमुख यांनी 'गावकळा' या या काव्यसंग्रहातून मांडली आहे .जागतिकीकरणाने गावापर्यंत पोहोचलेली मीडिया यासारखी साधने त्यातील मनोरंजनाने तरुण-तरुणींचा वर्ग शेती कामाकडे कसा दुर्लक्ष करतो आहे याचे चित्रण केले आहे जागतिकरणा विषयीची समस्या सामान्य माणसाचे अज्ञान या कविता संग्रहातून चित्रित केले आहे. परीक्षेच्या संदर्भातील गैरवर्तन पुढील कवितेतून टिपले आहे.

" हा गेट करार म्हणजे काय आस्ते बाबा?
अन जागतिकीकरणाचं वार कसं आस्ते?
कसा वास येतो त्या वाऱ्याले
यल्डाखालच्या पांदी सारखा
का कणग्यात चुडी लागल्या आंबूस गव्हासारखा?" (गावकळा-कविता)

जागतिकीकरणाचे कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्याचे दुःख भगवान ठग यांनी अन्नदात्याची धुळाक्षरे या कविता संग्रहातून अभंग शैलीच्या माध्यमातून मांडले आहेत तसेच प्रकाश होळकर यांनी कोरडे नक्षत्र या कविता संग्रहातून शेतकऱ्याच्या दुःखाची परवड सांगितली आहे.

पेरले ते उगवेल का? ,अन्न पिकल ते विकल का?,सांगता येत नाही. ('कोरडे नक्षत्र'कविता)

सामान्य माणसाच्या जीवनातील निश्चितता येथे स्पष्ट होत आहे. कवीने पिकण्या आणि विकण्याच्या मूळ प्रश्नाला हात घातला आहे. लक्ष्मण महाडिक यांनी 'समृद्ध पाऊल' या कवितेतून सामान्य माणसाची होत असलेली परवड मांडली आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रभावाखाली तुकाराम धोंडे ,एकनाथ पाटील, बालाजी इंगळे ,शंकर दिघे ,कल्पना दुधाळ, नारायण सुमंत, सुरेश शिंदे ,श्रीकांत देशमुख ,उत्तम कांबळे इत्यादी नव कवींनी आपल्या कविता निर्माण करून शेतकऱ्याच्या एकंदरीत ग्रामीण जीवनाच्या वास्तव परिस्थितीचे दर्शन घडविले आहे.

संदर्भ:

१) वासुदेव मुलाटे: ग्रामीण साहित्य चिंतन आणि चर्चा ,स्वरूप प्रकाशन औरंगाबाद प्रथम आवृत्ती 2002
२) रंगनाथ पठारे: जागतिकीकरण आणि देशीवाद, लोकवांगमय गृह मुंबई 2009
३) नलिनी पंडित: जागतिकीकरण आणि भारत, लोकवांगमय गृह मुंबई 2004
४) भालचंद्र नेमाडे: साहित्य, संस्कृती आणि जागतिकीकरण, लोकवांगमय गृह मुंबई 2009

प्रा.डॉ. जनार्धन परकाळे

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

१९७० च्या दशकातील भारताचे परराष्ट्र धोरण

प्रा. सुहास रामचंद्र नलावडे
इतिहास विभाग प्रमुख, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील महाविद्यालय नातेपुते

प्रस्तावना

भारताचे परराष्ट्रीय धोरण : स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाची स्थूल जडणघडण स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली. अखिल भारतीय काँग्रेसने आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांसंबंधी वेळोवेळी स्वीकारलेल्या धोरणातूनच ते उत्क्रांत झाल्याचे दिसून येते. हे बऱ्याच अंशी त्याच्या राजकीय अनुभवातून साकारले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीच काँग्रेसने आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांसंबंधी अनेक ठराव संमत केलेले होते. ब्रह्मदेश इंग्रजांनी जिंकल्याबद्दल असंतोष व्यक्त करण्यात आला (१८८५). ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावादी कारवायांसाठी भारतास तळ म्हणून वापरण्यास हरकत घेण्यात आली (१८९२). काँग्रेसचे हे साम्राज्यविरोधी धोरण पहिल्या महायुद्धानंतर अधिकच स्पष्ट झाले. इंग्रजांच्या खलीफाविरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून भारतात खिलाफत चळवळ सुरू करण्यात आली. १९२० मध्ये आयरिस लोकांच्या स्वातंत्र्यलढ्यास पाठिंबा देण्यात आला, तर १९२८ मध्ये ईजिप्त, सिंरिया, पॅलेस्टाईन आणि इराक यांचे त्यांच्या साम्राज्यविरोधी संघर्षाबद्दल अभिनंदन करण्यात आले. भारताचे हे धोरण स्वातंत्र्यानंतरही नेटाने चालविले गेले. भारत स्वतः ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा बळी असल्यामुळे यासंबंधी त्याच्या नेत्यांस वाटणारी तळमळ स्वाभाविक आहे. भारतीय नेत्यांचा साम्राज्यवादाचा अनुभव हा पाश्चिमात्य देशांपुरताच मर्यादित असल्याने साम्राज्यवादाचा संबंध त्यांनी फक्त पाश्चात्त्य देशांशी लावणे समजू शकते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्रांत ठराव संमत करून घेऊन, इंडोनेशिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को, अल्जीरिया इ. आफ्रिकीआशियाई देशांच्या मुक्तीसाठी वातावरण तयार करण्यात भारताने उल्लेखनीय कामगिरी बजाविली. या भूमिकेतूनच १९५६ मध्ये इंग्लंड व फ्रान्स यांनी सुएझ कालव्यासंबंधी केलेल्या सैनिकी हस्तक्षेपास भारताने विरोध केला.

उद्देश:- भारताचे परराष्ट्रीय धोरण व पंचसूत्रेचा अभ्यास करणे.

वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळावे, असा एक ठराव संयुक्त राष्ट्राने करून त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, हे पाहण्यासाठी एक २४ सदस्यांची समिती नेमली आहे. भारत हा या समितीचा प्रमुख सदस्य आहे. वसाहतवादाप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिकेतील वंशभेदाविरुद्ध जागतिक लोकमत संघटित करण्यासाठी भारताने खूप प्रयत्न केले आहेत. भारतीय राज्यव्यवस्थेत परराष्ट्रीय धोरणाची जबाबदारी ही परराष्ट्रमंत्र्याची असते. धोरणासाठी तो लोकसभेस जबाबदार असतो. नेहरूंचे चरित्रकार मायकेल ब्रेशर यांच्या मते नेहरू हे भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाचे शिल्पकार होत. इतकेच नव्हे, तर परराष्ट्रीय धोरण ही त्यांची मक्तेदारी होती. एका अर्थाने हे खरे आहे. काँग्रेसने १९२८ मध्ये परराष्ट्रीय धोरणासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केल्यापासून त्याची धुरा पंडितजी अखेरपर्यंत सांभाळीत होते. परराष्ट्रीय धोरणासाठी कॅबिनेटची एक समिती असली, तरीही नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील इतर कोणीही परराष्ट्रीय धोरणात फारसा रस घेतला नाही.

पाकिस्तानसंबंधीच्या धोरणाविषयी मात्र कधीकधी मतभेद व्यक्त होत. लोकसभेतही, हंगेरीतील पेचप्रसंग, तिबेटचे चीनने केलेले सामीलीकरण सोडता, १९५९ पर्यंत नेहरूंच्या धोरणावर फारशी टीका झालेली दिसत नाही. देशातील राजकीय पक्ष व एकंदर लोकमत यांच्यातही नेहरूंच्या धोरणाविषयी सर्वसाधारण मतैक्य होते. लोकसभा, पक्ष, उच्च नोकरवर्ग, लष्करी अधिकारी या सर्वांनी नेहरूंच्याच दृष्टीतून परराष्ट्रीय धोरणाकडे पाहिले; तथापि स्वतः नेहरूंनी मात्र यासंबंधी सर्व श्रेय स्वतःकडे घेण्याचे नाकारले. आपल्या जागी दुसऱ्या कोणीही हेच धोरण स्वीकारले असते, कारण ते भारताच्या परिस्थितीनेच ठरले आहे, असे ते म्हणत. भारतातील अभिजनवर्गाचे व नेहरूंचे जीवनानुभव आणि त्यावरील वैचारिक प्रभाव हे सारखेच असल्यामुळे नेहरू परराष्ट्रीय धोरणापुरते तरी भारतीय विचारांचे प्रतिनिधित्व करीत होते, असे म्हणता येईल. भारताची भौगोलिक स्थिती, रशिया व चीनशी असलेले निकटत्व लक्षात घेता, शीतयुद्धाच्या संदर्भात त्याने स्वीकारलेली तटस्थतेची भूमिका स्वाभाविक वाटते. एकीकडे भारताचे आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आणि समताधिष्ठित स्थापन करण्यासाठी रशियाच्या आदर्शाविषयी वाटणारे आकर्षण, तर दुसरीकडे पाश्चात्य उदारमतवादाच्या भारतीय नेतृत्वावरील पगडा, या दोन ध्रुवांतून मार्ग काढण्यासाठीही अलिप्ततावादी धोरण भारतास स्वीकारार्ह वाटले असावे.

भारतातील लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्या, त्यांच्या धार्मिक निष्ठा आणि खनिज तेलाविषयी भारताचे परावलंबित्व लक्षात घेता, मध्य आशियात भारताने अरब देशांस अनुकूल धोरण स्वीकारले यात नवल नाही. धोरणाचे समर्थन करण्यासाठी कितीही मोठमोठी तत्त्वे सांगितली, तरी अखेरीस देशहिताच्या दृष्टीतूनच परराष्ट्रीय धोरण ठरवावे लागते, असे नेहरूंनी म्हटले आहे आणि हे हित कोणते हे ठरविण्याबाबत नेहरूंचे नेतृत्व सर्वांनी मान्य केल्याचे दिसते. नेहरूंनंतरच्या कालखंडात वेगळा परराष्ट्रमंत्री जरी नेमण्यात आला, तरीही या क्षेत्रात तत्कालीन पंतप्रधानाचा प्रभाव टिकून राहिला. ताश्कंद करार वा सिमला करार यांसारख्या महत्त्वाच्या वाटाघाटी तत्कालीन पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालीच झाल्या. परराष्ट्रीय धोरणाची समीक्षा करण्यात मंत्रिमंडळाने आणि संसदेने या काळात जास्त भाग घेतला. महावीर त्यागी यांनी १९६६ मध्ये, तर अशोक मेहता यांनी १९६८ मध्ये आपला विरोध व्यक्त करण्याकरिता मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. मात्र १९७७ च्या सत्तांतरानंतर परराष्ट्रमंत्र्यानेही थोडी जास्त जबाबदारी उचलल्याचे दिसते. परराष्ट्रीय धोरणासंबंधी भारताने सतत अलिप्ततावादाचा पुरस्कारकेला आहे. १९७७ नंतर सत्तारूढ झालेल्या जनता पक्षानेही खरी खुरी अल्लिप्तता हेच आपले धोरण राहील, असे जाहीर केले आहे. ढोबळमानाने अलिप्तता याचा अर्थ कोणत्याही सैनिकी गटात सामील न होता, प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे, असा केला जातो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या आणि बड्या राष्ट्रांनी स्थापिलेल्या सैनिकी युतींच्या संदर्भात हे धोरण ठरविले गेले होते. एखाद्या गटात शिरल्यामुळे दुसऱ्या गटाचा रोष ओढवून आपली सुरक्षितता धोक्यात येते; दोन सैनिकी गटांच्या स्पर्धेतून युद्धाचा संभव वाढतो, तेव्हा अलिप्त राहून दोन्ही गटांत सामंजस्य घडवून आणून शांतता प्रस्थापित करणे हे अधिक श्रेयस्कर, असे नेहरूंना वाटत होते. सुरक्षेतून शांतता स्थापन करण्याऐवजी शांततामय सहजीवनातून सुरक्षितता साध्य करण्यावर त्यांचा भर होता. तीव्र शीतयुद्धाच्या काळात अनेक प्रसंगी (उदा., कोरियन

युद्ध, इंडोचायना संघर्ष, सुएझचा पेचप्रसंग) भारताने दोन्ही पक्षांत समझोता घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. म्हणून भारताची तटस्थता ही पारंपरिक तटस्थतेप्रमाणे नकारात्मक नाही, असे नेहरू म्हणत. हे धोरण अंमलात आणण्यासाठी अलिप्त राष्ट्रांच्या परिषदा घेऊन त्यांतून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व संयुक्त राष्ट्रांत एक तिसरी शक्ती निर्माण करण्यात भारताचा हातभार लागला. अशा परिषदा बेलग्रेड (१९६१), कैरो (१९६४), लूसाका (१९७०), अल्जिअर्स (१९७३) आणि कोलंबो (१९७६) येथे भरविण्यात आल्या. आपल्या धोरणासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा वापर करण्यावर या राष्ट्रांनी भर दिला. नवजात राष्ट्रांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी संयुक्त राष्ट्राने साह्य करावे, असा आग्रह भारताने धरला. अंकटॅड (UNCTAD), आशियाई विकास बँक यांसारख्या संस्था स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. या नवोदित राष्ट्रांच्या कारभारात बड्या राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपास वाव असू नये, यासाठी संयुक्त राष्ट्राचे शांतिसैन्य उभारण्यास भारताने इतर अलिप्त राष्ट्रांबरोबर मदत केली. तथापि संयुक्त राष्ट्रासंबंधीचे भारताचे धोरण आदर्शवादी कल्पनांवर आधारलेले नसून राष्ट्रहिताच्या पायावरच उभारलेले आहे, हे विसरून चालणार नाही.काश्मीरसंबंधी कडू अनुभव आल्यावर भारताने आपले द्विराष्ट्रीय प्रश्न स्वतः होऊन संयुक्त राष्ट्रांकडे नेले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर स्वतःच्या द्विराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या हस्तक्षेपास विरोध दर्शविला आहे. स्वहितास हानिकारक वाटणारे संयुक्त राष्ट्रांचे ठराव (उदा., आण्विक प्रसारबंदी ठराव) फेटाळून लावण्यात संकोच केला नाही. आपल्या धोरणाचे एक साधन या दृष्टीनेच भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडे पाहिले आहे. कष्टाने मिळविलेल्या स्वातंत्र्याचा गटस्थ होण्याने संकोच होतो, असे भारताप्रमाणे अनेक आफ्रिकी-आशियाई देशांना वाटल्यामुळे त्यांनीही या धोरणाचा स्वीकार केला. खरे अलिप्त राष्ट्र कोणते हे ठरविण्यासाठी अलिप्त परिषदांनी एक पंचसूत्री स्वीकारली आहे

पंचसूत्री

शांततामय सहजीवनाच्या तत्त्वावर आधारलेले स्वतंत्र धोरण आखणारे,

वसाहतींच्या मुक्तिसंग्रामास पाठिंबा देणारे,

कोणत्याही शीतयुद्धाशी संबंधित सैनिकी गटाचा सदस्य नसणारे,

पूर्व-पश्चिम संघर्षास चालना देणारा कोणताही लष्करी करार बड्या राष्ट्रांशी न करणारे व

स्वतःच्या भूप्रदेशावर परदेशास सैनिकी तळ उभारू न देणारे.

अशा राष्ट्रास या परिषदांत सामील करून घेण्यात येते. सर्वच बाबतींत हे नियम काटेकोरपणे पाळले जातात असे नाही. अलिप्ततेच्या या संकल्पनेविषयी अनेक प्रश्न निर्माण होतात. शीतयुद्धात गुंतलेल्या दोन गटांतील ताण शिथिल झाल्यावर अलिप्ततेचे धोरण प्रस्तुत राहील काय शीतयुद्धासारख्या इतर तशाच स्वरूपाच्या संघर्षात (उदा., रशिया-चीन संघर्षात) हे धोरण स्वीकारता येऊ शकेल काय? अशा संघर्षात या देशांनी कलह-निराकरणावर भर द्यावा की, त्यातील न्याय्य बाजूस पाठिंबा द्यावा? एखादे अलिप्त राष्ट्र स्वतःच जेव्हा सैनिकी संघर्षात गुंतते, तेव्हा इतर अलिप्त देशांची भूमिका काय असावी, इत्यादींवरून भारताने अलिप्तता हे लक्ष्य नसून ते गाठण्याचे एक साधन आहे असे मानल्याचे दिसते.

सारांश

राष्ट्रहितास आवश्यक वाटेल तेव्हा त्यास मुरड घातली आहे. उदा., १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर भारताने अमेरिकेकडून लष्करी मदत घेतली; तसेच चीनमधील गुप्तवार्ता कळाव्यात, म्हणून भारतीय प्रदेशात आण्विक यंत्र ठेवण्याची त्यास परवानगी दिली. १९७१ मध्ये संभाव्य भारत-पाक युद्धात चीनने हस्तक्षेप करू नये, या उद्देशाने रशियाशी करार केला. कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा त्याच्या संरक्षणव्यवस्थेशी निकटचा संबंध असतो. आपणास कोणत्या देशाकडून संभाव्य धोका आहे, हे हेरून त्यावर राजनैतिक आणि सैनिकी अशा दोन्ही प्रकारांची उपाययोजना करणे आवश्यक असते. या दोहोंचे प्रमाण अर्थातच त्या देशातील तांत्रिक, औद्योगिक प्रगतीवर, लोकसंख्येवर आणि राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचा विनियोग करण्यासाठी शासनाने कोणता अग्रक्रम ठरविला आहे, त्यावर अवलंबून राहील.भारतीय नेत्यांना सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानकडून आपणास सर्वात जास्त धोका आहे, असे वाटत होते. या काळातील संरक्षणव्यवस्था या दृष्टीतूनच उभी करण्यात आली होती. पाकिस्तानने अमेरिकेशी युती केल्यावरही, स्वसामर्थ्याच्या बळावर त्याचे संभाव्य आक्रमण परतवून लावू शकू, असा विश्वास भारतास वाटत होता. भारताची संरक्षक दले शस्त्रास्त्रांसाठी इंग्लंडवर अवलंबून होती, त्यामुळे पाश्चात्त्य देशांशी दुरावा निर्माण झाला, तरी भारताने त्यांच्याशी आपले संबंध तोडले नाहीत. चीनमधील राजकीय अस्थैर्य आणि हिमालयाचा अडसर लक्षात घेता, चीनकडून आपणास धोका आहे; असे भारतीय नेत्यांस वाटले नाही. नेपाळ, भूतान व सिक्कीम यांच्याशी जवळचे संबंध स्थापन करून व चीनशी मित्रसंबंध जोडून त्या भागाची सुरक्षितता वाढविता येईल, असेही त्यांना वाटले. त्यामुळे या काळात चीनमधील साम्यवादी शासनास राजनैतिक मान्यता देऊन, संयुक्त राष्ट्रांत साम्यवादी चीनला प्रवेश मिळावा, म्हणून भारताने प्रयत्न करून, चीन-अमेरिका (कोरियामधील) युद्धात मध्यस्थी करून चीनशी स्नेहसंबंध स्थापन केले. १९५४ मध्ये चीनशी झालेल्या करारातील पंचशील तत्त्वांमुळे भारतास आणखीनच सुरक्षित वाटले. चीनच्या १९६२ च्या आक्रमणानंतर याबाबत भारतीय नेत्यांचे चीनसंबंधीचे मूल्यनिर्धारण कसे चुकीचे होते, हे दृष्टोत्पत्तीस आले. त्यानंतर पाकिस्तान व चीन या दोन्हींपासून संरक्षण करण्याची आवश्यकता भारतास निर्माण झाली. चीनने अणुस्फोट केल्यानंतर ही जाणीव अधिकच तीव्र झाली.

रशिया-चीन दुफळी लक्षात घेता १९६२ नंतर भारताचे परराष्ट्रीय धोरण रशियाकडे जास्त झुकू लागल्याचे दिसते. भारताने रशियाकडून महत्त्वाच्या क्षेत्रांत लष्करी व आर्थिक साह्य मिळविले. शस्त्रास्त्रांच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठीही रशियाची मदत मिळाली. अणुतंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी मात्र भारताने कॅनडा व अमेरिका यांकडून साह्य मिळविले. या क्षेत्रातही स्वावलंबी होण्यासाठी १९७४ मध्ये भारताने अणुस्फोट केला. तथापि अद्यापही युरेनियमसाठी भारत अमेरिकेवर अवलंबून आहे. आर्थिक आणि लष्करी क्षेत्रांतील दोन्ही बड्या राष्ट्रांच्या साह्यामुळे भारताच्या अलिप्ततावादास एक नवी दिशा प्राप्त झाली. भारत-पाक १९७१ च्या युद्धानंतर भारताने चीन व पाकिस्तान यांच्याशी सर्वसामान्य संबंध स्थापन करून, परराष्ट्र धोरणावर व संरक्षणव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे; तसेच शेजारच्या सर्व राष्ट्रांसंबंधी असलेले प्रश्न सोडविण्याचे आवर्जून प्रयत्न केले आहेत. १९७७ नंतर या प्रक्रियेस अधिकच

गती प्राप्त झाली आहे. शेजारच्या सर्व राष्ट्रांशी स्नेहसंबंध निर्माण केल्यानेच अलिप्त व स्वतंत्र धोरण आखता येते, असे हे धोरण सुचविते.

संदर्भ :

1. Barnds, W. J. India, Pakistan and the Great Powers, New York, 1972.
2. Choudhury, G. W. India, Pakistan, Bangladesh and the Major Powers, London, 1975. 3. Jackson, Robert, South Asian Crisis : India, Pakistan and Bangladesh, New Delhi, 1978.
3. Kaushik, D. Soviet Relations with India and Pakistan, London, 1971.
4. Madan, Gopal, India, as a World Power : Aspects of Foreign Policy, Delhi, 1972. 6. Misra, K. P. Ed. Foreign Policy of India : a Book of Readings. New Delhi, 1977. 7. Nanda, B.R. Ed. Indian Foreign Policy : the Nehru Years, Delhi, 1976

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

प्रसार:माध्यम आणि शाश्वत विकास

डॉ. बालाजी लक्ष्मणराव शिंदे
वृत्तपत्रविद्या विभागप्रमुख पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालय राणीसावरगाव ता. गंगाखेड जि. परभणी.
E -mail- patilbalaji53@gmail.com

प्रसार-माध्यमात शाश्वत विकास पत्रकारिता हा संज्ञापनाचाच एक भाग आहे. प्रसार-माध्यमात होणाऱ्या विकास पत्रकारांची सुरवात वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सुरू होते. देशात पहिले वृत्तपत्र बेंगाल गॅझेट,सुधारक,केसरी आदि वृत्तपत्रे सुरू झाली. हा शाश्वत विकास पत्रकारितेचा प्रवाह आजही व्यावसायिक वातावरणात पाय रोऊन बसले आहेत. देशातील माध्यमांत भाषिक लिखाण, भाषा, स्थानिक मुद्द्यांवर चर्चा, वृत्तपत्रात छापून आलेल्या शब्दांची विश्वासार्हता,राजकीय स्वातंत्र्य आणि देशात वृत्तपत्र सृष्टीने केलेले बदल यामुळे नावीन्यपूर्ण माध्यमात बदल झाला. जनमानसातील स्थान वृत्तपत्रासंदर्भात आजही कायम आहे. मुद्रित माध्यमांबरोबर दूरचित्रवाणीवरील पत्रकारितेनेही गेल्या दशकात चांगलाच जम बसविला. ग्रामीण भागात दूरचित्रवाणीचा तर शहरी भागात वृत्तपत्रांचा प्रसार झाल। पाहिजे ती माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना ऐकायला, वाचायला मिळत गेली. नागरिकांची तहान भागत गेली. म्हणजेच शाश्वत विकास पत्रकारितेच्या चर्चेत दोन्ही माध्यमांचा समावेश आहे. शाश्वत विकासाविषयक कल्पना, योजना माध्यमांची कार्यपद्धत बदलली तरी असली तर शाश्वत विकास पत्रकारितेत मोठा बदल झाल्याचं दिसून आला नाही. शाश्वत विकास कोणी दिलेला दान नसून आपल्या स्वत:च्याच कामाची एक पावती असते. संदेश, माहिती समाजापर्यंत पोहचविण्याचे काम म्हणजेच शाश्वत विकास पत्रकारितेचे मुख्य उद्दिष्टे होय. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण प्रक्रिया आणि कामातील व्यक्ती, समाजातील बदल देशासमोर आणण्याचं काम केलं पाहिजेत. लक्ष वेधून घेण्यासाठी एखादा विषय समाजासमोर मांडून आपली राजकीय समाजाची पोळी भासविण्याचा काम करणे म्हणजे शाश्वत विकास नाही. माध्यमांमध्ये वाईट घटना चांगली बातमी आपल्याकडे चौकटीच्या बाहेर पडून शाश्वत विकास पत्रकारिता करता आली पाहिजे. याचा विचार करावा लागतो. शाश्वत विकास करण्यासाठी समाजातील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कृषी आदी बाबींकडे जातीने लक्ष दिले पाहिजेत. विकास आणि शाश्वत यामध्ये मोठा फरक आहे. शाश्वत विकास करण्यासाठी तंत्रज्ञान, औद्योगिकरण, नागरीकरण आदिमध्ये फायदे- तोटे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याची पडताळणी करून पाहावी लागते. शाश्वत विकास पत्रकारिता करणा-याला त्या- त्या विषयाची माहिती जमा करावी लागते. अर्थातच नुसती बातमी माहिती असून चालत नाही

बातमीच्या पाठीमागील बातमी,पाश्र्वभूमी विविध संदर्भ माहिती असणे आवश्यक आहे. या बाबीकडे दुर्लक्ष केले तर शाश्वत विकास पत्रकारितेला पत्रक पत्रकारिता, सरकारी पत्रकारिता' टेबल पत्रकारितेचे रूप येऊ शकते. विकास ही एक सांस्कृतिक प्रक्रिया आहे. शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मतभिन्नता असू शकत नाही.ते समान असत नाही.यात संघर्ष,लढा, आरोप-प्रत्यारोप, मत-मतांतरे अशा घटना घडतच असतात. त्याला शाश्वत विकास म्हणता येणार नाह। माध्यमांत मूलभूत तत्त्वे शाश्वत विकास पत्रकारितेला लागू आहे. माध्यमांची लक्षणे तपशीलवार माहिती, माहितीची खातरजमा, विश्लेषण, मांडणी, टीका, आरोप-प्रत्यारोप ही आहेत. शाश्वत विकास पत्रकारितेत चुकांवर बोट ठेवून चालता येत नाही.त्याला कासवाच्या गतीने चालावे लागते. विकास पत्रकारितेची आवश्यकता शहरी आणि ग्रामीण आहे. ग्रामीण भागातील विकासाचे विविध प्रश्न आहेत. यात शेती, शासन यंत्रणा, सरकारच्या विविध योजना, राजकारण, नवीन उपक्रम यांच्याशी निगडित आहेत तर विकास पत्रकारितेला जोड म्हणून पंचायतराज व्यवस्था, माहितीचा अधिकार, सोशल मिडियाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सोसायटी, ग्रामपंचायत, आरोग्य असून ग्रामीण पत्रकाराशी सरळ संबंध येतो. त्यामुळे त्याला जागरूक राहावे लागते. शाश्वत विकासामध्ये त्रिसूत्री व्यवस्थेचा गाभा आहे. या उद्दिष्टांची पूर्तता आपल्या गावपातळीपर्यंत कशा पध्दतीने होत आहे याचे भान पत्रकाराने ठेवणे आवश्यक आहे. विकास होऊन चालणार नाही तर शाश्वत विकास होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण व शहरी भागामध्ये पत्रकारांना अनेक विषय हाताळता येतील. कोणत्या -कोणत्या विषयाला महत्त्व द्यायला पाहिजे याचे भान पत्रकार, संपादकाला असणे आवश्यक आहे. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात न्यूज एजन्सीचाही खारीचा वाटा असते. यामार्फत ग्रामीण आणि शहरी भागातील समस्या देशापर्यंत पोहोचण्याचं काम करीत असतात. त्यातूनही शाश्वत विकास घडून येतो. त्याचा फायदा माध्यमाला होऊ शकतो. त्यांच्या संपर्कातून विधायक बातम्या मिळू शकतात. नागरी क्षेत्रात विकास पत्रकारितेला सरकारी क्षेत्रातभोवती घुटमळत बसावे लागत नाही. पर्यावरण, कामगार, शहरी समस्या, विज्ञान- तंत्र, न्यायालयीन प्रक्रिया आदी विषय शाश्वत पत्रकारितेमध्ये हाताळण्याची संधी मिळू शकते. आपण विकास पत्रकारितेवरच दैनिक चालविणे सोपे नाही. देशात अनेक दैनिक,साप्ताहिक, शाश्वत विकासाचा मुद्दा घेऊन चालवतात. त्याला प्रतिसादही मिळत गेला. वृत्तसेवा युनिक फीचर्स, चरखा, सर्वोदय, प्रेस सव्हिस आदींचा समावेश आहे. सध्या एकविसाव्या शतकात शाश्वत विकासाच्या बातम्या, कथा, माहिती, प्रकाशन करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. सध्या प्रतिदिन राजकारण, अपघात, खून, दरोडा, बलात्कार, चोरी, फसवा-फसवी, लुबाडणूक, बँक बंद, उद्योग, मानहानी, न्यायालयीन बातम्या, भ्रष्टाचार, बातम्या वाचून वाचक अक्षरशः कंटाळला आहे. वाचकही शाश्वत विकासाच्या बातम्याच्या शोधात आहे. त्यांना नावीन्यपूर्ण आणि विकासाच्या बातम्या वाचायला

आवडत आहेत. वृत्तपत्रे शाश्वत विकासाच्या बातम्यांना जागा, मांडणी, रचना, पुरवण्या, खास पाने देऊन चांगली प्रसिद्धी देण्याचं काम करीत आहेत. या बातम्या कमी असतील मात्र प्रसिद्धी आणि जागा माध्यमात दिली जाते. त्याला प्रतिसाद चांगला मिळत आहे. शाश्वत विकास एक सांस्कृतिक प्रक्रिया आहे. यात अनेक भागात निवड करावी लागते. लोकसहभाग आवश्यक आहे. त्यासाठी विकास पत्रकारितेला महत्त्व प्राप्त झाले.शाश्वत विकास प्रक्रियेमध्ये आधुनिक प्रसार-माध्यमांना महत्त्व देण्यात आले आहे. भारतानी शाश्वत विकासाचे निरनिराळे प्रकार हाती घेण्यात आले आहे. देशात दूरदर्शन, आकाशवाणी माध्यमाने शाश्वत विकासासाठी वापर करण्यात आला आहे. 'साईट खेडा' यासारखे मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. लोक सहभागाशिवाय शाश्वत विकास करणे शक्य नाही. यात स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. यातूनच ग्रामीण भागात शाश्वत विकास होऊ शकतो. या लेखामध्ये शाश्वत विकास ही संकल्पना कशी बदलत गेली. विकास प्रक्रियेत शाश्वत विकासाचे महत्त्व, उद्दिष्टे, कौशल्ये आदींचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे.

संदर्भ सूची

१. जैन रमेश, ग्रामीण पर्यावरण पत्रकारिता, सबलारय पब्लिकेशन जयपूर,आवृत्ती २००५
२. केवळ जे कुमार, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया,जयको-१९७९.
३. धारूरकर वि.ल., विकास संवादाची नवी क्षितिजे, चैतन्य प्रकाशन, औरंगाबाद.
४. दातार सुषमा, संवाद विश्व, संवाद विश्व प्रकाशन, पुणे.
५. www. agencyfagus.com

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR) ISSN – 2347-7075
Peer Reviewed Bi-Monthly Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

वैश्वीकरण और भारतीय समाज

प्रा. रज्जाक शेख
हिंदी विभाग प्रमुख स.म. शंकरराव मोहिते पाटील महाविद्यालय, नातेपुते जि. सोलापूर

वैश्वीकरण का स्थूल अर्थ है संपूर्ण विश्वमें स्थित मानव जाति का अपने क्षेत्र जाति, धर्म, संस्कृति तथा राष्ट्र के सीमित दायरे से निकलकर विश्वमानव के रूप में विस्तार | इस रूप में वैश्वीकरण एक मानवतावादी सामाजिक तथा राजनैतिक चेतना है | अंत: वैश्वीकरण को विश्व वादी भी कहा जा सकता है | भारतीय संस्कृति में 'वसुधैव कुटुंबकम' को एक जीवन आदर्श माना गया है | विभिन्न भेदों को त्याग कर संपूर्ण मनुष्य जाति परस्पर बंधुभाव रखकर सबके साथ अपनी उन्नति के लिए तैयार हो तो विश्व एक परिवार की तरह होगा | वैश्वीकरण के समर्थक भी यही कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति और सूचना क्रांती के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व 1 ग्राम में तब्दील हो गया है | वास्तव में वैश्वीकरण की प्रक्रिया विगत 30 वर्षों से चल रही है 1990 तक भारत में मिश्र अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया गया था | किंतु 1991 के बाद सारे विश्व की अर्थनीति में एल. पी. जी. अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा प्रचलित हुई | आज संपूर्ण आधुनिक समाज भूमंडलीकरण से प्रभावित हुआ हैं | भारत में 1991 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव और अर्थमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरुप वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली | भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु कुछ उपाय अपनाए गए उस समय विश्व में अनेक परिवर्तन हो रहे थे | इन परिवर्तनो से व्यापार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का दौर आरंभ हुआ और संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हुआ | वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व में सभी और से हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप विश्वस्तरीय आर्थिक परिवेश में प्रभावी भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बनना | विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला | वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरन से भारत की अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार हुआ | कुछ लोग इसे जागतिकीकरण कहते हैं तो कुछ लोग भूमंडलीकरण कहते हैं या वैश्वीकरण की संज्ञा देते हैं | जिसका वर्तमान समय में भारतीय समाज पर गहरा असर पाया जाता है | सामान्यत: निम्नलिखित अलग-अलग क्षेत्रों में भारतीय समाज पर इसका प्रभाव पाया जाता है |

१) आर्थिक विषमता में बढ़ोतरी :-

वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज संपूर्ण विश्वस्तर पर एक वैश्वीक समाज की स्थापना हो रही है | वैश्वीकरण में पूँजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है | जिससे पूँजी-पति वर्ग और शोषक वर्ग बनते जा रहे हैं | इससे कुछ लोगों की आय में बेइंतिहा इजाफा हुआ है | जैसे बिल गेट से लेकर अजीम प्रेमीजी तक की बड़ी-बड़ी हस्तियाँ वैश्वीकरण का ही परिणाम है | इससे दूसरे अमीर गरीब के भेद को बढ़ावा मिल रहा है | अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब होता जा रहा है | इस प्रकार का वर्ग भेट स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक होता है | इस प्रकार के वर्ग भेद के कारण संघर्ष भी उत्पन्न हो सकता है | वैश्वीकरण के कारण समाज में ठेकेदारों का एक वर्ग ही सामने आ रहा है | जिसका आघात मजदूरों पर हो रहा है |

२) बेरोजगारी में वृद्धि :-

वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक करण बढ़ रहा है | कारखानो की तादाद दिन—ब दिन बढ़ती जा रही है | बहुत सारे कम माशिनो के सहारे की जा रहे है | इसी कारण काम करने वाले हाथ बेकार रहने लगे हैं | युवा वर्ग में एक प्रकार की निराशा आ रही है | बेकार युवक अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ने लगे हैं | अनेक प्रकार के खून, चोरी, हिंसा ,आंदोलन जैसी घटनाएं हो रही है | आजादी के 70 साल बाद भी देश के 38 से 40 प्रतिषद लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं | रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं से अब भी वे लोग वंचित है | अपनी देश की आंतरिक समस्या से आँख मूँदकर हमने वैश्वीकरण में हिस्सा लिया है | जो अमीरोंको अमीर और गरीबों को गरीब रखने में मशगुल है |

३) कृषिक्षेत्र पर प्रभाव :-

भारत कृषि प्रधान देश है | देश के अधिकांश लोग गांव में रहकर खेती करते हैं | भारत की खेती को हमेशा मौसमकी अनियमितता का शिकार होना पड़ता है | खेती भारत की अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है | आज की वैश्वीकरण की स्पर्धा में टिकणे के लिए आधुनिक पद्धति से खेती करना जरूरी हो गया है | लेकिन भारतीय किसानों को आधुनिक खेती करना संभव नहीं हो रहा है | क्योंकि आधुनिक खेती के लिए कर्ज लेना पड़ता है | जिसे चुकाने के लिए माल का उचित और निश्चित मूल्य नहीं मिल पाता | परिणाम स्वरूप किसानों को आत्महत्या करने सिवा कोई चारा नहीं रहता | गरीब और अनपढ़ किसान पारंपारिक फसल उगाते हैं | आज वैश्विकरण मे अनाज को बाजार में कौड़ीमोल लिया जाता है | बेचारे किसान दिन रात मेहनत मजदूरी करकेभी भुका रहने की नौबत आती है | वह नहीं जानता कि वैश्विकरण क्या है ? औद्योगीकरण के नाम पर किसानों की अच्छी भली खेती कम दाम में खरीद लेने का सिलसिला शुरू हुआ | वर्तमान समय में दिल्ली में हो रहे कृषि विधेयक के खिलाफ किसान आंदोलन से समझ सकते हैं | परिणाम स्वरूप कारखानोंकी संख्या बढ़ाकर खेती कम होती जा रही है और बेचारा किसान भूमिहीन हो रहा है |

४) संमाज एवं संस्कृति पर असर :-

वैश्विकरण के परिणाम स्वरूप पश्चिमी संस्कृती ने सारी दुनियाको प्रभावित किया है | जो गैर पश्चिमी संस्कृती के लिये मारक साबित हो रही है | वैश्विकरण के नामपर अब औद्योगिक पूँजीवादी व्यवस्था ओर उसकी उपभोक्तावादी संस्कृतीको दुनियाके उन लोगोपर लादनेका प्रयास हो रहा है, जहा अभीतक पूँजीवादी व्यवस्था नही थी | वैश्विकरण के कारण किसी भी देश के लोग अपने देश मै आ सकते है | वैश्विकरण के कारण यहा के सामाजिक और सांस्कृतिक मुल्योपर असर पड रहा है | क्योकि हमारे देश की जनता बहुन जल्दी पाश्चात्यो का अनुकरण कर लेती है | जिसके अनेक उदाहरण मिलते है | अग्रेजो के बहुत सारे तौर तरीके हम सीख चुके है | हमारा रहन सहन और कपडोमे बदलाव आया है | फैशेन के नामपर कमसे कम कपडो मे एक प्रकारकी प्रतिष्टा महसूस करते है | यह पाश्चात्य संस्कृती कि ही देन है | हमारे देश मै पति पत्नि एक दुसरे का सम्मान करते है | एक पत्नीत्व को हम आदर्श मानते है | लेकिन पाश्चात्य संस्कृती में कितानि भी पत्निया अथवा पति बदलना उनकी संस्कृती है | वर्तमान समय में बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड प्रचलन पाश्चात्य संस्कृती की ही देन है | अर्थात वैश्विकरण की ही देन है |

५) **भाषा पर असर :-** वैश्विकरण का प्रभाव भाषिक क्षेत्र पर भी पाया जाता है | वैश्विकरण में हम अग्रेजी भाषाके गुलाम हो रहे है | आज समाज मे भ्रम फैला हुआ है की अन्ग्रेजीके बिना प्रगति नही कर सकते परिणाम स्वरूप ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अग्रेजीका प्रभाव है | शिक्षा, संचार माध्यम तथा सामान्य बोल चाल में भी अग्रेजीका प्रभाव पाया जाता है | वैश्विकरण के परिणाम स्वरूप हिंदी के हिंग्लिश रूप में निखार आ रहा है | जनता मे ही नही बल्की संचार माध्यमो और शासकीय कार्यालायो में भी अंग्रेजी शब्दो के बहुवचन हिंदी अर्थात हिंग्लिश रुपो का बे झीजक प्रयोग हो रहा है | आज कल अफसरों, अस्पतालों, होटलों, चैनलों, टेबलों, डॉक्टरों, मेनेजरों आदि हजारो शब्दोका प्रयोग हो राहा है | अग्रेजी भाषाके प्रभाव के कारण देशज भाषा का ऱ्हास हो रहा है | अनेक शब्द लुप्त होकर उनकी जगह अग्रेजी शब्दोका प्रयोग किया जा रहा है |

निष्कर्षत:- हम कह सकते है कि वैश्विकरण का प्रभाव हमारे जीवनके हर क्षेत्र पर हो रहा है | हमारा दैनंदिन जीवन इससे प्रभावित हुआ है | इसके अच्छे-बुरे दोनो प्रकार के परिनाम हमारे समाज और संस्कृति पर हो रहे है | अच्छे परीनामो के घटक को स्वीकारते हुये बुरे परीनामो के घटक हमे नकारने होंगे | हमारी संस्कृति की रक्षा करते हुये अधुनिकता को स्वीकारना होगा जिस प्रकार फिल्मो पर सेन्सर बोर्ड का नियंत्रण होता है | उसी प्रकार मिडिया पर भी कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिये | मिडिया द्वारा प्रसारित खबरे विज्ञापन, अश्लील साहित्य आदि पर रोक लगे | वैश्विकरण को हम रोक नही सकते और रोकना भी नही चाहिये | किंतु परंपरा और नैतिक मूल्योकी रक्षा करते हुये हमे अपना विकास करना होगा | संक्षेप में भौतिक उपलब्धियॉ, ओउद्योगिक प्रगती, तकनिकी प्रगती, कम्पुटर, इन्टरनेट आदि सभी आधुनिक बातोको स्वीकारते हुये उसकी निर्मिती एवं उपयोग की स्पर्धामे आगे बढते हुये हमे हमारी संस्कृति की और समाज की रक्षा करनी होगी | क्योकि प्रगतिशील, आदर्श एवं स्वस्थ देश के लिये स्वस्थ एवं आदर्श समाज की आवश्यकता होती है |

संदर्भ ग्रंथ :-

१) वैशिविकरण के परिप्रेक्ष में भाषा और साहित्य- सं. डॉ. माधव सोनटक्के, डॉ. अंबादास देशमुख.

२) मिडिया कालीन हिंदी स्वरूप एवं संभावनाएँ- डॉ. अर्जुन चव्हान.

३) वैश्विकता के संदर्भ में हिंदी – डॉ. शैलजा पाटील.

प्रा. रज्जाक शेख

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण

प्रा. मोहन भाऊसाहेब सावंत

इतिहास विभाग, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील महाविद्यालय नातेपुते

प्रस्तावना

भारतीय नागरिकांमध्ये शिक्षणाचा पुरस्कार करण्यासाठी भारत सरकारने आखलेले धोरण. भारतातील ग्रामीण व नागरी भागातील प्राथमिक ते महाविद्यालयीन शिक्षण कसे असावे, याची आखणी सदर धोरण करते. १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी प्रथमत: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविले. तेव्हापासून त्यात वेळो वेळी आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. इसवी सन १९४७ नंतर स्वतंत्र भारतातील नागरिकांच्या निरक्षरतेची समस्या दूर करण्यासाठी भारत सरकारने विविध कार्यक्रम आखले. त्यांमध्ये भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुलकलाम आझाद यांनी देशभरासाठी समान शैक्षणिक पद्धत आखून त्यावर केंद्र शासनाचे नियंत्रण आणले. त्यांनी भारतीय शिक्षणात आधुनिकता आणण्यासाठी विद्यापीठ शिक्षण आयोग (डॉ. राधाकृष्णन आयोग), मुदलियार आयोग (माध्यमिक शिक्षण आयोग) आणि कोठारी आयोग (भारतीय शिक्षण आयोग) हे आयोग प्रस्तावित केले. भारताचे प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू आणि केंद्र शासन यांनी उच्च गुणवत्तेचे वैज्ञानिक धोरण आखून त्यानुसार १ सप्टेंबर १९६१ रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ही स्वायत्त संस्था स्थापन केली. ही संस्था देशातील शालेय शिक्षणासंदर्भातील सर्व समस्यांबाबत अभ्यास करते. या संस्थेला राज्य शासन व केंद्र शासन यांनी शैक्षणिक धोरणांच्या आखणी व कार्यवाहीबाबत सल्ला द्यावा, हे अपेक्षित आहे.

उद्देश:- नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करणे

इंदिरा गांधी यांनी १९६४ ते १९८४ पर्यंतच्या शिक्षण आयोगांचे वृत्तांत व शिफारशी लक्षात घेऊन पूर्वीच्या धोरणांत आमूलाग्र बदल करून डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. आयोगाने पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास साधण्यासाठी भारतीय नागरिकांना समान शैक्षणिक संधी दिली गेली. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व बालकांना सक्तीचे शिक्षण आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेसाठी परिणामकारी प्रशिक्षण यांची गरज सदर धोरणाने प्रकट केले. देशातील कुशल व अकुशल जनतेमधील दरी दूर होऊन प्रादेशिक भाषांच्या अध्ययनास प्रेरणा मिळावी, यांसाठी माध्यमिक शिक्षण आयोगाने संपूर्ण राज्यातील सरकारी व निमसरकारी शैक्षणिक संस्थांनी शाळेचे माध्यम पहिली राज्यभाषा (प्रादेशिक भाषा), दुसरी हिंदी भाषा (राष्ट्रीय भाषा) आणि तिसरी इंग्रजी भाषा (आंतरराष्ट्रीय भाषा) हे त्रिभाषासूत्र प्रभावीपणे राबविण्याचे धोरण अमलात आणले. तसेच भारतीय संस्कृतीचा एक भाग म्हणून शिक्षण संस्थांत 'संस्कृत' हा विषय शिकवावा, असे म्हटले. सदर धोरणाने शिक्षणावरील खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६% निश्चित केला होता.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ च्या शैक्षणिक धोरणांच्या परिणामाचा अभ्यास करण्याठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली 'ईश्वरभाई पटेल पुनर्वलोकन समिती' ची

स्थापना झाली. या समितीनेही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी व त्यांच्या केंद्र शासनाने १९८५ मध्ये पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणात आवश्यक ते बदल करून १९८६ मध्ये देशातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. या धोरणात प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण, अनुसूचित जाति (एस. सी.) व अनुसूचित जमाती (एस. टी.) यांच्यातील भेद दूर करण्यासाठी समान शिक्षणसंधी यांवर भर दिला गेला. त्याचबरोबर त्यांनी शिष्यवृत्तींची संख्या वाढविणे, प्रौढ शिक्षण, मागास जमातींमधून शिक्षकभरती, गरीब कुटुंबांना शैक्षणिक प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या मुलांचे नियमित शिक्षण, प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी बालककेंद्री शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण सुधारण्यासाठी 'खडू-फळा मोहीम' इत्यादी बाबी कार्यान्वित केल्या. तसेच १९८५ मध्येच केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून सदर धोरणान्वये नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्तरावर 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ' (IGNU – इग्नू) या संस्थेची स्थापना करून मुक्त विद्यापीठ यंत्रणा सुरू केली. आजमितीला देशात दूरशिक्षण व मुक्त शिक्षणामध्ये सर्वांत मोठी संस्था म्हणून 'इग्नू'ला ओळखले जाते. विविध राज्यांमध्ये या विद्यापीठांतर्गत सुमारे १७ मुक्त विद्यापीठे, पारंपरिक विद्यापीठांतर्गत ८२ दूरशिक्षण संस्था, मानीव विद्यापीठे व खासगी संस्था अशा एकूण २५६ संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांमध्ये सुमारे ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यापीठांची संख्या देशातील पारंपरिक विद्यापीठांपेक्षा अधिक आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात १९८९ मध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ या संस्थेची स्थापना झाली. या विद्यापीठामधून दरवर्षी सुमारे ७ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तसेच महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानानुसार ग्रामीण भारताचा सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्यासाठी एका नमुनेदार ग्रामीण विद्यापीठाच्या निर्मितीचाही पुरस्कार सदर धोरणामध्ये केला आहे. १९९२ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने जनार्दन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९९६ (१९९२ सालच्या बदलांसह) प्रसिद्ध केले होते. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या किमान समान कृतिशील कार्यक्रमाधारित २००५ मध्ये नवे शैक्षणिक धोरण आखले गेले. त्यामध्ये व्यावसायिक व तांत्रिक कार्यक्रमांसाठी देशभरात समान प्रवेश परीक्षा सुरू केली. १८ ऑक्टोबर २००१ च्या भारत शासन निर्णयान्वये, जेईई, एआयईई (राष्ट्रस्तरीय) आणि एसएलईई या तीन परीक्षायोजना आखल्या गेल्या. त्यामुळे बदलते प्रवेश-अटी असताना व्यावसायिक स्तर राखण्याची दक्षता घेणे सोपे झाले. तसेच आशय पुनरावृत्ती, अनेक प्रवेश परीक्षांना सामोरे जाणे, मनोकायिक व आर्थिक बोजा विद्यार्थी-पालकांवर पडणे इत्यादी बाबींपासून सुटका झाली. त्यानंतर २००९ मध्ये मनमोहन सिंग यांनी निरक्षर व नवसाक्षरांसाठी (१५ वर्षीय व त्यापेक्षा मोठ्यांकरिता) ही केंद्र शासनपुरस्कृत शैक्षणिक योजना सुरू केली. २००१ च्या जनगणनेनुसार १२.७ कोटी भारतीय प्रौढ साक्षर झाले. त्यांपैकी ६०% स्त्रिया, २३% अनुसूचित जाती आणि १२% अनुसूचित जमाती या योजनेचा लाभ घेऊन साक्षर झाले आहेत.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) ही राज्याच्या उच्च शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी वास्तू उभारणीसाठी नियोजन व नियंत्रण करणारी मोहीम केंद्र शासनाने २०१३ मध्ये सुरू केली. त्यामध्ये राज्यातील दर्जेदार विद्यापीठ व महाविद्यालयांना स्वायत्तता देऊ केली आहे. या अभियानाने परीक्षा

सुधारणा अपेक्षित केले आहे. तसेच भारतीय विद्यापीठ व विदेशी विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक प्रगतीसाठी संवाद साधणे गरजेचे आहे असे म्हटले आहे. २०१४ नंतर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी २०१६ मध्ये माजी केंद्रीय सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय धोरण समिती नेमली. या समितीने पूर्वीच्या पुढील शासकीय योजनांचा आढावा घेतला : डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्रॅम (डीपीईपी), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए, २००१), राइट टू एज्युकेशन (आरटीई), नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर एज्युकेशन फॉर गर्ल्स ॲट एलिमेंटरी लेव्हल (एनपीईजीईएल), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए, २००९), माध्यमिक स्तरावर अपंगांसाठी इन्क्लुझिव एज्युकेशन फॉर दी डिसेबल्ड फॉर सेकंडरी स्टेज (आयईडीएसएस), प्रौढ साक्षर भारत (ॲडल्ड एज्युकेशनल इंडिया), उच्च शिक्षण विकासासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए, २०१३) इत्यादी. शासनाने २९ जुलै २०२० मध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देऊन ते संपूर्ण देशात लागू केले आहे. इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ समितीय सदस्यांनी या नव्या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. यानुसार शालेय शिक्षणाची रचना १० + २ ऐवजी ५ + ३ +३ + ४ अशी करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिली ३ वर्षे पूर्वप्राथमिक व २ वर्षे पहिली व दुसरी असणार (वय वर्षे ३ ते ८); पुढील ३ वर्षे तीसरी ते पाचवी असणार (वय वर्षे ८ ते ११); त्यानंतरची ३ वर्षे सहावी ते आठवीपर्यंत असणार (वय वर्षे ११ ते १४) आणि शेवटची ४ वर्षे नववी ते बारावी (वय वर्षे १४ ते १८) अशा एकूण १५ वर्षांमध्ये शालेय शिक्षणाची रचना अथवा आकृतीबंध आखण्यात आला आहे. सुरुवातीचे ३ ते ६ वर्ष वयोगटात असलेले मुले आतापर्यंत शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत येत नव्हती; परंतु नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे त्यांचा शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. २०१६ मध्ये भारतीय युवकांसाठी आखलेली 'प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना' ही पूर्वीच्या योजनांशी जोडल्यास युवा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगती साधणे या सुधारित राष्ट्रीय धोरणाने शक्य होणार आहे. या धोरणात संशोधनावर जास्तीत जास्त भर देण्यात आले असून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करणे, त्यांच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देणे इत्यादी कार्यक्रम आखण्यात आले आहे. सर्वांना शिक्षण, चांगले शिक्षण, शिक्षणाची समान संधी, आवाक्यातील शिक्षण आणि शिक्षणक्षेत्रातील सर्व घटकांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे या प्रमुख पाच सूत्रांवर धोरणाचा पाया आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची वैशिष्ट्ये : सुमारे ३४ वर्षांनंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये बदल करण्यात आले आले असून भाषा शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण इत्यादी विषयांमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण बदल करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत 'केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय' या विभागाचे नाव बदलून त्याचे 'शिक्षण मंत्रालय' असे नामकरण करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० धोरणातील महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे :

1. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.
2. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' या उपक्रमांतर्गत इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 'भारतातील भाषा' या प्रकल्पामध्ये सहभाग घेता येणार आहे.
3. विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षण स्तरावर विविध विदेशी भाषांचा पर्याय दिला जाणार आहे.

4. सुमारे ८ भारतीय भाषांमध्ये इ-कोर्सेस उपलब्ध होणार आहेत.
5. शिक्षण विभागाद्वारे पाली, पर्शियन आणि प्राकृत भाषांसाठी एक राष्ट्रीय संस्था उभारली जाणार आहे.
6. पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी एनसीइआरटीकडून अभ्यासक्रम आखला जाणार असून हा अभ्यासक्रम देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना लागू असणार आहे. तसेच पूर्वप्राथमिकचे शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्याचे प्रयत्न आहे.
7. इयत्ता तीसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना संख्या व अक्षरांची ओळख होऊन त्यांना ते वाचता येईल, यावर भर देऊन यापुढे हेच मुलभूत शिक्षण म्हणून मानले जाणार आहे.
8. ज्या ठिकाणी अंगणवाडी आणि पूर्व प्राथमिक शाळा नवीन अभ्यासक्रम राबविण्यात अपयशी ठरणार आहेत, त्या ठिकाणी सर्व सोयी-सुविधांसह नवीन स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक शाळा उभारली जाणार आहे.
9. सरकारी व खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता असणार आहे.
10. यापूर्वीच्या धोरणामध्ये ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत होते; मात्र नवीन धोरणानुसार ३ ते १४ वर्षे असा वयोगट करण्यात आला आहे.
11. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय सांकेतिक भाषा (आयएसएल) संपूर्ण देशात प्रमाणित करण्यात येणार आहे.
12. नवीन धोरणानुसार शालेय निकाल पत्रकावर केवळ गुण, श्रेणी व शिक्षकाच्या शेरा यांव्यतिरिक्त त्यामध्ये स्वत: विद्यार्थी व वर्गमित्र यांचाही शेरा असणार आहे. तसेच शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांचे जीवन कौशल्येसुद्धा नमूद करावे लागणार आहे.
13. पूर्वीच्या धोरणानुसार दहावी (एसएससी) आणि बारावी (एचएचसी) या दोन बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या जात होत्या. त्या परीक्षा वर्षातून एकदाच होत होत्या; मात्र आता नवीन धोरणानुसार इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या परीक्षा वर्षातून एकदा न घेता, त्या एकूण ८ शालेय अर्धवर्षांमध्ये (सेमीस्टर) विभागून घेण्यात येणार आहे.
14. पूर्वीच्या धोरणानुसार विद्यार्थ्याला दहावीनंतरचे शिक्षण कला, वाणिज्य व विज्ञान यांपैकी कोणत्याही एकाच शाखेत प्रवेश मिळून त्याला त्याच शाखेतील विषय शिकविले जात होते; नवीन धोरणात बदल केले असून विद्यार्थी एखाद्या शाखेत प्रवेश घेऊन दुसऱ्या शाखेतील काही आवडीचे विषयही त्याला घेता येणार आहे. उदा., कला शाखेत प्रवेश घेऊन विज्ञान शाखेतील जीवशास्त्र इत्यादी किंवा वाणिज्य शाखेतील सहकार इत्यादी विषय घेता येईल.
15. या धोरणांतर्गत शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण यांबरोबरच कृषी शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कायदा शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण इत्यादी व्यावसायिक शिक्षणाला कार्यक्षेत्रात आणले आहे.
16. देशातील महाविद्यालयांना श्रेणी देण्यासाठी उच्च शिक्षण नियामक ही संस्था स्थापली जाणार आहे.
17. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विदेशी विद्यापीठांना भारतामध्ये आपल्या शाखा उघडता येणार आहे.
18. शालेय शुल्क आकारणी रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.
19. सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, लिंग, अपंगत्व इत्यादी घटकांमध्ये भेदभाव न करता आर्थिक दृष्ट्या वंचित गटांवर विशेष भर दिला जाईल.

20. शिक्षकांची भरती सक्षम पारदर्शक प्रक्रीयेद्वारे केली जाऊन बहुस्रोत नियमित कामगिरी मूल्यांकन, उपलब्ध प्रगतीचे मार्ग इत्यादी गुणवत्तेवर आधारित शिक्षकाची शैक्षणिक प्रशासक म्हणून बढती दिली जाईल.
21. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि एसईडीजी या प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस प्रोत्साहन दिले जाईल; तसेच राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा विस्तार करून शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांचा मागोवा घेतला जाईल.
22. धोरण तयार करताना कोविड-१९ चा प्रसार लक्षात घेऊन पर्यायी शैक्षणिक पद्धतींचा व्यापक विचार करण्यात आला. त्यानुसार सर्वंकश महाजालकावरील शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षण या पर्यायी शैक्षणिक सज्जता सुनिश्चित केली जाणार आहे.

सारांश

देशातील सुमारे २ कोटी शाळाबाह्य मुलांना मुख्य शैक्षणिक प्रवाहात आणणे; शिक्षणातील ४.४३ % जेडीपीवरून ६.०० % वाढ करणे; मुलाच्या जन्माच्या वेळेची परिस्थिती अथवा अन्य पार्श्वभूमीमुळे कोणताही मुलगा-मुलगी शिकण्याच्या आणि आपल्यातील उत्कृष्ठतेची संधी गमाविणार नाही; व्यावसायिक शिक्षणासह उच्च शिक्षणामध्ये सकल नोंदणी गुणोत्तर २६.३ टक्क्यांवरून ५० टक्कयांपर्यंत वाढविणे (२०३५); देशातील सर्व अशिक्षित तरुण व प्रौढ यांना १०० टक्के साक्षर करणे इत्यादी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे उद्दिष्ट आहे. त्या प्रमाणे एकवीसाव्या शतकातील प्रमुख कौशल्ये, आवश्यक शिक्षण आणि चिकित्सात्मक विचार विद्यार्थ्यांमध्ये वाढविण्यासाठी अभ्यासक्रम कमी करणे आणि अनुभवातून शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हा शिकविण्याच्या पद्धतीचा व शालेय अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहे.

संदर्भ

1. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR) ISSN – 2347-7075
Peer Reviewed Bi-Monthly Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

शेतीचे यांत्रिकीकरण :सद्यस्थिती व भविष्यातील दिशा

डॉ.बी.टी.निकम
भूगोल विभाग प्रमुख, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील महाविद्यालय नातेपुते

सारांश

शेतीचे यांत्रिकीकरण हा विषय एका दशकापूर्वी गौण समजला जात होता : परंतु मागील काही वर्षांत मजुरांची कमतरता तिव्रतेने जाणवण्यास सुरुवात झाली व यांत्रिकीकरण हा विषय चर्चेत आला. विकसित देशांमध्ये यांत्रिकीकरण हाच शैतींचा महत्वाचा घटक आहे व त्याशिवाय तिथे शेती अशक्य आहे. हीच परिस्थिती आपल्याकडे हळूहळू येत आहे. ही वस्तुस्थिती आता सर्वांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळेच भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कृषि यांत्रिकी उपअभियान हे राष्ट्रीय कृषि विस्तार अभियानाचा एक प्रमुख भाग म्हणून राबविण्यात येत आहे. या उपअभियानांतर्गत नवीन कृषि यंत्रे व अवजारे यांचा प्रसार व त्यासाठी भरपूर अनुदान देण्यात येत आहे. कृषि यांत्रिकीकरणामुळे मजुरांची कमतरता भरून काढली जाते. त्याचबरोबर त्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे निर्विष्ठांचा कार्यक्षम वापर, वेळेवर शेती कामाची पूर्तता, उत्पादन खर्चात घट, शेतीतील कट कमी करणे व नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करणे हा होय. बदलत्या हवामानानुसार जमिनीतील अोलाव्याचे संवर्धन, पावसाच्या पाण्याचे नियोजनासाठी मशागतींची पद्धत, वळेवर व योग्य मात्रेत खते-र्बियाणे पेरणी, आंतर्मशागत. फवारणी, काढणी, मळणी, प्रथामिक प्रक्रिया, साठवण, वाहतूक व विक्री इत्यादी कामे करण्यासाठी अत्याधुनिक कृषि यंत्रांची गरज आज प्रकर्षाने जाणवत आहे. सद्यःस्थितीत ही सर्व यंत्रे गरजेप्रमाणे देशात उपलब्ध आहेतच, असें नाही व जी नवसंशोधित अवजारे व यंत्रे संशोधन केंद्रात उपलब्ध आहेत. त्यांचे व्यापारीकरणे झालेले नाही. यामुळे यंत्रांना मागणी वाढत असून पुरवठा त्यानुसार होत नाही. भारतातील मागणी लक्षात घेऊन अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मागील काही वर्षांत त्याचे उत्पादन देशात सुरू केले आहे. तसेच, परदेशातून मोठ्या प्रमाणात आयातही होत आहे. परदेशातून आलेली यंत्रे जशीच्या तशी आपल्या देशात उपयुक्त होत नाहीत. त्यासाठी स्थानिक गरजेनुसार बदल करणे आवश्यक आहे. विशेषतः ऊस तोडणी यंत्र, भात रोवणी यंत्र, पॉवर स्प्रेयर या आयात यंत्राचा ब-यापैकी वापर होताना दिसत आहे. कापूस वेचणी यंत्राचेही प्रयोग सुरू आहेत. ही सर्व प्रक्रिया मागील काही वर्षांत वेग घेताना दिसत आहे.

बीजे शब्द:- शेतीचे यांत्रिकीकरण, उत्पादन खर्च, कृषि

प्रस्तावना

शेतीचे यांत्रिकीकरण हा विषय एका दशकापूर्वी गौण समजला जात होता : परंतु मागील काही वर्षांत मजुरांची कमतरता तिव्रतेने जाणवण्यास सुरुवात झाली व यांत्रिकीकरण हा विषय चर्चेत आला. विकसित देशांमध्ये यांत्रिकीकरण हाच शैतींचा महत्वाचा घटक आहे व त्याशिवाय तिथे शेती अशक्य आहे. हीच परिस्थिती आपल्याकडे हळूहळू येत आहे. ही वस्तुस्थिती आता सर्वांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळेच भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कृषि यांत्रिकी उपअभियान हे राष्ट्रीय कृषि विस्तार अभियानाचा एक प्रमुख भाग म्हणून राबविण्यात येत आहे. या उपअभियानांतर्गत नवीन कृषि यंत्रे व अवजारे यांचा प्रसार व त्यासाठी भरपूर अनुदान देण्यात येत आहे. कृषि यांत्रिकीकरणामुळे मजुरांची कमतरता भरून काढली जाते. त्याचबरोबर त्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे निर्विष्ठांचा

कार्यक्षम वापर, वेळेवर शेती कामाची पूर्तता, उत्पादन खर्चात घट, शेतीतील कट कमी करणे व नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करणे हा होय. बदलत्या हवामानानुसार जमिनीतील अोलाव्याचे संवर्धन, पावसाच्या पाण्याचे नियोजनासाठी मशागतींची पद्धत, वळेवर व योग्य मात्रेत खते-र्बियाणे पेरणी, आंतर्मशागत. फवारणी, काढणी, मळणी, प्रथामिक प्रक्रिया, साठवण, वाहतूक व विक्री इत्यादी कामे करण्यासाठी अत्याधुनिक कृषि यंत्रांची गरज आज प्रकर्षाने जाणवत आहे. सद्यःस्थितीत ही सर्व यंत्रे गरजेप्रमाणे देशात उपलब्ध आहेतच, असें नाही व जी नवसंशोधित अवजारे व यंत्रे संशोधन केंद्रात उपलब्ध आहेत. त्यांचे व्यापारीकरणे झालेले नाही. यामुळे यंत्रांना मागणी वाढत असून पुरवठा त्यानुसार होत नाही. भारतातील मागणी लक्षात घेऊन अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मागील काही वर्षांत त्याचे उत्पादन देशात सुरू केले आहे. तसेच, परदेशातून मोठ्या प्रमाणात आयातही होत आहे. परदेशातून आलेली यंत्रे जशीच्या तशी आपल्या देशात उपयुक्त होत नाहीत. त्यासाठी स्थानिक गरजेनुसार बदल करणे आवश्यक आहे. विशेषतः ऊस तोडणी यंत्र, भात रोवणी यंत्र, पॉवर स्प्रेयर या आयात यंत्राचा ब-यापैकी वापर होताना दिसत आहे. कापूस वेचणी यंत्राचेही प्रयोग सुरू आहेत. ही सर्व प्रक्रिया मागील काही वर्षांत वेग घेताना दिसत आहे.

यांत्रिकीकरणाची सद्यस्थिती सध्याच्या स्थितीचा विंचार केला तर भारतात ट्रॅक्टरची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे बैलशेती आता ट्रॅक्ट्र शेतीत परिवर्तित झाली आहे. मागील चार दशकांत ट्रॅक्टरची संख्या ५.५५ लाखांहून ३० लाखांवर पोचली; पण त्याप्रमाणात अवजारांचा प्रसार म्हणावा तसा झाला नाही. याचे कारण देशातील हवामान, पीक व भौगोलिक विविधतेनुसार आणि स्थानिक गरजेप्रमाणे अवजारांची निर्मिती झाली नाही, हे आहे. कृषि अवजारांचे संशोधनसुद्धा मागील काळात प्राथमिकतेने केले गेले नाही. म्हणूनच आज जेव्हा गरज निर्माण झाली, तेव्हा आपल्याकडे पुरेसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. जे आहेत तें संशोधन केंद्राच्या तिजोरीत बंद आहेत. कारण त्याचे व्यापारीकरण करण्यासाठी खाजगी उत्पादकांसोबत काम करण्यासाठीचे धोरण व नियम सुट्सुटीत नाहीत. तसेच त्यासाठी संशोधकांना प्रोत्साहून मिळत नाही. जे उद्योजक कृषि यंत्रे व अवजारे क्षेत्रात काम करतात, त्यांनाही अनेक अड्थळे पार करत उद्योग करावा लागतो. त्यासाठी प्रोत्साहनाची गरज आहे. इतर देशांच्या तुलनेमध्ये यांत्रिकीकरणाच्या बाबतीत आपण बरेच मार्गे आहोत. अमेरिकेमध्ये फक्त २.४ टक्के लोक शेती करतात व १५ टक्के यांत्रिकीकरण झाले आहे. ब्राझीलमध्ये १५ टक्के लोंक शेती करतात व ७५ टक्के यांत्रिकीकरण झाले आहे. परंतु भारतात अजूनही ५५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत व यांत्रिकोरण फक्त ४० टक्के झाले आहे. शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या जास्त दिसत असली, तरी मगील दशकापासून शेतीत काम करणा-या मजुरांची संख्या घटली असून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे तसेच रोजगाराच्या शोधात शहरी स्थलांतरामुळे प्रत्यक्ष शेतीतकाम करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, तसेच मजुरीचे दरही वाढल्यामुळे शेतीसाठी आता यांत्रिकीकरण हाच पर्याय आहे.

शेतीमध्ये पशू व मनुष्यशक्तींचा वापर सन १९७१-७२ मध्ये ६१ टक्के होता, तो आता १o टक्के राहिला आहे. शेतीकामासाठी ट्रॅक्टरचा वापर वाढला असून शेतीत लागणारी प्रति हेक्टर अश्वशक्तीं सन १९७g मध्ये g.३५ किंलोवॉट होती ती आता १.८४ किंलोवॉटपर्यंत पोचली आहे. उपलब्ध प्रतेि हेक्टर अश्वशक्ती व पिंकांची उत्पादकता यांचे सकारात्मक समीकरण आहे. पंजाब, हरियाणा, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश या राज्यांत प्रति हेक्टर अश्वशक्ती १.६ ते ३.o किंलोवॉट असून, पिकांची उत्पादकता २ ते ४ टन प्रति हेक्टर आहे. तीच महाराष्ट्रासहित इतर १७ राज्यांमध्ये प्रति हेक्टर अश्वशक्ती 0.५ ते १.५ किंलोवॉट असून उत्पादकता १.0 ते १.४ टन प्रति हेक्टर आहे. याचाच अर्थ, प्रतेि हेक्टर अश्वशक्तीं वाढविण्याची गरज आहे. भारतीय सरासरी प्रतेि हेक्टर अश्वशक्ती सन २०२५ पर्यंत २.५ कैिलोंवॉटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. भारतात सध्या प्रति वर्षी सह्या लाख ट्रॅक्टरची निर्मिती होते व भारत जगातील सर्वांत जास्त ट्रॅक्टर निर्मिती करणारा देश झाला आहे. परंतु

त्या प्रमाणात अवजारे निर्माण करण्याची गरज आहे.ट्रॅक्टरसाठी कर्ज पुरवठा करण्यात बँका अग्रसेर आहेत; पण अवजारांची ती स्थिती नाही. मागील काळात कृषि कर्जाचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी बँकांना ट्रॅक्टर हा चांगला पर्याय मिळाला व काही भागात गरजेपेक्षा जास्त ट्रॅक्टर वाटण्यात आले. त्याचा योग्य अवजारांअभावी वाहतुकीसाठी जास्त वापर वाढला. अजूनही ट्रॅक्टरचा वापर कार्यक्षमतेने होत नाही व पूर्ण अश्वशक्तीचा वापर होत नसल्याने अर्थशास्त्र बिघडते. वर्षभरात कमीत कमी १000 तास ट्रॅक्टरचा वापर असला तरच अर्थशास्त्र जमते. तसेच शास्त्रीय प्रशिक्षणाअभावी ट्रॅक्टरचालक अशास्त्रीय पद्धती अवलंब करतात. त्यामुळे इंधन जास्त जळते व परिणामी ट्रॅक्टरचा देखभाल/दुरुस्तीचा खर्च वाढतो. यावर उपाय म्हणून ट्रॅक्टरचालकांचे प्रशिक्षण केंद्र उघडण्याची आवश्यकता असून, या केंद्राच्या प्रमाणापत्रधारकांनाच ट्रॅक्टर चालवण्याचा परवाना मिळणे बंधनकारक करणे भविष्यात अनिवार्य असावे, ही काळाची गरज आहे. ट्रॅक्टरची संख्या वाढत गेली तशी बँकांनी व वितरकांनी काही ठरविक अवजारे उदा. पलटी नांगर, नऊ फणी मशागत यंत्र व ट्रेलर हे ट्रॅक्टरसोबत जोडल्यामुळे त्याचा वापर वाढला. आज नांगरणी व मशागत या कामाचे यांत्रिकोरण ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. मागील काही वर्षांत मशागतीसाठी रोटोव्हेटरचा वापरही वाढला आहे. यासाठी बाजारात पर्याय उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर फवारणी, मळणी, वाहतूक व पाणी उपशासाठी विद्युतपंपाचा वापर या कामांचेही यांत्रिकीकरण झालेले आहे. यासाठी लागणारी अवजारे व यंत्रे बाजारात उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत यशस्वी अवजारांमध्ये पलटी नांगर, नऊफणी मशागत यंत्र, रोटाव्हेटर, मळणी यंत्र, थ्रेशर कॅम्बाईन, सूक्ष्म सिंचन संच इत्यार्दीचा समावेश आहे. या यंत्रांच्या वापरामुळे निविष्ठांची तसेच वेळ व खर्चाची २० टक्के बचत होते. याव्यतिरिक्त प्रत्येक यंत्राच्या वापरामुळे उत्तम मशागत, निविष्ठांचा काटेकोर वापर, वेळेवर काढणी-मळणीमुळे कमीत कमी नुकसान, सूक्ष्म सिंचनामुळे पाण्याची ५० टक्के बचत हे यांत्रिकीकरणामुळे झालेले काही यशस्वी बदल व फायदे आहेत. अजून फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे व त्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करण्याची गरज आहे. खालील शेतीकामांसाठी यांत्रिकीकरण अजूनही म्हणावे तसे उपलब्ध नाही व असेल तर ते प्रचलित झालेले नाही.

काटेकोर पेरणी, भातरोपण, आंतरमशागत, काढणी, प्राथमिक प्रक्रिया यांसाठी पुरेसे पर्याय अजूनही उपलब्ध नाहीत. तसेच, मूलस्थानी जलसंधारण यंत्र, रुंद वरंबा-सरी पद्धत, कंटूर मशागत, भातलावणी यंत्र, भात पेरणी यंत्र, कापूस वेचणी यंत्र, सोयाबीन एकत्रित काढणी-मळणी यंत्र, ऊस लागण यंत्र, ऊस काढणी यंत्र, कांदा पेरणी यंत्र, भाजीपाला काढणी यंत्र, फळ लागवडीसाठी खड्डु खोदणे, फळांची काढणी, फळ व भाज्यांची प्राथमिक प्रक्रिया, पॅकेजिंग, वातानुकूलित साठवण व वाहतूक इत्यार्दीसाठी अजूनही शेतकरी उत्कृष्ट यंत्रांच्या शोधात आहेत. हवामानबदलामुळे पिकांच्या उत्पादकतेत घट झाली आहे व काही पिकांमध्ये उत्पादकता स्थिर झाली आहे.

मृदा व जल व्यवस्थापनासाठी व संवर्धनासाठी विशिष्ट प्रकारच्या यंत्राद्वारे मशागतीची गरज आहे. त्यामुळे उत्पादकतेमध्ये वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यात रुंद-वरंबा व सरी टोकन यंत्र (बीबीएफ प्लॅटर), सबसॉईलर जे २-३ फूट खोल अरुंद खाच निर्माण करते व पावसाचे पाणी धरून ठेवते. तसेच खोल मशागतीसाठी पॉवर हेरो,

तव्याचा नांगर व कुळव, टोकन यंत्रसाठी डिस्क फरो ओपनर, कमी मशागतीत चालणारे टोकन यंत्र, शेतीतील काडीकचरा तुकडे करून शेतीत गाडण्यासाठीचे यंत्र इत्यादींचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त भारतात २0 टक्के शेती डोंगरभागात आहे. त्यासाठी वेगळी यंत्रे लागतात. भारतात १५ प्रमुख कृषि हवामान विभाग असून प्रत्येक विभागात जमिनीची प्रत पाहून पिकांची लागवड केली जाते. देशात ६० टक्के तर महाराष्ट्रात ८२ टक्के आहे. त्यासाठी विशिष्ट यंत्रांची गरज आहे. लहान व अल्पभूधारक शेतीसाठी व महिला कमी कष्टात चालवू शकतील, अशा लहान अवजारांची गरज आहे. बागायती पिकांच्या गरजाही पिकानुसार विविध व अमर्याद आहेत. याची येत्या काळात पूर्तता व स्थानिक पातळीवर उपब्धता करण्यासाठी भरीव उपाययोजना करण्याची व पूरक शासकीय धोरणाची आवश्यकता आहे.अवजारांची मागणी व पुरवठा यंत्र-अवजारांची गरजेनुसार उपलब्धता तसेच मागणी व पुरवठा यांमध्ये तारतम्य राखण्यासाठी भविष्यात कृषि यांत्रिकीकरण हा विषय मुख्य प्रवाहात व उच्चतम प्राथमिकता या सदरात आणावा लागेल. भविष्यात भेडसावणारे अन्नसुरक्षेचे संकट, पूरक धोरणाअभावी शेती क्षेत्राची होत असलेली दुर्दशा व त्याचे सामाजिक परिणाम, शेतीचे घटते क्षेत्र, ८0 टक्क्यांपेक्षा जास्त लहान शेतकरी, महाराष्ट्रातील ८२ टक्के असंचित शेती, हवामानबदलाचे अनिष्ट परिणाम, शेतीतून बिघडत्या अर्थशास्त्रामुळे त्रस्त झालेला शेतकरी, शेतीत कष्टाचे काम करण्यासाठी मनुष्यबळाची अनुपलब्धता इत्यादी सर्व विषय राष्ट्रीय व महत्वाचे असून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. कृषि हे देशाचे सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने प्राथमिक क्षेत्र आहे व ते राहील. शेतीक्षेत्राच्या स्थेर्यासाठी प्राथमिकता ठरविणे व त्यासाठी सकारात्मक पावले उचलणे, ही काळाची गरज आहे. भविष्यकाळात शेती जिवंत ठेवण्यासाठी यांत्रिकीकरण हाच पर्याय आहे व त्यासाठी प्राथमिकतेने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यांत्रिकीकरणाची भविष्यातील दिशा कृषि यांत्रिकीकरणाची भविष्यातील दिशा निश्चित करण्यासाठी खालील उपाययोजनांचा प्राथमिकतेने विचार करण्याची गरज आहे.

उपाययोजना

1. कृषि यांत्रिकीकरण संशोधनाचे देशभरात जाळे पसरविणे.
2. कृषि यंत्रे व अवजारे संशोधनात उद्योजकांना भागीदार बनवणे व संशोधनासाठी प्रवर्तित करणे.
3. कृषि यंत्रे व अवजारे चाचणीसाठी देशभर परिपूर्ण शासकीय-खाजगी भागीदारीत केंद्र उभारणे.
4. कृषि यंत्रे व अवजारांची गुणवत्ता निश्चित करणे व गुणवत्ता नियंत्रणासाठी वेगळी यंत्रणा निर्माण करणे.
5. कृषि यंत्रे व अवजारे उत्पादनासाठी पूरक धोरण तयार करून गुणवत्ता हा अतिमहत्वाचा घटक असावा. गुणवत्ता राखण्यात अपयशी फसवणूक केल्याबद्दल जबर शिक्षेची तरतूद असावी.
6. कृषि यंत्रे व अवजारांवर कमीतकमी दहा वर्षांसाठी कुठलाही कर आकारण्यात येऊ नये.
7. कृषि अवजारे पुरवठा उद्योगांना पाच वर्षांची वॉरंटी व दहा वर्षे विक्रीनंतरची सेवा बंधनकारक असावी.
8. परदेशी यंत्रे व अवजारे यांची संपूर्ण चाचणी करून स्थानिक वापरासाठी उपयुक्त असल्याबाबत कमीतकमी दहा शेतक-यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय त्याचा अनुदान योजनेत समावेश करू नये.
9. महागडी कृषि यंत्रे व अवजारांसाठी उपयुक्त अनुदान असावे. त्यासाठी गरजेनुसार यंत्रे व अवजारे निवड करण्याची मुभा शेतक-यांना असावी. अनुदान योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी संगणकीकरण करून अनुदान निश्चित कालावधीत बँक खात्यावर जमा करावे.
10. यंत्रे व अवजारे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी मंडळ पातळीवर यंत्रे व अवजारे यांची बॅक स्थापन करावी व स्थानिक युवकांना प्रशिक्षित करून त्यांना कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापन करण्यासाठी शेतक-यांप्रमाणेच अनुदान योजनेचा लाभ द्यावा.

11. भाडेतत्व केंद्रातील यंत्रे व अवजारांचे दर नियंत्रित असावेत व लहान शेतक-यांना उपयुक्त दरात कार्यक्षम यंत्रे व अवजारे उपलब्ध करावीत.
12. महागडे कृषि यंत्र व अवजार खरेदीसाठी माफक दरात व निश्चित कालावधीत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीची प्रक्रिया सरळ व सोपी करणे.
13. सन २00१ ते २०१० या दशकात कृषि यांत्रिकीकरणात फक्त २ टक्के वाढ झाली. भविष्यातील शेतीची आव्हाने लक्षात घेऊन सन २०२५ पर्यंत सध्याच्या ४o टक्क्यांवरुन ६० टक्के यांत्रिकीकरण वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरवावे, तरच विविध पिकांची उत्पादकता वाढवून शेतीला स्थेर्य आणणे शक्य होईल.
14. लहान शेतक-यांची संख्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने यांत्रिकीकरण सुलभ करण्यासाठी गटशेती/समूहशेती करणा-या गटांसाठी विशेष सवलतीची योजना राबवावी.
15. कृषि यांत्रिकीकरण यशस्वी करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची निकडीची गरज आहे. प्रत्येक यंत्र व अवजाराची रचना, कार्यपद्धत, देखभाल व दुरुस्ती यासाठी विशिष्ट कौशल्याची गरज असते. सध्या अशा प्रकारची प्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात नाही. राज्याच्या आठही कृषि विभागांत कृषि यंत्र व अवजारे कोशल्य निर्माण केंद्र स्थापन करावे.
16. कृषि यांत्रिकीकरणाच्या प्रसारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृषि यांत्रिकीकरण विस्तार केंद्र स्थापन करावे. हे केंद्र स्थानिक गरजेनुसार यंत्रे व अवजारे उपलब्ध करून त्याचा प्रसार करण्याचे काम करील.
17. राज्यामध्ये स्वतंत्र कृषि यांत्रिकीकरण विभाग स्थापन करून तज्ज्ञ कृषि अभियंत्यांची नियुक्ती करावी व या विभागाअंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण अभियान चालवून त्याअंतर्गतच वरील सर्व यंत्रणेचे संनियंत्रण करावे. वरील दिशादर्शक सूचना टप्प्याटप्प्याने का होईना अमलात आणल्यास शेतीच्या यांत्रिकीकरणातून शेतीला जीवदान व स्थैर्य देण्यास उपयोगी ठरतील.

संदर्भ

1. महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग
2. सामाजिक आर्थिक समालोचन अहवाल महाराष्ट्र राज्य

शेती : समस्या आणि उपाय

आपल्या देशातील लागवडीखाली असलेल्या जमीनधारणेचा विचार करता खाली चित्र दिसते.

जमीनधारणा प्रकार	**जमीनधारक कुटुंबांची संख्या %**	**त्यांच्याकडील जमिनीचे क्षेत्रफळ %**
अत्यल्प (१ हेक्टर खालील)	५९.४	१५.
अल्प (१-२ हेक्टर)	१८.८	१७.४
अर्ध-मध्यम (२-४ हेक्टर)	१३.१	२३.३
मध्यम (४-१० हेक्टर)	७.१	२७.१
मोठे (१० हेक्टरच्या वर)	१७.३	

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

जागतिकीकरणात आर्थिक क्षेत्रात उद्योगपती रतन टाटा यांचे योगदान

डॉ.मनीषा जगदीशलाल वर्मा

सहाय्यक प्राध्यापक इतिहास विभाग एस.पी.डी.एम.आट्‌र्स,कॉमर्स,सायन्स कॉलेज,शिरपूर जिल्हा- धुळे

सारांश:-

प्राचीन काळापासून भारतीय उद्योग व व्यापारांच्या इतिहास अत्यंत वैभवशाली आहे. प्राचीन काळात अंतर्गत उद्योग,व्यापाराबरोबर विदेशी व्यापार केला जात होता. प्राचीन काळात अनेक शहरे ही व्यापारी केंद्र म्हणून प्रसिद्ध असून नगर विकासासाठी या व्यापारी केंद्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती.प्राचीन काळात धातू उद्योग, खाण उद्योग,युद्धातील शस्त्रास्त्रे,हत्यारे,शेतीची अवजारे,गाड्या व जहाजबांधणी हे प्रमुख उद्योग होते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र व इतर समकालीन ग्रंथात आपल्याला भारतातील उद्योग, व्यवसाय व व्यापाराविषयी माहिती मिळते. तत्कालीन राज्यकर्ते,राजा,सम्राट व श्रेणीकांनी व्यापारासाठी प्रोत्साहन दिल्याचे दिसते.विदेशी व्यापार हा श्रीलंका,म्यानमार, जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया,मध्य आशिया,ग्रीस,इजिप्त आदी देशांशी व्यापार करीत असून त्यात प्रामुख्याने सुती व रेशमी कापड,कलावस्तू,मसाल्याचे पदार्थ,हिरे, माणिक,मोती आदी इतर वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात मागणी होती.मध्यकाळात व्यापाराचा विस्तार होऊन जलमार्ग व खुष्कीच्या मार्गाने व्यापार केला जात होता.विदेशी व्यापारात ब्रह्मदेश,तिबेट,चीन,जपान,इजिप्त,अरबस्थान आदी देशांशी व्यापारी संबंध होते. मोगल काळात अनेक परकीय प्रवासी भारतात आले व त्यांनी भारतातील संपन्नता याविषयी जगाला ओळख करून दिली. युरोपात प्रबोधन झाल्याने औद्योगिक क्रांती व भौगोलिक शोधाने 'व्यापारवादी' युगाला प्रारंभ झाला होता.मोगल बादशहा जहांगीरच्या काळात पाश्चात्त्य देशांनी व्यापारासाठी परवाना प्राप्त करून वसाहती स्थापन केल्या आणि भारतावर व्यापारा बरोबर राजकीय वर्चस्व प्राप्त केले.ब्रिटिशकाळात भारतीय उद्योग हा इंग्रजांच्या हाताचे बाहुले असून अंतर्गत व परराष्ट्र नीती त्यांच्यानुसार अनुकूल करून भारताचे आर्थिक शोषण केले.भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर विविध पंचवार्षिक योजने अंतर्गत आर्थिक सुधारणा करण्याच्या प्रयत्न केला.मध्ययुगात भारतीय अर्थव्यवस्था ही एक मागास अर्थव्यवस्था होती.भारतीय अर्थव्यवस्थेचे धोरण बदलले व अनेक उद्योगपतींनी भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.त्यात टाटा,बिर्ला,बजाज,वालचंद, धीरूभाई अंबानी इ.अनेक उद्योगपतींचा समावेश आहे.स्वातंत्र्य पूर्वीच टाटा व टाटा समूह उद्योग यांचे आर्थिक क्षेत्रात उद्योग व्यापाराला सुरुवात झाली होती. टाटा समूह उद्योगाने विविध वस्तूंची निर्मिती करून जागतिक बाजारपेठेत आपला वेगळा ठसा उमटविला आहे.या उद्योगाचे संस्थापक जमशेटजी टाटा असून वर्तमान काळात या समूहाचे अध्यक्ष उद्योगपती रतन टाटा आहेत.यांनी जागतिकीकरणात आर्थिक क्षेत्रात उद्योगविकासात अत्यंत महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.याविषयी प्रस्तुत विषयावर संक्षिप्त माहिती या संशोधन शोधनिबंधाद्वारे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

की वर्ड्स:- जागतिकीकरण,उद्योग,व्यापार, रतन टाटा,टाटा उद्योग समूह.

संशोधनाचे उद्देश:-

1) भारतातील उद्योग-व्यापाराचा इतिहास याविषयी माहिती प्राप्त करून घेणे.

2) भारतीय औद्योगीकीकरणा बद्दल माहिती मिळविणे.

3) जागतिकीकरणात आर्थिक क्षेत्रात झालेली प्रगती अभ्यासणे.

4) टाटा व टाटा उद्योग समूह विषयी माहिती प्राप्त करणे.

5) टाटा समूहात रतन टाटा यांचे योगदान अभ्यासणे.

संशोधनाचे गृहितके:-

1) प्राचीन काळापासून भारताचा उद्योग,व्यापार विदेशी देशांशी होता.

2) भारतात स्वातंत्र्यानंतर औद्योगीकरणाला सुरुवात झाली होती.

3) जागतिकीकरणात आर्थिक क्षेत्रात भारताची प्रगती झाल्याचे दिसते.

4) स्वातंत्र्यपूर्वी टाटा व टाटा समूह उद्योग अस्तित्व होता.

5 टाटा समूहात रतन टाटा यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण दिसते.

संशोधन पद्धती:-

प्रस्तुत संशोधन द्वितीय स्रोतवर आधारित असून त्यात संदर्भ ग्रंथ,वर्तमानपत्र,मासिक, ई- बुक,विविध वेबसाईट यांचा समावेश केला आहे. इतिहास हा विषय आंतरविद्याशाखीय असून विविध विषयांचा समावेश असल्याने प्रस्तुत संशोधकाने आर्थिक विषयाला अनुसरून एतिहासिक पद्धतीचा वापर केला आहे.

विषय वस्तू:-प्राचीन काळापासून भारतीय उद्योग,व्यवसाय व व्यापार यांचा इतिहास अत्यंत वैभवशाली व गौरवशाली आहे. प्राचीन काळात अंतर्गत व्यापारा बरोबर विदेशी व्यापार केला जात होता.सिंधू संस्कृती,वैदीक संस्कृती,महाजनपद,मौर्य,आदींनी समकाळात विविध देशांशी भारताने व्यापार केलेला होता.प्राचीन काळात संपन्न शेती,कारागिरी व्यवसायांच्या विकास, नाण्यांचा वापर यामुळे व्यापार व्यवसायाच्या विस्तार झाला आणि भारतातील अनेक नगर व शहरे व्यापारी केंद्र बनली. गुप्त कालखंड हा "सुवर्णकाळ"म्हणून ओळखला जातो, तसेच 'भौतिक प्रगतीचे योग' म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. या काळात भारताच्या विदेशी व्यापाराचा विस्तार झालेला होता त्यात ब्रह्मदेश,मलाया,सिलोन,मध्य आशिया,इराण-इराक,चीन,जपान इत्यादी देशांशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले होते. प्राचीन काळात भारताच्या अंतर्गत व्यापार याबरोबर विदेशी व आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा भरभराटीस आल्याने आर्थिक संपन्नता निर्माण झाली होती.मध्ययुगीन काळात भारतात राजकीय विकासाबरोबर सांस्कृतिक परिवर्तन झाले ह्या काळात भारताच्या व्यापार म्यानमार,थायलंड, लाओस,कंबोडिया,मलेशिया,व्हिएतनाम,जावा,सुमात्रा या देशांशी आर्थिक क्षेत्रात व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाल्याने भारताचा आर्थिक विकास झाला.विजयनगर शहराचे अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भरभराटीला आलेला व्यापार होय.मोगल काळात अनेक युरोपियन कंपन्यांनी मोगल बादशहाकडून व्यापारी सवलती मिळवून भारताशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले आणि भारतात वसाहती स्थापन केल्या.कालांतराने ब्रिटिश 'व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले' यानुसार ब्रिटिशांनी भारतावर आपले साम्राज्य निर्माण केले.अठराव्या शतकात बंगाल केवळ भारतातच नाही तर जगात कापड उद्योगाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखले जात होते.1813 मध्ये गव्हर्नरला ब्रिटन संसदेत एक प्रश्न विचारला की "औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतरही ब्रिटनमध्ये तयार झालेला कापड भारतात का विकला जात नाही?यावर गव्हर्नरने उत्तर दिले की "भारतातल्या कापडाची गुणवत्ता ब्रिटनच्या कापडा पेक्षा जास्त आहे"यावरून भारतात औद्योगिक क्रांती झाली नाही तरी भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तू उत्तम दर्जाच्या होत्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताचा विदेशी व्यापार इंग्लंड देशापुरताच मर्यादित होता.भारतातून कृषिप्रधान आणि परंपरागत वस्तूंचा कच्चामाल म्हणून निर्यात केल्या जात असल्याने भारतात यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञानाचा विकास झाला नाही परिणामी औद्योगिक विकास हा मंदगतीने होत होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताची अर्थव्यवस्था ही एक मागास अर्थव्यवस्था होती.ब्रिटन व युरोपियन देशांनी व्यापारातून वसाहतवाद वसाहतवादातून साम्राज्यविस्तार व त्यातून आर्थिक शोषण असे समीकरण निर्माण केले होते.ब्रिटिश काळात भारतातून प्रामुख्याने कच्च्या मालाची निर्यात होत असे तर भारतात पक्क्या मालाची व अन्नधान्याची आयात होत असे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात औद्योगिक प्रगतीसाठी स्वतंत्र विदेशी व्यापार धोरण निश्चित केले.दोन देशांमध्ये होणारा व्यापार म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापार होय.आधुनिक अर्थव्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतात विविध पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतात औद्योगिक विकास मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न केला गेला.जगातील काही देशांनी नैसर्गिक साधन संपत्ती,मानवी साधन संपत्ती,विज्ञान आणि तंत्रज्ञान,संशोधन,आंतरराष्ट्रीय व्यापार इत्यादी माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादन रोजगार आणि राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ घडवून आपल्या देशाच्या विकासाचा वेग वाढविला आहे, तर काही देश वरील घटकांच्या कमतरतेमुळे विकासाच्या बाबतीत मागे पडले आहेत तर काही देशांचा विकास मंद होत आहे. विविध देशातील विकासातील तफावतीतूनच जगाचे विकसित,विकसनशील आणि अविकसित देश असे विभाजन झाले आहे.भारत हा एक विकसनशील देश असल्याने सरकारने विदेशी भांडवल गुंतवणुकीसाठी जे धोरण स्वीकारले आहे.तसेच धोरण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बाबत देखील स्वीकारलेली आहे.1950 नंतर औद्योगिक क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल झाल्याने अनेक देशात योजनापूर्वक औद्योगिक विकास कार्यक्रम हाती घेऊन औद्योगिक विकास करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कोणत्याही देशाच्या औद्योगिक विकास हा देशातील औद्योगीकरण,उद्योग व्यवसायात वाढ,देशाच्या उद्योगात समतोल विकास यावर आधारित असतो.भारताच्या समतोल विकासा बाबतीत डॉ.राधाकमल मुखर्जी यांच्यानुसार,"स्वतंत्र भारतामध्ये संपूर्ण देशीहितासाठी एक राष्ट्रीय आर्थिक योजना असावी आणि दळणवळणाच्या साधनांची उन्नती तसेच जलविद्युत शक्तीचा विकासासोबतच उद्योगाचे विकेंद्रीकरण वैज्ञानिक रीतीने करण्यात यावे, यामुळे संपूर्ण राष्ट्राच्या विकास होऊ शकेल." यासाठी सर्वच विभागांमध्ये उद्योग वाढविले गेले पाहिजे.आद्योगिक विकास म्हणजे केवळ वस्तू निर्मिती करण्याच्या उद्योगाची स्थापना करणे नव्हे तर औद्योगिक विकास ही एक प्रक्रिया असून मागास शेतीप्रधान व दारिद्र्य व्यवस्थेकडून देशाला उद्योगप्रधान व संपन्न व्यवस्थेकडे नेण्याची प्रक्रिया होय.ह्यात तंत्रज्ञानाचा विकास,कामाचे कौशल्य,नियोजन,व्यवस्थापनाचा अनुभव आदी घटकांचा समावेश असतो.देशाच्या आर्थिक विकासात विदेश व्यापाराचे महत्त्व एक वादग्रस्त मुद्दा आहे.ॲडम स्मिथ, रिकार्डो,मिल यासारखे सनातन आणि नवसनातन पंथीय अर्थशास्त्रज्ञ कोणत्याही देशाचा आर्थिक विकास हा विदेश व्यापारावर अवलंबून आहे असे मानतात.ते विदेश व्यापाराला आर्थिक विकासाचे इंजिन मानतात परंतु गुन्नर,मिर्डाल, मिंट,सिंगर यासारखे अर्थशास्त्रज्ञ विदेश व्यापाऱ्याला आर्थिक विकासातील अडसर मानतात असे असले तरी मात्र आर्थिक विकासात विदेश व्यापाराचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. भारतात औद्योगीकरण बद्दल सम्यक दृष्टी असलेली व्यक्ती म्हणून भारतरत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांना ओळखले जाते.त्यांना उद्योग क्षेत्रांमध्ये पहिले भारतरत्न हा पुरस्कार मिळालेला आहे.त्यांच्यानुसार "औद्योगीकरणाची कास धरा नाहीतर विनाशासाठी तयार रहा" ही घोषणा देऊन त्यांनी भारताला औद्योगीकरणाची दिशा दाखवून भारताला खऱ्या अर्थाने विकासाचा एक नवीन मार्ग दाखवून दिला. आधुनिक काळातील दळणवळण, संदेशवहन आणि माहिती-तंत्रज्ञानामुळे भौगोलिक अंतर कमी झाले आणि हे जग एक छोटे गावच बनले.जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला जगातील सर्व राष्ट्रांनी माहिती तंत्रज्ञानाच्या व त्याच्याशी निगडित असलेल्या साधनसामुग्रीचा वापर करून संपूर्ण जग वर्ल्ड वाइड वेब झाले असून जग हेच एक बाजारपेठ बनले आहे. जागतिकीकरणामुळे राष्ट्रांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उद्योगधंद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा वाढली आहे.अनेक उद्योगपतींनी जागतिकीकरणात आर्थिक क्षेत्रात उद्योगात आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. जागतिक पातळीवर जगातील बहुतेक देशांनी 1970 च्या दशकापासून आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला. भारताने जुलै 1991 पासून आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला.औद्योगिकारण म्हणजे जलद आर्थिक विकास होय.विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून विविध देशांनी औद्योगिकीकरणास महत्त्व देण्यात सुरुवात केली.त्याचप्रमाणे भारतानेही औद्योगिकीकरणास महत्त्व दिले.औद्योगिकारण म्हणजे काय?याची अचूक आणि स्पष्ट व्याख्या करणे अवघड असले तरी ओद्योगीकरण म्हणजे वस्तूंची निर्मिती करणारा उद्योग संस्थांमध्ये वाढ घडवून येणे

असा अर्थ घेतला जातो. पै- कैग- चैग यांच्यानुसार,"औद्योगीकरण ही अशी प्रक्रिया आहे की ज्यामध्ये भांडवलाच्या सखोल प्रमाणात व विस्तृत प्रमाणात वापर केला जातो." पॉल एम.स्वीझी नुसार,"औद्योगीकरण म्हणजे नवीन उद्योगाच्या स्थापनेद्वारे केलेली उत्पादनाची निर्मिती होय."विदेशी व्यापाराने आर्थिक विकास होतो तसेच विदेशी व्यापार माध्यमातून विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकास हा विकसित देशाचा सहकार्यावर अवलंबून असतो.भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर विविध पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत औद्योगिक विकास करण्याचा प्रयत्न केला गेला.भारताचे पंतप्रधान मा.पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर 24 जुलै 1991 मध्ये नवीन औद्योगिक धोरणाची घोषणा केली त्यात त्यांनी उदारीकरण.खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा) याच्या स्वीकार करून भारताची अर्थव्यवस्था ही जगासाठी खुली केली.

खाजगीकरण म्हणजे जागतिकीकरणाचा आणि उदारीकरणाचा एक अविभाज्य भाग आहे. खाजगीकरण म्हणजे सरकारी मालकीचे उद्योग खाजगी उद्योजकांना विकणे होय.विविध उद्योगांमध्ये गुंतवलेले सरकारी भाग भांडवल काही प्रमाणात किंवा पूर्णपणे काढून घेणे म्हणजे खाजगीकरण होय उदा. विदेशी संचार निगमचे खाजगीकरण झाले व ते टाटा कंपनीला विकण्यात आले.उदारीकरण म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत उदार धोरण स्वीकारणे म्हणजे उदारीकरण होय. उदारीकरण म्हणजे बंदिस्त किंवा अनियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे मुक्त आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर करणे होय. उदारीकरण म्हणजे अर्थव्यवस्था खुली करणे, किमतीवरचे सरकारी नियंत्रण काढून टाकने,परवाने आणि लायसन्य ची पद्धत रद्द करणे,परकीय भांडवलाचे स्वागत करणे होय. उदारीकरण म्हणजे अर्थव्यवस्था देशी आणि विदेशी खाजगी संस्थांसाठी खुली करणे होय.जागतिकीकरण म्हणजे जगातील विविध अर्थव्यवस्थेचे आपसात एकात्मीकरण घडून घेणे होय.आर्थिक क्षेत्रातील जागतिकीकरण विषयी विविध विचारमंतानी आपले मत व्यक्त केले आहे. स्टिग्लिटझ नुसार,"जागतिकीकरण हे एक जगातील विविध देश आणि नागरिक यांचे घनिष्ठ समन्वयन आहे,जे वाहतूक आणि दळणवळण साधनांचा खर्चातील कपातीमुळे घडून आले आहे याचा परिणाम म्हणून वस्तू व सेवांच्या प्रवाहातील कृत्रिम अडथळे समाप्त झाले आणि सीमांवरून लोकांचे येणे- जाणे वाढले. डॉ. दीपक नायर नुसार," राष्ट्र राज्यांच्या भौगोलिक सीमांत पलीकडे जावून आर्थिक व्यवहारांच्या झालेला विस्तार म्हणजे जागतिकीकरण होय. औद्योगिकीकरण,पाश्चिमात्यीकरण व आधुनिकीकरण या प्रक्रियांचा विस्तारिय असा पुढचा टप्पा म्हणजे जागतिकीकरण होय.जागतिकीकरण ही संपूर्ण जगाची एकच बाजारपेठ निर्माण करणारी प्रक्रिया आहे किंवा जागतिक अर्थव्यवस्था निर्माण करणारी प्रक्रिया आहे. थोडक्यात जागतिकीकरण ही जगातील विविध लोक राष्ट्रे व समाज यांच्यातील आर्थिक, सामाजिक,शैक्षणिक,सांस्कृतिक संबंधाची जागतिक व्यवस्था निर्माण करणारी प्रक्रिया होय.आर्थिक क्षेत्रात जागतिकीकरणाची प्रक्रिया ही विविध माध्यमातून झालेली आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय संघटना,प्रादेशिक संघटना, बहुराष्ट्रीय महामंडळे, बिगरशासकीय संघटना,जनसंप्रेषण साधने, इंटरनेट आदींची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते भारतात जागतिकीकरणात पायाभूत उद्योगाची सार्वजनिक क्षेत्रात उभारणी, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता,औद्योगिक धोरणात योग्य बदल,खाजगी क्षेत्रातील उद्योगधंद्याच्या वाढीस प्रोत्साहन याद्वारे औद्योगिकरणाच्या वेग वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्यात अनेक उद्योगपतींची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

टाटा व टाटा उद्योग समूहाचा उदय:-

भारतीय उद्योगाचे जनक व भीष्मपितामह जमशेटजी टाटा यांनी भारतात सर्वप्रथम कापसाचे व्यवहार करणारी कंपनी स्थापन केली.जमशेटजी टाटा यांना टाटा व टाटा उद्योग समूहाचे संस्थापक म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी लोह,पोलाद,सिमेंट,खाणकाम,कोळसा यासारख्या उद्योगाची सुरुवात केली त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलगा दोराबजी टाटा यांनी काही वर्ष कंपनी सांभाळली पण लवकरच त्यांनी राजीनामा दिला त्यानंतर जे.आर.डी.

टाटा हे टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष झाले.त्यांचे पूर्ण नाव जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा उर्फ 'जेह'होय जे.आर.डी.यांनी टाटा व टाटा उद्योग समूहाच्या विस्तार केला.1931 मध्ये टिस्को कंपनीचे कामकाज सांभाळले.1939 मध्ये 'इंडियन स्टील अँड वायर प्रॉडक्ट'कंपनी स्थापन केली यात टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया,इंडियन स्टँडर्ड मेटल, इंडियन ट्यूब,अॅग्रीकल्चर इम्प्लिमेंटस कंपनी यासारखी अनेक नवी उत्पादने बाजारात आणली जे.आर.डी.टाटा यांनी अनेक पोलाद कंपन्यांशी करार करून "स्टील कॉर्पोरेशन" कारखाना सुरू केला.भारतामध्ये टिस्को कंपनी सर्वात जास्त पोलाद उत्पादन निर्माण करणारा कारखाना असून पोलाद उत्पादनाच्या उद्योगात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.1912 ला सिमेंट उद्योगाला सुरुवात केली,1926 ला विविध सिमेंट उद्योगाशी चर्चा करून एसीसी सिमेंट कंपनी स्थापन केली.हा देशातील अव्वल व मोठा सिमेंट उद्योग म्हणून नावारूपाला आला.1939 ला टाटा केमिकल्सची सुरुवात केली यामुळे देशात रासायनिक खते, फवारणीऔषधे,औषधी,रंगकाम,कंपन्यांसाठीचे केमिकल्स इ. उत्पादने निर्मिती केली ही कंपनी पहिल्या शंभर कंपन्यात गणली जावू लागली.जे.आर.डी.टाटा यांना बालपणापासून विमानाचे प्रचंड आकर्षण होते त्यांनी 1932 एअर इंडिया व इंडिया इंटरनॅशनल स्थापन करून 1948 मध्ये मुंबई ते लंडन ही पहिली आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू केली.ह्यांनी यासाठी त्यांनी जीवापाड मेहनत घेतली होती.त्यांना हवाई क्षेत्रातील सर्वात प्रतिष्ठित असलेला "टोनी जानूस" पुरस्कार मिळाला हा पुरस्कार प्राप्त करणारे ते पहिले भारतीय होय. उत्कृष्ट विमान सेवेबद्दलच्या व्यवस्थापनाबद्दल विविध पुरस्कार मिळाले त्यात एरोनॉटिकल इंटरनॅशनलचे सुवर्ण पदक,एडवर्ड वार्नर अॅवार्ड,डॅनियल गगेनहिम मेडल यांचा समावेश आहे.स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात राष्ट्रीयकरणाला सुरुवात झाली.टाटा समुहाच्या विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयकरण होवून वर्तमानात भारतीय आयुर्विमा महामंडळ नावाने ओळखले जाते. 1990 मध्ये टाटा उद्योग समूहाची मालमत्ता ही 10000 कोटींची होती त्यांनी आपला पुतण्या रतन टाटा यांची टाटा उद्योग समूहाच्या अध्यक्ष पदी निवड केली.जे.आर.डी.टाटा यांनी 29 नोव्हेंबर 1993 ला अखेरचा श्वास घेतला. भारताने त्यांना सर्वोच्च 'भारतरत्न 'पुरस्काराने सन्मानित केले त्यांनी टाटा उद्योग समूहाचे नाव उद्योग जगतात शिखरापर्यंत नेण्याची महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली होती.

रतन टाटा:-28 डिसेंबर1937ला मुंबईत झाला,वडिलांचे नाव नवल होरमसजी टाटा व आईचे नाव सूनू होते.रतन टाटा सात वर्षाचे असताना आई-वडील विभक्त झाले. त्यांचे पालनपोषण त्यांची आजी नवाजबाई यांनी केले त्यामुळे बालपणीच त्यांच्यावर टाटा घराण्याचे संस्कार कोरले गेले.त्यांच्यावर आजी नवाजबाई यांच्या मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव झालेला दिसून येतो.त्यांनी कॉरनेल विद्यापीठातून आर्किटेक्चरची पदवी प्राप्त केली असून हावर्ड बिझनेस स्कूलमधून ऍडव्हान्स मॅनेजमेंटची पदवी संपादन केली.भारतात आल्यावर त्यांना टाटा उद्योग समूहातील कंपनीत प्रशिक्षणासाठी पाठविले.त्यानंतर बिहार येथे दोन वर्षे प्रशिक्षण घेतले.जे.आर. डी.टाटा यांना मुलबाळ नव्हते.टाटा उद्योग समूहात अत्यंत दिग्गज व बुद्धिमान मंडळी होती यातून भावी व वारसदारांची निवड करणे हे अग्निदिव्य काम होते.शेवटी 22 मार्च 1991 मध्ये मुंबईच्या बॉम्बे हाऊस या टाटा समूहाच्या ऑफिसमध्ये जे.आर.डी. टाटा यांनी रतन टाटा यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली.याचे कारण 1983 ला रतन टाटा यांनी 2000 नियोजनात्मक निबंध तयार केला तो जे आर डी टाटा यांना आवडला आणि त्याच वेळेस त्यांना त्यात भावी वारसदार दिसू लागले होते.जेआरडी टाटा म्हणाले,"आता दुसऱ्याच्या हाती सूत्र देण्याची वेळ आली आहे त्याकरता माझ्या उजवीकडे बसलेल्या व्यक्तींचं नाव मी सुचवितो असं सांगून त्यांनी रतन टाटा यांचे नाव घेतले आणि पालनजी यांनी त्यांच्या सूचनेला अनुमोदन दिलं"अशाप्रकारे रतन टाटा यांचे नाव बिनविरोध मंजूर झाले.टाटा व टाटा समूहाचे अध्यक्ष पद स्वीकारले आणि त्यांनी उद्योग-व्यवसायाचे आठ विभागात वाटणी केली.त्यात धातू व त्यासंबंधीचे उद्योग,इंजीनियरिंग रसायने व कृषी आधारित उद्योग,उपयोगिता ग्राहकोपयोगी उत्पादने,विविध सेवा,उच्च तंत्रज्ञान व आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय यावरून त्यांची दूरदृष्टी लक्षात घेता टाटा उद्योग समुहाला नव्या क्षेत्रात प्रवेश करण्याची त्यांची नीती दिसून येते.टाटा उद्योग समूहाचे सूत्र हातात घेताच यांच्या संघर्षाला सुरुवात झाली.शॉप

फ्लोअरवरच्या कामगारांनी यंत्र बंद करून टाटाचे स्वागत केले.राजन नायर व रतन टाटा यात संघर्षाचे कारण त्यांना योग्यपद मिळाले नाही.दुसरे म्हणजे जे.आर.डी.टाटा यांचे विश्वासू सहकारी रूसी मोदी यांना अध्यक्षपद न मिळाल्याने ते नाराज होते.यामुळे टाटा समूहातील रतन टाटा यांना संघर्ष करावा लागला.भारतातील टाटा समूहातील कुशल नेतृत्व म्हणून रतन टाटा त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. एकविसाव्या शतकात आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाले व त्यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक उद्योगांची निर्मिती करून लहान उद्योग व व्यवसायात क्रांतिकारक बदल केले.वर्तमान काळात 250 यावर उद्योग आहेत.घरातील मिठापासून तर आकाशातील हवाई वाहतूक पर्यंत नानाविध उद्योग निर्माण केले.सर्वसामान्यांनाही कारने प्रवास करता यासाठी त्यांनी स्वप्नातील कार म्हणजे नॅनो कार अतिशय कमी किमतीत उपलब्ध करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहिले.यात त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले पण माघार न घेता धाडसी निर्णय घेऊन ती कार सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिली.

कंपनी	कंपनी कार्यक्षेत्र
टिस्को	लोह पोलाद
टेल्को	मोटार
टाटा टेन्ले	चहा
व्होल्टास होम अप्लायन्सेस	घरगुती सामान
एसीसी सिमेंट	सिमेंट
टॉल्मो	ऑइल प्रॉडक्ट
इंडियन हॉटेल्स ताज ग्रुप	हॉटेल
टाटा केमिकल्स	रसायन उद्योग
टाटा एअरलाइन्स	हवाई सेवा
टाटा लोकोमोटिव्हज	रेल्वे इंजिन
टाटा एनर्जी	विद्युत वितरण

रतन टाटा यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. टेल्को व ट्रक व वाहन निर्मिती कारखान्यातून दर्जेदार उत्पादने निर्माण केली.त्यात त्यांनी टाटा ट्रक,टाटा 800,टाटा सिएस,टाटा सुमो, टाटा सफारी,टाटा इंडिका यासारखी वाहने निर्मिती करून त्यांनी ग्राहकांस सोबत आपले नाते निर्माण केले.2007 ला लंडन स्थित 'कोरस स्टील' समूह टाटा स्टील ने विकत घेतला हा जगातील सर्वाधिक मोठा खरेदी-विक्रीच्या उद्योग जगतातील व्यवहार होता.2010 ला 'टाटा स्टील युरोप लिमिटेड' असे त्यांचे नाव करण्यात आले.जागतिक पातळीवर सर रतन टाटा यांच्या कामगिरीमुळे आधुनिक उद्योगाचे जनक म्हणून ते ओळखले जाऊ लागले.एका भारतीय उद्योजकाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेली ही एकमेव कामगिरी असावी.वर्तमानात 21000 कामगार असून 127 मिलीयन डॉलर्स उत्पन्न होत असून आज युरोपातील 100 देशात या कारखान्यातील निर्मित लोह पोलादाचा वापर

केला जातो. March मार्च 2008 रोजी रतन टाटा अंतर्गत टाटा मोटर्सने फोर्ड मोटर कंपनीकडून जगुआर व लँड रोव्हर कंपनी खरेदी केले. ब्रिटीश लक्झरीचे प्रतीक जगुआर आणि लँड रोव्हर 1.5 अब्ज पाउंड ($ 2.3 अब्ज डॉलर्स) मध्ये विकत घेतली गेली.आज जगभरात टाटा समूहाच्या 250 कंपन्या आहेत त्या सोबत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात टाटा कन्सल्टंन्सी,टाटा एनर्जी, टाटा इंडिकॉम, टाटा मनी,टाटा लाइफ केअर,टाटा स्काय,टाटा नेट,टाटा पॉवर आधी होय.त्यांचे फक्त आर्थिक क्षेत्रात महान कामगिरी नाही तर सामाजिक क्षेत्रातही त्यांचे कार्य उल्लेखनीय आहे. देशाच्या विकासासोबत सामान्य नागरिकांचे जीवन सुखकर व्हावे, त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारावा म्हणून एका शतकाहून अधिक काळ टाटा उद्योगसमूह कार्यरत आहे. रतन टाटा यांना २००० सालामध्ये पद्मभूषण (भारताचे तिसरे सर्वोच्च सन्मान) पुरस्कार व २००८ मध्ये पद्मविभूषण (भारताचे दुसरे सर्वोच्च मानधन) पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले होते.अशा महान उद्योगपतीस सलाम…

निष्कर्ष:-

उद्योगपती रतन टाटा यांनी फक्त भारतातच नाही तर अखिल जगतात उद्योग क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे.जी.आर. डी टाटा यांनी अध्यक्षपदी निवड करून त्याच्यावर टाकलेली जबाबदारी त्यांनी समर्थपणे सांभाळलेली आहे.जागतिकीकरणात माहिती तंत्रज्ञानात टाटा समूहाने जी प्रगती केली त्यात रतन टाटा यांचे योगदान मोलाचे आहे.रतन टाटा यांचे यशाचे गमक म्हणजे त्यांचे नियोजन, धाडसी निर्णय,कणखर आणि खंबीर नेतृत्व होय ते उद्योगपती जगतात यशस्वी उद्योगपती म्हणून ओळखले जातात.ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यशस्वी उद्योजक आहेत त्यांनी टाटा समूहाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्तम व्यवस्थापन केले आहे.त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे उत्तम माहिती असून देशातील लोकांना नेमके कोणते उत्पादन हवे यावर लक्ष केंद्रित करून ते वस्तूचे उत्पादन करत असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टाटा समूहाचे सफल नेतृत्व केल्याचे दिसते.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करावयाची असेल तर आधुनिक तंत्रज्ञान यंत्रसामुग्री याच्या स्वीकार केला पाहिजे.उद्योगपती रतन टाटा यांनी टाटा समूह व्दारे अनेक वस्तूंचे उत्पादन करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवले आणि जगभर टाटा समूहाचा विस्तार केला. जिथे कमी तिथे आम्ही या विचाराने प्रेरित होऊन त्यांनी जगाला जोडण्याचे काम केले. सामाजिक बांधिलकी, सामान्यांविषयी तळमळ, प्रामाणिक देशप्रेम, प्रचंड मेहनत, जिद्द चिकाटी यांच्या आधारावर टाटांनी भारताला जगाच्या नकाशात जे स्थान मिळवून दिलं आहे त्यासाठी संपूर्ण देश सदैव त्यांच्या ऋणात राहील.

संदर्भसूची

1. घोरपडे अक्षय,विजेंद्र पाटील (2017) बिजनेस लेजंडस,प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव.
2. पिरामल अनुवाद अशोक जैन, (2017) बिजनेस लेजंडस, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे.
3. आचार्य धनंजय,(2011) विसाव्या शतकातील जग,साईनाथ प्रकाशन,नागपूर द्वितीय आवृत्ती.
4. चव्हाण एन.एल.(2020)भारतीय अर्थव्यवस्था,प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव
5. फडतरे भूषण गोविंद (2015)विसाव्या शतकातील जगाचा इतिहास,अथर्व प्रकाशन, पुणे.
6. https://mr.wikipedia.org/wiki
7. https://www.marathibiography.com/ratan-tata-biography-in-marathi/
8. https://marathivarsa.com/education/amazing-facts-about-ratan-tata-in-marathi/
9. https://punerispeaks.com/tata-motors-information-in-marathi/

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे धार्मिक विचार

श्री. तेलसंग हनमंत भिमराव
संशोधक विद्यार्थी, सामाजिक शास्त्रे संकुल, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर.
Email - hanumanttelsang@

प्रस्तावाना -

विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये विशेष कार्य केले. विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा जन्म 23 एप्रिल 1873 रोजी कर्नाटक राज्यातील जमखंडी या संस्थानातील गावामध्ये झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव रामजी व आईचे नाव यमुनाबाई होते. वयाच्या नवव्या वर्षी त्यांचा विवाह त्यांच्या आत्याची मुलगी रुक्मिणी हिच्याबरोबर झाला. घराण्याची पूर्वापार संपत्ती गेल्यामुळे वडील रामजी हे काही काळ संस्थानामध्ये शिक्षकाची व कारकुन स्वरूपाची नोकरी करीत होते. विठल रामजी शिंदे याचे वडील पंढरपुरचे वारकरी व विठ्ठलाचे भक्त होते, त्यामुळे घरात धार्मिक वातावरण होते. आई सात्विक वृत्तीची असल्याने घरातील वातावरण जातीभेदाला थारा न देणारे होते.

जमखंडी येथे इंग्रजी शाळेतून 1811 साली विठ्ठल रामजी शिंदे मट्रीक ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले व 1893 मध्ये ते पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये दाखल झाले. विठ्ठल रामजी शिंदे यांची बहिण जनाबाई हिचा तिच्या सासरी छळ झाल्यामुळे त्यांनी तिलाही पुण्यामध्ये आणले आणि हुजूरपागा शाळेमध्ये घातले. श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांचेकडून मिळणारी कर्जाऊ शिष्यवृत्ती व खाजगी शिकवण्यांच्या थोड्याफार मिळकतीवर काटकसरीने राहून 1898 मध्ये विठ्ठल रामजी शिंदे बी.ए. उत्तीर्ण झाले. 1895 साली अमेरिकन युनेटीरिअन मिशनरी रेव्ह.जे.टी.सँडरलँड यांच्या व्याख्यानामुळे त्यांना एकेश्वर मताचा परिचय झाला. एकेश्वरवादी प्रार्थना समाजातील न्या.रानडे, रा. गो. भांडारकर, का. बा. मराठे यांच्या विचारांचा व सहवासाचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला. 1898 मध्ये त्यांनी प्रार्थना समाजाची दीक्षा घेतली. त्याच वर्षी ते कायद्याच्या अभ्यासासाठी मुंबईला गेले.

अभ्यासाचे उद्देश –

1. विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या कार्याविषयी माहिती करून घेणे.
2. विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या यांच्या कर्माची निष्ठा समजून घेणे.
3. विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या कामाची पद्धत समजून घेणे.
4. विठ्ठल रामजी शिंदे यांची अस्पृश्य लोकांबद्दलची तळमळ समजून घेणे.

विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे धार्मिक विचार –

मुंबई येथील प्रार्थना समाज व कलकत्ता येथील ब्राम्हो समाज यांनी विठ्ठल रामजी शिंदे यांची शिफारस केल्यानंतर ब्रिटीश अँड फॉरेन असोसियेशन ने त्यांची ऑक्स्फर्ड येथील मँचेस्टर कॉलेजमध्ये धर्म शिक्षण घेण्यासाठी निवड झाली. 1901 ते 1903 ही दोन वर्षे त्यांनी मँचेस्टर कॉलेजमध्ये तौलनिक धर्मशास्त्र, ख्रिती धर्मशास्त्राचा इतिहास, समाजशास्त्र, पाली भाषा व बौद्धधर्म यांचा अभ्यास केला. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी भारतात येण्यापूर्वी 1903 च्या सप्टेंबर मध्ये ॲमस्टरडॅम येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय उदार धर्मपरिषदेस ब्राम्हो समाजाचे भारतातील प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहून हिंदुस्थानातील उदार धर्म या विषयावर त्यांनी निबंध सादर केला. 1903 मध्ये मुंबईत आल्यानंतर प्रार्थना समाजाचे धर्म प्रसारक म्हणून त्यांनी कार्यास प्रारंभ केला.

धार्मिक कार्य –

विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी धर्म प्रचार कार्यात आपली कल्पकता व आपले संघटन कौशल्य दाखविले. पोस्टल मिशन, उदार धर्मग्रंथ वाचन वर्ग, तरुण ब्राम्हो समाज हे उपक्रम सुरु केले. मुंबई आणि मुंबईच्या बाहेरील प्रार्थना समाजामध्ये त्यांनी धर्मावर आधारित अनेक व्याख्याने दिली. प्रार्थना समाजाच्या सुबोध पत्रिका या मुखपत्रामध्ये सातत्याने धर्म विषयक लेखन केले. याचबरोबर विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मिशन स्थापन करून ते धडाडीने चालविले. तसेच त्यांची राजकारणाविषयी जहाल मते मुंबई प्रार्थना समाजातील धुरीणींना पसंत

नसल्याने प्रार्थना समाजाचे प्रसारक म्हणून त्यांचा असलेला संबंध 1910 मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर देखील त्यांनी आपले धर्मकार्य चालूच ठेवले. 1923 मध्ये मंगळूर येथे त्यांनी ब्राम्हो समाजाचे आचार्य म्हणून कार्य केले. पुण्यामध्ये 1928 मध्ये कौटुंबिक उपासना मंडळाची स्थापना केली. 1933 मध्ये वाई येथील ब्राम्हो समाजाच्या धर्म विषयक कार्यामध्ये विठ्ठल रामजी शिंदे सहभागी झाले होते. जीवनाच्या अंतापर्यंत ते एकनिष्ठ ब्राम्ह होते.

शतकानुशतके बहिष्कृत अवस्था लादून अस्पृश्य ठरल्यामुळे ह्या वर्गाला प्राप्त झालेला निकृष्ठपणा नाहीसा करून त्यांना स्वाभिमानी सुशिक्षित आणि उद्योगी बनविणे, हा त्यांनी आपल्या कार्याचा भाग मानला. उच्चवर्णीयांच्या मनातील अस्पृश्यांविषयी भ्रामक समजुती नष्ट करणे, हा त्या कार्याचा दुसरा भाग होता. डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन स्थापनेनंतर लगेच मुंबई, परळ, देवनार, कामाठीपुरा या भागामध्ये अस्पृश्यांसाठी मराठी शाळा आणि उद्योग काढले. निराश्रीत स्त्रियांची सेवा करण्यासाठी सेवासदन काढले. विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या भगिनी व वृद्ध आई-वडील हे या लोकांची सेवा करण्यासाठी त्यांच्या वस्तीमध्ये जाऊन राहिले. मुंबई बाहेर पुणे, मनमाड, अकोला, अमरावती, नागपूर, महाबळेश्वर याचबरोबर भावनगर, हुबळी, बेंगलोर, धारवाड, चेन्नई इ. ठिकाणी या मिशनच्या शाखा काढण्यात आल्या. या मिशनच्या स्थापनेनंतर 6 वर्षातच एकंदर 14 ठिकाणी 23 शाळा, 55 शिक्षक, 1100 मुले, 5 वसतिगृहे, अन्य 12 संस्था व 7 आजीवक प्रचारक एवढा मिशनच्या कामाचा व्याप विठ्ठल राकाजी शिंदे यांचेकडे होता. 1912 मध्ये त्यांनी या मिशनचे कार्यालय मुंबईहून पुण्यास हलविले. महात्मा फुले यांनी भोकरवाडी मध्ये ज्या जागेत अस्पृश्यांसाठी शाळा उघडली होती, ती जागा नगरपालिकेकडून संपादित करून श्रीमंत तुकोजीराव होळकरांच्या व मुंबई सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने सव्वा लाख रुपये खर्च करून अहिल्याश्रम ही सोयीस्कर इमारत बांधली. अस्पृश्यता निवारण कार्याचे 1920 पर्यंतचे पहिले पर्व हे जागृतीचे म्हटले, तर विठ्ठल रामजी शिंदे हे या पर्वाचे प्रवर्तक ठरतात. या पुढील पर्व संघर्षाचे व त्याचे प्रणेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. 1923 साली मिशन ही संस्था अस्पृश्यवर्गीय प्रतिनिधींच्या स्वाधीन करून विठ्ठल रामजी शिंदे बाहेर पडले. यानंतर ही पर्वती मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, अस्पृश्यांची शेतकरी परिषद, संयुक्त मतदार संघाची योजना इ. बाबतीत ते अस्पृश्य वर्गाच्या हिताच्या दृष्टीने सक्रियपणे भाग घेत होते. अशा या महान समाजसुधारकाचे 2 जानेवारी 1944 मध्ये निधन झाले.

निष्कर्ष –

1) विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या धार्मिक कार्याविषयी माहिती मिळविता आली.
2) विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या कामाची निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा आत्मसात करता आला.
3) विठ्ठल रामजी शिंदे यांची अस्पृश्यांबद्दल असणारी तळमळ समजून घेता आली.
4) विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या कामाचे आकलन झाले.

संदर्भ –

1. दिघे पी. डी., दोन कर्मवीर, कोल्हापूर, 1982.
2) पवार गो. मा., विठ्ठल रामजी शिंदे, नवी दिल्ली, 1990.
3) इंटरनेट लिंकिंग.
4) वर्तमानपत्र कात्रणे.
5) स्मरणिका.

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

जागतिकीकरणाचे प्रखर चित्रण करणारी कथासंग्रह 'गुलाबी सिर - द पिंक हेडेड डक'

प्रा. डॉ. अशोक गौरीशंकर माळगे
सी.बी. खेडगीज कॉलेज, अक्कलकोट
Email : malage79@gmail.com

प्रास्ताविक

1990 नंतर भारतीयांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, तसेच सांस्कृतिक जीवनात मोठे स्थित्यंतर घडताना दिसते. भारतीय आर्थिक धोरण टप्प्याटप्प्याने परंतु आक्रमकपणे उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या मार्गाने विकसित होत गेले. धर्ममूलतेकडे असलेला कल वाढत जाऊन त्याने धर्मांधतेचे भयंकर रुप धारण केले. त्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून मंदिर-मस्जितवाद, कारसेवा आणि बाबरी मस्जित विध्वंसन होण्यासारखे प्रकार घडले. याशिवाय समाजात विविध कारणांने अनेक उग्र आंदोलने झाली. भारतीय समाजात असहिष्णुता वाढत जाऊन धर्माच्या नावाने देशभर दंगली उसळल्या, समाजाचे धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण झाले. दुसरीकडे बदलत्या अर्थव्यवस्थेने सामान्य माणसाचे जगणे असाह्य बनले. गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावत गेली. बेकारी, कुपोषणाचे प्रमाण वाढले. बेकारीने व भ्रष्टाचाराने कळस गाठला. खेडी ओस पडून शहराकडे बेरोजगारांचा तांडा वळला. बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेच्या लाभार्थीचेच आर्थिक जीवनमान उंचावतच गेले. मॉलसंस्कृती, वाढते सेवाक्षेत्र, कॉलसेंटर्स, जाहिरातबाजी, माहिती-तंत्रज्ञानाचे वाढते महत्त्व व निर्माण झालेले जाळे, महागाई, भ्रष्टाचार, चंगळवादी संस्कृतीचा उदय व प्रभाव, मध्यमवर्गाची मूल्यभ्रष्टता, शेटजी, भटजी आणि लाटजीची अभद्र युती यातून साधनवंचिताच्या अमानवीकरणाच्या प्रक्रियेस गती आली. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा असमतोल निर्माण झाला. वसुंधरेचे वाढते तापमान सामाजिक अनारोग्याच्या समस्या, स्त्रियांचे उपभोग्य वस्तूत होऊ घातलेले अथवा झालेले रुपांतर, औद्योगिकीकरणाचे वाढते क्षेत्र, सेझ आणि शेतकऱ्यांची नागवणूक, वेश्या व्यवसायात झालेली वाढ, तसेच वाढलेली जातीयता इत्यादी अमानवीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देणाऱ्या घटना या काळात घडू लागलेल्या दिसतात. दुसरीकडे या काळात वरील शोषकव्यवस्था, धर्मवाद, अमानवीकरण, पर्यावरणाचा विध्वंस याविरुध्द जगभर तसेच भारतातही समतावादी, स्त्रीवादी, पर्यावरणवादी, लोकशाहीवादी चळवळींचा उदय झाला. या सर्वाचे परिणाम मराठी साहित्यावर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून येतात. कथा वाङ्मयही त्याला अपवाद नाही.

नव्वदीच्या दशकापासून देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या एकूण वास्तवात महत्त्वाचे बदल होऊ लागले. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यामुळे नवमध्यवर्गाचा झालेला उदय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वाढलेले प्राबल्य, विवक्षित अर्थशास्त्र समजून घेऊन त्यात स्वस्थान निर्माण करण्यासाठी आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या जीवघेण्या स्पर्धा, या स्पर्धेत कराव्या लागणाऱ्या तडजोडी, आत्यंतिक व्यक्तिवादातून आलेली आत्ममग्नता, अर्थकेंद्री जीवनव्यवहार, चंगळवादी जीवनशैलीचे स्तोम, हे सामाजिक संदर्भ हा काळ समजून घेताना विचारात घ्यावे लागतात. विशिष्ट आर्थिक धोरण स्वीकारल्यामुळे एका बाजूने ग्लोबल होऊ पाहणारा माणूस दुसऱ्या बाजूने विविध अस्मितांच्या चिरेबंद चौकटीत बंदिस्त होऊ लागण्याची प्रक्रियाही याच काळात गतिमान झालेली दिसते. धर्म, जात या संवेदनशील घटितांकडे राजकीय हितसंबंधाच्या प्रेरणेतून पाहिल्यामुळे समाजात सर्वस्तरीय असुरक्षितता निर्माण करणारा हा काळ आहे. राममंदिर-बाबरी मशीद प्रकरण, मुंबई बॉम्बस्फोट, गोध्रा हत्याकांड या घटना याच सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय रचिताचे अपत्य आहेत. या सगळयाचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे मानवी समाजाचे छोट्या छोट्या, विवक्षित गटांमध्ये विघटन झाले. समाजात विधायक बदल घडविण्यासाठी आवश्यक

असणारे समग्राचे चिंतन परिघावर सरकले. स्वजात, धर्म, स्वप्रदेश, स्वभाषा अशा आत्यंतिक चिंचोळ्या अवकाशात मानवी जगण्याच्या कल्पना बंदिस्त करण्याचे सांस्कृतिक राजकारणही या काळात बेमालूमपणे खेळले गेले. या दोन दशकात परिवर्तनवादी चळवळीही जवळजवळ प्रभावहीन झालेल्या दिसतात. याचा अर्थ समाजात सर्वस्तरीय अराजक निर्माण करणारा व समाजाला संभ्रमित करणारा हा काळ आहे, असे म्हणता येईल. जागतिकीकरण ही विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकारंभाच्या काळात ठळकपणे आणि वेगाने घडलेली एक विश्वव्यापी घटनासदृश प्रक्रिया होती, तर त्या घटनेचा परिणाम होऊन नव्वदोत्तर कालखंडातल्या, मराठी कथा वाङ्मयावर काय पडसाद उमटले अथवा उमटत आहेत याचा वेध घ्यायचा प्रयत्न केला आहे. जागतिकीकरणाचे मानवी जीवनावर झालेल्या परिणामाचे प्रखर चित्रण करणारी एक कथासंग्रह म्हणजे संतोष शिंत्रे यांचा 'गुलाबी सिर-द पिंक हेडेड डक' हा होय. मार्च 2012 मध्ये प्रकाशित झालेल्या या संग्रहात एकूण नऊ कथा आहेत.नव्वदोत्तरी एक महत्वाचे नाटककार व पत्रकार म्हणून लौकिकप्राप्त संतोष शिंत्रे यांचा हा एक महत्वाचा कथासंग्रह आहे. 'गुलाबी सिर-द पिंक हेडेड डक', ' नव्या शतकाच्या पहिल्या अकरा वर्षामध्ये लिहिलेल्या या कथा आहेत. माणसाचं व्यक्तिगत आणि सामूहिक अस्तित्व कधी वेढून, कधी उजळून, कधी झाकोळून तर कधी भोवंडून, चक्रावून टाकणारी ही वर्ष. माध्यम, तंत्रज्ञान, संधी, आव्हानं, आवाहन, मूल्यं, माणुसकी, परस्परसंबंध, शोषण, सामाजिक वास्तव सगळच ढवळून काढणारी वर्ष सोबतीला निसर्गाच्या सतत होणाऱ्या ऱ्हासाची गिरमिटयुक्त जाणीव, कुठेतरी आशेची एक न संपणारी लकेरही येथे प्रकटते. यातील 'गुलाबी सिर-द पिंक हेडेड डक' मधील कथा म्हणजे 'अपेक्षाभंग' आणि 'भ्रमनिरास' या जुन्या दोस्तांच्या सोबतीनेच पण आशेच्या त्या लकेरीसह या सगळया जाणिवांना, बदलांना एका ताज्या लिहित्या मनानं दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद म्हणावे लागेल. "श्रेयस आणि प्रेयस, यिन आणि यांग, सत्प्रवृत्ती आणि दुष्टप्रवृत्ती यात निवड करणं किती अवघड आहे... किंवा काही वेळा आपल्या मनाचा लंबक कोणत्या बाजूला जाऊन स्थिरावेल हे सांगणंही फार अवघड आहे."1"तत्वं, नीतिमूल्यं, बांधीलकी या सगळयाच गोष्टी बाकी परिस्थिती आलबेल, सुशेगात असताना किती सोप्या वाटतात. पाण साक्षात मृत्युच समोर दिसतो, त्या असहाय अवस्थेत सगळे निकषच उलटेपालटे होतात. आणि सगळं मंथन झाल्यावर तळाशी उरते, ती फक्त जीवनलालसा"2

संतोष शिंत्रे यांची कथा अशा प्रकारच्या जीवघेण्या मूलभूत पेचांची असते. संशोधन आणि पर्यावरण या दोन विषयांच्या पार्श्वभूमीवर माणसापुढे येणारे असले श्रेयस-प्रेयसाचे, चांगल्या-वाईटाचे पेच शिंत्रे मांडतात आणि शेवटी शिंत्रे यांचे नायक नैतिक श्रेयसाचा निर्णय घेऊन त्याची मोठी भौतिक किंमत चुकवतात. पण अंतिमत: खऱ्याखुऱ्या श्रेयसाचे धनी होतात. साहजिकच या कथा वाचताना सुबोध जावडेकरांच्या 'कुरुक्षेत्र' या कथासंग्रहाची आठवण होते. जावडेकरांच्या कथेत माणसाला विज्ञान आणि औद्योगिक जगताच्या पार्श्वभूमीवर असेच नैतिक-अनैतिकतेचे पेच पडतात. आणि तिथेही बहुतेक वेळा नैतिकतेच्या, श्रेयसाच्या दिशेने नायक झुकतात.'गुलाबी सिर...' या कथेतला संशोधन सॅम्युअल पिशवीकर असो किंवा 'यिन, यँग...' कथेतले साताळकर असोत, यांच्या विशिष्ट विषयातल्या अफाट ज्ञानामुळेच त्यांच्यासमोर अचानक प्रचंड मोठ्या भौतिक लाभाची संधी येते. अर्थात त्यासाठी त्यांना आपल्या प्राणप्रिय मूल्यांचा बळी देण्याची अट असते. आणि अशा वेळी हे नायक पूर्ण विचारांती सत्प्रवृत्तीच्या बाजूने कल देतात आणि भौतिक प्रेयसाकडे पाठ फिरवतात. या कथांमधल्या वाचकाला सहसा परिचित नसणाऱ्या वातावरणाच्या तपशीलांची अस्सलता हे संतोष शिंत्रे यांचे खरे बलस्थान आहे. 'गुलाबी सिर...' या कथेत म्यानमारमधल्या जंगलाचे आणि तिथल्या वनस्पती आणि पशुपक्ष्यांचे तपशील इतके अस्सल आहेत की, कथा वाचताना आपणही सॅम्युएलबरोबर त्या वाटेवरुन चालत असल्याचा भास होतो. सॅम्युअल पिशवीकर हा संशोधक पाणबदकांच्या संशोधनात जगप्रसिध्द असतो आणि रोनित बारुआ आणि जेराल्ड बॅक्स्टर हे दोन वन्यजीवतस्कर त्याचं अपहरण करुन करोडो रुपयांच्या तस्करीमध्ये येण्याची ऑफर सॅम्युएलला देतात. आणि ही ऑफर स्वीकारली नाही तर सॅम्युएलला आपले प्राण गमवावे लागतील असेही स्पष्ट करतात. ही तस्करी असते पृथ्वीच्या पाठीवरुन नामशेष होत चालेल्या अत्यंत दुर्मिळ आणि अतिसुंदर अशा गुलाबी डोक्याच्या बदकांची परदेशातले संग्राहक यासाठी

पाच कोटी डॉलर द्यायला तयार असतात. अर्थात त्यासाठी सॅम्युएलसारख्या जगविख्यात संशोधकाच्या सर्टिफिकेशनची मोहोर आवश्यक असते. एकीकडे करोडो रुपये आणि दुसरीकडे प्रत्यक्ष प्राणांची भीती अशा कात्रीत सापडलेला सॅम्युएल यातून कसा अफलातून मार्ग काढतो ते कथेत चित्रण केले आहे. थ्रिलर, रहस्यकथा, विज्ञानकथा, गूढकथा आणि बोधकथा यातले थोडेथोडे सगळे असूनही या कोणत्याच गटाचा शिक्का मारु नये अशी ही भन्नाट कथा आहे.शिंत्रे यांच्या कथेत सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरण-वन्यप्राणी संरक्षक वारंवार भेटतात. 'डॉट कॉम आणि डॉट ऑर्ग' सारख्या कथेत तर आधी ते एकमेकांसमोर उभे ठाकतात आणि मग एकत्र येतात. 'उद्यापासून सुरुवात' सारख्या कथेत जंगलातल्या आदिवासी वगैरे पोरांना हाताशी धरुन वन्यप्राणी तस्कारांशी मुकाबला घेणाऱ्या पेठेंची कथा आहे. एकूणच समाज, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, ह्यूमन राइट्सवाले यांपैकी कुणालाच खरे तर पर्यावरणाची, वन्यजीवांची काही चिंता अथवा पर्वाच नसते. आणि राज्यकारणी, गुंड आणि स्वार्थांध कंपन्या तर काय लुटालूट करायलाच टपलेले असतात. या सगळ्याविरुध्द उभे राहणारे नायक इथे भेटतात. 'हस्तरेषांच्या ललाटरेषा' ही कथा मात्र एक अगदीच वेगळा प्रयोग आहे. इतिहासातील काही घटना आणि पात्रे घेऊन त्याभोवती कल्पनेने ही कथा रचलेली आहे. याची पार्श्वभूमीही संशोधनाचीच आहे. हाताच्या बोटांच्या ठशावरुन गुन्हेगार शोधण्याचे तंत्र विकसित होण्याची ही गोष्ट संतोष शिंत्रे यांनी वेधक पध्दतीने सांगितली आहे. त्यातही संशोधक, वैज्ञानिकांतही कामाचे श्रेय मिळवण्यासाठीची चढाओढ दाखवली आहे. उच्च बुध्दीच्या संशोधकातले हे माणूसपण शिंत्रे कलात्मकतेने अधोरेखित करतात. याउलट 'मारिच' सारख्या कथा मात्र रीतसर रचलेली गुन्हेगारकथाच आहे. एक गमतीदार पण उत्कठावर्धक किस्सा अशा स्वरुपातली आहे. आध्यात्मिक आश्रमाच्या प्रमुखांचा विश्वास प्राप्त करुन घेऊन एक भामटा त्यांनाच कसा गंडा घालतो त्याची ही कथा आहे. 'एम्पथी' सारखी गोष्ट देखिल गमतीदार किस्सावजाच आहे. आणि ज्या कथेवरुन गाजलेले नाट्यरुपांतर केले गेले ती 'पावटॉलॉजी..' ही कथा देखिल एक गमतीदार किस्साच आहे.अशा काही किस्सेवजा गोष्टी वगळल्या तर संतोष शिंत्रे आणि कथाविश्व एखाद्या क्षेत्रातले संशोधक आणि त्यांचा मूल्यविवेक याभोवती फिरताना दिसते. पुस्तकातच दिलेल्या परिचयातून हे कळते की संतोष शिंत्रे यांचे शिक्षण सूक्ष्मजीवशास्त्र क्षेत्रातले तर नोकरी जैवतंत्रज्ञानाधारित उत्पादनांचे मार्केटिंग करण्याची आहे. त्यांच्या कथेत तपशीलांची अस्सलता असण्यामागे त्यांचे शिक्षण आणि व्यवसाय आहे. त्यामुळे त्यांची कथा केवळ प्रतिभेने नव्हे तर ज्ञान आणि अभ्यासाने श्रीमंत झालेली दिसते. पण तपशीलांच्या अस्सलतेमुळे शिंत्रे यांची कथा केवळ माहितीपर होत नाही किंवा नुसतीच घटनांची मालिका असणारी हकिकत होत नाही हे त्यांचे यश आहे. शिंत्रे याची कथा ही 'कथा'च असते कारण त्यांचा मुख्य रोख असतो ते माणसाचे माणूसपण शोधण्यात. मात्र एक आहे, शिंत्रे शोधतात आणि दाखवतात ते माणूसपण बहुतेक वेळा 'आदर्श' आणि स्वप्नवत माणूसपण असते. कारण ते कथेतल्या पात्रांची सुष्ट आणि दुष्ट अशी सरळ विभागणीच बहुतेक वेळा करतात. आणि आदर्शवादी पध्दतीने सुष्टांचे उदात्तीकरण करतात. 'गुलाबी सिर', 'उद्यापासून सुरुवात' किंवा 'यिन आणि यँग' सारख्या कथांतून पात्रांचे हे काळे किंवा पांढरे असणे अगदीच ढोबळ पध्दतीने येते. मात्र 'मारिच' सारख्या एखाद्या एरवी तद्दन रचीव गुन्हेगारी वाटणाऱ्या कथेत मात्र पात्रांचे काळे-पांढरे असणे धूसर होत एकमेकात मिसळले जाते. कारण इथे फसवणारा राजपाठक आणि फसवले गेलेले 'बापू' दोघेही म्हटले तर काळेच आहेत. अध्यात्माच्या नावाखाली करोडो रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती गोळा करणारे 'बापू' फसवले गेले तरी वाचकाची सहानुभूती मिळवत नाहीत. इतर बहुतेक कथांमध्ये पात्र लेखक म्हणून शिंत्रे आणि त्यांचे प्रोटॅगोनिस्ट सत्, नैतिक आणि श्रेयसवादी भूमिका घेत बहुसंख्य वाचकांना अपेक्षित अनुभूती आणि 'निर्णय' देण्याचा सोयीस्कर मार्ग स्वीकारतात. त्यामुळे या उत्तम असणाऱ्या कथा एका अर्थाने ढोबळ आणि बाळबोध होतात. वाचकाने 'आपण स्वत: खरेच अशा वेळी काय करु?' असा विचार न करता 'अशा वेळी काय केलेले चांगले असेल?' अशा सार्वकालीन नैतिक आणि सत् वैचारिकतेत यावे अशीच शिंत्रे यांची योजना असते. तपशीलांची अस्सलता आणि 'स्मार्ट' आणि शैलीदार अभिव्यक्ती यांच्यामुळे ती योजना कमालीची यशस्वी होते ते मात्र आवर्जून नोंदवायला हवे.

प्रा. डॉ. अशोक गौरीशंकर माळगे

कथासंग्रहाच्या शेवटी दिलेल्या मनोगतात शिंत्रे म्हणतात, "माणसाच्या व्यक्तिगत आणि सामूहिक वर्तनातले बदल, काही अत्यंत निषेधार्ह प्रवृत्तींच समाजमान्य होऊन रुजणं, राजकारणी उद्योगक्षेत्र ही युती करत असलेली निसर्गाची, संसाधनाची लूट हे सगळं मी माझ्या चूक-बरोबर नजेरनं टिपत होतो. माध्यमामंध्ये आणि समकालीन साहित्यात यातले बरेचसे विषय उमटतच नव्हते. हे सगळंच कुठेतरी या लेखनात उमटलं असावं"3 शिंत्रे म्हणतात त्याप्रमाणे हे सारं अगदी नेमकेपणानं आणि प्रभावीपणे त्यांच्या कथेत उमटले आहेच. मुख्य म्हणजे शिंत्रे याची करुणा केवळ माणुसकीपुरती सीमित नाही तर अवघी सृष्टीच त्यात सामावली जाते. हे वैश्विक कारुण्य जपत उत्तरोत्तर शिंत्रे यांच्या कथेचा प्रवास अधिक सुलभ होताना दिसतो.

निष्कर्ष :

1. जागतिकीकरणाचे परिणाम 1990 नंतर सर्वच घटकांवर जाणवू लागले. त्याचे पडसाद मराठी कथा वाङ्मयावर उमटलेले दिसून येतात.
2. 1990 नंतर जागतिक पातळीवर अनेक चांगले-वाईट घटना घडले. अनेक बदल घडून आले. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर, माध्यमांचा वापर, नवीन निर्माण झालेली संधी व आवाहन, मूल्ये-माणुसकी, परस्परसंबंध शोषण, सामाजिक वास्तव, संशोधन आणि पर्यावरण या दोन विषयांच्या पार्श्वभूमीवर माणसापुढे येणारे श्रेयस-प्रेयसाचे, चांगले-वाईटाचे पेच या सर्व गोष्टीचे वेध संतोष शिंत्रे यांनी 'गुलाबी सिर-द पिंक हेडेड डक' या संग्रहात घेतला आहे.

संदर्भ व टीपा

1. रा.ग. जाधव , 'निवडक समीक्षा' पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, प्र.आ. 2006
2. म.द.हातकणंगलेकर, 'मराठी कथा रुप आणि परिसर', सुपर्ण प्रकाशन, पुणे/औरंगाबाद, प्र.आ. 1986.
3. भीमराव कुलकर्णी, 'साहित्यिकी', चिरायू प्रकाशन, पुणे प्र.आ.1987.
4. इंदुमती शेवडे, 'मराठी कथा उद्गम आणि विकास', सोमैय्या पब्लिकेशन्स, मुंबई प्र.आ.1973.
5. राम कोलारकर, सर्वोत्कृष्ट मराठी कथा - उत्तरार्ध, 'पॉप्युलर प्रकाशन', मुंबई प्र.आ.2006.
6. संतोष शिंत्रे, 'गुलाबी सिर-द पिंक हेडेड डक,' मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई, प्र.आ. मार्च 2012, पृ. 83, 84
7. तत्रैव. पृ. 27
8. तत्रैव. पृ. 141

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

पर्यावरणविषयक चळवळी

डॉ. हरी साधू वाघमारे
भूगोल विभाग, संभाजी कॉलेज (Arts, Comm. & Sci.), मुरूड, ता.जि. लातूर-413531
Email : hariwaghmare68@gmail.com

प्रास्तावना :

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून समाजात विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी चळवळी होत आल्या आहेत. तथापि २० व्या शतकापासून "पर्यावरणविषयक चळवळी" हा समाजातील एक वेगळाच सूर ऐकू येत आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या व होत असलेल्या शास्त्रीय प्रगतीची ही परिणती आहे. दुसऱ्या महायुद्धाचे भयानक परिणाम जपान अजून भोगत आहे. लोकसंख्येचा विस्फोट झाला असून (झपाट्याने वाढत असून) महासंहारक शस्त्रे व अस्त्रे निर्माण झाली आहेत. अफगाणिस्तान व इराक, तसेच पॅलेस्टाईनमध्ये होत असलेला, भारतात काश्मीर खोऱ्यात चाललेला नरसंहार जगाला कोणत्या अवस्थेला नेणार आहे, याबद्दल सर्वजण साशंक आहेत. 'बलवान तोच जगेल' या निसर्ग नियमाचा चुकीचा अर्थ लावून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मानवी धुमाकूळ चालू आहे. वास्तविकपणे "नैसर्गिक परिस्थितीत जो जगेल तो जगेल' असा त्याचा अर्थ आहे. पृथ्वी हा एकमेव ग्रह मानवी अस्तित्वास योग्य आहे. ही जाणीव दुसऱ्या महायुद्धानंतर माणसास झाली. तिसरे महायुद्ध झाले तर फक्त इमारतींचे सांगाडे व झुरळांसारखे कीटक शिल्लक राहतील, असे अनुमान जाणकारांनी काढले आहे. म्हणूनच पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने मानवी हालचाल सुरू झाली आहे, तिलाच पर्यावरणविषयक चळवळ म्हणता येईल.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. पर्यावरण विषयक चळवळीची व्याख्या व पर्यावरणाचे प्रकार अभ्यासणे.
2. व्यक्तिगत, संस्थात्मक व गटात्मक चळवळींची ओळख करणे.
3. अंधश्रद्धा निर्मूलन ही एक पर्यावरणीय चळवळ कशी ते स्पष्ट करणे.
4. पर्यावरण चळवळींना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कसा हातभार लावता येतो हे स्पष्ट करणे.

1] पर्यावरणविषयक चळवळी :

"पर्यावरणाच्या 'चळलेल्या' म्हणजे ढासळलेल्या व ढासळणाऱ्या स्थितीला 'वळणावर' म्हणजे योग्य स्थितीला, घेऊन येण्यासाठी (राखण्यासाठी) माणसाने सातत्याने केलेली किंवा चालविलेली कृती, म्हणजे पर्यावरणीय चळवळ" अशी व्याख्या करता येईल. हे पर्यावरण दोन प्रकारचे असते.

1. **नैसर्गिक पर्यावरण :**
   a. यात मानवापूर्वी अस्तित्वात असणारे घटक व मानव स्वतः यांचा अंतर्भाव होतो. डोंगररांगा. त्यांची दिशा, उंची, आकार, नद्यांचे प्रवाह, धबधबे, जलाशय, मृदा व जमीन, वातावरण, हवामान, जंगले, प्राणी, सूक्ष्मजीव, मानव, चंद्रसूर्य-तारे यांचा यात समावेश होतो.
2. **मानवनिर्मित पर्यावरण :**

a. मूळ नैसर्गिक गोष्टींचा वापर करून व त्यात बदल घडवून माणसाने तयार केलेल्या पर्यावरणाला सामाजिक किंवा सांस्कृतिक पर्यावरण असेही संबोधतात. यात खाणी, बागा, इमारती वा घरे, रस्ते, शेती, कारखाने, पशुपालनकेंद्रे, मानवी कुटुंबे, मानवनिर्मित विविध पदार्थ, इत्यादींचा समावेश होतो.

निसर्गप्रकोपामुळे (वादळे, पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ, भूकंप, ज्वालामुखी उद्रेक, भूस्खलन, वीज पडणे, हिमवृष्टी, उष्णता वा थंडीची लाट, रोगराई, इत्यादी कारणांनी) मानवी जीवनास अपायकारक परिस्थिती निर्माण होते, किंवा मानवी चुकांमुळे (जंगलतोड, जमीनधूप, वाळवंटीकरण, वन्यजीव हत्येमुळे तुटणारी अन्नशृंखला; हवा-जल-वायू-मृदा-ध्वनीकचरा यांचे प्रदूषण, धरणे फुटून येणारे पूर, युद्धे, सामाजिक कलह, इत्यादी) प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होते. ती पूर्वपदावर आणण्यासाठी जे मानवी प्रयत्न होत असतात, ती पर्यावरणविषयक चळवळ होय. दुसऱ्या शब्दांत असे म्हणता येईल की निसर्गप्रकोप व मानवी चुका या पर्यावरणविषयक चळवळीला चालना देणाऱ्या असतात.पर्यावरणविषयक चळवळी प्रथम व्यक्तिगत पातळीवर घडतात, नंतर त्याचे संस्थात्मक वा गटात्मक म्हणजे सहकारी पातळीवर दृढीकरण होते, तसेच सरकारी मदतही होते. त्याची काही उदाहरणे आपण पाहू.

2] व्यक्तिगत, संस्थात्मक वा गटात्मक चळवळी :

(१) श्री. सुंदरलालजी बहुगुणा व 'चिपको' आंदोलन

भारताच्या उत्तर सीमेवरील हिमालय पर्वताच्या रांगा म्हणजे विविध प्रकारच्या उपयुक्त वनस्पतींचा व वन्य जीवांचा खजिनाच. या वृक्षांच्या आधाराने हिमालय पर्वतातील जमीन धूपेपासून सुरक्षित होती. तथापि व्यापाऱ्यांनी जंगलतोडीस प्रोत्साहन दिल्याने गढवाल भागांत व परिसरात पूर, इंधन, भूस्खलन, चाराटंचाई आदी समस्या उभ्या राहिल्या. राजकीय वजन वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांमुळे जंगल वाचविणे अवघड बनले. परंतु श्री. सुंदरलालजी बहुगुणा यांनी आपले आयुष्य वृक्ष वाचविण्यासाठी वेचण्याचे ठरवून सुमारे १० हजार किलोमीटरचा पायी प्रवास केला व वृक्षसंवर्धनाचे महत्त्व जनतेस समजावून दिले. लाकूडतोडे जंगलात आले की वृक्षास मिठी मारून प्रथम आपल्यावर वार करा असे बहुगुणा सांगू लागले. त्याचा परिणाम होऊन स्थानिक लोकांनी पुढाकार घेऊन त्याचा अनुनय केला. यांत सुमारे ४०० लोक मृत्युमुखी पडले. पण ही चळवळ बंद पडली नाही. वृक्षास मिठी मारून बसण्याच्या पद्धतीमुळे या चळवळीस 'चिपको आंदोलन' नाव पडले. राखी पौर्णिमेस झाडांना राख्या बांधून संकेतात्मक उत्सव केला. १९८१ मध्ये त्यांना पद्मश्री बहाल झाली होती. शिवाय नंतर त्यांना राष्ट्रीय एकात्मता व जमनालाल बजाज पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. जागतिक स्तरावर या कार्याची दखल घेण्यात येऊन अवलंबन केले जात आहे. पृथ्वी व स्त्रिया यांच्या बद्दलची कणव श्री. सुंदरलालजी बहुगुणा यांच्या या महानकार्याला कारणीभूत झाली.

(२) पश्चिम घाट बचाव योजना

ही एक सामाजिक चळवळ समजली जाते. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही लोकांनी एकत्र येऊन सह्याद्रीच्या पश्चिम उताराकडच्या जंगलाचे संरक्षण व संवर्धन करावयाचे ठरविले. त्यासाठी विद्यापीठीय मदतीचा हातभार लाभला. यांत वनश्रीबरोबरच जंगल प्राण्यांच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न गुंतला होता. 'जागतिक पर्यावरण संरक्षण योजनेचे' प्रमुख मार्गदर्शक श्री. अँथल व्हॉन कोटतलीट्झ यांनी त्याची योग्य दखल घेतली आहे.

(३) श्री. के. सी. श्रॉफ (रासायनिक परिषदेचे माजी अध्यक्ष) :

यांना महत्त्वपूर्ण प्रयोगांबद्दल (पर्यावरणविषयक) कामटेक फाऊंडेशनचे पहिले पारितोषिक लाभले. त्यांनी एक चळवळ म्हणून बडोद्याजवळ रसायन कारखान्यांच्या जवळ असलेल्या विहिरींच्या सभोवताली विश्वामित्री नदीतील गढूळ पाणी आणवून झाडे वाढविली. परिणामी त्या आटलेल्या विहिरींना कालांतराने पाणी लाभले. भावनगर भागात विशिष्ट वनस्पती वाढवून जमिनीतील नायट्रोजन संतुलन राखले. निलगिरीची वने वाढवून खाऱ्या जमिनीचा कायापालट केला.

(४) महाराष्ट्रातील सामाजिक वनीकरण :

महाराष्ट्र सरकारने सहकारी पातळीवर व व्यक्तिगत प्रोत्साहनावर सामाजिक वनीकरणाची चळवळ राबविली आहे. सरकारने प्रत्यक्षात वनीकरण करण्याऐवजी लोकांकडूनच ते करवून घेतले जाते व आवश्यक तेथे आर्थिक मदत केली जाते. कमी पर्जन्य प्रदेशात कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळणे, जमिनीतील जलपातळी संतुलित राहणे, आसमंतातील वातावरण थंड राहावे अशा पर्यावरणीय बहुउद्देशाने ही चळवळ अस्तित्वात आली व यशस्वी झाली. या योजनेतील सातत्य व लोकांकडून मिळणारा प्रतिसाद यांतून ही चळवळ उदयास आली.नाशिक जिल्ह्यातील श्री. विनायकराव पाटील यांच्यासारख्या किंवा अहमदनगर जिल्ह्यातील श्री. विखे पाटील पांच्यासारख्या प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने व 'झाडे जगवा झाडे वाचवा' या योजनेअंतर्गत सध्या काही उपाययोजना उत्स्फूर्तपणे अमलात येत आहेत. त्यांत हिंदुधर्मीयांत लाकडांच्या वापराऐवजी शव दहनास “विद्युत दाहिनी" चा वापर वा “डिझेल दाहिनी'चा वापर वाढतो आहे. दसऱ्यास आपट्याची पाने मोठ्या प्रमाणावर नष्ट केली जातात. ती "आपटा" वनस्पती औषधी असून तिच्या संरक्षणाची चळवळ उभारणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमधील अशा प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादाने ही यशस्वी चळवळ उभी राहिली आहे.

(५) श्री. विलासराव साळुखे (जिल्हा पुणे)

यांना पाणी पंचायतीचे प्रणेते असे म्हणतात. पुणे जिल्ह्यात पुरंदर तालुक्यात 'नायगांव' भागात त्यांनी उपलब्ध पाण्याचा कमाल उपयोग करण्याचा प्रयत्न यशस्वीपणे राबविला. दुष्काळी परिस्थितीने लोक स्थलांतर करीत असत. २५ वर्षांपूर्वी त्यांनी सुमारे हेक्टरी १ लाख घनफूट पाणी वापरून ६००० झाडे वाढविली. यात १/३ झाडे, फळझाडे असल्याने रोजगार संधी लाभली व स्थलांतर प्रमाण एकदम घटले. त्यांचा स्वीडन देशातर्फे सन्मान करण्यात आला.

(६) प्रा. श्री. तुळशीराम जाधव

हे नगर जिल्ह्यातील संगमनेरचे सामाजिक कार्यकर्ते असून त्यांनी पाणलोट क्षेत्र विकासाचे महत्त्व लोकांना कळण्यासाठी जनजागर कार्यक्रम सातत्याने चालविला आहे. पथनाट्यासारख्या माध्यमांतून ते जनजागृती करतात. प्रा. उल्हास पाटील व श्री. सारंगधर पांडे यांची संहिता लाभल्याने सदर कार्यक्रमाला सहकारी चळवळीचे स्वरूप आले. उत्तर महाराष्ट्र, द. महाराष्ट्र, प. महाराष्ट्र असे विभाग घेऊन प्रचार कार्य करीत आहेत अशी माहिती श्री. डी.के. वैद्य यांच्या 'जडणघडण' नामक लेखाद्वारा दैनिक सकाळ (२५.३.०३) वाचनात आल्याने सौजन्याने येथे उल्लेख केला आहे.

(७) श्री. विश्वेश्वरय्या

हे प्रसिद्ध स्थापत्य विशारद होते व त्यांना त्यांच्या सामाजिक पर्यावरणास पूरक कार्याबद्दल भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. धरण बांधल्यानंतर लोक विस्थापित होऊन सामाजिक पर्यावरण बिघडते. श्री. विश्वेश्वरय्या यांनी कर्नाटकात धरणांच्या योजना राबविण्यापूर्वी धरणाच्या पाण्याखाली जाणाऱ्या वस्त्यांना प्रोत्साहन दिले. आज ज्या योजनेची केंद्र सरकार हे खासदार श्री. सुरेश प्रभु यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्तता करीत आहे, ती गंगा-कावेरी नद्या जोडण्याची संकल्पना यांचीच आहे.

(८) श्रीमती मेधा पाटकर

धरण-विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी व मोठ्या धरणांमुळे नैसर्गिक व सामाजिक पर्यावरणाचा होणारा हास टाळण्यासाठी आज अनेक वर्षे श्रीमती मेधा पाटकर एक चळवळ राबवीत आहेत. रुंद व जास्त उंच धरण बांधले तर नदीचा पाणी फुगवटा क्षेत्र वाढून अगोदर वसलेली गावे पाण्याखाली जातात, पर्यावरण बदलते, लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागते. त्यांच्या मूळ जमिनी गेल्याने जीवन उभारणीस मदत अपेक्षित असते. तथापि सरकारांतर्फे प्रामाणिकपणे मदत प्रत्यक्षात पूर्णपणे मिळत नाही. नर्मदा नदीवर गुजरात, मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र राज्यांच्या पाणीसमस्येवर उपाय म्हणून सरदार सरोवर हे धरण बांधण्याचे ठरविले. परंतु अगोदर ठरविलेली उंची वाढविण्याचे गुजरात सरकारने ठरविले व परिणामी जमिनी, जंगले व आदिवासी लोकांचे जीवन धोक्यात आले. त्याला विरोध करण्यास व छोट्या योजनांच्या फायद्याचा प्रचार व प्रसार करण्याची मोठी चळवळ श्रीमती मेधा पाटकर यांनी उभारली आहे व आजही ती सुरू आहे. त्यांच्या जबरदस्त मनोधैर्याचा आदिवासींवर परिणाम घडून ही एक सामाजिक चळवळ बनली आहे.

(९) राळेगणशिंदीचे श्री. अण्णासाहेब हजारे

अहमदनगर हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून महाराष्ट्रात ओळखला जातो. दुष्काळी असल्याने वृक्षांची कमतरता, रखरखीतपणा, उन्हाळ्यात स्थलांतर अशी परिस्थिती ग्रामीण भागात आढळते. राळेगण शिंदी या गावचे श्री. अण्णासाहेब हजारे या समाजसेवकांनी श्रमदानाचे महत्त्व गावकऱ्यांना पटवून दिले. स्वत: वृक्षारोपण करून अगदी कावडीकावडीने त्यांना पाणी देऊन एक “हरित क्रांती" घडवून आणली. टेकडीवरून पावसाचे ओघळणारे पाणी साठवण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात एक चळवळ म्हणून राबविली. त्याला सर्व आबालवृद्धांनी हातभार लावला. परिणामी इतर गावांचा कायापालट करण्याची प्रेरणा त्यांना मिळाली. आज हे एक आदर्श गाव बनले आहे.

३] अंधश्रद्धा निर्मूलन : एक पर्यावरणीय

चळवळ विविध धर्मांची स्थापना विशिष्ट पर्यावरणात झाल्याने त्या पर्यावरणाशी निगडित प्रथा निर्माण झाल्या. बदललेल्या पर्यावरणाशी तादात्म्य पावण्याच्या दृष्टीने समाजमन बदलत नसल्याचे लक्षात येऊन काही तरुणांनी समाजातील अनिष्ट वाटणाऱ्या रूढी बदलण्याचा चंग बांधला आहे. पूर्वीपासूनच टिळक, आगरकर, फुले, आंबेडकर, सावरकर, इत्यादींनी आपल्यापरीने अनिष्ट प्रथा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहेच. तत्पूर्वी तुकारामांसारख्या संतांनी यासंदर्भात ताशेरे ओढलेच होते. "वृक्ष-वल्ली आम्हां सोयरी वनचरे" या अभंगातून त्यांचे पर्यावरण प्रेम व्यक्त होतेच. अलीकडच्या काळातील ताशेरे ओढणारा संत म्हणून संत गाडगेबाबांचे नाव घ्यावे लागेल. 'ग्रामस्वच्छता अभियान' ही चळवळ त्यांच्याच प्रेरणेचे फळ होय. अशाच महान व्यक्तींच्या विचारधारेतून अंध:श्रद्धा निर्मूलन चळवळ उभी राहिली. श्री. दातरंगे, दाभोळकर व त्याचे सहकारी गावोगाव जाऊन भाषणे, प्रत्यक्ष प्रयोग व पथनाट्याद्वारे भोंदूगिरीवर आघात करतातच पण त्याचबरोबर नाग किंवा साप, अजगर अशा प्राण्यांविषयीचे गैरसमज दूर करून त्यांची भीती घालविण्याचे विधायक काम करीत आहेत. अन्नशृंखलेत हे प्राणी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शेतकऱ्यांचे ते उपकारकर्ते आहेत. त्यांना न मारता पकडून योग्य ठिकाणी सोडून द्यावे' हा विचार आता हळूहळू लोकांना पटू लागला आहे. श्री. लकडे गुरुजीसारखे साप पकडण्यात पटाईत असणारे लोक, कोठे वस्तीत साप निघाल्यास पकडून योग्य जागी सोडून देतात.सध्या पुण्याच्या सर्पोद्यानाचे व्यवस्थापन पाहणारे श्री. निलमकुमार खैरे यांनी विषारी सर्पांच्या सान्निध्यात, बंदिस्त जागेत दीर्घ काळ वास्तव्य करून जागतिक

विक्रम (गिनीजबुकात नोंद) केला आहे. आजही जखमी पक्षी वा वनचरांवर तेथे वैद्यकीय उपचार करून योग्य पर्यावरणात परत सोडले जाते.

"देवराई' हा ग्रामस्थांचा खरा अंधश्रद्धेचा भाग पण पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने उपयुक्त. बऱ्यापैकी पर्जन्य असलेल्या काही भागात टेकडीचा एखादा भाग देवासाठी सोडून दिलेला असतो. तेथील झाडांना व प्राण्यांना ग्रामस्थांचे संरक्षण असते. त्यामुळे दुर्मिळ वनस्पतींचा हा खजिनाच असतो. ही ग्रामस्थांची पर्यावरणविषयक चळवळच म्हणता येईल.

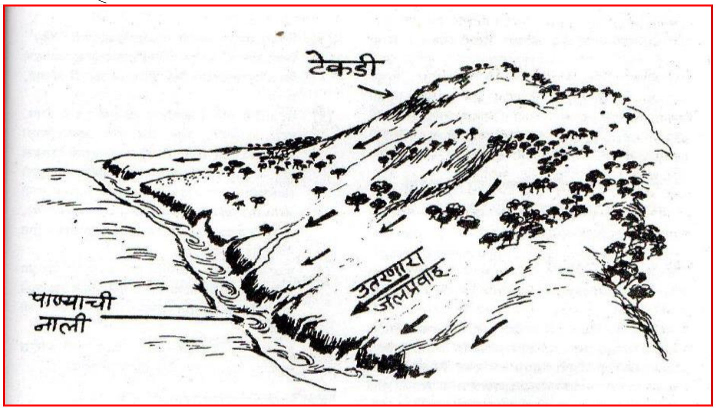

आकृती क्रमांक 1 : पाणी आडवा पाणी जिरवा अंतर्गत डोंग पायथ्याजवळ केलेली जलवाहिका

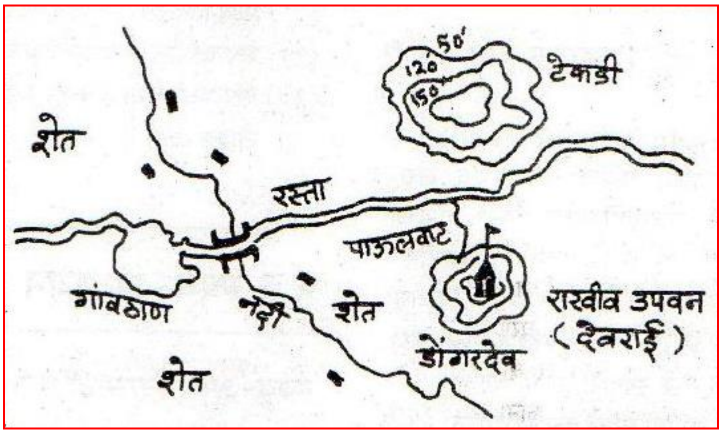

आकृती क्रमांक 2 : देवराई संकल्पना

४] चळवळींना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हातभार

काही व्यक्ती वा संस्थांचा पर्यावरणविषयक चळवळींना मिळालेला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हातभार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यासाठी स्वत: पर्यावरणाचा अभ्यास करून इतरांना प्रेरणा देणाऱ्या काही व्यक्ती वा संस्थांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.पक्षी निरीक्षक डॉ. सलीम अली यांनी स्वत: विविध पक्षांचे निरीक्षण करून माहिती संकलित केली. त्याची प्रेरणा अनेकांनी घेऊन दरवर्षी विविध तलावांवर ते पक्षी निरीक्षण करीत असतात. पुण्याचे श्री. प्रकाशगोळे व श्री. परांजपे यांनी वनस्पतीविषयक व वन्यजीवविषयक कार्य चालविले आहे. जीम कार्बेट यांचेही वन्यजीवविषयक योगदान महत्त्वाचे आहे.श्रीमती जमाल आरा लिखित 'पक्षी जगत' कै. मनोहरदासजी चतुर्वेदी लिखित 'मनी मावशीचा परिवार', बेंडा बिरम लिखित "कॅट्स", श्री. रस्किन बॉंड लिखित "वृक्षांच्या विश्वात कै. डॉ. वि.म. गोगटे लिखित औषधी वनस्पतीविषयक पुस्तके, तसेच मारुती चित्तमपल्ली यांची वन्यजीवविषयक पुस्तके, लेख; भारतीय सर्प विज्ञान संस्था व अंध:श्रद्धा निर्मूलन समिती, पुणे प्रकाशित “सर्प म्हणावा आपुला' ही पुस्तिका; डिस्कव्हरी, नॅशनल जिऑग्राफीकसारखे

टी.व्ही. चॅनल्स व मासिके, दिबॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी प्रणीत "स्टॅफेंडर्स' व "दि फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया' (इंडिया हाऊस) तसेच व्हिसलर लिखित बुक ऑफ इंडियन बर्डस" इत्यादी साहित्य प्रेरणादायक आहे.

पर्यावरणविषयक संतुलन राखण्यास काही संस्थाही हातभार लावीत आहेत.

1. **W.W.F. (World Wildlife Fund) :** ही आंतरराष्ट्रीय संस्था स्वित्झर्लंड स्थित असून वन्यजीवांविषयी जनजागृती करीत असते. युनोच्या मदतीने निबंधस्पर्धा, व्याख्याने, प्रदर्शने, प्रत्यक्ष सहली असा उपक्रम राबविला जातो. अनेक देश सदस्य असून भारतात ती “WW.F- India" म्हणून ओळखतात. ही संस्था १९६९ मध्ये स्थापना झाली. यांच्या अंतर्गत ५००च्या वर निसर्गप्रेमी मंडळे कार्यरत आहेत. दुर्मिळ जीवांकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जाते. संशोधन केले जाते.
2. विविध संस्था, व्यक्ती यांच्यातर्फे प्रतीवर्षी “दिन' साजरे होतात. उदाहरणार्थ, वृक्षारोपणदिन, पर्यावरण दिन, वसुंधरा दिन, विज्ञानदिन, वन्यप्राणी सप्ताह, इत्यादी. सरकारी मदतीने व जनतेच्या सहकार्याने पक्षी, वाघ, हरणे, काळवीट, सिंह, गवे, गेंडे, इत्यादींसाठी अभयारण्ये तयार करण्यात आली असून त्यांची देखभाल होते. उदाहरणार्थ, बोरीवली (वन्यजीव), रेहकुरी (काळवीट), गीर (सिंह), कर्नाळा व नाशिक-वापी रस्त्यावर एका डोंगराळ भागांत (पक्षी अभयारण्य), मेळघाट (व्याघ्र), ताडोबा (वन्यजीव),आसाम भागात गवे व गेंडे, इत्यादी.
3. कचऱ्याचे प्रदूषण टाळण्यासाठी 'घंटागाडी'सारख्या उपयुक्त योजना आखल्या आहेत. यात सातत्य असल्याने नाशिकसारख्या शहरात स्वच्छता राहण्यास मदत झाली आहे.
4. प्रसिद्ध व्यंग चित्रपटकार वॉल्ट डिस्ने यांची कार्टून्स प्राणीप्रेम वाढीस लागण्यास हातभारच लावतात.

सारांश :

निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी त्याचे मूळरूप आहे तसेच ठेवणे आवश्यक आहे. माणूसच त्याचे (निसर्गाचे) रूप बदलत असून जीवनविषयक समस्या निर्माण करीत आहे. ती दूर करून स्वत:च्या आरोग्याबरोबरच निसर्गाचेही आरोग्य (ढाचा) कायम राखण्यासाठी मानवाची सातत्याने चाललेली धडपड म्हणजे “पर्यावरणीय चळवळ' म्हणता येईल. यात व्यक्तींचे विविध प्रकारे होणारे प्रयत्न (संकल्पना, लेख, भाषणे, प्रदर्शने, इत्यादी) संस्था वा जनतेचा लाभणारा हातभार (आर्थिक व प्रत्यक्ष श्रमाचा) व सरकारी मदत यामुळे ही चळवळ यशाकडे वाटचाल करते. 'पृथ्वी' हा एकमेव ग्रह मानवी अस्तित्वाचा व अस्तित्वास योग्य असल्याची जाणीव माणसाने सतत ठेवून "पर्यावरण चळवळीचा" एक भाग होऊन राहणे इष्ट आहे.

संदर्भ सूची :

1. पर्यावरण व परिस्थितिकी : अतुल कोटलवार, इंद्रजीत यादव
2. पर्यावरण : सुमंत सुभाषराव सोळंके
3. पर्यावरण अभ्यास : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक
4. पर्यावरण आणि परिस्थितिकी : निरज नचिकेता

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

जागतिकीकरणाचा कृषी क्षेत्रावरील परिणाम

अभिनव गजानन फुटाणे
बी.टेक.-३(कृषी जैवतंत्रज्ञान) श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ ॲग्रीकल्चर बायोटेक्नॉलॉजी, अमरावती

सारांश :

ज्या देशाला आपला आर्थिक विकास साध्य करावयाचा असेल त्याने जागतिकीकरणाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. कारण त्या माध्यमातून देशातील समस्या उदा. स्पर्धा, कार्यक्षमता, उत्पादकता, किंमत स्थैर्य, यांत्रिक सुधारणा, आधुनिकीकरण इत्यादी बाबींमध्ये आवश्यक ते बदल घडून येतात. भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषीवर अवलंबून असून या भारतीय अर्थव्यवस्थेत जागतिकीकरण करण्याचे अनेक प्रयत्न केले गेले आहेत. त्याकरीता उद्योग, व्यापार, गुंतवणूक आणि इतर अनेक हक्क यामध्ये भारत व जगातील इतर देश यांचे एकत्रिकरण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. तसाच प्रयत्न भारतीय कृषी क्षेत्राच्या जागतिकीकरणाबाबत करण्यात आला आहे. जागतिकीकरणात आंतरराष्ट्रीय व्यापार मुक्त करण्यात येतो. आयात व निर्यात यावर बंधने नसतात. सर्व व्यवहार हे बाजारातील मागणी व पुरवठा यानुसार चालतात. तसेच भांडवली वस्तूचे उत्पादन, तंत्रज्ञान, सेवा-सुविधा यामध्ये देशी-विदेशी असा भेदभाव केला जात नाही. कोणत्याही देशात तयार झालेली वस्तू कोणत्याही बाजारपेठेत विकता येते. तात्पर्य असे की, जगातील कोणत्याही ठिकाणी तयार झालेली वस्तू उपभोक्त्याला खरेदी करता येऊ शकते. जागतिकीकरणामुळे अविकसीत, विकसनशील व विकसीत राष्ट्रांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. ही स्पर्धा अशक्त व सशक्तांमध्ये आहे. अशक्त राष्ट्रांना या स्पर्धेमध्ये टिकून राहायचे असेल तर सशक्तीकरणाचे मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अविकसीत राष्ट्रांनी कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात अनुदाने द्यावीत, जी गॅट कराराच्या मर्यादेत बसतात. आज गहू, तांदूळ यासारख्या अन्नधान्याची निर्यात भारत करतो. अन्नधान्याच्या उत्पादनातील वाढीचा दर हा कृषी क्षेत्राची कार्यक्षमता दर्शवितो.

बीजशब्द :जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण, औद्योगिकीकरण, तंत्रज्ञान, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था, कृषी उद्योग.

प्रस्तावना :

'जागतिकीकरण' हा शब्द वेगवान आणि व्यवसाय व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशांचे एकीकरण तसेच परस्परावलंबन सूचित करतो. जागतिकीकरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर एकत्रिकरण करणे होय. २० व्या शतकाच्या शब्दकोशानुसार 'जागतिकीकरण' म्हणजे जगभर पसरणे, एकाच वेळी संपूर्ण जगाचा किंवा जगातील सर्व लोकांचा विचार करणे होय. त्यात व्यापार, विदेशी थेट गुंतवणूक, भांडवल प्रवाह, प्रवास आणि तंत्रज्ञान यांच्या प्रसाराच्या माध्यमाने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांसाठी खुले केले जाते. भारतात १९९० च्या सुमारास जागतिकीकरणाला सुरुवात झाली. जागतिकीकरणात बाजार, नियम, कर रचना, आयात

शुल्क, साहाय्य, विक्री, व्यापार संघटन, तोडगा अशा व्यवसायाशी निगडीत सेवांचा समावेश होतो. जागतिकीकरण हे दळणवळण आणि तंत्रज्ञानामुळे तीव्र होत जाते.'जागतिकीकरण' ही संज्ञा अलीकडे लोकप्रिय झाली असली तरी, ही प्रक्रिया १९ व्या शतकापासून सुरु झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलीग्रामपासून ते २० व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणूकीवरील निर्बंध यामधील लवचिकतेतून जागतिकीकरण सुरु झाले. जागतिकीकरणाचा परिणाम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अशा सर्वच क्षेत्रावर झालेला दिसून येतो. सामाजिक क्षेत्राचा विचार केल्यास, कुटुंब व्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती,जनजाती, भाषा इत्यादी घटकांवर जागतिकीकरणाचा फार मोठा प्रभाव पडलेला आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग आणि वृध्दांचे जीवनमान या जागतिकीकरणामुळे प्रभावित झालेले आहे. तसेच ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. एवढेच नव्हे तर, जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात तर जागतिकीकरणामुळे बरेच परिवर्तन झालेले दिसते. सांस्कृतिक क्षेत्राचा विचार केल्यास, लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध या जागतिकीकरणामुळे पार बदललेला आहे. अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या गोष्टी तर लोकांच्या नित्य परिचयाच्याच झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणाचा प्रभाव जसा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या क्षेत्रावर झालेला आहे त्याचप्रमाणे त्याचा प्रभाव कृषी क्षेत्रावर सुध्दा झालेला आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रावर या जागतिकीकरणाचे अनेक चांगले-वाईट परिणाम झालेले आहेत. चांगल्या परिणामांचा विचार केल्यास कृषी उत्पादन आणि रोजगारात या जागतिकीकरणामुळे वाढ झाली आहे. शेतकऱ्याला बी-बियाणे खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य यामुळेच मिळालेले आहे. शेती आदानावरील सबसिडी व निर्यात, बियाण्यांचा निर्मिती हक्क, संकरीत बी-बियाण्यांच्या उत्पादनात वाढ, सुती कापड निर्यातीत वाढ, खतांच्या आयातीत वाढ, कृषीवर आधारित उत्पादनाच्या निर्यातीत वाढ अशा कृषी क्षेत्रातील सकारात्मक गोष्टी जागतिकीकरणामुळेच घडून आलेल्या आहेत. पण या जागतिकीकरणामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना प्रगत देशांशी स्पर्धा करणे अशक्य झाले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी या जागतिकीकरणामुळेच वाढलेली आहे. एवढेच नव्हे तर, कंत्राटी शेती पध्दतीची सुरुवात ही सुध्दा जागतिकीकरणाचीच देण आहे. या जागतिकीकरणामुळे लहान शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊन कृषी क्षेत्रावर संकटाचे सावट निर्माण झालेले आहे.

उद्दिष्ट्ये :''जागतिकीकरणाचा कृषी क्षेत्रावरील परिणाम'' या शोध निबंधाकरीता जी उद्दिष्ट्ये अध्ययनाकरीता घेण्यात आली ती अशी-

१) जागतिकीकरणाचा अर्थ स्पष्ट करणे.

२) भारतातील कृषी क्षेत्रावर प्रकाश टाकणे.

३) जागतिकीकरणाचा कृषीवरील अनुकूल परिणाम अभ्यासणे.

४) जागतिकीकरणाचा कृषीवरील प्रतिकूल परिणाम अधोरखित करणे.

संशोधन पध्दती : प्रस्तुत शोध निबंधाकरीता 'वर्णनात्मक संशोधन पध्दती' उपयोगात आणली आहे.

तथ्य संकलन : प्रस्तुत शोध निबंधाकरीता तथ्य संकलन हे लिखित साहित्य अर्थात पुस्तके, वर्तमानपत्रे, मासिके, संशोधन पत्रिका व इंटरनेट यांच्या आधारे केलेले आहे.

जागतिकीकरणाचा अर्थ : जागतिकीकरण ही विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यवसाय इत्यादींचा प्रसार, संप्रेषण व व्यापाराच्या माध्यमातून जगभरात होणारी प्रक्रिया आहे. जागतिकीकरणाचा अर्थ स्पष्ट करणाऱ्या व्याख्या खालीलप्रमाणे –

१) जागतिकीकरण म्हणजे खुली स्पर्धा व नवे तंत्रज्ञान या माध्यमातून उत्पादकता वाढविणे व संपूर्ण जगाची एकच बाजारपेठ निर्माण करणे होय.

२) जागतिकीकरण म्हणजे सर्व क्षेत्रात असणारी तीव्र स्पर्धा होय.

३) जागतिकीकरण म्हणजे जगाच्या इतर अर्थव्यवस्थांशी भारतीय अर्थव्यवस्थेला एकत्रितपणे संबोधणे होय.

४) जागतिकीकरण म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आणण्यासाठी सर्व राष्ट्रांची एकच बाजारपेठ तयार करणे होय.

५) जागतिकीकरण म्हणजे स्थानिक वस्तूंची किंवा घडामोडींची जागतिक स्तरावर स्थानांतराची प्रक्रिया होय.

६) जागतिकीकरण म्हणजे जगभर पसरणे, एकाच वेळी संपूर्ण जगाचा किंवा जगातील सर्व लोकांचा विचार करणे होय.

७) जागतिकीकरण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण करणे होय.

८) जागतिकीकरण म्हणजे प्रमुख व्यापारासाठी विविध देशांनी एकमेकांना जोडून घेत एकमेकांच्या भूमीत खुलेपणाने व्यापार करण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करणे होय.

९) जागतिकीकरण म्हणजे ज्या ठिकाणी स्वस्त आणि रास्त कच्चा माल व इतर स्त्रोत उपलब्ध असतील, अशा जगातील कोणत्याही ठिकाणी उत्पादन घेणे होय.

१०) जागतिकीकरण म्हणजे जगातील कोणत्याही कोपऱ्यापर्यंत वस्तू आणि सेवा पुरविणे होय.

११) जागतिकीकरण म्हणजे संपूर्ण जगाची एका मोठ्या बाजारपेठेत रुपांतरीत होण्याची प्रक्रिया होय.

१२)“जागतिकीकरण म्हणजे उपभोग्य वस्तुंसह सर्व वस्तुंच्या आयातीवरील नियंत्रण हळूहळू समाप्त होणे होय.” –
विश्व बॅंक अहवाल

१३)“जागतिकीकरण म्हणजे देशांच्या राजकीय सीमांमध्ये आर्थिक क्रियांचा विस्तार करणे होय.” – दिपक नायर

१४)“जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे सघनीकरण घडून येणे होय.” – ॲंथनी गिडन्स

१५)“जागतिकीकरण म्हणजे देशात खुला व्यापार, गुंतवणूकीसाठी मोकळी बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान तसेच कुशल व्यावसायिकांना देशांतर करण्यास सुलभ कायदे-कानून अशी जागतिक व्यवस्था होय.” – मो.वि.भाटवडेकर

१६)“जागतिकीकरण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे एका काल्पनिक विश्व अर्थव्यवस्थेकडे होणारे संक्रमण दर्शविणारी संकल्पना होय.”-हेराड, टाथेल व रॉबर्ट

१७)“जागतिकीकरण म्हणजे सीमापार उत्पादने,भांडवल सेवा व आर्थिक क्रिया-प्रक्रियांच्या वाढत्या प्रवाहाला लक्ष्य करणारी प्रक्रिया होय.”- एडवर्ड हार्मन

१८)“जागतिकीकरण म्हणजे जगाच्या विविध भौगोलीक क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांमध्ये वाढते सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक व्यापारी, सांस्कृतिक संबंध दर्शविणारी व्यापक प्रक्रिया होय.” - बायलिस आणि स्मिथ

१९)“जागतिकीकरण म्हणजे जागतिक भांडवलशाहीमधून निर्माण झालेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, संस्था यांचा प्रभाव असणारी आंतरराष्ट्रीय व आर्थिक व्यवस्थेत राष्ट्राची भूमिका मर्यादित करणारी प्रक्रिया होय.” - कॉक्स आणि कॉटन

२०)“जागतिकीकरण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय आणि सर्वांसाठी स्वातंत्र्य या मूल्यांचा समावेश असणारी आणि मुक्त व्यापार व अर्थव्यवस्थेचे फायदे सर्वांना मिळून देणारी सर्वसमावेशक प्रक्रिया होय.” - स्मिथ

२१) “जागतिकीकरण म्हणजे जगातील वेगवेगळ्या देशांनी परस्पर व्यापार करणे होय.” - डॉ. यशवंत मनोहर

२२)“जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय.” - थॉमस फ्रीडमन

२३)“जागतिकीकरण म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची प्रक्रिया होय.” - जागतिक बॅंक

थोडक्यात, जागतिकीकरण म्हणजे जागतिक आर्थिक व्यवहारांचा झालेला विस्तार होय. जागतिकीकरणात जगात एककेंद्रीय आर्थिक व्यवस्था निर्माण करणे, अधिक गुंतवणूक करुन औद्योगिकीकरण वाढवणे व आयात-निर्यात सुलभतेने करता येण्याची स्थिती निर्माण करणे या बाबींचा समावेश होतो. जागतिकीकरणामुळे ग्लोबल आणि लोकल यातून ‘ग्लोकल’ ही संकल्पना उदयास आल्यामुळे, जागतिकीकणाच्या प्रक्रियेत कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे. परंतु असे असले तरी, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून व माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्फोटातून राष्ट्र-राज्याच्या सीमा अंधुक होऊन राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व धोक्यात आलेले आहे ही बाब नजरेआड करता येणार नाही.

भारतातील कृषीक्षेत्र:

प्राचीन काळापासून कृषीक्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. कृषी हा भारतीय लोकांचा प्रमुख व्यवसाय असल्यामुळे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात, रोजगारात, औद्योगिक विकासात, विदेशी व्यापारात आणि देशाच्या आर्थिक विकासात कृषी क्षेत्राचे स्थान महत्त्वाचे आहे. कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे म्हटले जाते. यावरुनच आपल्याला कृषी क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील असणारे महत्त्व लक्षात येते. भारतासारख्या अल्पविकसीत राष्ट्रांचा आर्थिक विकास हा कृषी क्षेत्राच्या विकासावर अवलंबून आहे. भारतात नैसर्गिक संसाधने प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध असली तरी भांडवलाच्या कमतरतेमुळे औद्योगिकरणाचा वेग अल्प आहे. परिणामी, वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केले आहे. देशातील बेकारीचे प्रमाण कमी करण्यात कृषी क्षेत्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे. भारतामध्ये भांडवलाची कमतरता

मोठ्या प्रमाणात असली तरी या भांडवलाच्या कमतरतेवर मात कृषी क्षेत्राच्या माध्यमातून करता येते. कारण कृषी क्षेत्रात भांडवल-उत्पादन गुणोत्तर कमी असते व त्यामुळे कमी भांडवल गुंतवून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन मिळवता येते. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलनाची आवश्यकता सुध्दा औद्योगिक क्षेत्राएवढी असत नाही. यामुळे स्वातंत्र्यानंतर पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून भारताचा आर्थिक विकास घडवून आणतांना औद्योगिक क्षेत्राबरोबरच कृषी क्षेत्राला सुध्दा महत्त्वाचे स्थान पंचवार्षिक योजनांमध्ये दिले आहे.

प्रसिध्द अर्थतज्ञ कोल व हुवर यांच्यामते, देशाचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वप्रथम त्या देशातील कृषी क्षेत्राचा विकास घडवून आणणे आवश्यक असतो. जर कृषी क्षेत्राचा विकास हा पुरेशा प्रमाणात आधी घडून आला नाही, तर उद्योग व सेवा क्षेत्राच्या विकासात अडथळे निर्माण होतात. म्हणून पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत भारतातील नियोजन आयोगाने कृषी क्षेत्रावर सर्वात जास्त भर दिला. आज जागतिकीकरणामुळे कृषीक्षेत्र हे प्रभावित झालेले आहे. त्यात अनेक परिवर्तने घडून आलेली आहेत. या जागतिकीकरणामुळे कृषी क्षेत्रावर अनुकूल तसेच प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसून येते. अनुकूल परिणामामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राचा विकास झालेला आहे, तर प्रतिकूल परिणामामुळे अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणाचा कृषी क्षेत्रावर झालेल्या प्रतिकूल परिणामासाठी उपाययोजना करुन त्यावर मात करणे हे जरी भारतीयांसमोर एक मोठे आव्हान असले तरी, ते आव्हान पेलण्याची ताकद भारतीय लोकांमध्ये आहे हे मात्र विसरता येत नाही.

जागतिकीकरणाचा कृषीवरील परिणाम :

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषीला महत्त्वाचे स्थान आहे. कृषीच्या विकासाशिवाय मानवी जीवन कधीही सुखी आणि समृध्द होऊ शकणार नाही. कारण मानवाची अन्नधान्याची मुलभूत गरज ही कृषीमार्फतच पूर्ण होऊ शकते. उद्योगांना आवश्यक कच्च्या मालाचा पुरवठा सुध्दा कृषीतूनच होतो. कृषी हे देशातील लोकांच्या उपजिवीकेचे एक साधन आहे. म्हणूनच कृषीला 'भारताचा आत्मा' असे म्हणतात. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृषीची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. परंतु जागतिकीकरणामुळे कृषी क्षेत्रावर अनेक अनुकूल व प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत.

कृषीवरील अनुकूल परिणाम :

१) कृषी उत्पादनात वाढ-

जागतिकीकरणामुळे कृषी उत्पादन वाढले आहे. शेतकरी हा अधिक उत्पन्न देणाऱ्या बी-बियाण्यांच्या विविध जाती खरेदी करु लागला आहे. तसेच कृषीला लागणारी इतर आदानेही कमीत कमी किमतीत इतर देशातून खरेदी करु लागल्याने दर हेक्टरी उत्पादन वाढीला मदत झाली आहे.

२) बी-बियाणे खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य-

जागतिकीकरणामुळे शेतकऱ्याला कोणत्या प्रकारचे बी-बियाणे खरेदी करुन कृषीचे उत्पादन वाढवावे यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. यामुळे तो सर्वात चांगले बी-बियाणे वापरु शकतो. तसेच पारंपारिक पध्दतीप्रमाणे पिकातील काही हिस्सा 'बी' म्हणून ठेवू शकतो आणि त्याचा वापर पुढील वर्षी करु शकतो. शिवाय

शेतकरी हा त्याच्याकडील जास्तीचे बियाणे विकू शकतो. पंरतु असे असले तरी, बियाण्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. कारण नामांकित बियाणे तो विकू शकत नाही. शेतकरी हा बी-बियाण्यांचे उत्पादक म्हणून काम करु शकतो. तसेच संरक्षित बी-बियाणे उत्पादनाचा हक्क असलेल्या व्यक्तीच्या संमतीने तो बी-बियाण्यांची व्यापारी तत्त्वावर विक्री करु शकतो. अशाप्रकारे, कोणती बी-बियाणे वापरायची याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला आहे. जागतिकीकरणामुळे त्याला चांगल्या प्रतीच्या बी-बियाण्यांची खरेदी करता येऊन त्याच्या साहाय्याने कृषीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेता येते.

३) पिक घेण्याच्या पध्दतीत विविधता-

नवीन आर्थिक धोरणापूर्वी भारतीय शेतकरी हा प्राथमिक स्वरुपाचे खाद्यपदार्थ व नगदी पिकेच घेत होता. परंतु जागतिकीकरणाच्या आवश्यकतेनुसार आता भारतीय शेतकरी हा पंरपरागत अन्नधान्याऐवजी उद्यानविद्या, फुलबाग, औषधी वनस्पती अशा अखाद्य पिकांचीही लागवड करत आहे.

४) उत्पादनाला योग्य भाव-

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत स्पर्धेमुळे उत्पादनाची गुणवत्ता वाढत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव प्राप्त होत आहे.

५) कृषी आदानावरील सबसिडी-

कृषीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक बी-बियाणे, रासायनिक खते, अवजारे, पाणीपुरवठ्याच्या सोयी इत्यादींची गरज असते. भारत सरकार आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा व आधुनिक बी-बियाण्यांचा वापर करावा म्हणून त्यावर सबसिडी देत आले आहे. आता ह्या सर्व सबसिडीज बंद होतील अशी चर्चा केली जाते. परंतु जगातील काही देश मोठ्या प्रमाणात शेतमाल उत्पादनासाठी सबसिडीज देतात. यामध्ये जपान व पूर्व युरोपमधील काही देशांचा समावेश आहे. भारतात मुळातच सबसिडीचे प्रमाण एकूण शेतीमूल्याच्या १० टक्के म्हणजे अत्यंत कमी आहे. इतर देशातील शेतमालावरील सबसिडी कमी केल्याने त्यांच्या शेतमालाच्या किंमती वाढून भारतीय शेतकऱ्याला आपला शेतमाल इतर देशात पाठविण्याची व त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध झाली आहे.

६) उत्पादनाच्या निर्यातीत वाढ-

भारत सरकारने सन १९९३-१९९४ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेचे धोरणे स्वीकारले. त्यामुळे कृषीमालाची निर्यात वाढत असल्याचे दिसून येते. भारतासारख्या विकसनशील देशापेक्षा विकसीत देशांना नवनवीन प्रकारचा कृषीमाल निर्यात करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, असे जागतिक अन्न व कृषी संघटनेच्या अभ्यासात म्हटले आहे.

७) बियाण्यांचा निर्मिती हक्क-

बी-बियाण्यांचे उत्पादन करुन त्याची विक्री करण्याच्या भारतातील शेतकरी वर्गाच्या हक्कावर जागतिकीकरणाचा विपरीत परिणाम न होता भारतातील प्रयोगशाळेत वेगवेगळ्या हवामानात टिकून राहणाऱ्या वनस्पतीजन्य बी-बियाण्यांच्या नवनवीन जाती शोधून काढल्या गेल्या. भारतात १७५ प्रकारची संकरीत बी-बियाणे आहेत. त्यातील ९८ प्रकारची बी-बियाणे भारतातील शास्त्रज्ञांच्या संशोधनवृत्तीला चालना देणारी असल्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत झाली. तसेच बी-बियाण्यांची निर्यात करता येऊन त्यापासून

परकीय चलन मिळत आहे. अलीकडच्या काळात बी-बियाण्यांच्या ऐवजी उतीसंवर्धन हा प्रकार वेगाने विकसीत झाला आहे. त्याचा फायदा भारतीय संशोधकाला मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पादन वेगाने वाढविले आहे.

८) संकरीत बी-बियाण्यांच्या उत्पादनात वाढ-

सन १९९६-१९९७ मध्ये संकरीत बी-बियाण्यांचे एकूण उत्पादन हे ४६.०२६ क्विंटल एवढे होते, ते १९९९-२००० मध्ये ५०.७९८ क्विंटलपर्यंत वाढले आहे. तसेच पायाभूत बी-बियाण्यांचे एकूण उत्पादन वरील काळात ७३.२७ लाख क्विंटलवरुन ९१ लाख क्विंटलपर्यंत वाढले आहे.

९) निर्यात रचनेत बदल-

नवीन व्यापारी धोरणामुळे जकाती कमी केल्या व त्याचा परिणाम म्हणून निर्यातीच्या रचनेत बदल झाला.१९९० मध्ये भारताचा शेती व संलग्न वस्तूंच्या एकूण निर्यातीमधील हिस्सा १७.९ टक्के होता.१९९७-१९९८ मध्ये तो १८.८टक्क्यांपर्यंत वाढला. तसेच पूर्वी निर्यातीमध्ये कापूस,ताग,चहा,तेलबिया, मसाले, काजू इत्यादी वस्तूंचा समावेश होता.पण जागतिकीकरणामुळे अशा पारंपारिक वस्तूंच्या निर्यातीत घट झाली असून अपारंपारिक वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे. यामध्ये साखर,तांदूळ, कपडे, कॉफी,मासे व त्यांचे पदार्थ तसेच बासमती तांदूळ इत्यादी वस्तूंची निर्यात वाढली आहे.

१०) सुती कापड निर्यातीत वाढ-

जागतिकीकरणात बहुविध सुती कापडविषयीच्या करारामुळे कोटा पध्दती व नियंत्रणे रद्द झाली. यामुळे भारतातून सुती कापडाच्या निर्यातीत वाढ झाली. १९९७-१९९८ मध्ये सुती कापड व सुत यांची निर्यात १२,०९४ कोटी रुपयांची होती .

११) खतांच्या आयातीत वाढ -

उदारीकरणाच्या धोरणामुळे खतांची आयात वेगाने वाढली आहे. १९८५-१९८६ ते १९८९-१९९० या काळात खतांची सरासरी वार्षिक आयात १११४ कोटी रुपये होती, तर १९९७-१९९८ मध्ये ती ३७५५ कोटी रुपयांची होती.

१२) कृषी आधारित उत्पादनाच्या निर्यातीत वाढ-

जागतिकीकरणामुळे देशात कृषी आधारित उद्योगांची संख्या ही प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. या उद्योगांच्या वाढीमुळे रोजगाराची निर्मिती झाली आहे. अनेक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. तसेच कृषी आधारित उत्पादनाच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे. या उत्पादनाच्या निर्यातीमुळे देशाला परकीय चलन उपलब्ध झाले आहे.

१३) शेती करणे सोपे-

जागतिकीकरणामुळे व आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सिमांत शेतकरी व अल्प भूधारक शेतकरी यांना शेती करणे सोपे झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन हे शेतकरी जमिनीतून जास्त उत्पादन काढू लागले आहे. उदा. महाराष्ट्रातील सिन्नर येथील कासार नावाच्या ६० वर्षाच्या गृहस्थाने ५ गुंठे जागेत प्रती दिवशी ५०० लिटर पाण्यावर फुलांची शेती करुन पहिल्याच सहा महिन्यात एक लाखाच्यावर उत्पन्न मिळवले आहे. तसेच इतरांना रोजगार सुध्दा उपलब्ध करुन दिला आहे.

१४) उद्योगांच्या कार्यक्षमतेत वाढ -

जागतिकीकरणामुळे कृषी व कृषीवर आधारित उद्योगांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या स्पर्धेमुळे उद्योगांची कार्यक्षमता, उत्पादनक्षमता व गुणवत्ता वाढली आहे. भारतात सध्या २ टक्के कृषी मालावर प्रक्रिया केली जाते. पण प्रक्रिया केलेला माल सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यासाठी चांगल्या दर्जाची शितगृहे व गोदामे वांधण्याची आवश्यकता आहे.

कृषीवरील प्रतिकूल परिणाम :

१) प्रगत देशांशी स्पर्धा अशक्य-

जागतिकीकरणामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना प्रगत देशांशी आयात कृषी मालाबरोबर स्पर्धा करणे सध्या तरी शक्य नाही. भारतातील शेती व्यवसाय हा प्रामुख्याने सरकारी ध्येय-धोरणे, लहरी मोसमी हवामान यावर अवलंबून आहे. यातच भर म्हणून जागतिकीकरणाचा फार मोठा फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसत आहे. कारण गेल्या वर्षांपासून अमेरिका, फ्रान्स, जपान व इतर युरोपीय देश आपल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य करत आहेत. उदा. अमेरिका ६५ टक्के, तर जपान ५५ टक्के अर्थसहाय्य देते. त्यामुळे कृषी उत्पादनाच्या जागतिक किंमती कमी होऊन भारतासारख्या कृषीप्रधान देशातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणात सर्वच राष्ट्रांनी कृषीला दिले जाणारे सर्व अनुदान १९९९ पर्यंत २० टक्के पर्यंत कमी करावेत असा प्रस्ताव ठेवला. मात्र या प्रस्तावाला अनेक विकसीत राष्ट्रांनी विरोध केला. परंतु भारतात कृषीला देण्यात येणारे अनुदान १० टक्के पेक्षा कमी असल्याने अनुदान कमी करण्याचा प्रश्नच येत नाही, उलट विकसीत राष्ट्रांना आपल्या अनुदानात कपात करावी लागेल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कृषीमालाच्या किंमती भारतीय कृषीमालाच्या तुलनेत वाढतील. परिणामी, भारतीय कृषी मालाची निर्यात वाढेल व त्यातून अधिक परकीय चलन मिळेल. मात्र त्याचबरोबर जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणानुसार भारतासारखे जे देश कृषीमालाची आयात सहसा करीत नाहीत, अशा देशांना देशांतील उपयोगाच्या ३ टक्के कृषीमाल विकसीत राष्ट्रांकडून आयात करावा लागेल व त्यामध्ये ५ टक्के पर्यंत वाढ करावी लागेल. यामुळे भारतीय कृषी मालाच्या किंमती घटून त्याचा फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसेल.

२) किंमतीत अस्थिरता-

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील उत्पादन घटकांच्या किंमती आणि पीक पध्दती यामध्ये सातत्याने होणारे बदल हे देशांतर्गत किंमतीमध्येही अस्थिरता निर्माण करतात. त्याचा विपरीत परिणाम उपभोक्ते व शेतकरी या दोघांवरही होतो. एकूणच, जागतिकीकरणामुळे भारतीय कृषीमालाच्या किंमतीत अस्थिरता दिसून येते.

३) लहान शेतकऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात-

भारतात सुमारे ८० टक्के लहान शेतकरी आहेत. नवीन जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणानुसार लहान शेतकऱ्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. अन्नधान्यांच्या उत्पादनाजागी किफायतशीर उत्पादनाच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली तर अन्नधान्याची आत्मनिर्भरता नष्ट होऊन भारताला अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल. परंतु हे परावलंबित्व अत्यंत धोकादायक ठरेल. शिवाय आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जैविक विज्ञानानुसार ऊती संवर्धनाच्या सहाय्याने उत्पादन हे मोठ्या प्रमाणात होऊ लागेल. यामुळे शेतीचे कारखानदारीकरण होईल. सद्य:स्थितीत इस्त्राईल देश याच दिशेने जात

आहे. तसेच गोडी देणारे पदार्थ आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रयोगशाळेत निर्माण होऊ लागले तर भारतातील ऊसाची व संन्याची शेती धोक्यात येईल. परिणामी, भारतीय शेतकरी मोठ्या संख्येने बेकार होतील.

४) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था धोक्यात–

जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणानुसार, भारत सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या धान्यांची खरेदी आणि या व्यवस्थेद्वारे करावयाची धान्याची विक्री ही खुल्या बाजारभावाने करावी म्हणजेच सार्वजनिक व्यवस्थेला देण्यात येणारे अर्थसहाय्य हळूहळू कमी करुन ही व्यवस्था बंद करावी हे या करारामध्ये मान्य करण्यात आले आहे. यामुळे भारतातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था धोक्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने स्वस्त धान्य दुकानातील मालाच्या किंमती वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. रेशनिंग व्यवस्था नसती तर सरकारला स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये देशांतर्गत शांतता व सुव्यवस्था ठेवता आली नसती. तसेच किंमत पातळी रोखता आली नसती. आपल्या देशाला वारंवार दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती या गोष्टींना सामोरे जावे लागते. अशावेळी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शेतकरी व गरीब वर्गाला तारक ठरते. जर ही पध्दती बंद केली तर गरीब लोकांना जीवनाश्यक वस्तू खुल्या बाजारातून खरेदी कराव्या लागतील, जे त्यांना परवडणारे नाही.

५) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कृषी उद्योगाचे निमंत्रण–

जागतिकीकरणाचा फायदा घेण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतामध्ये उद्योगधंदे उभारण्याचे जणू निमंत्रणच दिले आहे. स्वस्त व भरपूर मजूर पुरवठा, सुरक्षिततेशी व पर्यावरणाशी संबंधित कमीत कमी निर्बंध याचा फायदा उठविण्यासाठी या कंपन्यांनी मोठ-मोठे उद्योगधंदे उभे करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अव्वाच्या-सव्वा भावाने विकत घेतल्या. या उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या पाण्यामुळे कृषी व पिण्याच्या पाण्याचे संकट उभे राहिले. १९९६ नंतर या समस्यांनी उग्र स्वरुप धारण केले. त्यामुळे प्रामुख्याने कालव्याद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या भागातील शेती धोक्यात आली. परिणामी, लहान शेतकरी वर्ग शेतीतून बाहेर पडू लागला. त्यामुळे गरीबी व बेरोजगारीत वाढ होऊन ते काम शोधण्यासाठी शहराकडे जावू लागले.

६) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी–

मोठी गुंतवणूक, आधुनिक तंत्रज्ञान व आक्रमक विपणन नीतीसह बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय कृषी क्षेत्रात फक्त प्रवेशच केला नाही, तर त्यांची मक्तेदारी सुध्दा आहे. जगातील वाढती लोकसंख्या व त्यानुसार अन्नधान्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन नवनवीन संकरीत बियाण्यांचा शोध लावण्यात येत आहे. या बियाण्यांच्या उत्पादनाचे हक्क जी बहुराष्ट्रीय कंपनी घेईल, त्याच कंपनीकडून शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी करावे लागतील. हे बियाणे साठवणे, विकणे व पुन्हा वापरणे याचा अधिकार शेतकऱ्यांना न राहता फक्त बहुराष्ट्रीय कपंनीलाच राहील. या कंपनीला रॉयल्टी देऊन शेतकऱ्यांना बियाणे विकत घ्यावे लागेल. भारतीय राज्यघटनेनुसार बियाण्यांच्या वापराचा, साठविण्याचा व पुनर्वापराचा अधिकार शेतकऱ्यांना आहे. तसेच भारत सरकार शेतकऱ्यांना अल्प दरामध्ये बियाणे उपलब्ध करुन देते. आता जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणानुसार हा

पुरवठा बंद करावा लागेल. या बियाण्यांचे पेटेंट मान्य करणे म्हणजेच शेतकऱ्यांचे घटनात्मक हक्क हिरावून घेऊन शेतीला उध्वस्त करणे होय.

७) कंत्राटी शेती पध्दतीस सुरुवात–

जागतिकीकरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतामध्ये येऊन येथील शेतकऱ्यांना कृषीकरीता बी–बियाणे, खते, किटकनाशके यांचा पुरवठा करतील. त्याचप्रमाणे जागतिक कृषी उत्पादन मिळविण्याच्या दृष्टीने 'संविदा कृषी व्यवस्था' स्थापन करण्याचा प्रयत्न करतील. याचाच एक भाग म्हणून या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतातील लहान शेतकऱ्यांच्या जमिनी आपल्या नियंत्रणाखाली आणून सांगतील त्या पिकांचा, म्हणतील त्या पध्दतीने व ठरवलेल्या किंमतीनुसार या लहान शेतकऱ्यांना शेती करावी लागेल. यातूनच कंत्राटी शेती पध्दती अस्तित्वात येईल.

निष्कर्ष :

''जागतिकीकरणाचा कृषी क्षेत्रावरील परिणाम'' या शोध निबंधाचा संशोधनात्मक दृष्टीने सखोल अभ्यास केल्यावर जे निष्कर्ष निघाले ते असे –

1. जागतिकीकरणाचा परिणाम हा ज्याप्रमाणे परंपरा, संस्कृती, जीवनशैली या गोष्टींवर झाला तसाच तो कृषी क्षेत्रावर सुध्दा झाला असे अध्ययनातून निदर्शनास आले.
2. जागतिकीकरणात आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा मुक्त असल्याने भारतीय कृषीतील उत्पादन मोठ्या प्रमाणात निर्यात केले जाते असे संशोधनातून दृग्गोचर झाले.
3. जागतिकीकरणामुळे कृषी व कृषीवर आधारित उद्योग यामध्ये स्पर्धा निर्माण झाल्याचे संशोधनातून आढळून आले.
4. जागतिकीकरणामुळे भारतीय शेतकऱ्याला कोणत्या प्रकारची बी–बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके वापरायची यांचे स्वातंत्र्य मिळाल्याचे दिसून येते.
5. जागतिकीकरणामुळे कृषी उत्पादनात आणि रोजगारात वाढ झाली आहे असे अध्ययनातून दृष्टीपथास आले.
6. जागतिकीकरणामुळे कृषी उत्पादनाची गुणवत्ता वाढून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव प्राप्त होत असल्याचे अभ्यासतून लक्षात येते.
7. जागतिकीकरणामुळे भारतीय शेतकऱ्याला आपला शेतमाल इतर देशात पाठविण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध झाल्याचे अध्ययनातून निदर्शनास आले.
8. जागतिकीकरणामुळे व आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना शेती करणे सोपे झाले असे संशोधनात्मक अध्ययनातून आढळून आले.
9. जागतिकीकरणामुळे लहान शेतकऱ्यांचे अस्तित्व तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था धोक्यात आल्याचे दिसून आले.

संदर्भग्रंथ सूची :

१) दुभाषी, डॉ. पद्माकर – 'उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि भारतीय कृषी'
२) कराडे, प्रा.जगन .– 'जागतिकीकरण: भारतासमोरील आव्हाने'
३) साठे, डॉ. मधुसूदन – 'जागतिक अर्थकारण'
४) पाटील, एकनाथ – 'जागतिकीकरण आणि वर्तमान आव्हाने'
५) क्षिरसागर, सौ. शोभादेवी – 'कृषीविषयक घटक'

६) डॉ. अनिरुध्द – ‘कृषीघटक : सर्वांगीण परामर्श’
६) कृषी विज्ञान मासिक – ‘अंक : फेब्रुवारी २००६’
७) कृषी संवादीनी – ‘अंक : २००५’, पि.के.व्ही., अकोला
८) कृषीभूषण मासिक – ‘अंक : जुलै–सप्टेंबर २०१७’

Journals :

1) Grip- The Standard Research, International Referred Online Research Journal, Issue IV : Oct 2012
2) Editor- Gawande , Prof. Virag- ‘Vidyawarta’ Harshwardhan Publication, Pvt. Ltd. , Beed, Issue: March 2018, Vol. -06

Websites :

1) https://mr.m.wikipedia.org
2) https://inmarathi.net

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

आळंदी येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या प्रादेशिक वितरणाचा भौगोलिक अभ्यास

दादासाहेब मारकड[१] डॉ.ओमप्रकाश मुंदे[२]
[१]सहाय्यक प्राध्यापक हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालय राजगुरूनगर ता.खेड, जि.पुणे.
[२]सहयोगी प्राध्यापक, नारायणराव राणा महाविद्यालय बडनेरा, जि.अमरावती.

सारांश –

आळंदी हे महाराष्ट्रातील एक महत्वाचे पर्यटनस्थळ आहे. हे वारकरी संप्रदायाचे लोकप्रिय श्रद्धास्थान आहे. आळंदी संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशातील काही राज्यातही प्रसिद्ध आहे. वारकरी संप्रदाय हा पूर्ण महाराष्ट्रात पसरलेला आहे. त्यामूळे पूर्ण महाराष्ट्रातून आळंदी येथे पर्यटक येत असतात. या शोधनिबंधात आळंदी येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या प्रादेशिक वितरणाचा अभ्यास केलेला आहे.

प्रस्तावना –

आळंदी हे पुणे जिल्हयातील एक महत्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. हिंदू धर्मातील वारकरी पंथातील भक्तांचे ते पुण्यधाम आहे. थोर संत, ज्ञानेश्वर महाराज आणि त्यांची भावंडे यांचे ते कार्यक्षेत्र आहे. वारकऱ्यांच्या दृष्टीने काशीपेक्षाही पंढरपूरचे महत्व अधिक आहे. परंतु संत नामदेव महाराज म्हणतात,

भू वैकुंठ एक पंढरी । त्याहुनि अधिक अलंकापुरी ।
सिद्धेश्वराशेजारी । इंद्रायणी ।
पंढरीहून हे सोपे । जनाची हरावया पापे ।
कळिकाळ कोपलिया कोपे। न चले अलंकापुरासी । (अभ्यंकर २००८)

वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेनुसार वैकुंठादि आठ पीठे आहेत. त्यापैकी आळंदी हे जुनाट शिवपीठ आहे. शिवपीठ हे जुनाट । ज्ञानाबाई तेथे मुकुट या आळंदीचा महिमा शैवशास्त्रात (स्कंदपुराणात आला आहे. (वक्ते वि.सं. २०६८) पवित्र इंद्रायणी नदीचे काठी श्री क्षेत्र अलंकापुरी (आळंदी) वसलेले आहे. अलंकापुरी हे क्षेत्र पुरातन काळापासून पवित्र व प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. या क्षेत्रासारखे त्रैलोक्यात दुसरे पावन क्षेत्र नाही. प्राचीन काळी आळंदी भोवतालचा प्रदेश अरण्यमय होता व त्यास आनंदवन असे नाव होते. असे याचे वर्णन स्कंद पुराणातील सह्याद्रीखंडात आलेले आहे. (खरात २००४) कृतयुगात आनंदवन त्रेतायुगात वरूण, व्दापारयुगात कपिल आणि कलियुगात अलका अशी निरनिराळ्या युगात या आळंदीला नावे लाभलेली आहेत. श्री अलंकापुरी क्षेत्र हे ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या अगोदरपासून प्रसिद्ध आहे. (बेणारे २०१८) आळंदीचे माहात्म्य अनेक साधु संतांनी, भाविकांनी, साहित्यिकांनी मुक्त कंठाने वर्णन केलेले असल्याने आळंदी अतिशय महत्वाचे धार्मिक पर्यटनस्थळ बनलेले आहे.

बीजसंज्ञा – धार्मिक पर्यटक, तीर्थक्षेत्र, प्रादेशिक वितरण, प्रशासकीय विभाग

उद्दिष्ट्ये –

१. आळंदी धार्मिक पर्यटनस्थळी येणाऱ्या पर्यटकांचे प्रादेशिक विभागनिहाय वितरण अभ्यासणे.
२. आळंदी येथे येणाऱ्या पर्यटकांचे जिल्हानिहाय वितरण अभ्यासणे.

गृहितत्वे –

१. आळंदी हे पसिद्ध धार्मिक पर्यटनस्थळ असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातून आळंदी येथे पर्यटक येतात.
२. अंतरानुसार पर्यटकांच्या संख्येत बदल होतो.

अभ्यासपद्धती –

आळंदी येथे येणाऱ्या पर्यटकांकडून दोन पद्धतीने प्रश्नावली भरून घेतली. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने १७१ लोकांकडून प्रश्नावली भरून घेण्यात आल्या. तसेच अनेक पर्यटकांकडून प्रत्यक्ष पद्धतीने प्रश्नावली भरून घेतल्या. या प्रश्नावलींबरोबरच वारकरी शिक्षण संस्थेतील अहवालामधील देणगीदारांच्या यादीचा अभ्यास केला. त्यावरून आळंदी येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या मूळ स्थान लक्षात आले. कोठून किती पर्यटक येतात हे निश्चित केले. त्यांची टक्केवारी काढून राज्य, प्रदेश आणि जिल्हानिहाय वितरण नकाशा आणि आलेखांच्या साहाय्याने दर्शविलेले आहे.

विषय विवेचन -

आळंदी या तीर्थक्षेत्रावर तीर्थयात्रा आणि पर्यटन करण्यासाठी भारत देशातील विविध राज्यांमधून तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधून पर्यटक येत असतात. आळंदी हे पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात इंद्रायणी नदीच्या काठी वसलेले तीर्थक्षेत्र आहे. आळंदी हे धार्मिक पर्यटनस्थळ तर आहेच, शिवाय आळंदीपासून २० कि.मी. अंतरावर पश्चिमेस देहू, २५ कि.मी. अंतरावर दक्षिणेस पुणे, याशिवाय निमगांव, तुळापूर, थेऊर, रांजणगांव या पर्यटनस्थळांचे सानिध्य यामुळे आळंदीस संपूर्ण महाराष्ट्रातून पर्यटक येतात.

१. **पर्यटकांचे राज्यनिहाय वितरण** - आळंदी येथे येणाऱ्या पर्यटकांपैकी यादृच्छिक नमुना पद्धतीने निवडलेल्या ५०० पर्यटकांपैकी वेगवेगळया राज्यांतून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या पुढीलप्रमाणे आढळून आली.

अ.क्र.	राज्य	पर्यटकांची संख्या	टक्केवारी
१.	महाराष्ट्र	४९४	९८.८
२..	मध्यप्रदेश	२	०.४
३.	पंजाब	१	०.२
४.	गोवा	१	०.२
५.	कर्नाटक	१	०.२
७.	तेलंगाणा	१	०.२
	एकूण	५००	१००

टेबल क्र.१ - राज्यनिहाय पर्यटकांची संख्या (स्त्रोत - अभ्यासकाने केलेले सर्वेक्षण)

. त्यांबरोबरच शेजारच्या काही राज्यांमधूनही आळंदी येथे पर्यटक येत असलेले दिसून येतात. मात्र त्यांचे प्रमाण फारच कमी आहे. विविध राज्यांतील पर्यटक पुढीलप्रमाणे आहेत.

महाराष्ट्र - सर्वात जास्त पर्यटक हे महाराष्ट्र राज्यातील आहेत. त्यांची संख्या ४९४ असून त्यांची टक्केवारी ९८.८ टक्के इतकी आहे. याचे कारण आळंदी हे क्षेत्र महाराष्ट्र राज्यात आहे. तसेच आळंदी हे प्रामुख्याने वारकरी संप्रदायाचे तीर्थक्षेत्र आहे. वारकरी संप्रदायाचा सर्वात जास्त प्रसार महाराष्ट्रात झालेला आहे. आळंदी हे संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे जन्मस्थान आणि समाधीस्थान आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे सर्व वाङ्मय मराठी भाषेमध्ये आहे. त्यामुळे त्यांना मानणारा, त्यांची भक्ती करणारा वर्ग हा सर्वात जास्त महाराष्ट्रातच आहे. त्यामुळे सर्वाधिक म्हणजे ९८.८ टक्के पर्यटक हे महाराष्ट्रातील आहेत.

मध्यप्रदेश - हे राज्य महाराष्ट्राच्या शेजारी आहे. तसेच त्या राज्यात अठराव्या शतकात शिंदे आणि होळकर या मराठा सरदारांचे राज्य असल्याने तेथे मराठी संस्कृतीचा आणि वारकरी संप्रदायाचा काही प्रमाणात प्रसार झालेला आहे. म्हणून मध्यप्रदेशातीलही काही पर्यटक आळंदीस भेट देतात. या अभ्यासाच्या सर्वेक्षणामध्ये मध्यप्रदेशातील २ व्यक्ती या मध्यप्रदेशातील असल्याच्या आढळून आलेल्या आहेत.

गोवा, कर्नाटक आणि तेलंगणा - ही राज्ये महाराष्ट्राच्या शेजारी असल्याने तेथूनही आळंदीस काही पर्यटक येतात. या राज्यांतून प्रत्येकी एक पर्यटक आढळून आलेला आहे.

पंजाब – हे राज्य महाराष्ट्रापासून दूर आहे. मात्र मात्र पंजाबमध्ये संत नामदेव महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांनी तीर्थयात्रा केलेली होती. तसेच संत नामदेव महाराजांनी पंजाब राज्यात वारकरी संप्रदायाचा प्रसार केलेला आहे. त्यामुळे त्या राज्यातून आळंदी येथे भाविक येत असतात. सर्वेक्षण करीत असताना पंजाब राज्यातील एक पर्यटक आढळून आला आहे.

प्रशासकीय विभागनिहाय वितरण –

महाराष्ट्रामध्ये एकूण सहा प्रशासकीय विभाग आहेत. कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर. या सर्व प्रशसकीय विभागातून आळंदी येथे पर्यटक येत असतात. सर्वेक्षणा दरम्यान या सर्व प्रशासकीय विभागातून खालीलप्रमाणे पर्यटक आल्याचे दिसनू आले आहे.

अ.क्र.	विभाग	पर्यटकांची संख्या	टक्केवारी
	कोकण	४६	९.३१
	पुणे	१६२	३२.७९
	नाशिक	९७	१९.६३
	औरंगाबाद	१३०	२६.३१
	अमरावती	३७	७.४८
	नागपूर	२२	४.४५
	एकूण	४९४	१००

टेबल क्र. २ विभागनिहाय पर्यटकांची संख्या (स्त्रोत – अभ्यासकाने केलेले सर्वेक्षण)

वरील आकडेवारी आणि वर्तुळालेखावरून सर्वसाधारणपणे असे लक्षात येते की, आळंदी या पर्यटनस्थळापासूनचे विविध विभागांचे अंतर जसजसे वाढत जाते तसतशी पर्यटकांची संख्या कमी होत जात आहे. कोकण विभाग मात्र त्यास थोडासा अपवाद आहे. आळंदीस येणाऱ्या पर्यटकांचे विभागनिहाय वितरण पुढीलप्रमाणे आहे.

पुणे विभाग –

आळंदी येथे येणाऱ्या पर्यटकांपैकी सर्वात जास्त पर्यटक हे पुणे विभागातील आहेत. आळंदी हे तीर्थक्षेत्र मुळातच पुणे जिल्ह्यात असल्याने सर्वात अधिक पर्यटक हे पुणे विभागातील आहेत. पुणे विभागात पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर हे जिल्हे आहेत. एकूण ५०० पर्यटकांपैकी सुमारे १६२ म्हणजे ३२.७९ टक्के पर्यटक हे पुणे विभगातील असल्याचे आढळून आलेले आहे.

औरंगाबाद विभाग –

औरंगाबाद विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नाशिक विभाग आणि मुंबई विभाग पुणे आळंदीस भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असूनही औरंगाबाद विभागातून त्यांच्यापेक्षा जास्त पर्यटक आलेले दिसतात. याचे कारण मुळातच औरंगाबाद विभाग मोठा आहे. तसेच औरंगाबाद विभागात वारकरी संप्रदायावर श्रद्धा असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण अधिक आहे. औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, बीड हे जिल्ह्यातील पर्यटकांचा आळदींकडे येण्याचा ओढा मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. सर्वेक्षण केलेल्या पर्यटकांपैकी १३० म्हणजे २६.३१ टक्के पर्यटक हे औरंगाबाद विभागातील असल्याचे आढळून आलेले आहे.

नाशिक विभाग –

नाशिक विभागातील पर्यटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. नाशिक विभाग आळंदीपासून अंतराने जवळ आहे. नाशिक विभागात नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगांव आणि नंदुरबार हे जिल्हे येतात. नाशिक विभागातून ९७ म्हणजे १९.६३ टक्के पर्यटक होते असे आढळून आले.

कोकण विभाग –

कोकण विभागाचा विचार करता मुंबइ महानगर वगळता अन्य जिल्ह्यातून येणाऱ्या पर्यटकांचे प्रमाण फारच कमी आहे. याचे मुख्य कारण कोकणात वारकरी संप्रदायाचा फारसा प्रभाव नाही. शिवाय मुंबईतून आळंदीस येणारे बरेचसे पर्यटकही मूळचे कोकणतील नसून ही देशावरून जाऊन मुंबईमध्ये स्थायिक झालेले लोक आहेत. कोकण विभागातून ४६ म्हणजे ९.३१ टक्के पर्यटक असलेले आढळून आलेले आहेत.

अमरावती विभाग -

अमरावती विभाग विभाग हा आळंदीपासून दूर अंतरावर आहे. तसेच या विभागात वारकरी संप्रदायाचा प्रसार आणि प्रचार कमी आहे. या विभागात बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, आणि यवतमाळ हे पाच जिल्हे अमरावती विभागात येतात. अमरावती विभागातून ३७ म्हणजे ७.४८ पर्यटक आढळून आलेले आहेत. त्यातही सर्वात जास्त पर्यटक हे बुलडाणा जिल्ह्यातून आहेत. बुलडाणा हा जिल्हा अमरावती विभागातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत आळंदीस जवळ आहे. तसेच त्या जिल्ह्यातील शेगाव येथे वारकरी शिक्षण संस्था आहे. संत गजानन महाराजांची मोठी दिंडी आळंदी येथे येत असते.

नागपूर विभाग -

नागपूर विभागातून सर्वात कमी पर्यटक आळंदी येथे येत असल्याचे आढळून आलेले आहे. नागपूर विभाग हा आळंदीपासून सर्वात दूर आहे. तसेच त्या विभागात वारकरी संप्रदायाचा प्रसारही फारच कमी आहे. नागपूर विभागातून केवळ २२ म्हणजे ४.४५ टक्के पर्यटक आळंदीस येत असल्याचे दिसून आलेले आहे. त्यातही सर्वात जास्त म्हणजे १७ पर्यटक केवळ नागपूर जिल्ह्यातील आहेत. इतर जिल्ह्यातून नगण्य पर्यटक असल्याचे दिसून आले आहे.

कोकण, अमरावती आणि नागपूर हे विभागच अंतराच्या दृष्टीने आळंदीपासून दूर आहेत. कोकण आणि विदर्भात वारकरी संप्रदायाचा प्रसारही कमी आहे. वारकरी संप्रदायातील संत ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तीनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, (आळंदी), संत नामदेव (पंढरपूर) संत चोखामेळा, दामाजीपंत (मंगळवेढा - सोलापूर) नरहरी सोनार (पंढरपूर) सावता माळी (अरण - सोलापूर), गोरा कुंभार (तेरढोकी - मराठवाडा) जनाबाई (पंढरपूर), संत एकनाथ (पैठण - औरंगाबाद), संत तुकाराम (देहू) संत निळोबाराय (पिंपळनेर - अहमदनगर) बहिणाबाई सिऊरकर (जळगांव) ही सर्व संतमंडळी पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मराठवाड्यातील आहेत. हे संत विदर्भ किंवा कोकणातील नाहीत. विदर्भामध्ये संत गाडगेमहाराज, संत तुकडोजी महाराज, गजानन महाराज असे संत होऊन गेलेले आहेत. परंतु ते वारकरी संप्रदायिक संत म्हणता येणार नाहीत. त्यामुळे विदर्भात वारकरी संप्रदायाचा फारसा प्रसार नाही. शिवाय विदर्भाचे भौगोलिक अंतर आळंदीपासून दूर असल्याने पर्यटकांचे प्रमाण कमी आहे.

पर्यटकांचे जिल्हानिहाय वितरण -

आळंदीत येणाऱ्या पर्यटकांचे जिल्हानिहाय वितरण पुढीलप्रमाणे आहे.

कोकण विभाग			
अ.क्र.	जिल्हा	पर्यटकांची संख्या	टक्केवारी
१.	मुंबई	३१	६.२७
२.	पालघर	२	०.४
३.	ठाणे	७	१.१४
४.	रायगड	४	०.८
५.	रत्नागिरी	१	०.२
६.	सिंधुदुर्ग	१	०.२
पुणे विभाग			
७.	पुणे	१०१	२०.४४
८.	सातारा	२०	४.०४
९..	सांगली	८	१.६१
१०.	कोल्हापूर	४	०.८
११.	सोलापूर	२९	५.८७
नाशिक विभाग			
१२.	नाशिक	३८	७.६९
१३.	अहमदनगर	२३	४.६५
१४.	धुळे	१०	२.०२

१५.	जळगांव	२४	४.८५
१६.	नंदुरबार	२	०.४
औरंगाबाद विभाग			
१७.	औरंगाबाद	३६	७.२८
१८.	जालना	१४	२.८३
१९.	परभणी	६	१.२१
२०.	नांदेड	५	१.०१
२१.	उस्मानाबाद	१८	३.६४
२२.	हिंगोली	२	०.४
२३.	लातूर	१९	३.८४
२४.	बीड	३०	६.०७
अमरावती विभाग			
२५.	अमरावती	६	१.२१
२६.	बुलढाणा	१५	३.०३
२७.	अकोला	९	१.८२
२८.	वाशिम	३	०.६
२९.	यवतमाळ	४	०.८
नागपूर विभाग			
३०.	नागपूर	१७	३.४४
३१.	वर्धा	३	०.६
३२.	भंडारा	१	०.२
३३.	गोंदिया	०	०
३४.	चंद्रपूर	१	०.२
३५.	गडचिरोली	०	०
	एकूण	४९४	१००

टेबल क्र. ३ पर्यटकांची जिल्हानिहाय संख्या (स्त्रोत - अभ्यासकाने केलेले सर्वेक्षण)

पर्यटकांची संख्या	जिल्हे	जिल्ह्यांची संख्या
० ते ५	रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, नंदुरबार, नांदेड, हिंगोली, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली,	१४
६ ते १०	सांगली, धुळे, परभणी, अमरावती, अकोला,	५
११ ते २०	सातारा, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बुलडाणा, नागपूर ठाणे व पालघर	८
२१ ते ३०	सोलापूर, अहमदनगर, जळगांव, बीड	४
३१ ते ४०	मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद	३
४१ ते १०१	पुणे	१

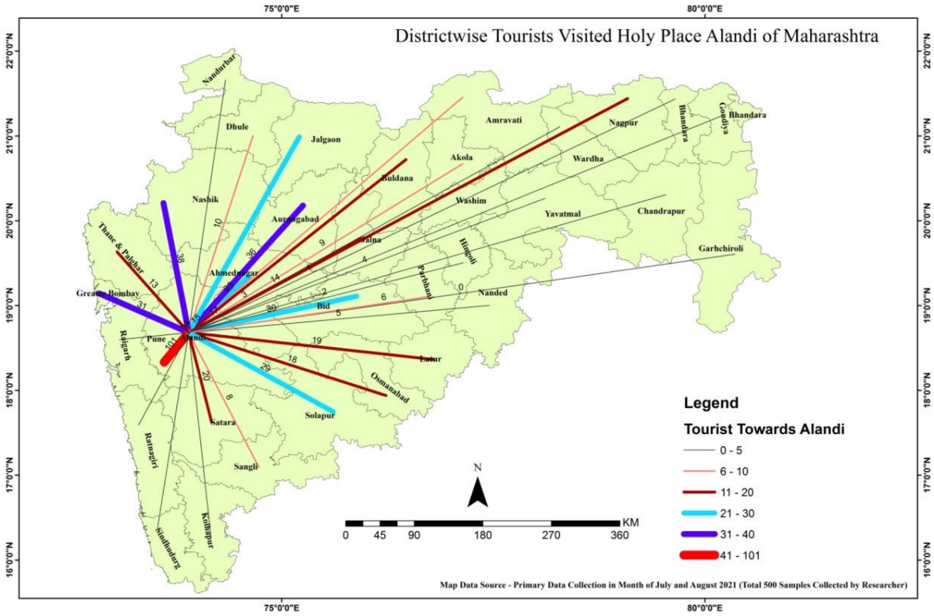

वरील आकडेवारी आणि नकाशावरून असे लक्षात येते की, गोंदिया आणि गडचिरोली हे दोन जिल्हे वगळता सर्व महाराष्ट्रातून आळंदी येथे पर्यटक येत असतात. आळंदीपासून जसजसे अंतर वाढत जात आहे तसतशी पर्यटकांची संख्या कमी झालेली सर्वसाधारणपणे दिसते. परंतु या नियमाला काही अपवादही दिसून येत आहेत. नागपूरपेक्षा रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, परभणी,हिंगोली इत्यादि जिल्हे जवळ असूनही नागपूरहून आळंदीला येण्याचे पर्यटकांचे प्रमाण त्या जिल्ह्यांपेक्षा अधिक आहे. आळंदीपासून सातारा, सोलापूर, हे जिल्हे जवळ असूनही औरंगाबाद येथून येणाऱ्या पर्यटकांचे प्रमाण अधिक आहे. नागपूर, औरंगाबाद ही शहरे लोकसंख्येने मोठी आहेत. त्याचाही हा परिणाम असू शकतो. तसेच आळंदीच्या उत्तर आणि ईशान्य दिशेकडून आळंदीला येणाऱ्या पर्यटकांचे प्रमाण अधिक आहे.

निष्कर्ष –

१. संपूर्ण महाराष्ट्रातून आणि महाराष्ट्राबाहेरूनही आळंदी येथे पर्यटक येतात.
२. आळंदीपासून जसजसे अंतर वाढत जाते तसतसे पर्यटकांचे प्रमाण घटत जाताना दिसते. मात्र नागपूर, औरंगाबाद, नागपूर हे जिल्हे त्यास अपवाद आहेत.
३. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रायगड, हे जिल्हे तुलनेने आळंदीला जवळ असूनही तेथून आळंदीकडे येण्याचे पर्यटकांचे प्रमाण कमी आहे.
४. आळंदीला येणारे सर्वात जास्त पर्यटक हे पुणे विभागातून येतात. तर सर्वात कमी नागपूर विभागातून येतात.
५. अतिपूर्वेकडील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, आणि अति दक्षिणेकडील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथून आळंदीस येणाऱ्या पर्यटकांचे प्रमाण नगण्य आहे.

संदर्भ ग्रंथ –

१. अभ्यंकर शंकर (२००८) – भक्तिकोश खंड ५ भारतीय मंदिरे व तीर्थक्षेत्रे. आदित्य प्रतिष्ठाण पुणे.
२. वक्ते निवृत्ती (वि.सं. २०६८), ब्रह्मचित्कलादर्शन अर्थात श्री मुक्ताबाई चरित्र व गाथा, गीता प्रेस गोरखपूर पृ. ३९१
३. खरात रंगनाथ (२००४) अशी ही अलंकापुरी, राहुल धार्मिक वाङ्मय सेवा प्रकाशन, आळंदी देवाची पृ. १४,१५ ४.
४. बेणारे पुष्पाताई (२०१८) श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज चरित्र, राहुल धार्मिक वाङ्मय सेवा प्रकाशन आळंदी देवाची, पृ. १९

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

जागतिकीकरणाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम

प्रा. डॉ. अनिल पंढरीनाथ कांबळे
लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील महिला महाविद्यालय, सोलापूर

प्रास्ताविक :

जागतिकीकरणामुळे संपूर्ण जगातील मानवाचे आर्थिक,,सामाजिक, सांस्कृतिक. आणि राजकीय जीवन बदलून गेले आहे जागतिकीकरण हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. भारतासाठी जागतिकीकरण हा काही नवीन शब्द नाही. ब्रिटिश काळामध्ये भारताची अर्थव्यवस्था युरोपीय देशासाठी खुली होती. या देशाबरोबर भारताचा व्यापार हा मोठ्या प्रमाणात होत असलेला दिसून येतो. परंतु जेव्हा आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि आम्ही नियोजनाच्या माध्यमातून आर्थिक विकास साध्य करण्याचे धोरण स्वीकारले तेव्हा मात्र आम्ही बंदिस्त स्वरूपाच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर कायदेशीर बंधने आणली निर्यात आणि आयातीवर मर्यादा आणल्या त्याचा परिणाम म्हणून भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार फारसा विकसित होऊ शकला नाही.या धोरणाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काही अनिष्ट परिणाम दिसून आले आणि त्याचाच एक भाग म्हणून सन 1991 मध्ये भारताने नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. या नवीन आर्थिक धोरणांमध्ये जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरण या त्रिसूत्री ला महत्त्व देण्यात आले.

भारतामध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारून 30 वर्षे पूर्ण झाले आहेत. 1980 पासूनच जगाला एक जागतिक खेडे बनविण्याचा ध्यास जगातील काही विकसित देशांनी घेतलेला दिसून येतो. भारताची अर्थव्यवस्था चार दशकापासून अनेक आर्थिक समस्या नी ग्रासली होती. 1990 मध्ये भारतात आर्थिक संकट निर्माण झाले होते. या काळात भारताकडे विदेशी चलनाची दुर्मिळता निर्माण झाली होती. देशात भाववाढ निर्माण झाली होती. वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली होती. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी दुसरा कुठलाही मार्ग नसल्यामुळे भारताने नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. या नवीन आर्थिक धोरणाचे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्थेवर काही चांगले परिणाम झाले तर काही वाईट परिणाम झालेले आपल्याला दिसून येतात. या परिणामाची माहिती करून घेण्याच्या हेतूने सदरचा शोधनिबंध मांडला जात आहे.

सन 1991 मध्ये भारतामध्ये जो आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न म्हणून नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार करण्यात आला. आर्थिक नियोजनाची चाळीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर भारतात प्रथमच अशी आर्थिक स्थिती निर्माण झाली होती की, ज्यामुळे वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली, परकीय चलनाचा साठा कमी होत गेला,उद्योगधंदे बंद पडले ,रोजगाराच्या संधी कमी होऊन बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले, मोठ्या प्रमाणात भाववाढ झाली, देशावर परकीय कर्जाचा बोजा वाढला ,भारत परकीय कर्जाच्या सापळयात अडकला. या सर्व बाबींचा परिणाम म्हणून भारताची जागतिक पातळीवरील परत धोक्यात आली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक या सारख्या संस्थांनी भारताला मदत करण्याच्या संदर्भात आपल्या धोरणात बदल केला. या आर्थिक पेचप्रसंगातून सावरून देशाची अर्थव्यवस्था विकासाच्या वाटेवर आणण्यासाठी नवीन आर्थिक धोरणाच्या माध्यमातून भारताने जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला. या सगळयांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्याकडून भारताला कर्ज देताना काही अटी घालण्यात आल्या म्हणजेच भारताने आर्थिक

सुधारणा केल्या पाहिजेत. आर्थिक परिस्थितीची अपरिहार्यता म्हणून भारताने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. या धोरणांमध्ये खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या तीन संकल्पना समाविष्ट आहेत.

अभ्यासाची उद्दिष्टे :

जागतिकीकरणाची माहिती समजून घेणे

जागतिकीकरणाचे परिणाम समजून घेणे.

जागतिकीकरनाच्या समस्या सोडवण्याच्या उपायावर चर्चा करणे .

संशोधन पद्धती:

सदर शोध निबंधासाठीची माहिती, दुय्यम साधन सामग्रीवर आधारित आहे. ही माहिती संदर्भ पुस्तके, वर्तमानपत्रे आणि जागतिकीकरण या वरील लेखाच्या आधारे घेण्यात आली आहे.

नवीन आर्थिक धोरणाची उद्दिष्टे:

भारतात नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार करण्यापूर्वी देशाच्या आर्थिक विकासाची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली होती. परंतु सरकार कडून म्हणावा तसा विकास नझाल्यामुळे आणि 1990 मध्ये देशात आर्थिक संकट निर्माण झाल्यामुळे सरकारला नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारावे लागले, या धोरणात आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सरकार बरोबर खाजगी क्षेत्र आणि विदेशी मदत यांची भागीदारी वाढविण्यावर भर देण्यात आला. आर्थिक विकासासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये मूलभूत बदल करण्यात आले. या धोरणामध्ये सरकारी क्षेत्र ,खाजगी क्षेत्र आणि विदेशी क्षेत्र यांचा समन्वय साधून देशाचा आर्थिक विकास साध्य करण्याचे धोरण होते. नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारताना जी उद्दिष्टे स्वीकारण्यात आली ती पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

1. देशाची वित्तीय तूट कमी करणे.
2. सातत्याने तोट्यात असलेल्या आणि आजारी असलेल्या सरकारी प्रकल्पामध्ये निर्गुंतवणूक करणे.
3. देशांतर्गत उद्योगांमध्ये स्पर्धा शक्ती वाढविणे.
4. जगातील इतर देशाबरोबर नियंत्रित आयात व निर्यातीद्वारे व्यापार वृद्धि करणे.
5. परकीय भांडवल आणि तंत्रज्ञानामध्ये वाढ करणे.
6. जागतिक व्यापाराच्या सीमा विस्तारणे.
7. देशावरील परकीय कर्जाचा भार कमी करणे.
8. शासनाची आर्थिक स्थिती सुधारणे.
9. सार्वजनिक क्षेत्रावरील रोजगाराचा भार कमी करणे.
10. निर्गुंतवणूककी द्वारे भांडवल उभा करणे.
11. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाची कार्यक्षमता वाढविणे.
12. लोकांना चांगल्या वस्तू आणि सेवा पुरविणे.
13. समाजामध्ये निरोगी स्पर्धात्मकता वाढविणे.
14. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक वाढविण्यास प्रोत्साहन देणे.

वरील उद्दिष्टेसाध्य करण्याच्या हेतूने भारतामध्ये आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या या सुधारणा केल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या तीस वर्षात जे परिणाम झाले. या परिणामाची मांडणी सदर शोध निबंधामध्ये करण्यात आली आहे.

जागतिकीकरणाचे परिणाम :

1991 मध्ये भारताने जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले या धोरणाचा प्रभाव भारतातील ग्रामीण आणि शहरी भागावर झालेला दिसून येतो. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात याचा प्रभाव अधिक पडला आहे. जागतिकीकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्थेवर कसा परिणाम झाला आहे या बद्दलची चर्चा पुढील प्रमाणे करण्यात आलीआहे..

अ . जागतिकीकरणाचे अनुकूल परिणाम:

जागतिकीकरणामुळे देशातील औद्योगिक क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम झाला आहे .जागतिकीकरणामुळे भारतात शहरीकरण वाढले आहे. औद्योगीकरण वाढत आहे. जागतिक बाजारपेठेचा विस्तार होत आहे. सेवा क्षेत्राचा विस्तार झाला आहे. देशाचे आर्थिक व्यवहार देशाच्या भौगोलिक आणि राजकीय सीमेच्या बाहेर विस्तारित होत आहेत. थोडक्यात असे म्हणता येईल जागतिकीकरणाचा भारताच्या विदेशी व्यापारावर, विदेशी चलनाच्या साठ्यावर, विदेशी गुंतवणुकीवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे .काही मुद्द्याच्या आधारे ते पुढील प्रमाणे सांगता येईल

१. औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढला:

जागतिकीकरणामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये औद्योगिकीकरणाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळालेली आहे. देशातील उद्योगाची स्पर्धात्मकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून काही महत्वाचे असे निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे परवाना पद्धतीच निर्मुलन करणे, परकीय गुंतवणुकीला संधी देणे, कर व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडून आणणे, बँकिंग व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडून आणणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापारा वरील जाचक अटी कमी करणे आणि परकीय कंपन्यांना देशांमध्ये उद्योग उभारण्यास योग्य वातावरण निर्माण करून दिल्यामुळे भारतात उद्योगधंद्याचा विस्तार आणि विकास होत असलेला दिसून येतो

२. बाजारपेठेचा विस्तार झाला:

जागतिकीकरणामुळे परकीय भांडवलाच्या आयाती मध्ये सुलभता आली.एवढच नाही तर उदारीकरणाच्या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा विस्तार झाला. भारताच्या विदेशी व्यापाराची रचना आणि दिशा बदलली. आयातीच्या वाढीबरोबरच भारताची निर्यात सुद्धा वाढली. भारताला नवीन बाजारपेठ मिळाली .तसेच जगाला भारत एक बाजारपेठ मिळाली. वस्तू बाजार, भांडवल बाजार आणि सेवा बाजाराचा विस्तार घडून आला हा एक जागतिकीकरणाचा अनुकूल परिणाम म्हणता येईल.

३. रोजगाराच्या संधीत वाढ:

असे म्हटले जाते जागतिकीकरणामुळे घटक बाजाराचा विस्तार झाला. विशेषतः आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नवीन आणि आधुनिक अशा रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या, पारंपारिक आणि शारीरिक रोजगार या पेक्षा बौद्धिक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. उच्चशिक्षित प्रशिक्षित तरुणांना देशात आणि विदेशांमध्ये चांगल्या प्रकारच्या नोकरीची संधी उपलब्ध झालीआहे.

४.सेवा क्षेत्राचा विस्तार झाला:

नवीन आर्थिक धोरण आणि जागतिकीकरणामुळे भारताच्या सेवाक्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. व्यापारी बँका आणि वाहतूक दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, पर्यटन इत्यादी सेवांची वाढ आणि विस्तार होत चालला आहे. संगणक, मोबाईल, माहिती तंत्रज्ञान ,इत्यादी संदर्भात मुबलक प्रमाणात सेवा उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे शहरी भागातील सेवा क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारक असे बदल झालेले दिसून येतात.

५. वैज्ञानिक प्रगती :

जागतिकीकरणामुळे जग विज्ञानवादी होत आहे. या जगामध्ये बौद्धिक भांडवलाला महत्व प्राप्त झाले आहे. माणसाच्या भौतिक गरजा वाढल्या आहेत. लोकांच्या सुखाच्या कल्पना बदलल्या आहेत.प्रसार माध्यमे ,इंटरनेट,

आधुनिक तंत्रज्ञान इत्यादी विज्ञानाचे नवीन क्षेत्रे विकसित होत आहेत. लोक घरी बसून आपल्या बऱ्याच गरजा पूर्ण करून घेत आहेत.

६. शेती उत्पादनात वाढ :

जागतिकीकरणामुळे भारताच्या शेती उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. विविध पिकाच्या बाबतीत भारताची शेतीची उत्पादकता वाढली आहे. शेती क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीचा ओघ वाढत चालला आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना आणल्या जात आहेत. विविध प्रकारच्या शेतमालाची निर्यात वाढविण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारलेला आहे.

७. आरोग्य विज्ञानामध्ये प्रगती :

भारतात आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून फार महत्त्वपूर्ण असे सकारात्मक बदल झालेलेआपल्याला दिसून येतात. दवाखान्याची संख्या वाढली. आधुनिक पद्धतीची उपचार पद्धती आली.आरोग्य विज्ञानामध्ये लागलेल्या अनेक शोधामुळे मानवी आयुष्य हे वाढत असलेले दिसून येते या सगळयाचा प्रभाव भारतीय आरोग्य व्यवस्थेवर अनुकूल झालेला दिसून येतो.

ब. जागतिकीकरणाचे प्रतिकूल परिणाम :

ज्या प्रमाणे जागतिकीकरणाचे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्थेवर अनुकूल परिणाम झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे काही प्रतिकूल परिणाम सुद्धा झालेले आहेत. त्या प्रतिकूल परिणामाचा पुढील प्रमाणे विचार करता येईल.

१ . आर्थिक विषमतेत वाढ :

जागतिकीकरणामुळे आर्थिक आणि सामाजिक विषमता वाढत चाललेली आहे. एका बाजूला श्रीमंत अधिक श्रीमंत बनत चालला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला गरीब अधिक गरीब बनत चालला आहे. लोकांची आर्थिक स्थिती घसरत चालली आहे. हे सर्व भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमुळे निर्माण झाले आहे असे म्हणता येईल .जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण हे सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्यात फार कमी पडतात उलट ते सामाजिक विषमता वाढविण्यात मदत करत असतात

२. लघु उद्योगावर आघात:

जागतिकीकरणाचा भारतातील लघु उद्योगावर आणि देशी उद्योगावर प्रतिकूल परिणाम झालेला दिसून येतो. या तीस वर्षाच्या काळात भारतामध्ये अनेक लघुउद्योग बंद पडले. जागतिकीकरणामुळे मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या बरोबर देशी उद्योग स्पर्धा करू शकत नाहीत. कारण उत्तम प्रकारच्या परकीय वस्तू मुबलक प्रमाणात व वाजवी दरात स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध होत असल्यामुळे स्थानिक उद्योजकांना विदेशी वस्तू सोबत स्पर्धा करावी लागत आहे आणि या स्पर्धेमध्ये देशी उद्योग टिकत नाहीत हा अनुभव आहे.

३. देशाचा कर्जबाजारीपणा वाढला:

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारताच्या विदेशी कर्जामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.जागतिकीकरणाच्या धोरणांमध्ये परकीय भांडवल, विदेशी तंत्रज्ञान, वस्तू आणि सेवा यांची सातत्याने आयात करावी लागते आणि या आयातीसाठी विदेशी भांडवलाची गरज असते. जर हे भांडवल पुरेशा प्रमाणात देशाकडे नसेल तर अशा वेळेस परकीय कर्ज काढावे लागते. देशाची आयात वाढल्यामुळे कर्ज वाढते, कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढावे लागते आणि अशा प्रकारे भारतासारखे विकसनशील राष्ट्र कर्जाच्या सापळयात मध्ये अडकतात.

४. नैसर्गिक साधन सामग्रीचा अयोग्य वापर :

जागतिकीकरणामुळे भारताच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढलाआहे. साधन सामग्री वापर गरजे पेक्षा जास्त होऊ लागल्यामुळे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आपण साध्य करू शकत नाही.

५. पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम :

जागतिकीकरणामुळे भारतात पर्यावरणीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्या जास्तीत जास्त फायदा मिळविण्याच्या हेतूने नैसर्गिक साधन संपत्तीचा स्वैरपणे वापर करत आहेत. यामुळे हवा, पाणी, भूमी यांचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढत चालले आहे. याचाच एक भाग म्हणून सध्या भारतासह संपूर्ण जग जागतिक तापमानवाढीच्या संकटामध्ये अडकलेले दिसून येते.

६ . मानवी मूल्याचा ऱ्हास :

जागतिकीकरणामध्ये मानवी मूल्यांची पायमल्ली केली जात आहे. सत्य, प्रामाणिकपणा इत्यादी मानवी मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे. स्वातंत्र्याचा अतिरेक, अप्रामाणिकपणा, समतेचा अभाव या सर्वामुळे मानवी मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे असे दिसून येते.

७. शिक्षणाचे व्यापारीकरण :

जागतिकीकरणामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्था संपूर्ण ढवळून निघालेली आहे. भारतामध्ये शिक्षण व्यवस्था खाजगी लोकांच्या हाती गेल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण घेणे महाग बनत चालले आहे. खाजगी विद्यापीठे, विदेशी विद्यापीठे आणि खाजगी शिक्षण संस्था यामुळे शिक्षणाचे व्यापारीकरण होऊन बसले आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला हे परवडणारे नाही. कारण आजही भारतामध्ये असलेला बहुसंख्य समाज शिक्षणापासून वंचित आहे. आदिवासी, भटके-विमुक्त, अनुसूचित जाती-जमातीतील लोक या शिक्षणाच्या व्यापारी कारणामुळे शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत.

अशाप्रकारे गेल्या तीस वर्षात जागतिकीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था बदलून निघाली आहे. लोकांच्या जीवनशैलीमध्ये बदल झाला आहे. राहणीमाना मध्ये बदल झाला आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय या सर्व क्षेत्रात जागतिकीकरणामुळे महत्वपूर्ण बदल झालेले दिसून येत आहेत .जागतिकीकरणाचे यावरील क्षेत्रांमध्ये काही चांगले परिणाम घडून आले आहेत तर काही प्रतिकूल परिणाम घडून आलेल्या आहेत हे स्पष्ट होते.

निष्कर्ष :

1. जागतिकीकरणामुळे भारताच्या विदेशी व्यापारात वाढ झाली.
2. विदेशी चलन साठ्या मध्ये वाढ झाली.
3. देशाचा जीडीपी वाढला.
4. सेवा क्षेत्राचा विस्तार झाला.
5. आर्थिक विषमता वाढली.
6. लघुउद्योग बंद पडले.
7. देशाच्या औद्योगिक रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले.

शिफारशी :

1. जागतिकीकरणाचे प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल करणे आवश्यक आहेत.
2. विकसित देशा सोबत स्पर्धा करायची असेल तर भारताने विज्ञान क्षेत्रामध्ये फार मोठी प्रगती करणे आवश्यक आहे.
3. देशी उद्योगांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी त्यांना तांत्रिक आणि भांडवली दृष्टिकोणातून सरकारने मदत केली पाहिजे.
4. चित घटकाकडे लक्ष देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे त्यामुळे आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत होईल.
5. शेती क्षेत्रावरील प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी शेतमालाला योग्य भाव आणि बाजारपेठा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत

संदर्भ ग्रंथ:

१. जागतिकीकरण आणि देशीवाद ---- रंगनाथ पठारे

२. जागतिक अर्थव्यवस्था- ---- मधुसूदन साठे

३. जागतिकीकरण-समस्या आशय आणि अनुभव ---- सी .पं.खेर

४. जागतिकीकरण आणि भारत- ------ नलिनी पंडित

प्रा. डॉ. अनिल पंढरीनाथ कांबळे

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

ग्रंथालय माहितीचे व्यवस्थापन व अर्थकारण विविध उदाहरणांसह स्पष्ट करून ग्रंथालयीन व्यवस्थापनातील माहितीच्या अर्थकरणाचे उदाहरणांसह विवेचन

प्रा. पाटील रमेश नवनाथ-
ग्रंथपाल, सहकार महर्षि शंकरराव मोहिते-पाटील महाविद्यालय, नातेपुते, ता.- माळशिरस जि.- सोलापूर, महाराष्ट्र

प्रास्ताविक

पूर्वीच्या काळी माहितीचे आर्थिक व्यवस्थापन करण्यात येत होते त्या काळी अनुदान मिळविणेशी संबंधित असे. आर्थिक व्यवस्थापनाच्या आधुनिक काळाचा विचार करता ग्रंथालय व्यवस्थापनात हा सर्व सामान्य व्यवस्थापनाचाच एक अविभाज्य घटक आहे. ग्रंथालयाची वाढ आणि विकास होणेसाठी परिणामकारक आर्थिक व्यवस्थापनाची गरज असते. सामान्यपणे ग्रंथालयास “नफा न कमावणारी संस्था” (non profit organisatoion) असे म्हटले जाते नफा न कमावणाऱ्या संस्था समाजात वस्तू व सेवा मोफत पुरवितात किंवा त्या क्षेत्रातील नफा कमाविणाऱ्या इतर संस्था पेक्षा कमी दरामध्ये वस्तू व सेवा पुरवतात. नफा न कमावणारी संस्था असून सुद्धा ग्रंथालये आपल्या सेवेसाठी काही शुल्क आकारतात. अर्थात हे शुल्क नफा मिळवण्यासाठी नसून ग्रंथालयाचे जमाखर्चाची तोंड मिळवणी करण्यासाठी तसेच संभाव्य दुरुपयोग टाळण्यासाठी असते.

शैक्षणिक ग्रंथालय पालक संस्थेचे सेवा केंद्र म्हणून कार्य करीत असते. शैक्षणिक ग्रंथालय नफा मिळवित नसल्यामुळे निधीचा चिकित्सकपणे योग्य वापर करणेच अत्यावश्यक असते.

दिवसेंदिवस शैक्षणिक ग्रंथालयाचे अनुदानात कपात केली जात असून वाचन साहित्याच्या किंमतीत आज वाढच होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शैक्षणिक ग्रंथालयातील ग्रंथपालांनी आर्थिक व्यवस्थापनाकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक ठरते.

1) माहितीचे व्यवस्थापन :-

1) माहिती ची व्याख्या :- माहिती या शब्दाचा नेमका अर्थ सांगणे कठीण आहे. निर्णय घेणेसाठी उपयुक्त असणारे ज्ञान म्हणजे माहिती असे थोडक्यात म्हणता येईल. एखादी विशिष्ट बाब, विषय किंवा प्रसंग यासंबंधीचे विदित करण्यायोग्य स्वरूपात असलेले ज्ञान म्हणजे “माहिती” होय._१

माहिती या संकल्पनेचे (Concept) किंवा संज्ञेचे (Term) स्पष्टीकरण व्यवहारात “ज्ञान” (Knowledge) आणि “माहिती” या संज्ञा एकाच अर्थाने वापरल्या जातात, पण दोन्ही पूरक आहे. ज्ञान या संज्ञेचे शब्दकोशानुसार दिलेले स्पष्टीकरण “सुसंघटीत” माहिती म्हणजे ज्ञान किंवा सुसंघटीत माहिती प्राप्त केल्यावर होणारा समज (Understnading) किंवा जाणीव म्हणजे ज्ञान. (रँडम हाऊस डिक्शनरी ऑफ दि इंग्लिश लैंग्वेज १९८३ पृ.७३०) यावरून असे म्हणता येईल की, मानवाच्या माहितीचा आवाका (Range) हे त्याचे वैयक्तिक ज्ञान होते.

२) व्यवस्थापन व्याख्या :-

१) “प्रत्येक व्यक्तीस निश्चित स्वरुपाचे काम देणे, काम करणे आवश्यक आहे. अशी प्रवृत्ती निर्माण करणे आणि सर्वांनी मिळून संस्थेचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सक्षमतेने काम करणे आवश्यक आहे, असे वातावरण संस्थेत निर्माण करणे व ते सातत्यपूर्ण टिकून राहील, अशी काळजी घेणे या सर्व प्रक्रियेस व्यवस्थापन म्हणता येईल.”

२) “व्यवसायाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी विविधतेचे निर्देशन व नियंत्रण यांच्याशी संबंधित असलेले व्यवसायाचे कार्य म्हणजे व्यवस्थापन होय.”विलियम स्प्रिगेल _२

अर्थशास्त्र व्याख्या :- “अर्थशास्त्र म्हणजे संपत्तीचा अभ्यास करणारे शास्त्र होय.” ॲडम स्मिथ_३.

३) आर्थिक व्यवस्थापन :-

व्याख्या :- संस्थेच्या आर्थिक साधनाचे (उत्पन्न व खर्च) नियोजन आणि नियंत्रण करणारी व्यवस्था प्रक्रीया म्हणजे आर्थिक व्यवस्थापन यालाच वित्तीय व्यवस्थापन असे म्हणतात.

व्याप्ती :- कोणतीही संस्था आर्थिक व्यवस्थापनात उत्पादन आणि विपणन (Marketing) हे तीन प्रमुख कार्ये करणे म्हणजे ही संस्थेची व्याप्ती असते. संस्था (शासन, वित्त, संस्था इत्यादी) किंवा व्यक्तिगत ठेविदारांकडून निधी मिळविला जातो. हा निधी नफा मिळवण्याच्या हेतूने योग्य कार्यामध्ये (जसे वस्तूचे उत्पादन) गुंतवला जातो.

उपलब्ध निधीची गुंतवणूक करून विविध सेवांची वा वस्तूंची निर्मिती केली जाते. तसेच निर्माण केलेल्या वस्तूंचे विपणन केले जाते._३.

जबाबदारी :- शैक्षणिक ग्रंथालयाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे सांगता येतील _४.**ग्रंथालयाचे अंदाजपत्रक तयार करणे.**

१) उपलब्ध निधीचे विविध विभागांसाठी वाटप.(Allotment)

२) ठरवून दिलेल्या कालावधीमध्ये म्हणजे आर्थिक वर्षामध्ये अनुदानाची रक्कम खर्च करणे साधारण हे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे विचारात घेतात.

३) ग्रंथालयीन खर्चाचा (Accounting) करणे.

४) ग्रंथालयाच्या वर्षभरातील आर्थिक व्यवहाराचा अहवाल तयार करणे.

५) आजच्या बदलत्या काळामध्ये निधी उभारण्याचे कार्य शैक्षणिक ग्रंथालयाच्या आर्थिक व्यवस्थापनात अंतर्भूत असते.

४) ग्रंथालयीन आर्थिक (वित्तीय) व्यवस्थापनातील मार्गदर्शक तत्त्वे :-

परिणामकारक आर्थिक व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त मार्गदर्शक तत्वे खालीलप्रमाणे आहेत.

१)आर्थिक काटकसर २) उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या निधींचा जास्तीत जास्त वापर. ३) सुलभ कार्यपद्धती ४) वेळेचे नियोजन ५) लवचिक कार्यपद्धती ६) नियमांचे पालन.

१) **आर्थिक काटकसर :-** भारतामधील ग्रंथालयांना पुरेसे अनुदान मिळत नाही, त्यामुळे शैक्षणिक ग्रंथालयांना नेहमीच आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. आर्थिक काटकसर करून शैक्षणिक ग्रंथालये या अडचणींवर काही प्रमाणात मात करू शकतात अनावश्यक खर्च टाळून उपलब्ध निधीचा दुरुपयोग टाळून काटकसर करणे शक्य आहे. काटकसर केल्यामुळे ग्रंथालयाच्या उद्दिष्ट पूर्तीमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही. याची काळजी आर्थिक व्यवस्थापनाने घेतली पाहिजे.

२) **उपलब्ध साधनसंपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर :-** वाचन साहित्य, इमारत, उपकरणे आणि प्रशिक्षित सेवक ही ग्रंथालयाची साधन संपत्ती आहे. या सर्व साधनसंपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर होणे आवश्यक आहे. कारण या साधनांच्या उपलब्धतेसाठी मोठी रक्कम खर्च होत असते. साधन संपत्तीच्या दुरुपयोगावरही नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असते.

३) **सुलभ कार्यपद्धती :-** आर्थिक व्यवस्थापनासाठी वापरावयाची कार्यपद्धती साधी असावी. वापरण्यास सुलभ असावी. कार्यपद्धतीतील साधेपणामुळे काटकसर साधता येते. तसेच कार्यक्षमता वाढते ग्रंथालय सेवकही सुलभ आर्थिक कार्यपद्धती पसंद करतात.

४) **वेळेचे नियोजन :-** कोणत्या वेळेस कोणते कार्य करावे, विशिष्ट कार्यासाठी किती वेळ लागणार आहे त्याचे नियोजन केले पाहिजे. विशेषत: अंदाजपत्रक तयार करताना वेळेचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. ग्रंथालयातील प्रत्येक विभागप्रमुखांकडून त्यांच्या आर्थिक गरजांची माहिती ग्रंथपालाकडे विशिष्ट वेळेत आली पाहिजे. त्यामुळे अंदाजपत्रक वेळेत तयार करून ते मंजुरीसाठी व्यवस्थापनाकडे पाठविणे शक्य होते.

डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांनी त्यांच्या Library Administration (ग्रंथालय व्यवस्थापन) या ग्रंथामध्ये ग्रंथ आणि नियतकालीके उपार्जित करताना वेळेचे नियोजन कसे करावे हे सांगितले आहे. वर्षाच्या शेवटी घाईघाईने मंजूर रक्कम संपवू नये. दर तिमाहीला ठराविक रकमेचा वापर कसा करावा असे त्यात सांगितले आहे.

५) **लवचिक पद्धती :-** बदलत्या परिस्थितीनुसार कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याची क्षमता असावी म्हणजेच लवचिकता असावी लागते. काही वेळा अत्यंत आणीबाणीची अवघड किंवा विशेष अशी आर्थिक परिस्थिती अचानक उद्भवते अशा परिस्थितीत पूर्वनियोजित निधी दुसऱ्याच कारणासाठी खर्च करावा लागतो. काही वेळेस असे बदल करताना शासकीय नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. काही वेळेस ग्रंथालयास एखादे विशेष अनुदान विद्यापीठ अनुदान मंडळ वा तत्सम संस्थांकडून मिळते. अशा वेळी विशिष्ट ग्रंथ स्थायी विक्रेत्याकडे (Standing Vender) उपलब्ध नसेल तर असा ग्रंथ इतर विक्रेत्यांकडून खरेदी करता आला पाहिजे. अशा प्रकारचे अनुदान थोड्या वेळात खर्च करावयाचे असते व आपणास विशिष्ट ग्रंथही खरेदी करावयाचे असतात अशा वेळी प्रचलित कार्यपद्धतीत लवचिकता असल्याने योग्य असे ग्रंथ खरेदी करता येऊ शकतात व आपल्या ग्रंथालयात उपयुक्त ग्रंथ उपलब्ध होऊ शकतात.

६) **नियमांचे पालन :-** शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने आर्थिक व्यवहारासाठी, खरेदीसाठी काही नियम केलेले असतात. वित्तीय व्यवस्थापन करताना या नियमांचे आणि कार्यपद्धतीचे पालन केले पाहिजे. महाविद्यालय ग्रंथालयात ग्रंथ खरेदी करणेसाठी निविदा मागविणे आवश्यक असते. तसेच ठराविक रक्कमेपेक्षा अधिक रक्कम फर्निचर खरेदीसाठी लागत असेल तर निविदा मागवून फर्निचर, कपाटे, खरेदी करणे आवश्यक ठरते.

५) **ग्रंथालयांची आर्थिक उत्पन्नाची साधने/ स्त्रोत :-** विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन ग्रंथालयांना खालील मार्गानंनी अर्थ (वित्त) पुरवठा होतो.

अ) पालक संस्थेकडून (महाविद्यालय, विद्यापीठ) मिळणारे अनुदान.

आ) विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मुल्णारे अनुदान.

इ) शासकीय अनुदान

ई) सामाजिक प्रतिष्ठान आणि संस्थांकडून मिळणारे अनुदान आणि देणग्या.

उ) वाचकांकडून घेतलेले विलंब शुल्क , हरविलेल्या पुस्तकांची भरपाई इ.

ऊ) ग्रंथालय सेवा शुल्क (जसे प्रतिलिपी सेवा, इंटरनेट सेवा)

ए) इतर मार्ग

अ) पालक संस्थेकडून मिळणारे अनुदान :- महाविद्यालय ग्रंथालयास महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडून काही निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच विद्यापीठ ग्रंथालयास विद्यापीठाकडून काही रक्कम दिली जाते. शैक्षणिक ग्रंथालयास हा एक वित्त पुरवठा होण्याचा महत्वाचा मार्ग आहे.

आ) विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळणारे अनुदान :- महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय ग्रंथालयांना विद्यापीठ अनुदान आयोग अनुदान देते. १) वाचन साहित्य खरेदी करण्यासाठी अनुदान तसेच २) इतर किरकोळ खर्चासाठी विद्यापीठ अनुदान देते _५

भांडवली अनुदान हे विशिष्ट हेतूसाठी दिले जाते. ग्रंथालय इमारत बांधणे, फर्निचर व उपकरणे खरेदी करणे. विशेष वाचन साहित्य संग्रह विकसित करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग “विकास निधी” उपलब्ध करीत असते. महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय ग्रंथालयांना लागणारे बहुतांशी अनुदान विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळत असते. महाविद्यालयीन व विद्यापीठ ग्रंथालयाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विविध योजना सदर केल्या आहेत. विद्यापीठीय अनुदान मंडळ (University Grands Commission)

भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी भारत सरकारने डिसेंबर १९५३ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना केली. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाला कायदेशीर संस्था म्हणून मान्यता देण्यात आली _६

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची कार्ये व अधिकार :-

महाविद्यालयातील आणि विद्यापीठातील शिक्षण, परीक्षा आणि संशोधनाचा दर्जा टिकवण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार कायद्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला देण्यात आले आहेत.

या अधिकार कक्षेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे कार्ये व अधिकार :-

१) विद्यापीठांच्या आर्थिक गरजा बाबत चौकशी करू शकते व अनुदान देऊ शकते.

२) उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी योग्य अशा शिफारशी करू शकते.

३) अनुदानाच्या विल्हेवाटीबाबत महाविद्यालयांना व विद्यापीठांना मार्गदर्शन करू शकते.

४) नवीन विद्यापीठाच्या स्थापनेबाबत शासणाला सल्ला देऊ शकते.

५) विद्यापीठ अनुदान आयोग भारतातील उच्च शिक्षणाचे धोरण ठरविते आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयांना व विद्यापीठांना मार्गदर्शन करते.

महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ ग्रंथालयांना मदत करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे धोरणात्मक उपक्रम खालील प्रमाणे :-

१) गहू खरेदी कर्जाअंतर्गत शैक्षणिक अदलाबदल उपक्रम.

२) बुक बँक उपक्रम.

३) प्रादेशिक ग्रंथालय केंद्र.

४) अभ्यास केंद्र.

५) राष्ट्रीय माहिती सेवा केंद्र आणि विद्यापीठ माहिती सेवा केंद्र.

६) विभाग अभ्यास केंद्र.

७) वाचन साहित्य संग्रह विकास उपक्रम.

८) मुलभूत सुविधा.

९) वार्षिकोत्सव अनुदान.

१०)COSIP आणि COHSSIP योजना.

इ) **शासकीय अनुदान :-** राज्य शासन राज्यातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना अनुदान देत असते. महाराष्ट्र शासन विद्यापीठ व महाविद्यालयातील मान्यता पदावरील सेवकांचे वेतन व भत्ते देत असते, त्याला वेतन अनुदान म्हणतात. याशिवाय ठराविक दरानुसार परीक्षण अनुदान देत असते. या अनुदानातून विद्यापीठ अथवा महाविद्यालय काही रक्कम ग्रंथालयास अदा करत असते.

ई) **सामाजिक प्रतिष्ठान आणि इतर संस्थांकडून मिळणारे अनुदान आणि देणग्या :-** काही सामाजिक प्रतिष्ठाने आणि संस्था ग्रंथालयास भरीव देणग्या व अनुदान देत असतात – अमेरिकेने गहू दान (Wheat Loan Programme) योजनेत भारताला १९५४ ते १९६२ या काळात १७,००,००० डॉलर रकमेचे अनुदान दिले होते. या रकमेतून भारतीय ग्रंथालयाने अमेरिकन वाचन साहित्य खरेदी करावे व भारतीयांना अमेरिकन वाचन साहित्याचा अभ्यास करता यावा यासाठी हि रक्कम उपलब्ध केली होती. आशिया फाउंडेशन, रॉक फेलर फाउंडेशनतर्फे भारतातील अनेक विद्यापीठांच्या ग्रंथालयांना मोठी अनुदाने मिळाली आहेत. फोर्ड फाउंडेशन मार्फत दिल्ली विद्यापीठाला अनुदान मिळाले. या अनुदानातून ग्रंथालय शास्त्रातील विषयावरील वाचन साहित्य व ग्रंथालय शास्त्र विभागासाठी उपकरणे खरेदी करण्यात आली .

देणगी :- व्यक्ती आणि संस्थांकडून रोख रकमेच्या वा वस्तूंच्या स्वरूपात ग्रंथालयास देणग्या मिळत असतात. पण भारतीय ग्रंथालयांना लक्षणीय अशा देणग्या मिळत नाहीत, म्हणून हा उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग होऊ शकत नाही.

उ) वाचकाकडून घेतलेले शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, विलंब शुल्क दंड :- महाविद्यालयीन ग्रंथालय आणि विद्यापीठ ग्रंथालय विद्यार्थ्यांकडून काही ठराविक रक्कम ग्रंथालय शुल्क म्हणून घेत असते. जास्त विद्यार्थी असतील तर या मार्गाने ग्रंथालयास ठराविक असे चांगले उत्पन्न मिळते. तसेच ठराविक दिनांकानंतर (Due Date) वाचन साहित्य परत न केल्यास विलंब शुल्क घेतले जाते. वाचन साहित्य हरविल्यास त्याची किंमत वसूल केली जाते, वाचन साहित्य खराब केल्यास दंड घेतला जातो_८

ऊ) इतर मार्ग :- १)ग्रंथ सूची, नियतकालिके निर्देशानुसार, ग्रंथालय मार्गदर्शिका इत्यादी प्रकाशनाच्या विक्रीतून थोडा निधी मिळतो २) रद्दी विक्री – जुनी वर्तमानपत्रे रद्द बातल नियतकालिके इत्यादी विक्रीतून थोडा निधी मिळू शकतो.३) अनामत रक्कम – ग्रंथांच्या किंमती वाढल्यामुळे काही ग्रंथालयांनी अनामत रकमेत वाढ केली आहे. ४) आंतर ग्रंतालयीन देवघेव – प्रतीखंड २५ रुपये + पोस्टेजचा खर्च वसूल केला जातो. ५) रात्रीचे वाचन – यासाठी काही संस्था वीज शुल्क्ल आकारतात.

६) **समारोप –** विद्यापीठ व महाविद्यालयीन ग्रंथालयांना नफा न मिळविणाऱ्या संस्था समजले जाते. कारण हि ग्रंथालये आपल्या सभासदांना बहुतांश मोफत सेवा देतात. बहुतांश ग्रंथालयात माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रवेश झाला आहे. माहिती तंत्रज्ञान महाग आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांवर शुल्क आकारणे आवश्यक झाले आहे. विद्यापीठांनी आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केली आहे वाचन साहित्याच्या किंमतीत सतत वाढ होत आहे. वीज, पाणी, बांधकाम खर्च यामध्ये ही सतत वाढ होत आहे. संगणक व इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल्स या उपकरणांची देखभाल मध्येही वाढ झाली आहे. त्यामुळे सेवा शुल्क आकारण्याचा ग्रंथालयाचा दृष्टीकोन आणखी दृढ झाला आहे. ग्रंथालय सेवेच्या बदलत्या प्रवाहामुळे ग्रंथालये जास्तीत जास्त सेवांना शुल्क आकारत आहेत. तसेच ग्रंथालय सेवांचे दरही दिवसेंदिवस वाढत आहेत. माहितीचे व्यवस्थापन व अर्थकारण या संबंधी ग्रंथालयीन व्यवस्थापनातील माहितीच्या अर्थकारणाची कल्पना वरील विवेचनावरून स्पष्ट होते. उपलब्ध निधीचा परिणामकारक वापर करणे हे आर्थिक व्यवस्थापनाचे प्रमुख कार्य आहे. कार्यक्षम आर्थिक व्यवस्थापनामुळे उत्तम सेवा देणे शक्य होते.

संदर्भ ग्रंथ यादी

1. प्रलेखन आणि माहिती शास्त्र, नरगुंदे रेवती, पुणे, युनिव्हर्सल प्रकाशन
2. व्यवसाय व्यवस्थापन , मानकर सुधाकर एस., क्षीरसागर रा. ना. कोल्हापूर फडके प्रकाशन
3. संशोधन पद्धती व संख्याशाश्त्र, कुंभोजकर ग. वि., कोल्हापूर फडके प्रकाशन
4. ग्रंथालय परिचर, पारखी गंगाधर र., पुणे, युनिव्हर्सल प्रकाशन
5. ग्रंथालय व्यवस्थापन, भागवत शशिकला गं., पुणे, युनिव्हर्सल प्रकाशन
6. ग्रंथालय व माहिती शास्त्र, पवार एस. पी., बडवत्ते सविता कोल्हापूर फडके प्रकाशन
7. ग्रंथालये आणि सामाजिक विकास, नरगुंदे रेवती, पुणे, युनिव्हर्सल प्रकाशन
8. ग्रंथालये आणि सामाजिक विकास ,नरगुंदे रेवती, पुणे, युनिव्हर्सल प्रकाशन

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

जागतिकीकरणाचा ग्रामीण हुंकार : सिझर कर म्हणतेय माती

डॉ. सुनीता पांडूरंग सुर्यवंशी
सहाय्यक प्राध्यापिका,
स.म.शंकरराव मोहिते-पाटील महाविद्यालय, नातेपुते, ता. माळशिरस जि. सोलापूर
Email- sunitagandhale@gmail.com

प्रस्तावना :

'सिझर कर म्हणतेय माती' हा कल्पना दुधाळ यांचा पहिलाच कवितासंग्रह अनेक पुरस्कारांचा मानकरी ठरला. या संग्रहात त्यांनी जागतिकीकरणाचा प्रभाव असलेल्या ग्रामीण कृषी संस्कृतीचे अत्यंत वास्तववादी चित्रण केलेले आहे. हा कवितासंग्रह सन २०१० मध्ये प्रकाशित झालेला आहे. ग्रामीण जीवनावर झालेल्या जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे शेती आणि शेतकरी यांच्यामध्ये कसा विलक्षण बदल झालेला आहे, याचे चित्रण या संग्रहातील कवितांमधून कवयित्री सहजपणे रेखाटतात आणि आधुनिक काळातील वास्तवाचे चित्र डोळ्यापुढे उभे करतात. 'सिझर कर म्हणतेय माती' या कवितासंग्रहात कल्पना दुधाळ यांनी 'वरचा बांध : अस्तित्त्व...', 'मधला बांध : सहज गं...', 'खालचा बांध : चिखलात कोरलेले ठसे...' या तीन विभागांमध्ये कविता लिहिलेल्या आहेत. या कवितांमधून त्यांनी आधुनिक जगात शेतकऱ्यांच्या बदलेल्या कृषी जीवनाचे रेखाटन करताना, समकालीन वास्तवाचे भान ठेऊन जागतिकीकरणाच्या रेट्यात बदलत्या ग्रामिण संस्कृतीचे दर्शन घडविलेले आहे.

जागतिकीकरणाचा प्रभाव असलेले ग्रामीण आणि कृषी जीवन :

जागतिकीकरणामुळे विविध क्षेत्रात अनोखे बदल झाले आणि जग अगदी जवळ येऊन ठेपले. जागतिकीकरणाचा प्रभाव आणि परिणाम ग्रामीण जीवनावरच नव्हे तर ग्रामीण कृषी जीवनावरती देखील खूप मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येतो. 'सिझर कर म्हणतेय माती...' या कविता संग्रहाच्या 'मातीतून उगवलेल्या कवितेविषयी...' या प्रस्तावनेत उत्तम कांबळे आधुनिक काळातील जागतिकीकरणाची स्थिती सांगताना लिहितात, "जागतिकीकरण काही नवं राहिलं नाही आता... ते आता पसरतंय. आंब्याच्या फांदीपासून गावाच्या पांदीपर्यंत, संसदेच्या उंबरठ्यापासून शेतीच्या बांधापर्यंत... बाटलीतल्या पाण्यापासून ते धान्यापासून करावयाच्या दारुपर्यंत... मॉडर्न शाळांपासून ते विहिरीतल्या गाळापर्यंत... ऊस तोडणाऱ्या यंत्रापासून ते कत्तलखान्यात पोचलेल्या म्हाताऱ्या बैलापर्यंत... रोजगार हमी योजनेवर सुगडी मागण्यापासून ते मॉलमध्ये मस्ती करणाऱ्या बर्गरपर्यंत. इव्हेन्टपासून ते ज्वारीच्या पट्ट्यात होणाऱ्या हुरड्यांच्या पार्टीपर्यंत... हे सारे तरंग आणि रंग आता मराठी कवितेतही उगवायला लागले आहेत..."[१] उत्तम कांबळे यांच्या मीमांसेवरून ग्रामीण भागात जागतिकीकरण हे किती खोलवर पोहोचलेले आहे याची कल्पना येते.

जागतिकीकरणाच्या या युगात परदेश आणि स्वदेश यांच्यातील अंतर फार जवळ येऊन ठेपलेले दिसते. एखाद्या गावाला जायचे कॅन्सल करुन आपल्या कामाला जायचे माणूस ठरवतो, तसे काहीसे आजच्या काळात झालेले दिसून येते. कवयित्री लिहितात,

"परदेशातील पोरानं पाठवलेलं, माय फेअर लेडीचं तिकिट, कॅन्सल करुन...
घेतल्या तिनं खंडीभर शेळ्या, आणि पोसत राहिली तुतीवर ...रेशमी अळ्या"
(सिझर कर म्हणतेय माती) (पृ.१७)

यांत्रिकीकरणाच्या युगात माणूस हा अत्यंत आळशी बनलेला आहे. तो आधुनिक सोयी-सुविधांवर फार अवलंबून राहु लागलेला आहे. त्यामुळे शेतीला मजूर मिळानाशे झाले आहेत. अत्याधुनिक बी-बीयाणे, खते आणि औषधांच्या फवारणीमुळे शेती गुदमरुन जाऊ लागलेली आहे. कवयित्री म्हणतात,

"बॅलन्स आणि बॅटरी संपलेल्या मोबाईलसारखी, बिनकामाची माणसं...

चावीच्या खेळण्यागत, जेवढ्यास तेवढी पळणारी माणसं..." (लढाई) (पृ.२६)

माणसाच्या अंग राखुन काम करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे आधुनिक काळात माणूस आळशी बनलेला आहे. त्यामुळे शेतीमध्ये कष्ट करण्याची माणसाची इच्छा राहिलेली नाही. त्यामुळे शेतीमध्ये अनेक नवनवीन प्रयोग झालेले दिसतात,

"रासायनिक खतं, विद्राव्य खतं... बुरशीनाशकं... तणनाशकं...
ठिबक सिंचन... कृषी पर्यटन... ट्रॅक्टर... मळणी... कापणी यंत्रं...
ॲटोस्वीच... मोबाईल स्टार्टर... ऊस तोडणी यंत्र... बचत गट...

कृषी कॉल सेंटर... हेल्पलाईन... कित्येक जोडधंदे... कित्येक नवे प्रयोग..." (लढाई) (पृ.२६)

जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे असे कितीतरी नवनवे प्रयोग केले, तरी प्रत्येकाला आपल्या आयुष्याची लढाई ज्याच्या त्यालाच लढावी लागते. छातीची ढाल करुन नव्या युगाला सामोरे जावे लागते आहे. यातही माणूसपण टिकवून ठेवावे लागते आहे. शेती, जनावरे आणि ग्रामीण जीवन यांची नाळ तुटू देऊन चालणार नाही. सामाजिक बांधिलकी जोपासणे हे माणसाचे आद्य कर्तव्य आहे. "समाजव्यवस्थेतील अन्यायावर व रुढींवर प्रहार करणे आणि व्यापक राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून मानवतावादाचा पुरस्कार करणे, हे सामाजिक कवितेचे गुण होत."[२] ही वा. भा. पाठक यांनी कल्पना दुधाळ यांच्या सामाजिक कवितेविषयी केलेली मीमांसा अत्यंत बोलकी आहे.

आधुनिक काळातील नव्या बदलाबरोबरच माणूस देखील बदलत चालला आहे. त्याला त्याच्या स्वार्थापलीकडे दुसरे काहीही दिसत नाही. जागतिकीकरणाच्या या वाऱ्यात तो बेभान होऊन गेलेला दिसत आहे. कवयित्री म्हणतात,

"मातीतल्या माणसाचं माणूसपण, भिरूड लागून नष्ट होताना,

जग मुठीत घेऊन, एक्सप्रेस युवरसेल्फ...

कनेक्टिंग पिपल... म्हणायचं?" (वाटण्या) (पृ.३६)

जग कितीही जवळ आलं तरी माणसांच्या गर्दीत माणूस एकटाच असल्याची जाणीव माणसास होत असते. माणूस स्वतःच्या भावविश्वात एकटाच रमत असतो. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्रीने गगनचुंबी यश संपादन केलेले असले तरीही पोटाला मात्र भाकरीचीच गरज असते,

"छपरावर छत्री बसविली,
तेव्हापासून... पोरं-सोरं... मोठ्यांनीही गर्दी केली,
शेकडो चॅनल्स... रात्रंदिवस... बघा कितीही,
आख्खं जग... पडद्यावर, पण इथं...
पोटातल्या कावळ्यांना, कुणी जरा तुकडा टाका रे... (झलक दिखला जा)(पृ.७०)

आधुनिक काळातील नव्या कृषी संस्कृतीत अनेक बदल घडलेले आहेत. ते सर्व बदल कल्पना दुधाळ यांच्या कवितेतून अत्यंत सूक्ष्मपणे उमटताना दिसतात. पिकणारी राने, शिवारे कचरा डेपो होत आहेत. त्यात जागतिकीकरणामुळे नवनव्या गोष्टींचे संक्रमण झालेले दिसते,

"खाद्यपदार्थांच्या रिकाम्या पिशव्या... गुटख्याच्या पुड्या...
क्रीम... शाम्पू... कंडोम... पॅड्सचे पुडके...

फुटलेल्या बाटल्या...” (खत) (पृ.२२)

आधुनिक काळातील बदलत्या जीवनचक्रातील घटक असलेला हा सगळा कचरा खतावाटे शेतात पसरतो. नांगरात, कुदळीत, खोऱ्यात अडकतो. पिकाच्या मुळ्या मातीपर्यंत पोहोचून अन्नद्रव्य शोषतात. तेव्हा गुणसुत्रातून वेगळंच काहीतरी बाहेर येईल. ही जुन्या सेंद्रिय शेतीची जागतिकीकरणामुळे झालेली नवी ओळख आहे, असे कवयित्रीला वाटते.

जागतिकीकरणामुळे शेतीमध्ये नव-नवे बदल झाले. अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री, शेतीसाठी आवश्यक असलेले खते, औषधे यांचा वापर करुन सधन भागातील किंवा देशातील शेतकरी भरघोस उत्पन्न घेतो आणि फायदा मिळवू लागला. त्यामुळे भारतीय कृषी संस्कृतीत पारंपारीक शेती करणारा शेतकरी नापिकीमुळे, बेभरोशाच्या पावसामुळे आणि शेतमालास हमी भाव मिळत नसल्यामुळे हताश होतो आणि आत्महत्या अघोरी कृत्य करण्याचे धारिष्ठ करतो, तेव्हा संवेदनशील मनाच्या कवयित्री देखील या समस्येतील वास्तव आपणासमोर मांडताना म्हणतात,

“अठराविश्व दारिद्रय, गावाला तसं नवं नव्हतं,

कर्जापायी फाशी घेणं, गावाला कधीच ठावं नव्हतं.” (कुसळाचं गाव) (पृ.७७)

दुष्काळ तसा ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला असतो. रानात कुसळंच उगवायची. गायीगुरं कुसळंच खायची. चार थेंब पडलेच तर करडईचं पीक यायचं. हुलगा, मटकी पिकायची. पण मन कणखर होतं. कितीही संकटं आली तरी शेतकरी फाशी घ्यायचा नाही. आता या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात मात्र गुरांच्या दावणीचं दावं शेतकऱ्याच्या गळयात पडू लागलेलं आहे, ही व्यथा त्यांना वाटते. पण या आधुनिक काळात कोणतेही रडगाणे न गाता या जगरहाटीत शेतकऱ्यांनी देखील काळाबरोबर पावलं टाकली पाहिजेत असे त्यांना वाटते,

“गावामधलं पोर आता कार्व्हर झालं पाहिजे,

प्रयोगाचं पिक लावून बांडगूळ काढलं पाहिजे.”(कुसळाचं गाव) (पृ.७८)

असा आशावाद त्या व्यक्त करतात. जागतिककरणाच्या प्रवाहामुळे बदलेल्या ग्रामीण संस्कृतीत ज्ञानगंगा खेडोपाडी पोहोचली. मातीत जन्म जाऊ नये म्हणून बाप गरीबी सहन करीत, पोटाला चिमटा घेऊन मुलांना शिक्षण देतो. पण शहरात जाऊन पदवी घेऊन आलेल्या पोराला शिवार नकोसे वाटते, जनावरांची किळस येते. चकचकीत शहरे पाहिलेल्या मुलाला धुळीत माखलेलं गाव, जनावरं, माणसं यांच्याबद्दल आस्था राहत नाही. जागतिकीकरणात जवळ एकमेकांच्या जवळ आलेल्या चकचकीत तोंडवळयाच्या शहराकडेच त्याची ओढ राहते. त्यामुळे तो शेती विकून नोकरी करण्यासाठी बापाला तयार करतो तेव्हा कवयित्री लिहितात,

“शिपायाच्या जागेसाठी पोरानं, एकर विकायचा विषय काढला,

तसा बाप ताडकन् उठला, विहीर खणल्यागत...” (काय चुकलं) (पृ.२३)

पोराच्या आधुनिक विचाराने बापाला वेदना होतात. ‘शिक्षणाच्या शहाणपणाने आणि जागतिकीकरणाच्या प्रभावाने पोराचे विश्व बदलले’ याची जाणीव बापाला होते. स्क्रीनवर झळकणारे बाजारभाव वाचून काहीच मिळत नाही. ‘पांढऱ्यावर काळं करण्यापेक्षा काळ्यातून हिरवं काढ, निदान पोट तरी भरेल’ हे बापाचे तत्त्वज्ञान आदिम मानवाच्या जीवनचक्रातील मूळ गाभ्यावर प्रकाश टाकणारे आहे.

शहरात जाऊन साहेब झालेल्या मुलाला, जागतिकीकरणाच्या भंपक व्यापात गुंतल्यामुळे गावी यायला वेळ नाही. तो आईबापांना विसरत चालला आहे. पण त्याचे अगतिक, वृद्ध झालेले वडील मुलाच्या प्रेमासाठी आसुसलेले असताना म्हणतात,

“सायेब झालास पोरा तू, खीनभर घरला येऊन जा

तुटायला झालंय दावं आता, तोंड तरी दावून जा...” (सायेब) (पृ.८४)

अशाप्रकारच्या कवितांमधून कवयित्री जागतिकीकरणामुळे नात्यांमध्ये पडत चाललेल्या दरीमुळे सामाजिक वास्तवाशी सहकंप होतात. “सामाजिक वास्तवाशी सहकंप होण्याची शक्ती ज्याच्या प्रतिभेत असेल, त्याच कविच्या हातून उत्कृष्ट सामाजिक जाणिवेची कविता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.”[३] हे गो. वि. करंदीकर यांनी नमूद केलेले विधान कल्पना दुधाळ यांच्या बदलत्या कृषी जीवनातील सामाजिक वास्तवतेशी मिळते जुळते आहे.

समारोप :

‘सिझर कर म्हणतेय माती’ हा कवितासंग्रह शेती आणि शेतकरी यांच्या समकालीन समस्या मांडताना विद्रोही वाटेने जात असला तरीही जागतिकीकरणाचा ग्रामीण आणि कृषी जीवनावर पडलेला प्रभाव याची मीमांसा करतो. कृषी, कृषी संस्कृतीतील बदल, जागतिकीकरण यासारख्या विषयांवर कवयित्री अत्यंत वास्तवपणे लिहितात. “सऱ्या-वरंबे ओढलेल्या रानात www दिसायचं आणि माती ग्लोबल झाली असं वाटायचं.”[४] साध्या, सोप्या भाषेतील त्यांच्या कविता वाचकाच्या मनाचा तळ गाठतात. भारतीय संस्कृतीच्या कितीतरी खुणा त्यांच्या कवितांमध्ये पानोपानी विखुरल्या आहेत. एक सर्जनशील मनाची, शेतीत राबणारी स्त्री या सर्व कवितेत पहायला मिळते. तसेच कल्पना दुधाळ यांचे सामाजिक भानही या कवितासंग्रहातून जाणवत राहते. कल्पना दुधाळ यांच्या कवितांचा गौरव करताना उत्तम कांबळे म्हणतात, “एक बहुआयामी आणि अस्वस्थ श्वास सोडणारी कल्पनाची कविता प्रत्येकाला अस्वस्थ करते. मोठा पिसारा घेऊन ती जागतिकीकरणाला आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना पकडते. विशेष म्हणजे वाचकांना पकडून त्याला विचार करायला लावते.”[५]

संदर्भ टिपा :

१) दुधाळ कल्पना, ‘सिझर कर म्हणतेय माती’, कांबळे उत्तम ‘मातीतून उगवलेल्या कवितेविषयी…’, नवसिद्धांत प्रकाशन, नाशिक, (पृ.९).

२) पाठक वा. भा., ‘आधुनिक मराठी काव्याचे अंतःप्रवाह’, ठोकळ प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती-१९६४, (पृ.१४६).

३) करंदीकर गो. वि., ‘परंपरा आणि नवता’, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, प्रथमावृत्ती-१९६७ (पृ.४७).

४) दुधाळ कल्पना, ‘सिझर कर म्हणतेय माती’, ‘दोन शब्द रुजव्यातून’, नवसिद्धांत प्रकाशन, नाशिक, प्रथमावृत्ती-२०१०.

५) दुधाळ कल्पना, ‘सिझर कर म्हणतेय माती’, कांबळे उत्तम ‘मातीतून उगवलेल्या कवितेविषयी…’, उनि, (पृ.९)

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.1 Issue-2 Sept- 2021

जगतिकीकरण आणि भारतीय शेती

प्रा. डॉ. पी. डी. हुडेकर
अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख विदर्भ महाविद्यालय, बुलडाणा
मेल : hudekarfinance@gmail.com

प्रस्तावना :

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. आजही जवळ जवळ ७० टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर उदरनिर्वाह करतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी हा सव्रात मोठा घटक राहीला आहे. कृषी क्षेत्राचे महत्व हे आर्थिक घटकातच नाही तर सामाजिक सुरक्षिततेसाठी लोकांचे प्रमाण १९९३.—९४ मध्ये ६४.८ टक्के होते ते २०११—१२ मध्ये ४८.९ टक्के झाले. पण तरीही जास्तीत जास्त लोकांना रोजगारासाठी त्यावरच अवलंबुन राहावे लागते.

जागतिकीकरण ही एक संपुर्ण जगाची बाजारपेठ एकच निर्माण करणारी प्रक्रिया आहे. जागतिकीकरणामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्विकार केला गेला. भारताने फार पुर्वीपासुनच आंतरराष्ट्रीय व्यापारात शेती उत्पादनाचा समावेश मर्यादित ठेवण्याचे धोरण अंगीकारले होते. कारण भारत सरकारला विकसनशिल देशासाठी शेती उत्पादन हे केवळ एक उत्पादनाचे धोरण अंगीकारले होते. कारण भारत सरकारला विकसनशिल देशासाठी शेती उत्पादन हे केवळ एक उत्पादनाचे साधन म्हणून शेती उत्पादनात उदारीकरणाचे धोरण स्विकारले. जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेचा उदय विसाव्या शतकाच्या पुर्वाधातच झाली. तत्कालीन भारताचे प्रधानमंत्री पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी १९९१ मध्ये नविन आर्थिक धोरणाचा स्विकार केला. व भारतात जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरणाचे वारे वाहु लागले. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवे वळण व दिशा मिळाली. या ‘खाऊजा’ — च्या धोरणामुळे शेती, उद्योग, व्यापार, दळण—वळण, बॅका, पायाभुत व मुलभूत सुविधा यामध्ये अनेक प्रकारचे बदल घडून आले. जागतिकीकरणामुळे भारतीय समाज व्यवस्थेत खूप मोठा बदल घडून आला.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतातील जवळजवळ ६५ ते ७० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबुन आहे. एकविसाव्या शतकामध्ये शेतीचे स्वरुप बदलत चालले आहे याची सुरूवात साधारण २० व्या शतकाच्या माध्यमातून झाली. खाजगीकरण उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय शेतीवर याचा फार मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडलेला दिसून येतो.

भारताने १९९१ साली भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये उदारीकरण हे धोरण स्वीकारले. तेव्हा पासूनच भारताने आपली अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये समाविष्ट केली.

जगतिक व्यापारातील परिस्थिती बदलली पाहिजे यासाठी वेगवेगळ्या संघटना स्थापन होऊ लागल्या. याचीच परिणीती मिळाली.

जगतिकीकरण ही प्रक्रिया आर्थिक, तांत्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय शक्तीचे संयोगीकरण आहे. जागतिकीकरणामुळे शेतीमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग सर्वत्र होऊ लागला आणि उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.

१) संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :

i) जागतिकीकरण या संकल्पनेचा अभ्यास करणे.

ii) जागतिकीकरणाचा भारतीय कृषी क्षेत्रावर झालेला प्रभावाचा अभ्यास करणे.

iii) जागतिक व्यापार संघटनेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामाचा अभ्यास करणे.

iv) जागतिकीकरण आणि जागतिक संघटनाचा आणि भारत याचा आढावा घेणे.

२) जागतिकीकरणाचा अर्थ :

साध्या व सोप्या शब्दात जागतिकीरणाचा अर्थ सांगावयाचा झाल्यास 'एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थकारणाशी संलग्न करणे म्हणजे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण होय.'

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, 'जागतिकीकरण म्हणजे वस्तु, सेवा, आंतरराष्ट्रीय भांडवल प्रवाह, अतिजलद व प्रसरण पावणारे तंत्रज्ञाने यांचे वाढते प्रमाण, तसेच विविधता ह्यांच्या सहाय्याने जगातील देशाचे सतत वाढते परस्परावलंबीत्व होय.

रुसी मोदी, ''जागतिकीकरण म्हणजे खुली स्पर्धा आणि नविन तंत्रज्ञान यातुन उत्पादकता आणि उत्पादन वाढविणे तसेच संपुर्ण जग एक बाजारपेठ निर्माण करणे आणि वस्तू व सेवायांची विक्री करणे होय.''

जगतिकीकरणामध्ये मुक्तअर्थव्यवस्थेचा स्विकार केला गेला यामुळे राष्ट्राराष्ट्रामध्ये परस्परावलंबीत्व वाढत गेले व त्यातुन स्पर्धा निर्माण झाली. म्हणून अविकसीत राष्ट्रांनी शेती आणि शेतीशी निगडीत असणारे व्यवसास व इतर पुरक व्यवसाय यामध्ये प्रगती करुन उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला गेला. म्हणुनच जागतिकीकरण म्हणजे एक प्रकारे सर्व क्षेत्रात असणारी तीव्र स्पर्धा होय.

जगतिकीकरण हे मुख्यतः नवआर्थिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आतंतराष्ट्रीय आणि आर्थिक गुंतवणुकीमधील अडथळे दूर केले जातात. अधिक प्रमाणात व्यापार सर्वसंबंधितांना चांगला फायदा हे जागतिकीकरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

१९९१ साली Liberalisation, Globalisation, Privatlization ही संकल्पना उदयास आली. यामधूनच भारताने आपली अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थे बरोबर संलग्न केली म्हणजेच आपली अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये समाविष्ट केली.

३) जागतिकीकरणाची व्याख्या :

i) ''जागतिकीकरण हे आर्थिक संबंधाशी निगडित असल्यामुळे राष्ट्रीय सीमांचे अडथळे कमी किंवा दूर करुन वस्तु, भांडवल सेवा आणि श्रम सेवा यांचा प्रवाह सुलभ करणे होय.''

ii) ''जागतिकीकरण म्हणजे प्रत्येक देशाने आपली अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये समाविष्ट करणे होय.''

४) संशोधन पध्दती :

प्रस्तुत संशोधनासाठी दुय्यम साधनसामग्रीचा वापर केला असून आकडेवारी संकलित करण्यासाठी विविध संदर्भ ग्रंथ, मासिके, शासकीय अहवाल, वृत्तपत्रे, शोधप्रबंध यांचा वापर केला आहे.

५) गृहितके :

i) जगतिकीकरणाचा कृषी क्षेत्रावर फार मोठा परिणाम झालेला आहे.

ii) जगतिकीकरणामुळे कृषी क्षेत्रावर नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे.

iii) उत्पादन केलेला माल जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता निर्माण करेल.

६) संशोधन विषयाचे विश्लेषणात्मक विश्लेषण :

i) जागतिकीकरण आणि भारतीय शेती :

जागतिकीकरण अस्तित्वात आल्यानंतर देशामध्ये खुल्या व्यापाराचे वातावरण निर्माण होईल. भारतातील शेतमालाची निय्रत मोठ्या प्रमाणावर वाढेल अशा आशावाद निर्माण झाला कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मुळी शेती हा आहे. म्हणून भारतीय कृषीव्यवस्थेत झालेले बदल हे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दुरगामी परिणाम करणारे ठरतात. कृषी हा केवळ एक व्यवसाय नसून एक जिवनपध्दती आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा मार्ग हा शेतीच्या विकासाशी निगडीत आहे. १९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत जागतिकीकरणाचा शिरकाव झाला आणि त्याचा प्रभाव अनेक क्षेत्राबरोबरच कृषीक्षेत्रावर सुध्दा पडला.

ii) जागतिकीकरणाचा शेती क्षेत्रावरील प्रभाव :

१९९० च्या सुमारास मुक्त व्यापाराचा एक करार झाला त्याविषयी जगभर मत भिन्नता होती पण ती दडपडल्या गेली आणि तो करार १ जाने, १९९५ पासून लागू झाला. १९४८ मध्ये दुसरे महायुध्द संपल्यानंतर मुक्त व्यापाराचा जो करार झाला त्यात मुख्यतः औद्योगिक वस्तुंचाच समावेश होता. कृषी उत्पादनाचा समावेश नव्हता. १९९५ पासून सुरू झालेल्या जागतिक व्यापार संघटन करारामध्ये कृषी वस्तुंचा समावेश करण्यात आला. त्याचा भारतीय कृषीक्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडला.

अ) भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्के लोक शेती व्यवसाय गुंतलेले आहेत, तरी शेतीपासून भारताचे GDP उत्पन्न फक्त २०.०६ टक्के एवऐच प्राप्त होते.

ब) सन २००२—०३ साली कृषी उत्पादन १२.०६ टक्के ने घटले होते. त्यांच्यानंतर सन २०१३—१४ मध्ये सुध्दा घट झाली होती.

क) शेतीमधील वाढ १९९६ मध्ये ४.६९ टक्के होती. ती १९९७—९८ मध्ये २.०६ टक्के पर्यंत खाली आली. आणि २००२—०३ साली ती १.१ टक्के पर्यंत खाली आली.

ड) भारतामध्ये आजही कृषी मजुरीचे दर १.५ ते २ डॉलर दरम्यान आहे ते जगामध्ये फारच कमी आहेत. बऱ्याच शेतकऱ्यांना पतसंस्थांकडून त्यांच्या गरजेच्या फक्त २० टक्के कर्ज प्राप्त होते बाकी खाजगी सावकाराकडून घ्यावे लागते.

iii) कृषी अनुदारने :

विकसीत राष्ट्रे आपल्या शेतकऱ्यांना सबसिडी देऊन सुरक्षा देतो. त्यामुळे त्यांच्या शेतीची उत्पादकता ही जास्त आहे. मात्र जागतिकीकरणामुळे शेतकरी हा अनुदानालाच मुकला, तर इकडे WTO ने भारतातील शेतमाल बाजार खुला करावा व त्यात खाजगीपणाचा आग्रह धरला होता. मात्र तो भारतातील राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्षित केला. कृषी निविष्ठीवरील अनुदानामुळे सरकारी तिजोरीचा भार वाढतो म्हणुन नविन आर्थिक धोरणात या निवेदेवर दिले जाणारे अर्थसहाय्य हळुहळू कमी करण्याचा प्रस्ताव होता व याचा फटका लहान व सिमांत शेतकऱ्यांना बसला. कृषी अर्थसहाय्याचा फायदा फक्त सधन शेतकऱ्याचा झाला. भारतातील शेतकरी विकसीत देशाशी स्पर्धा करू शकत नाही. कारण विकसीत देशात अर्थसहाय्य देऊन उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. जापानमध्ये कृषी उत्पादनाच्या एकूण किमतीच्या ८२.५ टक्के दक्षिण कोरीयात ६२ टक्के चीनमध्ये ३४ टक्के अमेरिका २८ टक्के अनुदान दिले जाते. तर भारतात हे अनुदान केवळ ३.३४ टक्के आहे. अमेरिका व युरोप राष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष सबसिडी दिली जाते. भारतात प्रती शेतकऱ्याला १११ डॉलर सबसिडी दिली जाते तर तीच अमेरीका ४०,००० डॉलर, युरोपिय राष्ट्र ३४,००० डॉलर सबसिडी देते त्यामुळे शेती उत्पादनाच्या किमती कमी होऊन त्याचा तोटा भारतीय शेतीला होत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने १९९९ च्या अहवालात सर्व देशांनी शेतीवरील अनुदान २० टक्के पर्यंत कमी करावेत असे मत मांडले तो याचाच परिणाम होय.

iv) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रवेश :

जागतिकीकरणाचा अंमलबजावणीमुळे भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रवेश झाला. उदा. कारगील सीड्स सॅडोज पायोनियर, हिंदुस्तान लिव्हर, ॲग्रोटेक यासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या शेतीसाठी लागणाऱ्या बि—बियानांच्या बाजारात उतरल्या यावेळी या कंपन्यासाठी राष्ट्रसंघाने आचारसंहितेचा मसूदा तयार केला होता. त्यात भारतीय कृषी

v) शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा :

जगतिकीकरणानंतर आपल्याकडील राष्ट्रीयकृत बॅकावर बरेच निर्बंध लादण्यात आले. पुर्वी गाय, बैल, खते इतर घेण्यासाठी बॅका शेतकऱ्यांना कर्ज देत होत्या. शेतकऱ्यांचा विकास झाला पाहिजे त्याला सावकाराकडे जावे लागू नये हा त्याचा उद्देश होता. पण हळुहळू बॅकांनी ग्रामीण भागातील आपला व्यवहार कमी केला. त्यामुळे खाजगी सावकारीचे प्रमाण वाएले. विदेशी कंपन्यांनी शेतकऱ्याना बि—बियाने, खते, औषधाचे प्रमाण याविषयीची माहिती दिली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक भुर्दंड बसला. त्यामुळे खर्चात वाढ व उत्पादन कमी अशी परिस्थिती

निर्माण झाली. खरे पाहता कंपन्यांनी खते किटकनाशके बि—बियाणे यांच्या वापराबाबत शेतकऱ्याचा किती कर्जबाजारीपणा वाढत गेला. सावकाराच्या दाराशी वाढत गेलेला शेतकऱ्याला सावकाराचे व्याजाचे दर नेमके किती हे कळलेच नाही त्यामुळे सावकाराच्या दारात एकदा गेलेला शेतकरी कायम त्यात अडकला. अलिकडील एन.एस.एस.च्या निरीक्षणानुसार भारतीय शेतकऱ्यावर सरासरी १२,५८५ रू. कर्ज होते त्यामध्ये पंजाबच्या शेतकऱ्यावर सर्वाधिक म्हणजे ४१,५६५ रू. कर्ज असल्याचे दिसून आले.

vi) शेतकऱ्याची आत्महत्या :

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. आज जरी कृषी क्षेत्राचा हिस्सा कमी होत असला तरी आज अजुनही ५९ ग्रामीण भागातील गरीब जनतेशी रोजीरोटी या व्यवसायाशीच जुडलेली आहे. नविन अधिक धोरणानंतर कृषीक्षेत्राचा देशातील एकूण उत्पन्नातील हिस्सा कमी होत गेला. जागतिकीकरणाच्या नादात भारताने कृषी व्यवस्थाकडे दुर्लक्ष झाले. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भारतातील शेतकऱ्याची स्पर्धा आता जागतिक बाजारपेठेशी झाले. त्यामुळे आपला शेतकरी या स्पर्धेत टिकणार नाही. पर्यायाने भारतीय शेतकरी अधिक दरिद्री बनत गेला. शेतीत गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी झाले. शेतकऱ्यानी दिल्या जाणाऱ्या सबसीडीत कटौती केल्यामुळे शेतकऱ्याच्या शेतीवरील खर्च वाढला. नैसर्गिक अनियमितता, शेतकऱ्याचे अज्ञान यातून शेतकऱ्याच्या कर्जबाजारीपणा वाढत गेला. हा वाढलेला कर्जबाजारीपणा शेतकऱ्याच्या जीवनात असुरक्षीततेकडे ढकलला जाऊ लागला व त्यातुन शेतकऱ्याच्या आत्महत्या वाढल्या. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी या ऐवजी या ऐवजी उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ शेती अशी अवस्था दृढ झाली आहे. १९९७ पासून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचे प्रमाण वाढत गेले. १९९७ ते २००१ या काळात राष्ट्रीय पातळीवरील आत्महत्यांची सरासरी १५,७४७ शेती नंतरच्या २००२ ते २००६ या काळामध्ये ही सरासरी १७,३६६ वर जाऊन पोहचली. महाराष्ट्रामध्ये / विदर्भात आत्महत्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. २००६ मध्ये १४४८ शेतकऱ्यांनी तर २००७ मध्ये १२४६ तर २००८ व २००९ मध्ये अनुक्रमे ३०५ व २०१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. सर्वाधिक आत्महत्या ह्या विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये झाल्या.

vii) जगतिकीकरणाचा कृषीवर झालेला परिणाम :

i) उदरनिर्वाह शेतीचे व्यापारीकरण — पूर्वी शेती फक्त उदरनिर्वाहासाठी केली जात असे. परंतु सध्या ही शेती वेगवेगळ्या व्यापारी पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. उदा. भाजीपाला, कापूस, नारळ, फळे इ.

ii) नवनवीन बि—बियाणे — अधिक उत्पादन घेण्यासाठी व बाजारपेठेत कृषी मालाला जास्त भाव मिळण्यासाठी शेतकरी कीटक नाशके, बि—बियाणे, रासाणनिक खते इ. चा वापर करू लागला.

iii) खते आणि कीटकनाशकांच्या वाढत्या किंमती — जागतिकीकरणाचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना असा बसला की, भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन २५ टक्के झाले. पीक उत्पादने स्वस्त झाली.

iv) विजेचे दर देखील वाढले.

v) माल वाहतूक व माल साठवणूक सुलभ — नाशवंत माल बाजारपेठेत लवकर पोहोचणे आवश्यक असते. त्यासाठी वाहतूक व साठवणूक करणे आवश्यक असते.

vi) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रभाव — जागतिकीकरणामुळे शेतीचे करारीकरण झाले. ठराविक कंपन्यांचा प्रभाव वाढला.

vii) शेतचे प्रायोगिकरण — जैविक विज्ञानामुळे उती संवर्धनाचे शेतीचे प्रयोग शाळेचे स्वरूप प्राप्त झाले.

viii) नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला — उदा. पीक फवारणी, शेती अवजारे, पीक लागवड.

ix) जागतिकीकरणामुळे कृषी भूगोलाचे स्वरुप व व्याप्ती यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.

x) जागतिकीकरणामुळे कृषी भूगोलामध्ये वेगवेगळ्या शेतीपध्दतीचा विकास झाला. उदा. सखोल शेती, फळबाग शेती इ.

xi) कृषीच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर संशोधन होऊ लागले.

xii) कृषीमध्ये वेगवेगळ्या जलसिंचनाचा वापर होऊ लागला. उदा. ठिबकसिंचन, तुषारसिंचन

xiii) जागतिकीकरणामुळे शाश्वत शेतीचा विकास झाला.

निष्कर्ष :

i) पारंपारिक पध्दतीने शेती केल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढ होत नव्हती. ती जागतिकीकणामुळे भरमसाठ वाढ झाली.

ii) कृषी भूगोलामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आणि शेतकरी प्रयोगशील बनला.

iii) जागतिकीकरणामुळे अर्थव्यवस्था प्रगत झाली.

iv) जागतिक बाजारपेठ निर्माण झाल्यामुळे शेती मालाला योग्य तो भाव मिळू लागला.

v) जागतिकीकरणामुळे कृषीचे प्रादेशीकरण झाले.

vi) जागतिकीकरणामुळे कृषीचे भूमी उपयोजन वाढले.

vii) जागतिकीकरणामुळे कृषी भूगोलामध्ये अमुलाग्र बदल होऊन शेतीचा विकास झाला आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दर्जा सुधारला, कालांतराने ग्रामीण भागाचा विकास झाला.

हरितक्रांतीने भारतीय उत्पादन व्यवस्थेत बदल करून अधिक उत्पादन करणारे बाब विकसित केल्यामुळे अल्पावधीत भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्व झाला. पण १९९१ मध्ये जागतिकीकरणाचे धोरण स्विकारल्यामुळे कृषीक्षेत्रात अनेक परिवर्तने घडून आले. बि—बियाने किटकनाशके रासायनिक खते यांच्या किमती वधारल्या पण त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकले नाही. सबसिडीत कटौती केल्या गेली. एकीकडे अनुदाने संपुष्टात आणल्या गेली तर दूसरीकडे निसर्गावर अवलंबुन असणाऱ्या शेतीत निसर्गाच्या अनियमितपणामुळे संकट कोसळला.

संदर्भग्रंथ :

i) डॉ. जयप्रकाश मिश्र — कृषी अर्थव्यवस्था, साहित्यभवन पब्लिकेशन, आग्रा

ii) खरे सी. प. ‘जागतिकीकरण समस्या आशय आणि अनुभव’, दिलीपराज प्रकाशन, पुणे, २०१२

iii) पंडीत नलिनी ‘जागतिकीकरण आणि भारत’ लोकवाङमय गृह, मुंबई, २००३

iv) योजना ‘भारतीय शेती निर्णायतेकडे’ (विशेषांक) वर्ष ३८, अंक ६, जाने, २०११०

v) योजना ‘जागतिकीकरण आणि भारतीय शेती पुढील आव्हाने’, वर्ष ३७, अंक ६, जाने, २०१०

vi) डॉ. झामरे जी. एस. ‘भारतीय अर्थव्यवस्था विकास व पर्यावरणात्मक अर्थशास्त्र’ पिंपळापुरे ॲण्ड पब्लिशर्स, नागपूर, ५ वी आवृत्ती, २०१ ९८

vii) Prakash B. A. – The Indian Economy since 1991, peason Publication, Delhi

viii) Vasant Desai – Rural Development in India – Past, Present and Future, Himalaya Publication, New Delhi

Chief Editor
P. R. Talekar
Secretary, Young Researcher Association, Kolhapur (M.S), India

Executive Editors
Dr. C. B. Kolekar
Principal
Sahakar Maharshi Shankarrao Mohite Patil Mahavidyalaya, Natepute

Co- Editors		
Dr. R. J. Khandare	S. R. Nalawade	D. S. Thorat
J. D. Mulik	S. H. Pawar	Dr. B. T. Nikam
R. A. Shaikh	U. A. Sawant	